

**RURAL DEVELOPMENT AND SOCIAL CHANGE :  
A CASE STUDY OF BHANPUR TAHSIL  
DISTRICT BASTI  
U. P.**



**THESIS**  
Submitted for the degree of  
**DOCTOR OF PHILOSOPHY**  
IN  
**GEOGRAPHY**

*Under the supervision of*  
**Dr. Kum Kum Roy**  
Professor in Geography  
University of Allahabad

*Submitted by*  
**PRAMOD KUMAR UPADHYAY**


**DEPARTMENT OF GEOGRAPHY  
UNIVERSITY OF ALLAHABAD  
ALLAHABAD-211002**

**2002**



**This is to certify that Shri  
Pramod Kumar Upadhyay has  
worked for the full period prescri-  
bed under D. Phil ordinances of  
Allahabad University, Allahabad,  
under my supervision. It is reco-  
mmended that his D. Phil thesis  
entitled: "Rural Development  
and Social Change: A Case Study  
of Bhanpur Tehsil District Basti  
U.P.", which embodies the results of  
his personal investigations, may be  
submitted for evaluation.**

**Dated**

  
**Prof.(Dr.)Kumkum  
(supervisor)**

परम पूज्य चाच जी  
श्री सन्त राम उपाध्याय  
को  
समर्पित

## साभार

सर्वप्रथम इस शोध प्रबन्ध की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिये वन्दनीय, परम श्रद्धेया डॉ० कुमकुम रॉय, प्रोफेसर भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होंने मेरे पथ प्रदर्शन का गुरुतर भार स्वीकार कर मुझे शोध-कार्य करने हेतु अभिप्रेरणा प्रदान की। आपके उत्तम निर्देशन, उदात्त विचार एवं अप्रतिम सहयोग के परिणामस्वरूप ही मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ। आपकी प्रज्ञा-ज्योति से मेरे शोधमार्ग में आया तिमिर सरलतया दूर होता गया जिसके परिणामस्वरूप मैं इस दुस्तर अम्बुधि का सहजता से उत्तरण कर सका हूँ।

शोध से सम्बन्धित समस्याओं के निवारण में प्रदत्त अमूल्य योगदान हेतु मैं परमपूज्य गुरुवर डॉ० आर०सी० तिवारी, प्रोफेसर भूगोल विभाग तथा शोध कार्य में प्रदत्त विभागीय सुविधाओं हेतु विकास पुरुष डॉ० सविन्द्र सिंह विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति श्रद्धावनत हूँ। डॉ० एच० एन मिश्र प्रोफेसर भूगोल विभाग का मैं अर्न्तमन से आभारी हूँ जिन्होंने अपने उत्तम सुझावों द्वारा मेरे मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास किया। मैं विभाग के उन समस्त गुरुवृन्दों को जिन्होंने अपने ज्ञान और व्यक्तित्व-प्रकाश से मेरा अन्धतम मार्ग आलोकित किया उसके लिये मेरे जीवन की श्रद्धा उनके चरणों में समर्पित है। मित्र अनुपम पाण्डेय (प्रवक्ता भूगोल विभाग) का सहयोग अपेक्षित रहा तथा विभाग के समस्त कर्मचारियों का आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया।

अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी, कर्मठता के प्रतीक, परमादरणीय चाचा श्री सन्तराम उपाध्याय (प्रवक्ता दि०इ०, कालेज, रुधौली, बस्ती) एवं धार्मिक आस्था से परिपूर्ण चाची श्रीमती सावित्री देवी से प्राप्त अनन्य सहयोग के लिये आभार व्यक्त करना मेरी सामर्थ्य से परे है क्योंकि इनके द्वारा प्रदत्त सहयोग को शब्दों में अभिव्यक्त करना असम्भव है। जहाँ परम पूज्य पिता श्री हरीराम उपाध्याय एवं ममतामयी माता श्रीमती शान्ती देवी का निश्चल स्वभाव सहृदय प्रेम मुझे प्रगति की प्रेरणा देता रहा वही अग्रज श्री अनिल कुमार उपाध्याय, श्री सुशील कुमार उपाध्याय तथा श्री अनिरुद्ध मिश्रा का सदैव ऋणी रहूँगा जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में भी शोध कार्य से सम्बन्धित तथ्यों के संग्रहण में सहयोग प्रदान किया।



शोध कार्य में अनन्य सहयोग के लिये डॉ० कमलेश्वर त्रिपाठी (भूगोल विभागाध्यक्ष किसान डिग्री कालेज, बस्ती) डॉ० आर०के० पाठक (विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग ए०पी०एन० डिग्री कालेज, बस्ती) डॉ० एस०एन० मिश्रा, ए०एन० चौधरी, डॉ० रघुनाथ चौधरी, श्री दीपक उपाध्याय एवं श्री एम०आर० वर्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

तहसील, जनपद एवं जनपद के विभिन्न भागों में स्थित कार्यालयों से आवश्यक अभिलेख एवं तथ्य युक्त सामग्री उपलब्ध कराने में जिलाधिकारी, सख्याधिकारी, सूचनाधिकारी, उपजिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, सहित सभी ग्राम प्रधानों, ग्रामवासियों को जिन्होंने शोध कार्य में सहायता प्रदान की उसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा आकड़ा संग्रहण में सहयोग हेतु श्री प्रमोद कुमार पाठक, श्री अजय कुमार द्विवेदी, श्री विजय प्रताप उपाध्याय, श्री जर्नादन प्रसाद मिश्रा, श्री पारसनाथ चौधरी, श्री शिव कुमार पाण्डेय, श्री राजेश कुमार पाण्डेय एवं श्री बी०एल० वर्मा का हृदय से मैं आभारी हूँ। आकड़ा संग्रहण, आरेखण एवं शोध कार्य में सहयोगी रहे मित्र शिवेन्द्र अग्रहरि, भूपेन्द्र तिवारी, प्रशान्त एवं अपनी सम्पूर्ण शक्ति से समर्पित सेवाएँ देने के लिये अनुज समतुल्य उमाशंकर सिंह को सधन्यवाद देता हूँ।

समादरणीय अग्रज श्री राजू शुक्ला, बड़े भैया श्री बिनोद कुमार उपाध्याय (अधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद), श्री आशुतोष तिवारी (अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद), श्री बलराम सिंह, श्री धमेन्द्र सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री समीउल्लाह सहित सभी शुभेच्छुओं का मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे शोध कार्य के प्रति प्रेरणा प्रदान करते रहे। मेरे सर्वप्रिय अनुज पवन उपाध्याय का अहर्निश सहयोग तथा छोटे भाई मनोज का प्रेम मुझे क्रियाशील रखा।

मैं गुरुपति स्वर्गीय श्री धीरज कुमार रॉय के दिवंगत आत्मा के प्रति नतमस्तक हूँ जिनके उत्तम कृत्य एवं विचार मेरा मनोबल बढ़ाते रहे हैं। गुरुपुत्र संदीप रॉय एवं पुत्री शिल्पी रॉय को ओजस्वी तथा प्रगति हेतु शुभकामना प्रदान करना अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ।

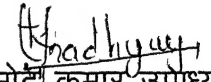
अभिन्न मित्रों में सजीव बाजपेयी, नवीन द्विवेदी, अवनीश सिंह, पीयूष पाण्डेय, आलोक त्रिपाठी, सतीश चन्द मौर्य, सुरेश, बिमलेन्द्र, सुनील, मनीष एवं राकेश श्रीवास्तव को धन्यवाद देता हूँ, जिनका सहयोग सदैव मिलता रहा। शोध मित्रों में सर्वश्री अनिल

शुक्ला, सजय मिश्रा, प्रदीप सिंह, ए0आर0 त्रिपाठी, विनय रॉय, आर0पी0 यादव, मनोज सिंह, पूनम कुशवाहा, मजू सिंह, को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शोध कार्य में सहयोग देने वाले अनुजो में परितोष तिवारी, विवेक सिंह, करुणेश शुक्ला, राजेश मौर्या, रानू एव सोनू को मैं सहृदय आशीर्वाद देता हूँ।

आदरणीय बड़ी भाभी श्रीमती रीता एव उषा उपाध्याय का अनन्य प्रेम प्रेरक रहा वही पुत्र लोकेश, रूपेश एव देवेश की चंचलता मुझे कर्म के प्रति क्रियाशील रखी।

मानचित्रण कार्य हेतु डॉ0 राजमणि त्रिपाठी, कम्प्यूटर मालिक डॉ0 रफी उल्लाह का सहयोग तथा द्रुतगति टाइप के लिये दिलीप दुबे एव आरेखन हेतु जिया भाई को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध पूर्ण होने में सहायता प्रदान की।

19 नवम्बर,  
कार्तिक पूर्णिमा,  
2002

  
प्रमोद कुमार उपाध्याय

## अनुसूची

पृष्ठ संख्या

आभार

List of Figures

XIV

चित्रों की सूची

XV

तालिका क्रमांकों की सूची

XVI, XVII

### अध्याय-1

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन : संकल्पना

1-53

प्रस्तावना

1.1 ग्रामीण विकास : अर्थ एवं परिभाषा

1.1.1 ग्राम एक सामाजिक इकाई के रूप में

1.1.2 विकास की संकल्पना एवं उद्देश्य

1.1.3 ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले कारक

1.2 भारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक विकास

1.2.1 स्वतन्त्रता से पूर्व ग्रामीण विकास

1.2.2 स्वातंत्र्योत्तर ग्रामीण विकास

1.3 पंचवर्षीय योजनाएं और ग्रामीण विकास

1.3.1 ग्रामीण विकास की योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन

1.3.2 नियोजित ग्रामीण विकास और सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

1.4 सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा

1.5 ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन

1.6 ग्रामीण विकास और सामाजिक रूपान्तरण की प्रकृति एवं दिशा

1.7 वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य

## 1.8 शोध-विधितंत्र

181 आकडो का सग्रहण

182 शोध विधितंत्र का विश्लेषण एव व्याख्या

## अध्याय-2

### भौतिक प्रतिरूप

54-77

2.1 स्थिति एवं विस्तार

2.2 उच्चावच्च एवं संरचना

2.3 अपवाह प्रणाली तथा जलाशय :-

231 कुआनो नदी

232 कठिनइया नदी

233 आमी नदी

234 नाले एव तालाब

2.4 जलवायु :-

241 तापमान

242 वर्षा

243 सापेक्षिक आद्रता

244 वायुदाब एव पवन

2.5 मृदा :-

251 बलुई मिट्टी

252 बलुई दोमट मिट्टी

253 मटियार दोमट मिट्टी

254 लवण युक्त 'रेह' या ऊसर मिट्टी

255 भूमिगत जल

2.6 भ्वाकृतिक प्रदेश

2.7. प्राकृतिक वनस्पति

2.8 खनिज सम्पदा

### अध्याय—3

#### जनसंख्या प्रतिरूप

78—123

#### प्रस्तावना

3.1 जनसंख्या विवरण

3.2 जनसंख्या वृद्धि

3.3 जनसंख्या वितरण प्रतिरूप

3.4 जनसंख्या घनत्व :—

341 अति न्यून जनसंख्या घनत्व क्षेत्र

342 निम्न जनसंख्या घनत्व क्षेत्र

3.43 मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र

344 उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र

345 अत्यन्त उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र

3.5. आयु—लिंग संरचना

3.6 साक्षरता

3.7 व्यावसायिक संरचना :—

3.7.1. कार्यरत एवं अकार्यरत जनसंख्या

3 7 2 1 कृषक

3 7 2 2 कृषि श्रमिक

3 7 2 3 उद्योग एव निर्माण

3 7 2 4 अन्य कार्यों मे लगी जनसख्या

3 8 जनसंख्या—ग्रामीण विकास एव सामाजिक परिवर्तन

#### अध्याय—4

कृषि विकास और सामाजिक परिवर्तन

124—17

#### प्रस्तावना

4.1 भूमि उपयोग

4.2 शस्य प्रतिरूप

4 3 शस्य क्रम

4.4. अध्ययन क्षेत्र में कृषि की आधारभूत सुविधाओं की स्थिति

4 4 1 सिंचाई

(अ) नहर

(ब) नलकूप

(स) कूप

(द) तालाब एव अन्य साधन

4 4 2 उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं

4.4.3 कृषि यन्त्र एव उपकरण

4.4.4. पशु ससाधन

4.4 5. पशु चिकित्सालय एव अन्य सेवाये

- 4 5 कृषि मे अभिनव विकास की प्रवृत्तिया
- 4 5 1 वाणिज्यिक फसलो के क्षेत्रफल मे वृद्धि
- 4 5 2 बागवानी मे वृद्धि
- 4 5 3 नलकूपो की सख्या से वृद्धि
- 4 5 4 रासायनिक उर्वरको का अधिक प्रयोग
- 4 5 5 कृषि का यन्त्रीकरण
- 4 5 6 कृषि जोत आकार मे ह्रास
- 4 6 कृषि समस्यायें :-
- 4 6 1 मौसमी परिवर्तन
- 4 6 2 भूक्षरण
- 4 6 3 अव्यवस्थित विद्युत आपूर्ति
- 4 6 4 अज्ञानता एव निर्धनता
- 4 6 5 कृषि उत्पाद विपणन एव कृषि ऋण
- 4 7. कृषि विकासार्थ नियोजन

#### अध्याय—5

ग्रामीण यातायात, संचार व्यवस्था एवं सेवा केन्द्र

172—209

#### प्रस्तावना

#### 5.1. परिवहन तंत्र का स्थानिक प्रतिरूप

##### 5 1 1 सडक मार्ग

##### 5.1.1.1 सडक यातायात प्रवाह

##### 5.1.1.2 सडक सम्बद्धता

- 5 2 यातयात नियोजन
- 5 3 संचार प्रतिरूप
  - 5 3 1 डाकघर
  - 5 3 2 तारघर
  - 5 3 3 दूरभाष
  - 5 3 4 अन्य संचार साधन
- 5 4 संचार नियोजन
- 5 5 यातायात एवं संचार माध्यमों का ग्रामीण विकास तथा सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव
- 5.6 सेवा केन्द्र का अभिप्राय
- 5 7 सेवा कार्य एवं केन्द्रीयता मान
- 5 8 सेवा केन्द्रों का निर्धारण
- 5 9 सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता
- 5 10 सेवा केन्द्रों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप
  - 5 10 1 सेवा क्षेत्र
  - 5 10 2 प्रस्तावित सेवा कार्य
- 5.11 सेवा केन्द्र, ग्रामीण विकास और परिवर्तन

## अध्याय—6

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में उद्योग एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका

प्रस्तावना

210—239

### 6.1 उद्योग का वर्गीकरण



6 1 2 लघु स्तरीय उद्योग

6 1 3 पूरक उद्योग

6 1 4 अति लघु उद्योग

6 1 5 खादी एवं ग्रामोद्योग

## 6 2. औद्योगिक प्रतिरूप

## 6 3 उद्योग अवस्थापन तथा कार्यक्रम

6 3 1 जिला उद्योग केन्द्र योजना

6 3 2 एकल मेज व्यवस्था

6 3 3 स्वरोजगार बन्धु योजना

6 3 4 उद्यमिता विकास कार्यक्रम

6 3 5 उद्योग बन्धु

6 3 6 उ0प्र0 लघु उद्योग आधुनिकीकरण योजना

6 3 6 बीमार एवं लघुतर औद्योगिक इकाइयो का पुर्नवासन

6 3 8 कलस्टर योजना

## 6.4 उद्योग संबंधी प्रमुख संस्थाएँ एवं विभाग

## 6.5 औद्योगिक समस्याएँ

6 5.1 खनिजो का अभाव

6.5 2 तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव

6.5.3 औद्योगिक औद्योगिक उत्पादो का वितरण

6.5.4 ऊर्जा, परिवहन एवं संचार साधनो का अभाव

6.5.5 साक्षरता की कमी

- 6 6 औद्योगीकरण की अभिनव प्रवृत्तियाँ एवं औद्योगिक नियोजन
- 6 7 औद्योगिक सम्भाव्यता एवं प्रस्तावित उद्योग
  - 6 7 1 कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग
  - 6 7 2 पशु एवं पशु आधारित उद्योग
  - 6 7 3 वनोत्पाद आधारित उद्योग
  - 6 7 4 मॉग पर आधारित उद्योग
- 6 8 औद्योगिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन
  - 6 8 1 सामाजिक जीवन में परिवर्तन
  - 6 8 2 पारिवारिक जीवन में परिवर्तन
  - 6 8 3 धार्मिक जीवन में परिवर्तन
  - 6 8 4 राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन

## अध्याय—7

### ग्रामीण विकास की प्रमुख समस्याएँ सुविधायें एवं समस्यायें

प्रस्तावना

240—272

#### 7.1 शिक्षा

- 7 1 1 शिक्षा का वर्तमान प्रतिरूप
- 7 1 2 प्राथमिक शिक्षा
- 7 1 3 माध्यमिक शिक्षा
- 7 1.4 उच्च शिक्षा
- 7 1 5 प्राविधिक शिक्षा
- 7 1 6 अनुसूचित जाति शिक्षा
- 7 1.7 स्त्री शिक्षा

## 7 2 शिक्षा की समस्यायें

7 2 1 बेरोजगारी

7 2 2 निर्धनता एवं अवसरो का अभाव

## 7 3 ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु नियोजन

## 7 4 ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्यायें एवं निवारणार्थ सुझाव

7 4 1 प्रदूषित ग्रामीण पर्यावरण

7 4 2 दूषित पेयजल

7 4 3 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाये

7 4 4 नशीले पदार्थों के प्रति बढ़ती अभिरुचि

7 4 5 स्ववास्थ्य सुविधाओ की कमी

7 4 6 ग्रामीण रूढिवादिता

## 7 5 पेयजल सुविधा

## 7.6 बैंक

## 7 7 विद्युत आपूर्ति

## 7.8 नागरिक सुरक्षा

## 7.9 सामाजिक समस्याएँ

7 9 1 दहेज प्रथा

7 9 2 जाति व्यवस्था

7 9.3 अस्पृश्यता

7.9 4 पर्दा प्रथा

7 9.5 बाल विवाह

ग्रामीण विकास के स्तर और सामाजिक परिवर्तन

प्रस्तावना

273—292

8 1 ग्रामीण विकास के सूचकांक

8 2 ग्रामीण विकास के स्तर

8 2 1 कृषि विकास

8 2 2 ग्रामीण शैक्षणिक विकास

8 2 3 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं का विकास

8 2 4 ग्रामीण यातायात एवं संचार साधनों का विकास

8 2 5 ग्रामीण औद्योगिक विकास

8 3 समेकित ग्रामीण विकास स्तर

8 3 1 विकसित ग्रामीण क्षेत्र

8 3 2 विकासशील ग्रामीण क्षेत्र

8 3 3 अविकसित ग्रामीण क्षेत्र

8.4 ग्रामीण सामाजिक जीवन में परिवर्तन

8.5 सामाजिक जीवन पद्धति में परिवर्तन

8.5 1 ग्रामीण पारिवारिक संरचना में परिवर्तन

8.5 2 वैवाहिक परम्परा में परिवर्तन

8.5.3 जाति व्यवस्था

8.5.4 आहार में परिवर्तन

8.5.5 परिधान में परिवर्तन

8.5.6 आवास व्यवस्था में परिवर्तन

857 ग्रामीण सामुदायिक जीवन

8.6 धार्मिक क्रिया कलाओं में परिवर्तन

8.7 ग्रामीण मनोवृत्ति एवं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन

8.8 अध्ययन क्षेत्र के उन्नयन हेतु सुझाव

### अध्याय-9

## ग्रामीण विकास नियोजन

293-311

### प्रस्तावना

9.1 ग्रामीण विकास नियोजन हेतु कार्यक्रम

9.1.1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम

9.1.2 गहन कृषि विकास कार्यक्रम

9.1.3 लघु कृषक विकास कार्यक्रम

9.1.4 सीमांत कृषिक एवं कृषिक श्रमिक कार्यक्रम

9.1.5 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

9.1.6 कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

9.1.7 विशिष्ट पशु उत्पादन कार्यक्रम

9.1.8 कार्य बदले अनाज भोजन कार्यक्रम

9.1.9 नकद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

9.1.10 सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

9.1.11 मरुभूमि विकास कार्यक्रम

9.1.12 जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

9.1.13 समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

9.1.14 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

- 9 1 15 स्वरोजगार हेतु ग्रामीण नवयुवको का प्रशिक्षण
- 9 1 16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
- 9 1 17 ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चे के लिये विकास कार्यक्रम
- 9 1 18 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
- 9 1 19 जवाहर रोजगार योजना
- 9 1 20 इन्दिरा आवास योजना
- 9 1 21 मिलियन कुआ योजना
- 9 1 22 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
- 9 1 23 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

## 9.2 उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास की अद्यतन योजनायें

- 9 2 1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
- 9 2 2 जवाहर ग्राम सवृद्धि योजना
- 9 2 3 ग्रामीण आवास योजना
- 9 2 4 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
- 9 2 5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- 9 2 6 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)
- 9 2 7 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल)
- 9 2 8 ग्रामीण पेयजल योजना
- 9 2 9 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना
- 9.2.10 रोजगार छतरी योजना
- 9.2.11 दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान
- 9 2 12 पोषण परियोजना

### 9 3 ग्रामीण विकास नियोजन में पंचायती राज की भूमिका

9 3 1 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

9 3 2 विकास पर पंचायती राज का प्रभाव

9 3 3 मूल्यांकन

9 3 4 निष्कर्ष

सारांश तथा निष्कर्ष

312—322

परिशिष्ट

## **LIST OF FIGURES**

<b>FIG NO.</b>	<b>TITLE</b>	<b>Page No.</b>
2 1	Location Map Tahsil Bhanpur, District Basti	55
2 2	Drainage System	60
2 3	Climate	66
	(A) Temperature	
	(B) Hyther Graph	
	(C) Climograph	
	(D) Pressure	
2 4	Soils	70
2 5	Physiographic division	74
3 3	Distribution of population, 2001	89
3 6	Population density, 2001	98
3 7	Sex-ratio Map, 2001	100
3 9	Rural literacy, 1991	107
3 10	Distribution of S C Population 1991	110
4 2	Land Use pattern, 1998-99	130
4 5	Source of Irrigation	142
4 6	Distribution of Cannals & Tube-wells	145
5 1	Transport Network, 2001	176
5 2	Spatial pattern of P O, P S and P.T.O	189
5 3	Service Centre	201
6 1	Proposed Industries	236
7.1	Education facilities	249
7 2	Banking facilities	261
8.1.	Trends in level of Rural development	280
1	Village location map	



## आरेखों की सूची

चित्र सख्या-3 1	भानुपुर तहसील	जनसख्या विवरण	82
चित्र सख्या-3 2	भानपुर तहसील	जनसख्या वृद्धि	84
चित्र सख्या-3 4	भानपुर तहसील	जनसख्या घनत्व	92
चित्र सख्या-3 5	भानपुर तहसील	जनसख्या घनत्व	96
चित्र सख्या-3 8	भानपुर तहसील	साक्षरता	105
चित्र सख्या-3 11	भानुपुर तहसील	व्यवसायिक संरचना	115
चित्र सख्या 3 12	भानपुर तहसील	कार्यरत जनसख्या	119
चित्र सख्या 4 1	भानपुर तहसील	भूमि उपयोग का विवरण	126
चित्र सख्या 4 3	भानपुर तहसील	रबी के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र (1988-99)	134
चित्र सख्या 4 4	भानपुर तहसील	खरीफ के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र	138
चित्र सख्या 4 7	भानपुर तहसील	उर्वरक विवरण	150
चित्र सख्या 4 8	भानपुर तहसील	पशु संसाधन (2000-2001)	155

## तालिका क्रमांक : सूची

- |      |                        |                 |  |
|------|------------------------|-----------------|--|
| (1)  | तालिका क्रमांक-2 1     | भानपुर तहसील    | प्रशासनिक सगठन                               |
| (2)  | तालिका क्रमांक-2 2     | भानपुर तहसील    | सामान्य तापमान                               |
| (3)  | तालिका क्रमांक-2 3     | भानपुर तहसील    | वायुदाब                                      |
| (4)  | तालिका क्रमांक-3 1     | भानपुर तहसील    | आबाद ग्रामों का विवरण                        |
| (5)  | तालिका क्रमांक-3 2     | भानपुर तहसील    | जनसंख्या विवरण                               |
| (6)  | तालिका क्रमांक-3 3 (A) | भानपुर तहसील    | जनसंख्या वृद्धि                              |
| (7)  | तालिका क्रमांक-3 3 (B) | बस्ती जनपद      | जनसंख्या वृद्धि                              |
| (8)  | तालिका क्रमांक-3 4     | भानपुर तहसील    | जनसंख्या वितरण                               |
| (9)  | तालिका क्रमांक-3 5     | भानपुर तहसील    | जनसंख्या घनत्व                               |
| (10) | तालिका क्रमांक-3 6     | न्याय पंचायतवार | जनसंख्या घनत्व                               |
| (11) | तालिका क्रमांक-3 7     | भानपुर तहसील    | यौनानुपात                                    |
| (12) | तालिका क्रमांक-3 8     | भानपुर तहसील    | साक्षरता                                     |
| (13) | तालिका क्रमांक-3 9     | भानपुर तहसील    | अनुसूचित जाति का विवरण                       |
| (14) | तालिका क्रमांक-3 10    | भानपुर तहसील    | विभिन्न कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की स्थिति |
| (15) | तालिका क्रमांक-3 11    | भानपुर तहसील    | व्यवसायिक जनसंरचना                           |
| (16) | तालिका क्रमांक-3 12    | भानपुर तहसील    | कार्यरत जनसंख्या का विवरण                    |
| (17) | तालिका क्रमांक-4.1     | भानपुर तहसील    | भूमि उपयोग का विवरण                          |
| (18) | तालिका क्रमांक-4.2     | भानपुर तहसील    | विकास खण्ड में भूमि उपयोग का विवरण           |
| (19) | तालिका क्रमांक-4 3     | भानपुर तहसील    | रबी के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र               |
| (20) | तालिका क्रमांक-4.4     | भानपुर तहसील    | खरीफ के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र              |

- |      |                    |              |                                    |
|------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| (21) | तालिका क्रमांक-4 5 | भानपुर तहसील | स्रोतानुसार सिंचित क्षेत्र         |
| (22) | तालिका क्रमांक-4 6 | भानपुर तहसील | सिंचाई साधन का विवरण (1999-00)     |
| (23) | तालिका क्रमांक-4 7 | भानपुर तहसील | उर्वरक विवरण                       |
| (24) | तालिका क्रमांक-4 8 | भानपुर तहसील | पशु ससाधन                          |
| (25) | तालिका क्रमांक-4 9 | भानपुर तहसील | क्रियात्मक भूमिजोत का विवरण        |
| (26) | तालिका क्रमांक-5 1 | भानपुर तहसील | प्रमुख सडक मार्ग                   |
| (27) | तालिका क्रमांक-5 2 | भानपुर तहसील | पक्की सडको की लम्बाई               |
| (28) | तालिका क्रमांक-5 3 | भानपुर तहसील | सडक घनत्व                          |
| (29) | तालिका क्रमांक-5 4 | भानपुर तहसील | सडक सम्बद्धता                      |
| (30) | तालिका क्रमांक-5 5 | भानपुर तहसील | यातायात एव संचार सेवाओ का प्रतिरूप |
| (31) | तालिका क्रमांक-5 6 | भानपुर तहसील | यातायात एव संचार सुविधाओ का वितरण  |
| (32) | तालिका क्रमांक-5 7 | भानपुर तहसील | सेवा कार्यो का तुलनात्मक मान       |
| (33) | तालिका क्रमांक-7 1 | भानपुर तहसील | मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाए      |
| (34) | तालिका क्रमांक-7 2 | भानपुर तहसील | शिक्षण सस्थाओ का विवरण 2002        |
| (35) | तालिका क्रमांक-7 3 | भानपुर तहसील | बैंक शाखाओ की सूची                 |

## ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन : संकल्पना

प्रस्तावना :-

ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्यायिक समस्याओं से घिरा हुआ है। यह निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण असुरक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, रूढ़िवादिता तथा विविध अवसरचनात्मक सुविधाओं की कमी तथा बाढ़, सूखा एवं अन्यान्य प्राकृतिक विपदाओं से निरन्तर जूझ रहा है। इसकी निर्धनता का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, निम्न उत्पादकता, व्यवसायिक शिथिलता तथा रोजगार का अभाव है। इस देश की लगभग 74% जनसंख्या कृषि कार्य में सलग्न है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है एवं इससे सम्बन्धित क्रियाकलापों में विकास द्वारा भारतीय ग्रामों को समृद्ध बनाया जा सकता है। हमें इस देश में ग्रामीण संस्कृति के चरमोत्कर्ष पर विकास का लक्ष्य रखना है। सम्प्रति ग्रामवासियों में नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। ग्रामीण जनसंख्या में गरीबी एवं बेरोजगारी का निराकरण, ग्रामीणों को नगरों में भेजना ही नहीं है। अधिक आय एवं सम्पूर्ण रोजगार के अवसर तथा साधन ग्रामों में ही उपलब्ध कराये जा सकते हैं केवल उनके उचित विकास की आवश्यकता है।

भारतवर्ष गाँवों का देश है। किसी समय भारतीय ग्रामों में दूध की नदियाँ बहती थीं लेकिन स्थिति परिवर्तित हो गयी है और नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में जो असन्तुलन दृष्टिगोचर हो रहा है काफी हद तक वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी असन्तुलित बना रहा है। इस असन्तुलन को कम

करने के लिए, सर्वांगीण तथा समुचित ग्रामीण विकास की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास की आवश्यकता समझते हुए समय-समय पर विभिन्न उपायो तथा कार्यक्रमो को अपनाया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे क्षेत्रीय विषमता और असन्तुलन पूर्ण रूप से व्याप्त है तथा असन्तुलित आर्थिक विकास योजना के कारण यह यह स्थिति और दुरुह बन गयी है।

निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक विषमताओ को दूर करना भारत मे नियोजित विकास का स्थायी लक्ष्य रहा है। देश की तीन -चौथाई जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे निवास करती है अतः ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी मिटाना राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिये अनिवार्य है। भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो के विकास को प्राथमिकता दे रही है। गरीबी दूर करने के अनवरत प्रयासो के बाद भी अभी भारी सख्या मे लोग निर्धनताग्रस्त है। ग्रामीण विकास का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नही, बल्कि प्रगति के साथ-साथ सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना भी है।

गाँव मे रहने वाले निर्धन व्यक्ति को अपना जीवन स्तर सुधारने, अपनी क्षमताओ का इष्टतम उपयोग करने, तथा पूरी गरिमा के साथ देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मे भागीदारी के अवसर मिलने चाहिये। देश की वर्तमान स्थिति इस बात का द्योतक है कि आर्थिक विकास जहाँ एक तरफ समाज के एक वर्ग को भौतिकवादी, सर्वसुविधासम्पन्न बनाता है, वही दूसरी तरफ एक वर्ग शोषण का शिकार होता है और उसकी अपनी मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति भी नही हो पाती जिससे आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता को प्रश्रय मिलता है परिणामस्वरूप सामाजिक मूल्यों एव नैतिकता मे गिरावट आती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्यक विकास हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान दसवीं पंचवर्षीय योजना तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। कार्यान्वित उपायों से अनुकूल अन्तर तो आया है लेकिन चुनौती इतनी कड़ी है कि ग्रामीण क्षेत्रों का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। भारतीय गाँवों की जीवन शैली, रहन-सहन, आर्थिक गतिविधि और मानसिकता में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा के त्वरित प्रसार अभूतपूर्व संचार क्रान्ति और कारगर समाचार माध्यमों के सर्वव्यापी प्रभाव से अब ग्रामवासी भी अछूते नहीं रहे हैं।

अगली सदी में समय और तेजी से बदलेगा। रहन-सहन के स्तर में सुधार और शिक्षा के प्रसार के कारण ग्रामवासियों की भी त्वरित संचार साधनों की अपेक्षाएँ बढ़ेंगी। श्रम और कृषि उपज का मूल्य बढ़ेगा, और रोजगार विनियोजन की शैली भी तेजी से बदलेगी। अधिकांश उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होगा। गाँव में उद्यम स्थापित किये जायेंगे। क्योंकि वही सस्ता श्रम, कम खर्चीली जगह और किफायती दरों पर कच्चा माल मिलेगा। स्थानीय उद्योगों का भी विकास होगा। ग्रामीण हस्तशिल्प और पारम्परिक व्यवसायों की नयी तकनीकों के समावेश से प्रगति होगी।

अगली सदी में गाँवों में मकान बनाने की शैली बदल जायेगी। सौर-ऊर्जा घरेलू कार्यों में खूब इस्तेमाल की जाने लगेगी। हर घरों में छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाये जायेंगे। जरूरत की अधिकांश बिजली स्थानीय प्रयासों से प्राप्त की जायेगी। हर गाँव आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनेगा। खेती का स्वरूप बदलकर व्यापारिक बन जायेगा। सघन कृषि के नये-नये रूप प्रचलित होंगे। कृषि व्यवसाय भी एक आर्थिक उद्यम का रूप ले लेगा। गाँवों के आधुनिक

और ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल बहुत बढ़ जायेगा। कम्प्यूटर, आधुनिक फोन, मोबाइल तथा अन्य संचार साधन गाँवों के जीवन का अंग बन जायेंगे।

विगत वर्षों का अनुभव बताता है कि अब तक ग्रामीण विकास के लिये जो योजनाएँ चली हैं और उन पर जो व्यय हुआ है उसका उतना लाभ ग्रामीण स्तर पर नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मिलने वाले अवसरों और योजनाओं की जानकारी उन निर्धन और काम की तलाश में भटकने वालों को नहीं थी जिनके लाभ के लिये इन योजनाओं को लागू किया गया था।

इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय पहलू यह है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका केन्द्रीय होती है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज की नवीनतम समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनेक जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण ऐसे हैं जो अपने राज्यों में विकास कार्यक्रमों के लिये आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर पाये हैं। क्रियान्वयन के आकलन से यह भी पता चला है कि चालू वित्त वर्ष में कई राज्यों ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये निर्धारित राशि की पहली किश्त भी नहीं मागी है।

दसवी योजना के दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण विकास के लिये अब तक चलाये गये कार्यक्रमों की समीक्षा में इनके क्रियान्वयन में अनेक कमियाँ सामने आयी हैं। इनमें एक आधारभूत कमी यह थी कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधनों का उपयोग करने तथा इन योजनाओं को सही प्रकार से संचालित करने का कोई कारगर संस्थागत तन्त्र नहीं था। इस आधारभूत अक्षमता

का निराकरण पचायती राज सस्थानों को और शक्ति सम्पन्न बना कर और उन्हें ग्रामीण विकास योजनाओं का दायित्व सौंपकर किया जा सकता है।

अतः भारत के सम्यक विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे नियोजन की आवश्यकता है जिससे स्थानीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा निर्धन ग्रामीण समाज का अधिकतम आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके।

## 1.1 ग्रामीण विकास : अर्थ एवं परिभाषा :-

ग्रामीण विकास दो शब्दों से मिलकर बना है जहाँ ग्रामीण का तात्पर्य ग्राम एवं विकास का तात्पर्य सकारात्मक परिवर्तन से है। ग्राम की अपनी कुछ विशिष्टताएँ होती हैं जिनके कारण वे सांस्कृतिक प्रतिमानों, जीवन प्रणाली, अर्थव्यवस्था और रोजगार एवं सामाजिक सम्बन्धों के संदर्भ में नगर से भिन्न होता है। प्रशासन की लघुतम इकाई ग्राम होती है जिसके अर्थतन्त्र का मुख्य आधार कृषि होता है, जिसमें अधिकांश जनसंख्या संलग्न रहती है। 'ग्रामीण' शब्द उस क्षेत्र का द्योतक है जहाँ जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जिनमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की प्रमुखता होती है। व्यवसाय के रूप में लोग कृषि-पशुपालन से सम्बन्धित क्रियाओं पर निर्भर होते हैं।

भारत मूलतः गाँवों का देश है क्योंकि इसमें 6 लाख से अधिक गाँव हैं। भारत के सामाजिक जीवन की तीन निर्णायक संस्थाएँ, गाँव, जाति, और संयुक्त परिवार हैं। इन्होंने न केवल विदेशी आक्रमण और आन्तरिक विरोधाभासों से उत्पन्न आघातों को ही झेला है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की ताकतों को आत्मसात किया है और सम्मुख आयी हुई आवश्यकताओं और चेतावनियों के अनुसार अपने आप को ढाल भी लिया है।



डॉ० मजूमदार गाँव को एक जीवन विधि एवं एक अवधारणा के रूप में परिभाषित करते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से 'ग्राम' वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिक सम्बन्ध, हम की भावना, तथा सामुदायिक भावना विशेषतः पायी जाती है।

“एक परिवार से बड़ा सम्बन्धित एवं असम्बन्धित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान अथवा निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ सम्बन्धों में आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूलरूप से संयुक्त रूप में कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है, [ - Encyclopaedia of Social Science vol X V , 1949 ] ।

#### 1.1.1 गाँव एक ~~ग्रामीण~~ इकाई के रूप में : —

फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमो ने ग्रामीण समुदाय शब्द के तीन अर्थ बता लाये हैं (1) राजनैतिक समाज के रूप में (2) भूमि के सह-स्वामियों की इकाई के रूप में (3) परम्परागत अर्थव्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था के प्रतीक (भारतीय देश-भक्ति का आदर्श वाक्य) के रूप में। इस मत के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय भारत की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था का अंग रहा है। एक गाँव मात्र एक स्थान, घरों, गालियों और खेतों का पुंज ही नहीं है। ये प्रतिक्रियाएँ इसलिये उभरकर आईं क्योंकि भारतीय गाँवों की स्वतन्त्रता व स्वावलम्बन को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। आज भी गाँव एक सबद्ध क्षेत्रीय इकाई के रूप में है। परन्तु गाँवों में ग्रामीण पहचान, एकता और निष्ठा की भावना, जाति और समुदाय की भावना से कहीं ऊपर है। गाँव के अन्दर और अन्य गाँवों के साथ गुटबन्दी तथा संघर्ष आम बात है। भूमि सुधारों, पंचायतीराज, संस्कृतिकरण और अन्य रचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों द्वारा गाँव की सामाजिक, संरचना और गाँव के बृहद संसार के साथ सम्बन्धों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं।

मैडेलबॉम ने कहा है कि एक गाँव स्पष्ट रूप से इसके निवासियों के लिये एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सामाजिक इकाई है। वे लोग बृहद समाज की गतिविधियों में भाग लेते हैं और सभ्यता के प्रतिमान में भागीदार हैं। अध्ययनों के उद्देश्य से कुछ हालतों में गाव को विलग किया जा सकता है परन्तु अन्य हालत में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिये गाव का अध्ययन इसके स्थानीय परिवेश और बृहद परिपेक्ष्य दोनों ही दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है।

विभिन्न विद्वानों ने 'ग्रामीण' शब्द की अनेक व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। कुछ लोगो ने इसे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा बताया है तो कुछ ने कृषि व्यवसाय को प्रमुखता दी है। वही कुछ लोग जनसंख्या को निर्धारक मानते हैं। 'ग्रामीण' की व्याख्या 'नगरीय' शब्द के विपरीत की गयी है। अर्थात् नगरीय विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र ग्रामीण है। किन्तु इन सभी व्याख्याओं में किसी न किसी प्रकार की कमी है। पिछड़े व्यक्ति नगरों में भी निवास करते हैं।

के०एन० श्रीवास्तव ने 'ग्रामीण' एवं 'नगरीय' की व्याख्या मनुष्य और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अन्तःक्रिया के आधार पर की है। "एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात् प्रकृति के सहयोग से वे वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन वाले हों, (के०एन० श्रीवास्तव 1971)।

पॉल एच० लैण्डिस— ने 'ग्रामीण' शब्द की व्याख्या में तीन बातों को विशेष महत्व दिया है। (1) प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, (2) सीमित आकार (3) घनिष्ठ और प्राकृतिक सम्बन्ध

“ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो, जिसका आकार सीमित हो और जिनसे घनिष्ठ एवं प्राथमिक सम्बन्ध पाये जाते हो,” (Paul H Landis P 18) ।

वरट्रान्ड ने ‘ग्रामीणता’ के निर्धारण में दो आधारों (1) कृषि द्वारा आय अथवा जीवनयापन (2) कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र, को प्रमुख माना है,” (Bertrand, P P 9,10) ।

संक्षेप में ‘ग्रामीण’ शब्द के प्रयोग में जो बातें मुख्य हैं वे हैं

- (1) प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता
- (2) सीमित आकार
- (3) धार्मिक और प्राथमिक सम्बन्धों की प्रधानता
- (4) कृषि द्वारा जीवनयापन
- (5) जनसंख्या का कम घनत्व

भारतीय ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं में संयुक्त परिवार, कृषि प्रमुख व्यवसाय, जाति प्रथा, जजमानी प्रथा, ग्राम पंचायत, भाग्यवादी, सरल एवं सादा जीवन, जनमत का अधिक महत्व, सामाजिक समरूपता, प्रथाओं और धर्म का महत्व, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अशिक्षा, आत्मनिर्भरता आदि स्पष्ट परिलक्षित होता है।

#### 1.1.2. विकास की संकल्पना एवं उद्देश्य :-

विकास एक प्रक्रिया है जो प्रगति का सूचक है, किसी भी तत्व में गुणात्मक मात्रात्मक तथा कल्याणपरक सकारात्मक परिवर्तन ही विकास है। विकास से अभिप्राय जीवन के भौतिक स्तर में समग्र रचनात्मक परिवर्तन से है।

इसलिये विकास के लिये केवल आर्थिक सवृद्धि ही नहीं बल्कि आर्थिक सवृद्धि के लाभो का न्यायोचित वितरण भी आवश्यक है। दूसरे शब्दो मे 'विकास का अर्थ न्यायमुक्त सवृद्धि से है। इसका अर्थ है कि बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास व कल्याण द्वारा जीवन स्तर मे सुधार।

विकास के मूल तत्व –

- (1) असमानता व निर्धनता का उन्मूलन ।
- (2) लोगो के भौतिक कल्याण मे वृद्धि ।
- (3) सामाजिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास कल्याण आदि मे वृद्धि ।
- (4) क्षेत्र या देश मे विभिन्न जनसमूहो के बीच विकास के लाभो का न्यायोचित वितरण ।
- (5) ऐसे सस्थागत ढाँचे का निर्माण करना जिसमे निर्णय लेने के सभी स्तरों के योगदान की अनुमति हो। विकास के लिये सभी को समान अवसर प्राप्त हो तथा असमानताये दूर हो।

आर्थिक सवृद्धि और विकास की सकल्पना मे मूलभूत अन्तर है जहाँ आर्थिक सवृद्धि से अभिप्राय अर्थव्यवस्था मे उत्पादित सभी वस्तु और के मूल्य और सेवाओ के मूल्य मे वृद्धि से है। जबकि विकास का अर्थ भौतिक कल्याण मे लगातार सुधार, विशेष रूप से उन लोगो के, जो निर्धन है और निर्धनता के कुचक्र मे फँसे हुये है तथा अशिक्षित है और जिनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी हालत अच्छी नहीं है।

विकास की अवधारणा एक नूतन आयाम है, जबकि प्रगति की अवधारणा प्रबोध और औद्योगिक क्रान्ति से जुडी हुई है। विकास की प्रकृति सन्दर्भात्मक और सापेक्षिक है। प्रगति की प्रकृति सामान्य है और औचित्यात्मक कारको पर आधारित

है। योगेन्द्र सिंह के अनुसार “समाज के सदस्यो मे वाछनीय दिशा मे नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते है। अत विकास की धारणा सामाजिक – सास्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक समाज मे भिन्न-भिन्न पायी जाती है।”

“विकास एक सम्मिश्र अवधारणा है।” समाज के विकास मे लगातार कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रो मे प्रगति को गिना जाता है। विकास मे कमजोर वर्गों, स्त्रियो, और बच्चो, बीमार, बेरोजगार और वृद्ध लोग और अल्पसंख्यको के कल्याण को भी शामिल करते है। विभिन्न नीतियो और कार्यक्रमो का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो, अनुसूचित जातियो, जनजातियो, महिलाओ, कृषि मजदूरो और औद्योगिक श्रमिको के कल्याण का है।

अत विकास एक मूल्य-धारित व्याख्या है। यह एक समाज, क्षेत्र और जनता की सामाजिक सास्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओ से सम्बद्ध है। विकास (परिवर्तन) की चार कसौटिया है। पैमाना, क्षमता, पारस्परिकता और स्वतन्त्रता मे वृद्धि। विकास के लिये पैमाना मुख्य कसौटी है। इसीलिये विकास एक रेखीय है। इस प्रकार विकास का अभिप्राय एक सामाजिक प्रघटना के पूर्णतर वृद्धिरूपी उद्विकास से है।

गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक “एशियन ड्रामा” में यह मत प्रकट किया है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र मे विकास का अर्थ “आधुनिकीकरण के आदर्शों को सामाजिक जीवन मे उतारने से है।” मिर्डल लिखते हैं “विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था मे उन अनेक अवाछनीय अवस्थाओ का सुधार करना है जिनके कारण अल्पविकास की स्थिति बनी हुई है।”

विकास, जो कि बुद्धिसगत तरीको से तालमेल बैठाते हुए नीतिपरक उपायो की एक व्यवस्था है, नियोजन के द्वारा सम्भव बनाया जा सकता है।

ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में गाँधी जी ऐसे ग्राम समुदाय की कल्पना करते थे जो स्वयं समर्थ हो, स्वशासी हो, व आत्मनिर्भर हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताये पूरी हो और लोग सद्भाव तथा सहयोग के वातावरण में रहे। संक्षेप में गाँधी जी ऐसे ग्राम समुदाय की कल्पना करते थे जिसे राजनीतिक स्वायत्ता प्राप्त हो, जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, सामाजिक समानता पर आधारित हो और जहाँ शोषण न हो।

ग्राम विकास का उद्देश्य –

- (1) ग्राम क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
- (2) ग्राम संस्थाये बनाना और मजबूत करना, जो लोगों को ग्राम विकास में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेगी।
- (3) ग्राम क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना।

“ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य नगरीय क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोगों का सम्मिलित प्रयास से विकास करना है” (कॉप 1972)।

“ग्रामीण विकास निर्धन ग्रामीण स्त्री-पुरुष तथा उनके पाल्यों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें योग्य बनाने की व्यापक रचना है” (चैम्बर्स, 1983)।

“ग्रामीण विकास का अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों से घनात्मक परिवर्तन से है” (मिश्र एवं सुन्दरम् 1979)।

असमानताओं, गरीबी, ससाधनों के समुचित उपयोग से सबधित नहीं हैं वरन् निम्न कृषि उत्पादकता, स्थिर या घटती कृषि उत्पादकता (एशिया एव अफ्रीका) कुछ क्षेत्रों में ससाधनों की कमी, मानव ससाधन में गुणवत्ता की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कृषि पर आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, अवस्थापना सुविधाओं और निवेश में कमी तथा रोजगार के अवसरों में कमी भी कई समस्याओं के मूल जड में हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा भूमि तक सीमित पहुँच भी ग्रामीण विकास में बाधक हैं।

मूरे के शब्दों में ग्रामीण विकास सम्पूर्ण जनसंख्या, जो स्पष्टतः नगरीय क्षेत्र से बाहर रहती है, के लिए सामाजिक कल्याण एवं भौतिक पदार्थों में सुधार की एक प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास प्रकृति से अन्तर्विषयक एवं क्रियान्वयन की दृष्टि से बहुखण्डीय है। जिसको अनेकानेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लागू किया जा सकता है। ऐसे उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादन, रोजगार एवं आय का समान वितरण, विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, आधुनिक निवेशों और सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, आत्मनिर्भरता, वातावरण जागृति आदि प्रमुख हैं।

भारत में सतुलित ग्रामीण विकास नियोजन की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है –

- 1 कृषि विकास
- 2 भूमि सुधार
- 3 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण
- 4 अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ जाल
- 5 ससाधन विकास
- 6 बुनियादी सुविधाओं का विकास
- 7 ग्रामीण दबाव में कमी लाना

- 8 स्थान का समुचित प्रबन्धन
- 9 ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों में समन्वय
- 10 क्षेत्रीय अधिवास संश्लिष्टों का सृजन
- 11 गरीबी उन्मूलन क्षेत्रों के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना।

### 1.1.3. ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले कारक

हमारे सबसे प्रिय लक्ष्य हमसे आज भी उतने ही दूर है, जितने वे तब थे जब हमने योजनाबद्ध विकास की अपनी यात्रा प्रारम्भ की थी, ग्रामीण विकास को बाधित करने वाले कारक निम्न हैं –

- (क) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का बढ़ता हुआ अन्तर्विरोध एवं आर्थिक द्वैतवाद
- (ख) भारतीय ग्रामों में अमीर एवं गरीब की खाई बढ़ाने वाली वर्ग संरचना का बना रहना
- (ग) वर्तमान कृषि संरचना एवं तन्निहित पारस्परिक सबंध
- (घ) स्पष्ट ग्रामीण विकास नीतियों का राष्ट्रीय स्तर पर अभाव
- (ङ) आन्तरिक एवं स्थानीय विकास स्रोतों के समुचित उपयोग करने में असफलता
- (च) विदेशी तकनीकी एवं आर्थिक निर्भरता
- (छ) देशी तकनीकों का अभाव तथा विदेशी तकनीकी, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी हैं, का प्रयोग
- (ज) औद्योगिक एवं कृषि संबंधी नीतियों में वांछित समीकरण का अभाव
- (झ) भूमि संबंधी सुधारों को कार्यान्वित करने में असफलता
- (ट) विकास प्रक्रियाओं का एकांगी होना
- (ठ) विकासोपयोगी राजनीतिक चेतना एवं नेतृत्व का अभाव
- (ड) कमजोर वर्गों के हितों वाली संस्थाओं का अभाव तथा
- (ढ) क्षेत्रीय एवं स्थानीय प्रकृति के अनुरूप योजनाओं का अभाव।



## 1.2. भारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक निरूपण

### 1.2.1. स्वतन्त्रता से पूर्व ग्रामीण विकास

भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया बीसवीं सदी में प्रारम्भ हुई। स्वतन्त्रता के पूर्व ग्रामीण विकास के लिए 1901 में सिचाई आयोग, 1927 में शाही कृषि आयोग एवं 1932 में खाद्य उत्पादन सभा आदि का गठन कर एक सामान्य प्रयास किया गया। ये कार्यक्रम एकांगी प्रकृति के थे। साथ ही दोष-पूर्ण भू-धारण पद्धति में वास्तविक कृषक जोत का स्वामी न था। अतएव वह जोत में किसी स्थायी सुधार के प्रति उदासीन था। भारतीय ग्रामोद्योगों की दुर्लभ नीति के कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था जर्जर हो गयी। उद्योगों में ह्रास के कारण अधिसंख्यक जनता कृषि पर आधारित हो गयी। फलतः कृषि भूमि पर दबाव बढ़ा है। भू-स्वामित्व की दुर्नीति और दोषपूर्ण लगान निर्धारण पद्धति आदि से जनता गरीबी, बेरोजगारी और ऋण में दबती गयी। आर्थिक विपन्नता बढ़ी। समाज में कमजोर वर्ग की वृद्धि हुई। भारतीय ग्राम पिछड़ते चले गये और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक द्वैतवाद बढ़ता गया, (दूबे तथा सिंह 1985)।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए 1921 से 1930 का दशक सबसे महत्वपूर्ण रहा। इस समय 'श्रीनिकेतन इन्स्टीट्यूट आफ रूरल रिकान्स्ट्रक्शन' श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित किया गया। मि० एमहर्स्ट के निर्देशन में इस संस्थान ने ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों में पूर्णरूपेण नवजीवन का संचार, ग्रामीणों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, संस्कृति का परिज्ञान एवं उपलब्ध संसाधनों, के सम्यक् उपयोग द्वारा भौतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक दशाओं में सुधार रहा। टैगोर की प्रेरणा से ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य प्रारम्भ किये गये यथा स्वास्थ्य

सहकारिता, सगठन, कृषि प्रदर्शन, उत्तम बीज एवं उर्वरकों की आपूर्ति, कुटीर एवं हस्तकला में सुधार आदि। इन्हें वृत्तचारी आन्दोलन एवं शिक्षा सत्र के नाम से अभिहित किया गया। शिक्षा सत्र के अन्तर्गत ग्रामीण बालकों को शिक्षा देने के साथ-साथ पठन-पाठन हेतु नये साहित्य का सृजन भी किया गया। इससे ग्रामीण विकास को नयी दिशा मिली।

1921 में ही डा० स्पेन्सर हैच के नेतृत्व में मारतण्डम् की स्थापना ग्रामीणजनों के आध्यात्मिक-मानसिक-भौतिक सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए की गयी। इसके अनुभव के आधार पर बडौदा, मैसूर और हैदराबाद में ग्रामीण पुनर्रचना के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हुई, जो बाद में श्रीलंका, वर्मा तथा मिश्र तक पहुँची।

गुडगॉव प्रयोग 1927 में मि० ब्रेने द्वारा प्रारम्भ किया गया। इसमें कड़ी मेहनत, आत्मसम्मान, आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता, पारस्परिक निर्भरता एवं समादर को ग्रामीण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आदर्श मानकर ग्रामीण विकास की धारा प्रवाहित की गयी। वस्तुतः सुधार की इच्छा ही आर्थिक उत्थान की कुंजी है, इसे आधार माना गया। साथ ही इसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न पक्षों-कृषि-संसाधन-सगठन और स्थानीय विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यद्यपि यह विचारधारा उत्तम रही, लेकिन शासकीय एवं उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग प्रदान नहीं किया।

1932 में बडौदा में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रारम्भ की गयी। इसमें आवागमन एवं संचार में सुधार पेयजल, कूप निर्माण, मलेरिया, उन्मूलन, चरागाह सुधार, उत्तम बीजों का वितरण गृह एवं हस्तकलाओं का प्रशिक्षण, पचायती एवं सहकारी संस्थाओं की स्थापना एवं ग्रामीण विद्यालयों

का विकास ताकि वे कृषि एवं उत्तम जीवनयापन के केन्द्र के रूप में कार्य कर सकें, आदि उद्देश्यों को समाहित किया गया। यद्यपि इन कार्यक्रमों के लिए कोई बहुद्देशीय ग्रामस्तर का कार्यकर्ता नहीं था, फिर भी ये उदार, विस्तृत, संगठित एवं कृषि प्रधान कार्यक्रमों को संयोजित करने में सक्षम रहे।

गाँधीजी ने सेवा ग्राम से कई रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया, यथा—खादी का उपयोग, ग्रामीण उद्योगों का विकास, अस्पृश्यता निवारण, मौलिक एवं प्रौढ शिक्षा, ग्रामों की स्वच्छता, सामुदायिक सौहार्द, नशाबन्दी, स्वास्थ्य शिक्षा, नारी उत्थान एवं राष्ट्रभाषा की अभ्युन्नति। इन्होंने आत्मनिर्भरता, विशेषतः भोजन, वस्त्र पर विशेष बल दिया। इन विकास परक तथ्यों के साथ ही उन्होंने नैतिक मूल्यों के ह्रास को रोकने के लिए सत्य, अहिंसा, सत्कार, आत्मसंयम, कार्य की महत्ता, आत्मनिर्भरता आदि का प्रचार भी किया। इन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज एवं सहकारी समाज का आन्दोलन प्रारम्भ किया।

विनोबा का ग्रामदान एवं भूदान तथा जयप्रकाश नारायण की गाँधीवादी परम्परा सामुदायिक विकास से जुड़ी थी। 1937—39 के मध्य कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के समय ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए विभाग बने। लेकिन इनका प्रयास ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में नगण्य ही रहा। स्वतन्त्रता के पूर्व ग्रामीण विकास के लिए किये गये प्रयास व्यक्तिगत थे। इसलिए इनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा फिर भी ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास को अकुरित करने में निश्चिततः सफल रहे।

#### 1.2.2. स्वतन्त्रता के बाद का ग्रामीण विकास :-

स्वतन्त्रता के पश्चात् विस्थापितों की सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 1947 में निलोखेरी अभियान के अन्तर्गत 7000 विस्थापितों को 1100 एकड़ दलदली भू-भाग पर बसाया गया। यह उपनिवेशवाद में नगरीय रूप धारण कर

लिया तथा 100 ग्रामो को समन्वित कर इसे मजदूर-मजिल से अभिहित किया गया। “काम नहीं तो भोजन नहीं” इसमें सिद्धान्त रूप में माना गया। साथ ही इसमें शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रसार आदि पर सबका समान अधिकार मानते हुये धर्म निरपेक्षता का ध्यान रखा गया।

इटावा पायलट परियोजना, 1952 में सामुदायिक परियोजना के रूप में इल्वर्ट मेयर के नेतृत्व में स्थापित की गयी। इसमें विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये इटावा के ही महेवा विकास खण्ड के 97 ग्रामों को चुना गया और विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया। मि० मेयर के अनुसार सामुदायिक अभिगम छोटे समुदायों में स्वयं विकास का माध्यम, गौंधीवादी विश्वास के साथ, हो सकता है। आत्मसंतोष से भौतिक पूर्णता एवं कल्याण फलप्रद हो सकता है।

उनकी विचारधारा में सफल योजना के अन्तर्गत सभी समुदाय सम्मिलित होते हैं, समस्याएँ विशद रूप में हल होती हैं, तथा बेरोजगारी का निराकरण होता है। इसमें वाह्य अभिकरणों से सहायता मिलती है लेकिन प्रशासनीय प्रस्थिति पर विचार करते समय उन्होंने पाया कि इसमें निम्न अवगुण भी हैं। (1) नैतिकता एवं ईमानदारी की कमी (2) आत्मवीक्षण एवं समालोचना की कमी (3) ऊपर एवं नीचे के अधिकारियों एवं व्यक्तियों में सम्बन्ध की कमी (4) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के पुनरीक्षण की कमी तथा (5) वैयक्तिक आवश्यकता की अवहेलना। समवेत प्रशासकीय पुर्नगठन के सम्बन्ध में मेयर का महत्वपूर्ण योगदान आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण का रहा।

ग्रामीण विकास के लिये स्वतन्त्रता के पश्चात समयबद्ध कार्यक्रम अपनाये गये। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया इसके अन्तर्गत

ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसार तथा विपणन सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य रखा गया। कृषि विकास भी इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य रहा। इसके साथ ही 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को व्यवस्थित किया गया। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासखण्डों की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गयी कि ये क्षेत्र अपने ससाधनों द्वारा विकसित किये जाय।

परन्तु कार्यक्रमों को व्यवस्थित स्वरूप नहीं दिया जा सका। 1960 में खाद्यान्न की कमी से ग्रामीण विकास की मुख्य धारा के रूप में कृषि विकास ही प्रस्फुटित हुआ और विकास के अन्य विविध पक्षों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। फलतः ग्रामीण विकास का रूप एकांगी हो गया और उसमें भी पूर्ण सफलता नहीं मिली (दूबे तथा सिंह 1985)।

इस प्रकार राष्ट्र के ग्रामीण विकास के इतिहास की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में ग्रामीण विकास के महत्व पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के उत्तरार्द्ध में विशेष ध्यान दिया गया और अनेक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया। मार्च 1950 में 'योजना आयोग' का गठन इसी अभिप्राय के साथ किया गया कि "राष्ट्र में उपलब्ध साधन स्रोतों का सन्तुलित उपयोग कर प्रभावी बनाया जा सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके।"

इस उपयोग का उद्देश्य यह भी था कि विकास की प्रक्रिया में आम नागरिक की भागीदारी हो, सामान्य लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके, एवम् आर्थिक विकास के बहुआयामी अवसरों का सृजन हो सके। फलतः इस अभिप्राय एवं उद्देश्य को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और मौलिक अधिकार, और 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' को संविधान की महत्वपूर्ण कड़ी बनाया गया।

### 13. पंचवर्षीय योजनायें और ग्रामीण विकास :-

प० जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में "योजना भारत के 40 करोड़ व्यक्तियों की जन्मपत्री है। यह जन्मपत्री चन्द्रमा तथा ग्रहों के आधार पर नहीं तैयार की गयी है, यह देश के साधनों को भली-भाँति देखकर तैयार की गयी है ताकि जनता को आगे बढ़ने का अवसर मिले। अतः स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजनायें भारत की पुनर्निर्माण की योजनायें हैं और चूँकि भारत गाँवों एक आधारभूत अंग है। योजना आयोग द्वारा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को कार्यरूप दिया गया। वर्ष 1951-52 से लेकर नवी पंचवर्षीय योजना तक के व्यय सम्बन्धी आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में गाँवों की मूलभूत एवं न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई विकास कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं जिनका बुनियादी उद्देश्य है, गरीबी उन्मूलन के उपाय, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता में कमी, विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं अन्य ग्रामीण समस्याओं का समाधान।

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-52 से 1955-56 तक विकास योजनाओं का प्रारम्भिक प्रयोग समझा जाता है, जिसके पीछे लक्ष्य यही था कि आम नागरिक विकास के सिद्धान्त से अवगत हो सकें और राष्ट्र में प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करते हुये विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्धारित मुख्य उद्देश्य थे – कृषि एवं सिंचाई का विकास ऊर्जा (बिजली) स्रोतों का विकास, उद्योगों को प्रोत्साहित करना एवं यातायात सुविधा का विकास करना आदि।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास प्रखण्डों की स्थापना (1952) की गयी और सभी विकास

कार्यक्रमों को एक विशेष प्रशासनिक तन्त्र द्वारा कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956-57 से 1961-62 की अवधि के लिये तैयार की गयी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अपेक्षाकृत पूर्व की योजना से अधिक विस्तृत एवं महत्वाकांक्षी बनाया गया। संक्षेप में यह ध्यान में रखा गया कि आम नागरिक की आय में पर्याप्त वृद्धि हो, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, बुनियादी एवं बृहद उद्योग का विकास हो एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार हो (150 लाख लोगों के लिये रोजगार के अवसरों का सृजन) एवं आय और सम्पत्ति की असमानता में कमी की जा सके।

सामुदायिक विकास प्रखण्डों द्वारा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर विकास कार्यक्रमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण संस्थाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता महसूस करते हुये पंचायती राज प्रणाली लागू की गयी। दुर्भाग्य वश इस अवधि में देश को लगातार गम्भीर सूखे की स्थिति से गुजरना पड़ा। परिणामतः सघन कृषि विकास कार्यक्रम (1961) एवं हरित क्रान्ति जैसी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न उत्पादन में द्रुत एवं क्रमिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर लागू किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-62 से 1965-66 तक चलाई गयी। इस पंचवर्षीय योजना को अपेक्षाकृत अधिक ठोस एवं कारगर बनाने के ध्येय रखे गये, जिसमें राष्ट्रीय आय में 5% की वार्षिक वृद्धि करना, पूँजी निवेश पर आधारित विकास को सुदृढ़ करना, अन्न उत्पादन में स्वावलम्बन, अन्न उत्पादन में वृद्धि करना, उद्योग जैसे—इस्पात, पेट्रोलियम एवं रसायन, ऊर्जा एवं भारी मशीन के उद्योग की स्थापना कर छोटे मशीन के उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्र को दस वर्ष

के अन्दर स्वावलम्बी बनाना, रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि को सुनिश्चित करना, आय और सम्पत्ति की असमानता में कमी लाना एवं आर्थिक शक्ति का अधिकाधिक सरल वितरण करना।

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों की सफलता एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनेक ऐसे भी विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गयी जो क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधन स्रोतों पर आधारित थे जैसे— कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एवं मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में अर्थात् 1965-66 में राष्ट्र में आन्तरिक सकट एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सकटों के कारण 1965-66 को “प्लान होलिडे” माना गया। तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के मध्य के समय में दो वार्षिक योजनाएँ चलायी गयीं। जिसके फलस्वरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन 1969-70 में प्रारम्भ हुआ। यह कहा जा सकता है कि 1966-67 से 1968-69 तक की योजना सिर्फ योजना के रूप में बनी जिसमें पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता रहा। वर्ष 1969-70 से 1973-1974 तक की अवधि में चतुर्थ योजना को कार्यान्वित किया गया और इस योजना में भी पूर्व की योजनाओं के उद्देश्यों के अतिरिक्त कई अन्य नए उद्देश्यों को सलग्न किया गया, जिसमें यह लक्ष्य रखे गये — कृषि एवं धार्मिक उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करना एवं विदेशी सहायता में कमी लाना।



उपरोक्त लक्ष्यो को ध्यान मे रखकर कुछ प्रयास किये गये जिसमे प्रमुख—  
प्रतिव्यक्ति आय मे वृद्धि करना, उत्पादन का समान वितरण एव विभिन्न  
सामाजिक समूहो की असमानता मे कमी लाना, आय मे स्रोतो को सुनियोजित  
करना एव आय को अर्द्धविकसित क्षेत्रो मे निवेश करना विकास के लाभ को  
स्थायी करते हुये स्वालम्बन प्राप्त करना, विदेशी सहायता मे 50% की कमी लाना,  
औद्योगिक बहुमुखी विकास जैसे—कृषि उत्पादन एव घरेलू निवेश मे क्रमिक वृद्धि  
करना, खाद्यान्न के आयात को वर्ष 1970—71 तक समाप्त करने का प्रयास  
करना, सहकारी समितियो जैसी इकाइयो को सुदृढ करना एव चौदह वर्ष की  
आयु तक के बालक/बालिकाओ के शिक्षा को अनिवार्य एव निशुल्क बनाते हुये  
व्यावसायिक शिक्षण पर बल देना है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि मे लघु कृषक विकास कार्यक्रम, एव सीमान्त  
कृषक विकास कार्यक्रमो को कार्यान्वित कर एक खास समूह को लाभ पहुँचाने का  
प्रयास किया गया। इस अवधि मे एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना “न्यूनतम  
आवश्यकता 1975 कार्यक्रम” — एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप मे कार्यान्वित  
किया गया जो किसी कारण कई वर्षो तक प्रभावकारी कार्यक्रम के रूप मे नही  
उभर सकता।

वर्ष 1974—75 से 1978—79 की अवधि पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत  
आती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एवम आर्थिक उथल—पुथल के कारण  
पंचम पंचवर्षीय योजना को अधिक प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से कई आमूल  
परिवर्तन किये गये। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण एवं बेरोजगारी  
जैसी बुनियादी समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी, अनेक लक्ष्य अभिमुखीकृत  
कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया जैसे—गरीबी पर सीधा प्रहार करना, आय के

पुर्नवितरण के लिये प्रयास करना, विज्ञान एवं तकनीकी में स्वावलम्बी बनाना, आन्तरिक साधन स्रोतों को विस्तारित करना, कृषि एवं औद्योगिक विकास के बुनियादी सम्बन्ध पर बल देना एवं दोनों को परस्पर सहयोगी बनाना, शहरी सम्पत्ति के प्रत्यक्ष करो में क्रमिक वृद्धि करना, शहरी भूमि का समाजीकरण करना, जन वितरण प्रणाली को लागू करना, आय व्यक्ति की बचत में वृद्धि लाना, विदेशी सहायता में कमी लाना, एवं विदेशी सहायता का पूर्ण सदुपयोग करना, भू-हदबन्दी एवं भूमि वितरण को कारगर बनाते हुये समाज के कमजोर वर्ग, लघुसीमांत कृषक एवं भूमिहीन मजदूरों के उत्थान के लिये प्रयास करना।

पॉंचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में राजनैतिक उथल-पुथल के कारण देश गम्भीर रूप से प्रभावित रहा, फलतः कोई दूरगामी प्रभावशाली योजनाएँ नहीं बन सकी। अल्प अवधि के लिये “अन्त्योदय कार्यक्रम” एवं “काम के बदले अनाज” कार्यक्रम जैसी योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर उन्हें जल्दबाजी में लागू किया गया, हालांकि इसकी सफलता कई क्षेत्रों में लगभग सन्तोषप्रद रही, लेकिन राजनैतिक परिवर्तन के कारण कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ।

इसी पंचवर्षीय योजना में ही कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम (1974), मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम (1977), जनजातीय क्षेत्रीय प्रोग्राम, पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम (1979), पायलट सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाये गये। इस प्रकार पॉंचवी योजना अन्न उत्पादन में वृद्धि के अलावा किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकी।

छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ एक राजनैतिक परिवर्तन की अवधि में सन 1977-78 में हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक लम्बी अवधि यानी दो दशक से अधिक की अवधि के बाद राष्ट्र में बड़े पैमाने पर राजनैतिक परिवर्तन

हुआ। फलस्वरूप प्रशासनिक कार्यनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। छठी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा नये सिरे से तैयार की गयी जिसमें मात्र एक वर्ष के लिये कार्यक्रम तैयार कर लागू किये गये।

तत्कालीन सरकार ने पिछली पाँच पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, एवं असमानता को दूर करने के लिये प्रभावकारी या परिणामोन्मुख नहीं बनाया जा सकता। फलस्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना में सामान्य उद्देश्यों के अतिरिक्त कई लक्ष्य आधारित उद्देश्य को भी शामिल किया गया।

जैसे — बेरोजगारी दूर करने के कड़े एवं सघन उपाय, निर्धनतम वर्ग के परिवारों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष सहायता एवं अनुदान देकर ऊँचा उठाना, न्यूनतम आवश्यकता जैसे शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा सहित, प्राथमिक चिकित्सा ग्रामीण यातायात एवं ग्रामीण आवास सुविधा के लिये विकसित करना, कमजोर एवं निर्धन वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान देना आदि हैं।

उपर्युक्त क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति के लिये गरीबी उन्मूलन पर विरोध बल दिया गया और पोषण तत्व के उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। 1977-78 में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर यह अनुमान किया गया कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में 48% एवं शहरी क्षेत्र में 41% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल संख्या 2900 लाख हो गयी। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन को महत्वपूर्ण स्थान देते हुये सभी विकास कार्यक्रमों जैसे—पूर्व के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा

क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि को एकीकृत कर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित करने का एकजुट प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में गरीबी और बेरोजगारी पर प्रत्यक्ष और सीधे प्रहार की रणनीति अपनाई गयी और प्रशासन को सवेदनशील बनाने के लिये कारगर प्रयास किया गया।

इस अवधि में गरीबी एवं बेरोजगारी के बढ़ते प्रकोप के कारण देश में अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ। फलतः इन दोनों समस्याओं के लिये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये ही प्रत्यक्ष एवं सीधे लाभ वाले अनेक कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास (I.R.D.P.) कार्यक्रम 1980, ग्रामीण युवा स्वनियोजन कार्यक्रम (D.W.C.R.A.) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम 1982, के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 1983, जैसे कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सघन रूप से कार्यान्वित किया गया। इन कार्यक्रमों को सातवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1981-86 से 1989-90 तक कार्यान्वित किया गया जिसमें खाद्यान्न रोजगार एवं उत्पादकता पर विशेष बल दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाये गये गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुये इसे सभी कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ा गया। इस योजनावधि में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रयास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं अर्द्धबेरोजगारी की गम्भीरता में कमी के लिये ठोस कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित किया गया। जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिये कई विशेष कार्यक्रम भी

चलाये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों एवं कृषक मजदूरों के लिये रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का अपेक्षाकृत अधिक गहन और विस्तृत बनाने का प्रयास किया गया। विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी एवं प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। समूह कार्यक्रम के अतिरिक्त क्लस्टर कार्यक्रम को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया गया।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अच्छे परिणाम देखते हुये इन कार्यक्रमों को आठवी पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) में भी विस्तार किया गया। इस अवधि में ग्रामीणों की भागीदारी को प्रभावशाली बनाने के विचार से जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में लागू की गयी और पचायतो एवं आम नागरिकों को योजनाओं बनाने एवं कार्यान्वित करने का प्रत्यक्ष भार सौंपा गया है।

आठवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर देश की धनराशि का कम से कम 50% व्यय करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त देश के बुनियादी ढाँचे में प्रभावकारी परिवर्तन के उपाय से यह रणनीति तैयार की गयी है— अधिकारों का विकेंद्रीकरण, सघीय ढाँचे को सुदृढ़ करना, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्र का सतुलित विकास, रोजगार के अवसर का सृजन एवं विस्तार, जनसंख्या नियन्त्रण एवं मानव ससाधन की गुणवत्ता में सुधार करना, पर्यावरण विकास एवं प्रौद्योगिकी के जरिये विकास की गति तेज करना।

ग्रामीण विकास के लिए आठवी योजना में आवंटित राशि 30,000 करोड़ रुपये को बढ़ाकर नौवी योजना में 42,874 करोड़ रुपये कर दिया गया। ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने वर्ष 2000-2001 के लिये विभिन्न योजनाओं हेतु 9760 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिये 6,790 करोड़ रुपये, भूसाधन विभाग की योजनाओं के लिए 900 करोड़ रुपये

तथा पेयजल आपूर्ति विभाग की योजनाओं के लिए 2,100 करोड़ रुपये सम्मिलित है, (भारत 2001, पृष्ठ 455)।

इसी अवधि में रोजगार आश्वासन योजना (1993), इन्दिरा आवास योजना (1988), सिटारा, (दस लाख कुओं की योजना), सासद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, गंगा कल्याण योजना, सामूहिक जीवन बीमा योजना, महिला समृद्धि योजना प्रमुख योजनाएँ हैं जो कि गरीबी उन्मूलन एवं गाँवों के बहुमुखी विकास हेतु चलायी गयी।

### **पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन**

यदि हम सभी नौ पंचवर्षीय योजनाओं की जानकारी ले तो ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के पाँच दशकों में हमारी सभी योजनाएँ किसी न किसी विषय की ओर उन्मुख थी, कभी कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता, कभी औद्योगिक विकास आदि, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी हमेशा वृद्धि की ओर रहे हैं।

1951 से 50 वर्षों की अवधि में आर्थिक विकास की औसत दर 3% रही है। यद्यपि यह विश्व के 4% की तुलना में बुरी नहीं है तथापि विकासशील देशों के 7% से 10% की तुलना में कम है। 1951 से 2000 के बीच हमारी वार्षिक राष्ट्रीय आय 3.5% की दर से बढ़ी है, कृषि उत्पादन 2.7% औद्योगिक विकास 6.1% और प्रतिव्यक्ति आय में 1.1% की वृद्धि हुई है। यद्यपि सरकार ने दावा किया है कि गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 1999 में 36% ही थी लेकिन बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, अतः हम यह नहीं कह सकते कि गरीबी कम हो गयी है। इसमें आश्चर्य नहीं कि आज अधिक लोग कुण्ठा का अनुभव करते हैं और प्रतिवर्ष आन्दोलन बढ़ रहे हैं।

योजना आयोग के माध्यम से कृषि, पेयजल, सिचाई, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य संचार, परिवहन पशुपालन तथा समाज कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में विकास, पशुपालन तथा समाज कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन पचास वर्षों से जारी है लेकिन राष्ट्र की बुनियादी समस्याओं आज भी यथावत बनी हुई हैं। इसमें गरीबी, कुपोषण, जनाधिक्य, स्वास्थ्य का निम्नस्तर, बेरोजगारी, शोषण असमानता तथा पेयजल परिवहन एवं ऊर्जा की कमी इत्यादि प्रमुख हैं।

क्या कारण है कि नौ पंचवर्षीय योजनाएँ पूर्ण करने के बावजूद भी हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, नौकरशाही का परम्परागत मॉडल तथा परम्परागत समाज की दूषित मानसिकता सहित राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी ने विकास की प्राथमिकताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बार-बार प्रभावित किया है। रूसी ग्रास प्लान पर आधारित भारतीय योजनाओं की प्राथमिकताएँ तथा अभिगम योजना — दर — योजना परिवर्तित होते रहे हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में सतत विकास नहीं हो पाया है। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिचाई, तथा विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी तो दूसरी योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी। लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा राष्ट्रीयकरण के उस दौर में विकास के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया।

तीसरी योजना में खाद्यान्न, औद्योगीकरण तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्राथमिकता में एवं तदनुसार कार्यक्रम निश्चित करने पड़े तो चौथी योजना युद्ध, अकाल, विदेशी सहायता के कारण देरी से शुरू हो पायी, जिसमें हमने पुनः कृषि, सिचाई को वरीयता दी। पाँचवी योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था।

अतः स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सामाजिक सेवा क्षेत्र तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम को एकीकृत स्वरूप में संचालित किया गया लेकिन छठी योजना में कृषि के साथ-साथ उद्योगों एवं ऊर्जा को विकसित करना अधिक जारी समझा गया। सातवीं योजना में पुनः ऊर्जा की प्राथमिकता के साथ ही मानव ससाधन विकास को महत्व दिया गया।

आठवीं योजना के समय भारत में निजीकरण का दौर आरम्भ हो चुका था। अतः सरकार ने इस योजना में प्राथमिक शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य के साथ ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी लेकिन भारत में ऊर्जा की कमी पूर्ववत् बरकरार है।

नौवीं योजना में ग्राम विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, आवास के साथ समग्र विकास को लक्ष्य रखा गया। वही दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आगामी 10 वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय को दो गुना करने का है किन्तु नौवीं योजना की समीक्षा नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

यह दुर्भाग्य ही है कि पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई गयी अभिगम प्रणाली, माडल तथा रणनीति कभी भी लम्बे समय तक यथावत् जारी नहीं रही बल्कि प्रत्येक योजना में हमने नया प्रयोग किया। उदाहरण के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हैरोड डोमर माडल था तो दूसरी योजना महालनोविस माडल (असंतुलित सवृद्धि मॉडल) पर आधारित थी। इसी प्रकार तीसरी योजना जॉन सैण्डी एवं एस0 चक्रवर्ती, मॉडल पर, चौथी योजना एलन मान्ने एवं अशोक-रूद्र माडल (सामाजिकता माडल) पर, पाँचवीं योजना आयोग के स्वनिर्मित प्रारूप पर, छठी योजना संरचनात्मक परिवर्तन तथा वृद्धि उन्मुख माडल पर, सातवीं योजना दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल पर एवं



आठवी योजना निजीकरण एवं वैश्वीकरण के डब्ल्यू मिल्लर माडल पर आधारित थी।

इन सभी अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों की अपनी-अपनी शेष गुण तथा अवगुण हैं। यूरोपीय तथा विकसित राष्ट्रों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक परिवेश विकासशील राष्ट्रों की तुलना में भिन्न है। अतः भारत जैसे रूढ़िवादी तथा बहुसांस्कृतिक देश में विशुद्ध भारतीय माडल ही विकास करवा सकता है।

21वीं सदी में एक अरब से अधिक नागरिकों को लेकर प्रवेश कर चुका भारत पुनः यह सोचने को मजबूर है कि पहले विकास किया जाय अथवा जनसंख्या को नियन्त्रित किया जाय। विकास को समग्र रूप में आँकने तथा आधारभूत संरचना को विकसित करने की दिशा में हमने अभी तक नहीं सोचा है। दरअसल सड़क तथा विद्युत दो ऐसी मूलभूत सुविधायें हैं जिनपर सम्पूर्ण विकास चक्र टिका है किन्तु हमारे देश में ये दोनों सुविधायें ही जर्जर अवस्था में हैं। स्पष्ट है कि सड़क ऊर्जा के अभाव में पेयजल सिंचाई उद्योग, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लक्ष्य भी अघर में लटक जाते हैं।

स्वतन्त्र भारत में नियोजन की पचास वर्षीय यात्रा के वर्तमान मोड़ पर यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब केन्द्रीय स्तर पर सम्पूर्ण देश के लिये एक समान योजनाएँ बनीं तथा विकास कार्यक्रम संचालित हुये तो ऐसे क्या कारण रहे कि केरल, तमिलनाडु तथा पंजाब तो अधिक विकसित हो गये किन्तु भरपूर संसाधनों से युक्त बिहार तथा यूपी० पिछड़ गये स्पष्ट है कि इसका उत्तर हमारी स्थानीय संस्कृति, मानसिकता तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित जनजागरूकता के मापदण्डों में समाहित है। कुछ विद्वान यह भी प्रश्न उठाते हैं

कि भारत में योजनाओं का वैधानिक आधार नहीं है। अतः योजनाएँ या विकास कार्यक्रम असफल रहने पर सरकार को न्यायालय के कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। वस्तुतः समस्या योजनाओं की अवैधानिकता की कम तथा प्रशासनिक तन्त्र की कठोरता, अप्रतिबद्धता तथा राष्ट्रप्रेम के अभाव की प्रक्रिया है।

### 1.3.1. ग्रामीण विकास की योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन

सरकार ने ग्रामीण भारत में तीव्र विकास, सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तन तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण विकास की कुछ प्रमुख योजनाओं में परिवर्तन करने का फैसला किया है। ये नये परिवर्तन 1 अप्रैल 1999 से लागू हुये। मार्च 1999 में तत्कालीन ग्रामीण विकास मन्त्री (बी०जी० पाटिल) ने इन परिवर्तनों की घोषणा की। इनके तहत स्वरोजगार की चल रही सभी योजनाओं को मिलाकर एक नयी स्वरोजगार योजना शुरू की गयी जिसका नाम “स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना” है।

इसमें IRDP, ड्वाकरा, ट्राइसेम, सिटरा, गंगा कल्याण योजना और दस लाख कुओं की योजना का विलय कर दिया गया है। इसके तहत अब गरीबी उन्मूलन के लिये हर जिला अपने ससाधनों के आधार पर व्यापक योजना तैयार करेगा। इसमें सामूहिक विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिये स्व सहायता समूहों का गठन किया जायेगा और इन समूहों को अपने आर्थिक, कार्यकलाप कारगर ढंग से चलाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। हर विकास खण्ड में कम से कम आधे स्वसहायता समूह केवल महिलाओं के लिये होंगे, गरीबों की पहचान ग्राम सभाएँ करेगी। ग्रामीणों में कौशलों का विकास करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। लाभार्थियों को स्वरोजगार परियोजना लगातार की 30% तक की सब्सिडी दी जायेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये

सब्सिडी योजना लागत के 50% तक होगी। जवाहर रोजगार योजना का भी पुर्नगठन किया गया है और इसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया है।

अब इसके अन्तर्गत गाव के स्तर पर ही बुनियादी ढाँचे को विकसित करने पर जोर दिया जायेगा। इसलिये योजना की पूरी धनराशि ग्राम पचायतो को दी जायेगी। श्रम प्रधान कार्यक्रमो पर ही ज्यादा जोर रहेगा और मजदूरी तथा सामग्री के 60/40 के अनुपात मे भी उचित छूट दी जायेगी। पचायतो को 50 हजार रुपये तक के कार्यक्रम स्वयं शुरू करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले से बनी परिसम्पत्तियो के रखरखाव पर खर्च को भी 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। योजना की धनराशि का 22.5% अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लाभार्थियों पर खर्च किया जायेगा। ग्राम पचायते प्रत्येक वर्ष 7500 रुपये या मिली धनराशि का 75% दोनो मे से जो भी कम हो को प्रशासनिक व्यय के रूप मे खर्च कर सकेगी।

सुनिश्चित रोजगार योजना अब जिला/प्रखण्ड स्तर पर लागू की जाने वाली एक मात्र योजना रह गयी है। जिसमे जिले को मिलने वाली धनराशि का 70% प्रखण्डो को दिया जायेगा और 30% जिला स्तर पर खर्च करने के लिये रखा जायेगा। जिस किसी प्रखण्ड मे काम की माँग होगी, जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ काम शुरू करवा सकेंगे, कार्यों के चुनने का दायित्व उस क्षेत्र के सासदो की सलाह से जिलापरिषदो का होगा। अगर वहाँ चुनी हुई निकाय नही होगी तो स्थानीय सासदो, विधायको और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियो की एक समिति गठित की जायेगी जो कार्यों का चयन करेगी।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) के लिये अलग बजट का प्रावधान किया जायेगा। इन एजेंसियों के कर्मचारियों में व्यवसायीकरण लाया जायेगा। इसके लिये उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों में अब केन्द्र-राज्य अनुपात 75:25 का होगा जो कि इसके पहले 80:20 का अनुपात था।

ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख मकान प्रतिवर्ष बनाने की एक आवास कार्ययोजना तैयार की गयी। इस कार्ययोजना के साथ सरकार ने कई कदम एक साथ उठाने की मजूरी दी है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आवास, और पर्यावरण मिशन की स्थापना, श्रम और सब्सिडी की नयी स्कीम, इन्दिरा आवास योजना के तहत मकानों की मरम्मत, ग्रामीण निर्मित केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक धन हेतु हुडको द्वारा और ज्यादा सहायता तथा ग्रामीण आवास विकास के लिये एक नयी योजना योजना शामिल है।

अब अनुसूचित जाति, जनजाति के अलावा अन्य ग्रामीण परिवार को भी यह सुविधा मिलेगी। इन लोगों हेतु एक नयी योजना लागू की जा रही है जिसके तहत मकान बनाने हेतु आशिक सब्सिडी मिलेगी और आशिक रूप से ऋण मिलेगा। जिन ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 32,000 रुपये से कम है वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। गरीबी से नीचे रहने वालों को वरीयता दी जायेगी। इन नयी योजना को व्यावसायिक बैंक, आवास वित्त संस्थानों और हाऊसिंग बोर्डों के जरिये लागू किया जायेगा। अगले तीन वर्षों में इस योजना के तहत पाँच

इन्दिरा आवास योजना को दो घटकों में लागू करने का फैसला किया गया। पहले घटक में बेघरों को मकान बनाने की योजना के तहत मैदानी इलाकों में 20 हजार और पहाड़ी इलाकों में 22 हजार रुपये प्रति मकान आबंटित करने की योजना जारी रखी गयी और योजना की 80% राशि इसी पर खर्च की जाय। इसके लिये प्रति मकान दस हजार रुपये की सहायता की जाय। मकान की मरम्मत का मतलब उसमें शौचालय और धुँआ रहित चूल्हा भी बनाया जाये।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्यों को अब आवश्यकता के आधार पर सहायता दी जायेगी। जिन राज्यों में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पेयजल उपलब्ध नहीं है या सूखाग्रस्त, मरुस्थल या चट्टानी क्षेत्र हैं उन्हें अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा सहायता दी जायेगी जहाँ पेयजल के स्रोत उपलब्ध हैं।

योजना के कुल परिव्यय का 20% प्रोत्साहन राशि के रूप में उन राज्यों के लिये रखा गया है जो समुदाय आधारित कार्यक्रम को सथागत बनाने के लिए ग्रामीणों को परियोजना और प्रबन्ध में भागीदारी इस प्रकार देते हैं कि पूँजीगत लागत का आंशिक और संगठन तथा व्यवस्था का शत प्रतिशत खर्च उपभोक्ताओं द्वारा किया जाय। सरकार ने ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण में तेजी लाने के लिये वर्ष 1999-2000 को “ग्रामसभा वर्ष” घोषित किया है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मन्त्रालय का नाम 9 अप्रैल 1999 से ग्रामीण विकास मन्त्रालय कर दिया गया। अब इस मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि ससाधन विभाग नामक दो विभाग होंगे जो विकास के कार्यक्रम का क्रियान्वित करेंगे। वर्ष 2001-2002 के बजट में देश के सभी गाँवों में अगले छ वर्ष में बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखते हुये ग्रामीण विकास के लिये गतवर्ष

की तुलना में बजट में 336 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गयी है। बजट में कुल 9224.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है (कुरुक्षेत्र अप्रैल 2001 पृष्ठ 14)।

### 1.3.2. नियोजित ग्रामीण विकास एवं सूक्ष्म स्तरीय नियोजन :-

देश की जनसंख्या का तीन-चौथाई हिस्सा ग्रामीण भारत में निवास करता है। अतएव राष्ट्र तभी शक्तिशाली व समृद्ध हो सकता है, जब हमारे गाँव गरीबी व पिछड़ेपन से मुक्त हों। भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुतगामी तथा निरन्तर विकास के लिए कटिबद्ध है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में सलग्न है, जिनका उद्देश्य है, ग्रामीण जनता को अपना जीवन स्तर सुधारने के योग्य बनाना। गरीबी उन्मूलन तथा त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ, विकास कार्यक्रमों को एक विविधतापूर्ण रणनीति द्वारा समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग तक पहुँचाने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास तथा सड़क सम्पर्क को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

निराश्रितों और गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को अत्यन्त महत्व दिया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता व प्रोत्साहन तथा ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को त्वरित ग्रामीण विकास का हिस्सा बनाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को दायित्व, अधिकारों और वित्त के मामले में अधिकार संपन्न बनाने के लिए मंत्रालय निरन्तर प्रयासरत है। एक नई पहल के रूप में ग्राम सभा एक अत्यन्त उल्लेखनीय संस्था बन चुकी है। भागीदारी आधारित लोकतन्त्र को सार्थक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों और

पचायती राज सस्थाओं को उचित भूमिका प्रदान की गयी है। भूमि सुधारों के साथ-साथ, बजर भूमि, मरुभूमि तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

भूमि के निरन्तर विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र पहल के अन्तर्गत मन्त्रालय ने ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त, दो अन्य विभागों भू-ससाधन विभाग तथा पेयजल आपूर्ति विभाग का गठन किया है। इससे क्षेत्र विकास योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ समन्वित नीति अपनाने में भी मदद मिलेगी।

ग्रामीण जीवन को दो प्रकार की नीतियाँ प्रभावित करती हैं (1) उत्पादन परक क्रियाएँ, जिनका उद्देश्य उत्पादन और सेवाएँ प्रदान करना हो, उदाहरणार्थ, सब्सिडी प्राप्त खादे, सिचाई व ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण उद्योगों का पता लगाना आदि। (2) गैर उत्पादन क्रियाएँ, जिनका उद्देश्य जीवन स्तर उठाना हो। प्रथम प्रकार की क्रियाएँ ग्रामीण विकास उपाय कहलाते हैं। ये क्रियाएँ या तो समस्त समुदाय को प्रभावित करती हैं या समुदाय के किसी विशेष वर्ग को। प्रथम प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण हैं सामुदायिक विकास योजनाएँ (1952), पचायती राज (1962), भूमि सुधार (1950), गरीबी हटाओ कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979), आदि, जबकि दूसरे प्रकार की क्रियाएँ हैं, जनजातीय विकास कार्यक्रम (1959), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (1979), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (1977), काम के लिये भोजन कार्यक्रम (1977), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980), ट्राइसेम आदि (दीप सागर, 1990)।

कुछ कार्यक्रम सम्पत्ति (उत्पादन बढ़ाने सहित) बढ़ाने के उद्देश्य से और लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से थे, जैसे आई0आर0डी0पी0

न्यूनतम कृषि मजदूरी, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि जबकि अन्य कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों का सामाजिक उत्थान था, जैसे – जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, पंचायती राज, ट्राइसेम आदि। कुछ कार्यक्रम वास्तव में गरीबी उन्मूलन के लिये थे (जैसे एन0आर0ई0पी0 का स्वयं रोजगार कार्यक्रम डी0पी0ए0पी0, ट्राइसेम का प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि) जबकि कुछ कार्यक्रम राजनीति से अधिक प्रेरित थे जैसे गरीबी हटाओ, और बीस सूत्रीय कार्यक्रम। लेकिन सामुदायिक भागीदारी, सामाजिक बुराइयों को दूर करना तथा जीवन की गुणवत्ता को सुधारने जैसे मूल उद्देश्यों को अभी भी प्राप्त करना शेष है।

ग्रामीण विकास के लिये तीन उपाय अभी तक किये गये हैं (1) प्रारम्भ में 1950 के दशक में नीति निर्माताओं ने पूँजी निवेश बढ़ाकर आर्थिक विकास की अधिकता पर बल दिया, यह मानते हुये कि इसके लाभ नीचे तक पहुँचेंगे और ग्रामीण समाज के सभी वर्गों तक प्राप्त होंगे। लेकिन 1970 के दशक में यह अनुभव किया गया कि कृषि विकास के लाभ गरीब ग्रामीणों तक नहीं पहुँचे। (1) इससे सरचनात्मक सम्प्रदाय द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का उदय हुआ जिसने यह सुझाव दिया कि सम्पत्ति का वितरण भूमि सुधारों, सामुदायिक विकास योजनाओं, और सहकारी खेती द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यह भी व्यावहारिक सिद्ध नहीं हुआ (3) 1980 के दशक में एक नया विचार आया कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा गरीबों पर प्रहार किया जाये (जैसे I.R.D.P., TRYSEM, और NREP, RLEGP जो बाद में I.R.Y कार्यक्रम में विलय हो गया )

जनमत यह है कि ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सकता है यदि लोगों के संसाधनों को गति प्रदान की जाये और उन्हें निर्णय करने के लिये प्रेरित किया जाय जो जीवन और जीवनयापन को प्रभावित करता है। वर्तमान में हमारे गाँवों में



गहरी गुटबाजी है। धन का दुरुप्रयोग, शक्तिशाली लोगो का दबाव, स्त्रियो को अवसरो का निषेध, दलितो के विरुद्ध आतक और चुनावो मे व्यवस्था भजन कार्य आदि गाँवो मे प्रचलित है। इन समस्याओ का निदान कठिन है।

आज भी यह विवाद का विषय है कि सूक्ष्मस्तरीय नियोजन मे नियोजन की इकाई क्या हो, ग्राम सभा, न्यायपचायत, ब्लाक, तहसील या जनपद। क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाओ का निर्माण प्रायः राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर हुआ तथा इसके क्रियान्वयन की प्रशासनिक इकाई के रूप मे जनपदो को स्वीकार किया गया, जिसका परिणाम अपेक्षित नहीं रहा। असफल योजनाओ के कारणो के विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि निचले स्तर पर बनायी गयी योजना उच्च स्तर पर बनायी गयी योजना की तुलना मे ज्यादा सफल होगी। इस प्रकार सूक्ष्म स्तर पर योजनाओ के क्रियान्वयन की अवधारण का विकास हुआ। चूँकि ग्राम और जिले के मध्य की इकाई विकास खण्ड होती है तथा इनका क्षेत्र भी कम होता है अतः इस स्तर पर भी योजनाओ का संचालन उपयुक्त हो सकता है किन्तु ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु नियोजन की इकाई ग्रामसभा अथवा न्यायपचायत ही होनी चाहिए। जिसका प्रमाण जवाहर रोजगार योजना है। इस प्रक्रिया से ग्रामीणो का विकास उनके सुलभ ससाधनो द्वारा उनकी आवश्यकताओ के अनुरूप उन्हें प्राप्त होगा।

इस प्रकार भारत मे बहुस्तरीय नियोजन छोटे स्तर के प्रशासनिक इकाई से प्रारम्भ कर क्रमशः बृहद स्तर से केन्द्रीय स्तर तक पदानुक्रम के प्रशासनिक इकाइयो के लक्ष्यो, उपायो एवं कार्यक्रमों के बीच तालमेल बैठाते हुए सशक्त रूप से विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने का सुविचारित एवं नितान्त व्यावहारिक उपागम है। इसमे यदि ऊपर से चला जाय तो केन्द्र से राज्य, जिला, ब्लाक,

तहसील तथा यदि नीचे से चला जाय तो ग्राम सभा, या ब्लाक, तहसील स्तर की योजनाएं अपनी उच्च स्थानिक स्तर के राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं से तालमेल बैठाती हैं।

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2001 के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 10000 करोड़ रुपये की नई महत्वाकांक्षी योजना, संपूर्ण रोजगार योजना की घोषणा की। इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और ज्यादा सुनिश्चित तौर पर उपलब्ध होंगे। इस योजना के अर्न्तगत पंचायतों द्वारा दिये गये रोजगार के तहत जो लोग स्थायी परिसम्पत्तियों का करेंगे उन्हें नकद तथा अनाज के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र द्वारा 50 लाख टन अनाज हर वर्ष राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है। जिसकी कीमत 5000 करोड़ रुपये है। केन्द्र सरकार की सभी रोजगार संबंधी योजनाओं का इस बड़ी योजना में विलय कर दिया जायेगा इस योजना से 100 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

ग्रामीण लोगों को इस योजना से अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए चतुर्मुखी रणनीति अपनाई गयी है, जिसमें योजना के बारे में लोगों को जानकारी देना, योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए सामाजिक लेखा-जोखा करना शामिल है। ग्रामीण विकास के लिए आठवीं योजना में आवंटित राशि 30,000 करोड़ रुपये को बढ़ाकर नवीन योजना में 42874 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को वर्ष 2001-02 की विभिन्न योजनाओं हेतु 12265 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग की

योजनाओं के लिए 9205 करोड़ रुपये, भू-ससाधन, पेयजल आपूर्ति विभाग की योजनाओं के लिए 900 करोड़ रुपये तथा पेयजल आपूर्ति विभाग की योजनाओं के लिए 2160 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं, (भारत 2002 पृष्ठ 476)।

ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एम०के० पाटिल ने राज्य सभा में बताया कि दसवें पंचवर्षीय योजना के दौरान 48,538 करोड़ रुपये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए तथा 9850 करोड़ स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए प्रस्तावित किया गया है (हिन्दूस्तान टाइम्स, 12 नवम्बर, 2002)।

#### 1.4. सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा .—

परिवर्तन विश्वव्यापी घटना है। इसकी गति, स्वरूप और दिशा अलग-अलग होती है। परिवर्तन का सामान्य तात्पर्य है किसी क्रिया अथवा वस्तु की पूर्वावस्था में बदलाव आ जाना। परिवर्तन का सम्बन्ध मुख्य रूप से तीन बातों से है—वस्तु, समय और भिन्नता। इस प्रकार किसी वस्तु में दो समयों में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। सामाजिक सम्बन्धों के स्थापित स्वरूपों, सामाजिक मूल्यों, संरचनाओं या व्यवस्थाओं में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है।

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है— समाज की भौतिक तथा गैर-भौतिक संस्कृति में पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है। इसका अर्थ ऐसे परिवर्तनों से है जो सामाजिक तन्त्र की संरचना तथा कार्य व्यापार में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है। यह सभी समाजों में और समाज के सभी चरणों में पाया जाता है। केवल उन्हीं परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है जिनसे समाज का अधिकांश वर्ग प्रभावित होता है। सामाजिक परिवर्तन सदैव समाज तथा इसके सदस्यों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होते। सामाजिक

परिवर्तन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। सामाजिक परिवर्तन की गति सभी समाजों में एक जैसी नहीं होती और इसी तरह एक ही समाज में भी इतिहास के सभी युगों में भी एक जैसी नहीं होती। सामाजिक परिवर्तन के गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों पहलू होते हैं।

परिवर्तन विकास का पर्यायवाची नहीं है। परिवर्तन से विकास हो भी सकता है और नहीं भी ग्रामीण तथा जनजातीय समाजों के ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहाँ सामाजिक परिवर्तन से जीविका का स्रोत जाता रहा, गरीबी बढ़ी और परिवारों को विघटन हुआ। सामाजिक परिवर्तन एक ओर मानव आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के बीच और दूसरी ओर सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करने के लिये एक नियोजित संस्थात्मक प्रक्रिया है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो आज है वह भावी कल से भिन्न होगा। अतः प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित स्तरों के माध्यम से सदैव परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के इच्छा अथवा प्रयत्नों से नहीं होता बल्कि यह प्राकृतिक दशाओं के प्रभाव से होता है। जिन पर मनुष्य का कोई नियन्त्रण नहीं होता है (स्पेन्सर – 1967 पृष्ठ 32)।

मैकाइवर (1972) ने सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रतिमानों का उल्लेख किया है।

- (1) परिवर्तन रेखीय हो सकता है जिसमें विकास एक सीधी रेखा में सम्पन्न होता है।
- (2) परिवर्तन उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है जिसमें कुछ समय तक तो परिवर्तन प्रगति की ओर होता है लेकिन इसके बाद इसकी दिशा समृद्धि तथा ह्रास किसी भी ओर मुड़ सकती है।

(3) परिवर्तन तरंगित-प्रकार का हो सकता है। जिससे यह पता नहीं चल पाता है कि परिणाम ह्रास का सूचक होगा या प्रगति का।

“सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात् समाज की संरचना तथा कार्यों में उत्पन्न होते हैं,” (किंग्सले डेविस)।

इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन वह स्थिति है जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत सम्बन्धों, प्रक्रियाओं, प्रतिमानों और संस्थाओं का रूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है कि उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है (मैकाइवर 1982)।

इससे स्पष्ट है कि सभी क्षेत्र सामाजिक सम्बन्धों से प्रभावित होते हैं और सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। इस प्रकार समाज में विकास के कारणों से हुआ परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है।

#### 1.5. ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन :—

ग्रामीण क्षेत्रों में बृहद विकास योजनाओं के प्रारम्भ होने से जहाँ एक तरफ आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र के विकास में सहायता मिलती है वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में भी रूपान्तरण होता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ पुराने सामाजिक मूल्यों एवं धारणाओं और सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएँ ग्रामीणों के जीवन स्तर में परिवर्तन कर देती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त गैर पारम्परिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप भाषा, वेशभूषा, धार्मिक, दृष्टिकोण, पारस्परिक व्यवहार एवं मानवमूल्यों में भी परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इनमें अन्धविश्वास, रूढ़ियों, मान्यताओं आदि के सम्बन्ध में ग्रामवासियों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। यदि

मानव समाज को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाय, कि वह परिवर्तित सामाजिक वातावरण में स्वयं को अनुकूलित कर सके और इस वातावरण का अपने हित में अधिकतम प्रयोग कर सके तो यही ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे-जैसे विकास की किरणें प्रस्फुटित होंगी, उसी प्रकार ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक स्तर, रहन-सहन खान-पान, वेशभूषा तथा जीवन शैली में अपने आप परिवर्तन होगा।

इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन स्थान, समय और सन्दर्भ के परिपेक्ष्य में सामाजिक संरचना के अन्दर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रियाओं के पुंज के समान है। सामाजिक परिवर्तन एवं ग्रामीण विकास के व्यापक अध्ययन के लिये संसाधनों, वितरण प्रक्रियाओं, संस्थापक उपायों, शैक्षणिक व्यवस्था, जीवन स्तर की प्रकृति, भूमि सम्बन्ध, आदि को समय, लोग और सन्दर्भ को दृष्टि में रखना आवश्यक है।

#### 1.6 ग्रामीण विकास और सामाजिक रूपान्तरण की प्रकृति एवं दिशा :—

रूपान्तरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो परम्परागत या अर्धपरम्परागत क्रम को एक निश्चित व वांछित अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करती है, एवं इसका सम्बन्ध सामाजिक संरचना, मूल्यपरकता, संवेगों एवं मानकों से है। रूपान्तरण के अन्तर्गत मानव की आर्थिक गतिविधियों के कारण भूतल में होने वाले परिवर्तनों, उभरते प्रतिरूपों की प्रवृत्ति और आयाम तथा उनके माध्यम से किसी क्षेत्र या देश के वर्तमान सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण में होने वाले विकासों का अध्ययन व व्याख्या किया जाता है (तिवारी 1984 पृ० 139)।

बीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारतीय समाज को परम्परागत समझा जाता था यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश को औद्योगिक बनाने का प्रयत्न किया और अनेक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने की भी कोशिश की, लेकिन लोगो के जीवन में गुणात्मक सुधार करने और जीवन स्तर उठाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी।

परम्परागत समाज वह है जिसमें (1) व्यक्ति की प्रस्थिति उसके जन्म से निश्चित व निर्धारित होती है अर्थात् व्यक्ति सामाजिक गतिशीलता के लिये संघर्ष नहीं करता है, (2) व्यक्ति का व्यवहार रिवाजों और प्रथाओं से संचालित होता है और लोगो के व्यवहार में पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा ही परिवर्तन आता है। (3) सामाजिक संगठन का आधार संस्तरण होता है। (4) व्यक्ति अपनी पहचान प्राथमिक समूह से बनाता है तथा परस्पर अन्तर्क्रिया में नातेदारी सम्बन्ध महत्वपूर्ण होते हैं। (5) प्रस्थिति की अपेक्षा व्यक्ति को सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना से अधिक महत्व दिया जाता है। (6) लोग रूढ़िवादी होते हैं। (7) अर्थव्यवस्था सरल होती है तथा जीविका से परे आर्थिक उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। (8) समाज में मिथकीय (Mythical) विचार प्रभावी होते हैं।

इसके विपरीत आधुनिक समाज यह है जिसमें (1) समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति उसकी स्वयं की योग्यता एवं सामर्थ्य से निर्धारित होती है। (2) सामाजिक संरचना का आधार समानता होता है (3) द्वितीयक सम्बन्ध प्राथमिक सम्बन्धों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं (4) समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति अर्जित होती है। (5) लोग नवीनता में विश्वास करते हैं। (6) अर्थव्यवस्था जटिल तकनीक पर आधारित होता है। (7) समाज में तार्किक विचारों का बोलबाला होता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि परम्परावाद और आधुनिकता दो चरम सीमाये हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। योगेन्द्र सिंह तथा एस0सी0 दुबे जैसे विद्वानों का मत है कि दोनों का सह-अस्तित्व हो सकता है। परम्परावाद को स्वीकारने का यह अर्थ नहीं कि आधुनिकता को अस्वीकार कर देना। इसका सरल सा अर्थ है आधुनिकता की शक्तियों पर नियंत्रण। इस दृष्टिकोण के आधार पर हमें यह पता लगाना है कि किस सीमा तक ग्रामीण भारतीय समाज परम्परागत है और किस सीमा तक यह आधुनिक हो गया है।

यह कहना गलत न होगा कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें आधुनिक व परम्परा का स्पष्ट समन्वय दिखाई देता है। एक ओर तो हमने उन विश्वासों, प्रथाओं और संस्थाओं की उपेक्षा की है जिनकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी, तो दूसरी ओर हमने उन मूल्यों को अपनाया है जिनको हमने अपने मौलिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक माना है।

ब्रिटिश काल की तुलना में आज स्वतन्त्रता अधिक है। सामाजिक पैमाने में उन्नति के अधिक अवसर प्राप्त हैं। हम परम्परागत सामाजिक प्रथाओं को छोड़ने में तथा नयी संस्थात्मक रचनाओं के निर्माण में अधिक विवेकी हो गये हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है। गणतन्त्र बनने के बाद गत 50 वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय में कई गुना वृद्धि हुई है।

हमारे समाज में विद्यमान वृहद असंतोष अनेक बढ़ते हुए विरोधाभासों का परिणाम है। कुछ विरोधाभास इस प्रकार हैं — हमारी भूमिकाये तो आधुनिक हो गयी है किन्तु हमारे मूल्य अभी भी परम्परागत हैं। हम समतावाद दर्शाते हैं किन्तु हम भेदभाव का व्यवहार करते हैं। हमारी आकांक्षाये बहुत ऊँची तो हो गयी है लेकिन



योग्यता एवं साधन की उपलब्धता उतनी नहीं है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं लेकिन क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देते हैं।

हम दावा करते हैं कि हमारा गणतन्त्र समानता लाने के लिये समर्पित है। किन्तु यह जाति व्यवस्था के शिकजे में जकड़ा हुआ है। हम तर्कशील होने का दावा करते हैं लेकिन भाग्यवादी भावना को स्वीकारते हैं। हम व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। लेकिन हम समूहवाद को लागू करते हैं। हम आदर्शवादी बनते हैं लेकिन भौतिक संस्कृति के पक्षधर हैं। विधान, कानून अनेक हैं किन्तु न्याय बहुत कम। कार्यक्रम व सरकारी कर्मचारी अनेक हैं किन्तु जनसेवा कम। अनेक योजनाएँ हैं किन्तु कल्याण कम।

इन सभी विरोधाभासों का परिणाम यह है कि हमारे समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है। भ्रष्ट तन्त्र तथा अप्रतिबद्ध राजनैतिक अभिजात वर्ग अपने निजी स्वार्थों में रूचि लेते हैं। जिन्हें देश के भविष्य की कोई चिन्ता नहीं होती वही आज विकास के विरोधी हैं। इस प्रकार यह सत्य है कि भारतीय ग्रामीण समाज परिवर्तित हो रहा है और विकास की कुछ दिशाएँ स्पष्ट होती जा रही हैं फिर भी सत्य यह है कि हम सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाये हैं जो हम चाहते थे। ग्रामीण भारत की आर्थिक कमजोरी का कारण लोगों में तकनीकी कुशलता की कमी नहीं है बल्कि साहस, स्थिति सुधारने की दृढ़ इच्छा, श्रम का सम्मान करने में कमी है। इसमें सुधार कर ग्रामीण भारत की खुशहाली को अक्षुण्ण रखा जा सकता है।

#### 1.7 वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य :-

स्वतन्त्रता के बाद से ग्रामीण विकास के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जो सरकार, प्रशासक, नियोजक एवं शिक्षाविदों के व्यापक विचारविमर्श का केन्द्र बिन्दु बना हो। परन्तु उसकी स्थिति में आज भी मानूसन की

अनिश्चितताओं से ग्रस्त, पिछड़े वन का द्योतक माना जाता है। समाज में बड़े भूस्वामियों का वर्चस्व है, कृषि उत्पादकता कम है, बेरोजगारी और निर्धनता बनी हुई है, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास एवं विकेन्द्रीकरण नहीं हो पाया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न यह है कि इन समस्याओं का निदान क्या है ? वर्तमान शोध कार्य भी इसी प्रश्न के उत्तर प्राप्ति का एक प्रयास है। शोधकर्ता के मन में ग्रामीण समाज में होने वाले क्रिया-कलापों तथा उनके प्रभावों से सम्बन्धित अनेक प्रश्न उठते रहे हैं जैसे—

- (1) विभिन्न योजनाओं में प्रमुखता पाने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित विकास के लक्षण क्यों नहीं स्पष्ट होते ?
- (2) गाँवों की सामाजिक-आर्थिक संरचना पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा रहा है ?
- (3) गाँवों के बहुमुखी विकास हेतु क्या ये योजनाओं सही अर्थों में अपनायी गयी है।
- (4) ग्रामीण समाज में व्याप्त रूढ़ियों, परम्पराओं तथा सामाजिक संस्कारों से बचने का क्या कोई उपाय है ?
- (5) सरकार द्वारा लागू की गयी विभिन्न विकास योजनाओं पर ग्रामीण जनता की कैसी प्रतिक्रिया रही है ?
- (6) इन विकास योजनाओं से ग्रामीण समाज कितना लाभान्वित हुआ है।
- (7) क्या सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में ग्रामीण विकास योजनाएँ अपना प्रभाव डाल सकी हैं ?
- (8) क्या सामाजिक कुरीतियों का निदान सम्भव है ? यदि हाँ तो कैसे ? यदि नहीं तो क्यों ?

इन प्रश्नों तथा ऐसे ही अनेक प्रश्नों के समाधान हेतु शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध प्रबन्धन में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की भानपुर तहसील को एक प्रतिदर्श मानकर स्वातन्त्रोत्तर काल में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों के निरूपण के साथ-साथ ग्रामीण योजनाओं की सफलता एवं असफलता के कारणों का आकलन करने का प्रयास किया है। ग्रामीण समाज में व्याप्त प्राचीन कुरीतियों के समापन के ही साथ ही ग्रामीण समाज के सर्वांगीण विकास के परिप्रेक्ष्य में सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

सम्पूर्ण विषय वस्तु 9 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के सैद्धान्तिक पक्ष का वर्णन तथा अध्ययन के उद्देश्य एवं विधितन्त्र को निरूपित किया गया है।

द्वितीय अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के भौतिक प्रतिरूप उच्चावच्च, जलवायु, वनस्पति तथा मृदा आदि का विश्लेषण किया गया है।

तृतीय अध्याय में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, साक्षरता तथा व्यवसायिक संरचना को निरूपित किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में ग्रामीण विकास के मुख्य अवयव कृषि के प्रतिरूप तथा समस्याओं का अध्ययन किया गया है तथा विकासार्थ सुझाव भी दिये गये हैं।

पंचम अध्याय में ग्रामीण यातायात, संचार व्यवस्था एवं सेवा केन्द्रों का विवेचन किया गया है।

षष्ठम अध्याय में ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में ग्रामीण उद्योग एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन किया गया है।

सप्तम अध्याय में ग्रामीण विकास की आधारभूत सुविधाओं एवं समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है और सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

अष्टम अध्याय में विकास के स्तर का निर्धारण किया गया है एवं आर्थिक विकास से सम्बद्ध सामाजिक परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है।

नवम अध्याय में ग्रामीण विकास नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण एवं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास की अद्यतन योजनाओं तथा पंचायती राज की भूमिका का वर्णन किया गया है।

## 1.8 शोध-विधि तन्त्र :-

शोध-परिरूप अध्ययन या शोध का युक्ति सगत और व्यवस्थित नियोजन है जिसे शोधकर्ता शोध-विधितन्त्र द्वारा प्राप्त करता है।

### 1.8.1. आकड़ों का संग्रहण :-

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों का संग्रहण प्रमुखतः तीन स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं।

- (1) लिखित अभिलेख (दस्तावेज)
- (2) मानचित्र तथा आरेख
- (3) सर्वेक्षण और साक्षात्कार

#### (1) लिखित अभिलेख (दस्तावेज) .-

प्रस्तुत अध्ययन में जनपद गजेटियर बस्ती 1984, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका जनपद बस्ती (1961, 1971 1981 और जनसंख्या निदेशालय लखनऊ से प्राप्त। 1991 की भानपुर तहसील की प्राथमिक जनगणना रिपोर्ट, (कम्प्यूटर फ्लपी के माध्यम से) सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती (1990, 2000, 2001) भारतीय स्टेट बैंक, मार्ग दर्शी बैंक, कार्यालय बस्ती, समाजार्थिक समीक्षा पत्रिका जनपद बस्ती 2000-2001, उत्तर प्रदेश वार्षिकी, भारत 2001-2002 तथा तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्डों से प्राप्त अभिलेख आदि का उपयोग किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भौगोलिक ग्रन्थों, शोध प्रबन्धों तथा इतिहास, धर्म, दर्शन और समाज पर आधारित कई पुस्तकों का अध्ययन क्षेत्र की समस्त भौगोलिक जानकारी के हेतु उपयोग किया गया है।

(2) मानचित्र तथा आरेख :-

शोधकार्य में जनपदीय गजेटियर मानचित्र, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के मानचित्र, नलकूप प्रखण्ड, सरयू नहर परियोजना, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त मानचित्र, सांख्यिकीय पत्रिका मानचित्र, तहसील, विकासखण्ड तथा न्यायपंचायत का मानचित्र जनगणना हस्तपुस्तिका तथा एडमिनिस्ट्रेटिव एटलस 1971 एवं जनसंख्या निदेशालय लखनऊ से प्राप्त किया गया।

(3) प्राथमिक आँकड़े व्यक्तिगत सर्वेक्षण, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली आदि से किये गये हैं।

1.8.2. शोध विधितन्त्र का विश्लेषण एवं व्याख्या :-

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में यथास्थान तालिका क्रमांक और मानचित्र तथा आरेख प्रस्तुत कर क्षेत्र का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। स्थानिक प्रतिरूप की स्पष्ट व्याख्या के लिये शोधप्रबन्ध में कोरोप्लेथ मानचित्र का प्रयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार विश्लेषण हेतु बिन्दु विधि, सममान, मानचित्रण, आरेखों आदि का भी उपयोग हुआ है।

अध्ययन में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन अधिक उपयुक्त होता है अतः प्रस्तुत अध्ययन में न्यायपंचायत को प्रतिदर्श इकाई माना गया है। किन्तु कहीं-कहीं पर ग्राम स्तरीय आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण विकास खण्ड को भी आधार माना गया। व्याख्या में विगत एवं वर्तमान स्थिति की तुलना करके निष्कर्ष निकालने तथा अध्ययन क्षेत्र के विकासार्थ योजना बनाने का प्रयास किया गया है। ✓

## REFERENCES

Bertrand Rural Sociology (p 9, 10)

Chambers, Robert, 1983 Rural Development Putting the Last First  
(Longmans Group Ltd ) p 147

Copp, J H 1972 . Rural Sociology and Rural Development, Vol 37, No 4  
(December), p p 515-533

Davis, Kingsley, 1969 Human Society, p 622, Mac Millan, New York

Deep Sagar "Rural Development Policies of India "India Journal of Public  
Administration, April-June 1990, 251-261

Encyclopaedia of Social Science Vol X V, 1949

Ginsberg, 1958, Social change, British Journal of Sociology (Sept 1958)  
p 205

Lessey, W R , 1977 · Planning in Rural Environments, (New York, Mc Graw  
Hill.)

Maciver and Page, 1967 . Society, p 511, Mac Millan, London

Misra, R P and Sundaram, 1979 Rural Area Development-perspective and  
Approaches ( New Delhi, Sterling Publication), p. 428.

M N Srinivas · Social Change in Modern India.

M N Srinivas India – Social Structure

Mukherjee : R N. Sociology (Hindi)

Mukherjee : R.N. Indian Society.

Paul. H Landis : Rural Life in Process p. 18.

Sharma K L. : Indian Society , N.C.E.R.T (Hindi)

Shrivastava K N “What is Rural” Rural India march & april 1971. P 87

Tiwari R C 1984 Settlement system in Rural India . A case study of the  
lower Ganga-Yamuna Doab (All India Geographical Society  
Allahabad p 139)

Todaro M P , 1977 Economics for A Developing World, (London  
Longmans Group Ltd ), p 249

भारत 2001, पृ० 455, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई  
दिल्ली ।

कुरुक्षेत्र, अप्रैल 2001, पृ० 14, ग्रामीण विकास, मन्त्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

भारत 2002, पृ० 476 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई  
दिल्ली ।

सिंह, महेन्द्र बहादुर एव दूबे, कमलाकान्त प्रादेशिक विकास नियोजन पृ० 255–256

दूबे, बेचन एव सिंह मगला — 1985, समन्वित ग्रामीण विकास जीवनधारा प्रकाशन,  
वाराणसी, पृ० 3–5–1

आहूजा, राम — भारतीय समाज ।



## अध्याय-2

### भौतिक प्रतिरूप

#### 2.1 स्थिति एवं विस्तार .

अध्ययन क्षेत्र—भानपुर तहसील, उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में अवस्थित बस्ती जनपद का उत्तरी सीमान्त क्षेत्र है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से सन् 1989 तक इस तहसील का अस्तित्व दो अलग-अलग तहसीलों के विकास खण्ड के रूप में था। सन् 1971 में जनपद बस्ती में कुल 6 तहसीले डुमरियागज, नौगढ़, बौंसी, हरैया, बस्ती तथा खलीलाबाद थी। उस समय भानपुर तहसील का अस्तित्व नहीं था। वर्तमान समय में भानपुर तहसील के दो विकास खण्ड रामनगर तथा सल्टौवा गोपालपुर हैं, जो पहले क्रमशः डुमरियागज तथा बस्ती तहसील के विकास खण्ड थे।

जब 1989 में बौंसी, नौगढ़, डुमरियागज तहसील अलग होकर जनपद सिद्धार्थनगर बना तो रामनगर विकास खण्ड को बस्ती तहसील में सम्मिलित कर लिया गया। 1989 में बस्ती जनपद में बस्ती, हरैया, खलीलाबाद नामक केवल तीन तहसीले थी। 1989 में ही बस्ती तहसील के उत्तरी सीमान्त में स्थित विकास खण्ड रामनगर तथा सल्टौवा गोपालपुर को मिलाकर एक नयी तहसील भानपुर का सृजन किया गया। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उक्त प्रशासनिक परिवर्तन के उपरान्त निर्मित भानपुर तहसील का ही अध्ययन किया गया है।

इस प्रकार 1997 तक बस्ती जनपद में चार तहसील बस्ती, हरैया, खलीलाबाद एवं नवसृजित भानपुर थी। 1997 में खलीलाबाद तहसील के 6 विकास खण्डों सहित जनपद सन्तकबीर नगर के सृजन के बाद बस्ती जनपद में तीन तहसीले बस्ती, हरैया, भानपुर रही। वर्ष 2002 में रुधौली नामक एक नयी



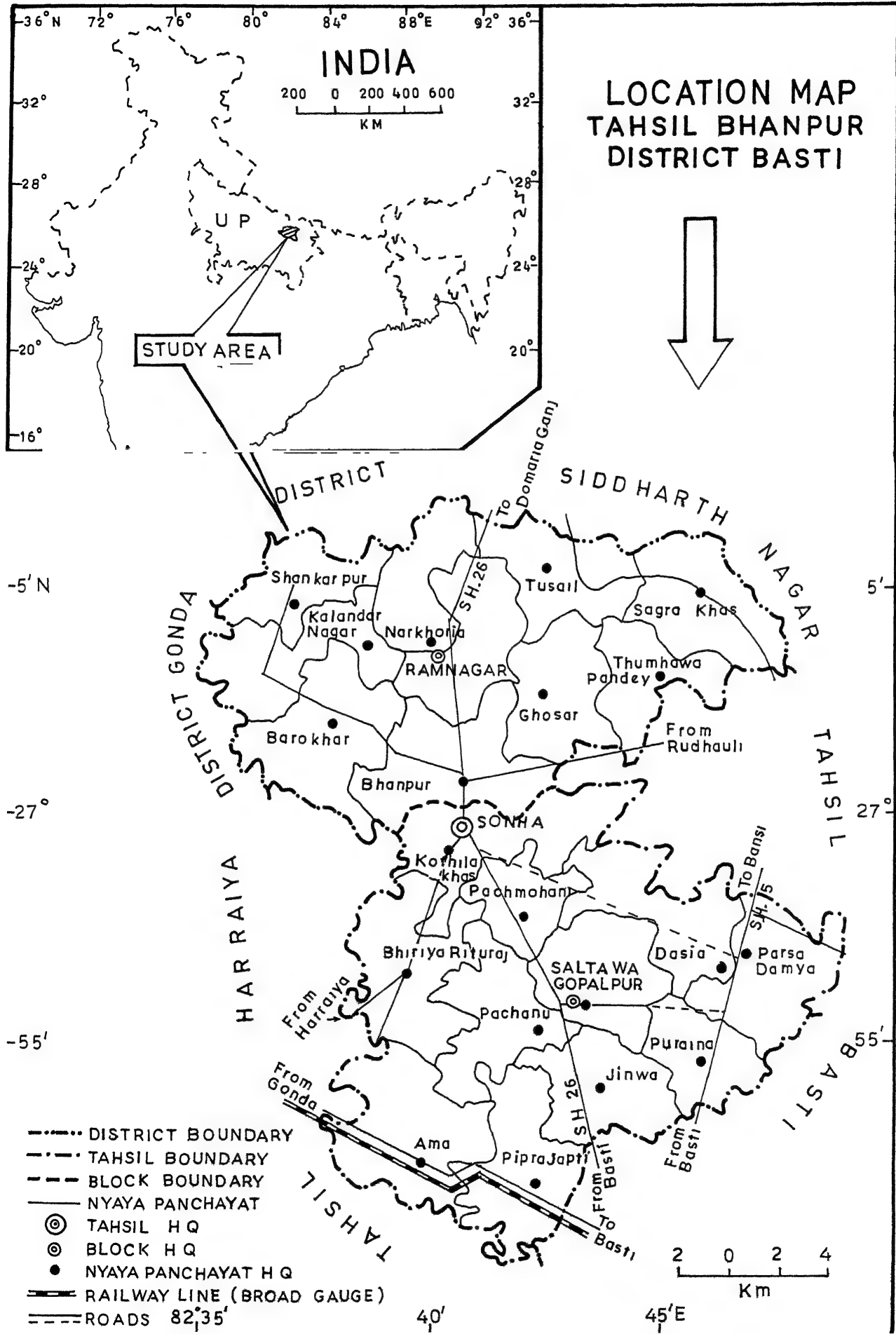


Fig. 2.1

तहसील के सृजन के साथ सम्प्रति जनपद में कुल चार तहसीलों का प्रतिनिधित्व करता है।

भानपुर तहसील का विस्तार  $26^{\circ}50'15''$  उत्तर से  $27^{\circ}7'20''$  उत्तरी अक्षांश एवं  $82^{\circ}34'30''$  पूर्व से  $82^{\circ}48'50''$  पूर्वी देशान्तर के मध्य पाया जाता है। इसके पूरब में बस्ती जनपद की बस्ती तहसील एवं दक्षिण पश्चिम में हरैया तहसील है। उत्तर में जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर पश्चिम में जनपद गोण्डा द्वारा इसकी बाह्य सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। वही पश्चिम में कुआनो नदी एवं उत्तर पूरब में आमी नदी इसकी भौतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। बैडवा तथा रेहवर नाला इसके मध्य से प्रवाहित होकर तहसील के विकासखण्डों के सीमा को निर्धारित करती हैं। तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्रफल **451.99** वर्ग किमी है। जो जनपद बस्ती के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.31% है। इसकी पश्चिम से पूरब की चौड़ाई कम पायी जाती है। उत्तर एवं दक्षिण में लगभग 20 किमी तथा मध्य में इसकी चौड़ाई 10 किमी पायी जाती है। उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 30 किमी से भी अधिक पायी जाती है। सन 1991 की जनगणना की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार तहसील की कुल जनसंख्या 2,47,643 थी। जोकि जनपद की कुल जनसंख्या का 15.66% थी।

तहसील की शतप्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जनघनत्व 1991 में 548 था। तहसील मुख्यालय द्वारा प्राप्त 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार तहसील की वर्तमान जनसंख्या 30,2041 है। जिसमें पुरुष 1,54,702 तथा स्त्री 1,47,339 हैं। जिसके अनुसार जनघनत्व 668 पहुँच गया है।

## तालिका क्रमांक : 2.1

भानपुर तहसील (जनपद बस्ती) : प्रशासनिक संगठन

विकास खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हे०में)	न्यायपंचायतों की सं०	ग्राम पंचायत	कुल ग्राम	आबाद ग्राम	गैर आबाद
रामनगर'	23,509	10	69	177	170	7
सल्टौआ गोपालपुर	21,690	11	82	258	239	19
योग	45199	21	151	435	409	26

स्रोत :- प्राथमिक जनगणना अभिलेख, जनपद बस्ती 1991 तथा

सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 2000 से संगणित

विभाजन के पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्ती जनपद प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा जनपद था। परन्तु अब यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल 2771.7 वर्ग किमी है। जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.15% है। प्रशासन को ठीक रूप से चलाने एवं विकास के प्रकाश को सभी ग्रामों। नगरों में पहुँचाने हेतु जनपद को तीन तहसीलों एवं 13 विकास खण्डों में विभक्त किया गया है। जनपद में 139 न्यायपचायत हैं। जिसमें 1050 ग्राम पचायत, 3066 आबाद ग्राम व 285 गैर आबाद ग्राम हैं।

प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण तहसील 2 विकास खण्डों, 21 न्यायपचायतों 151 ग्राम पचायतों एवं 435 ग्रामों में विभक्त है (तालिका क्रमांक 2.1)। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विकास खण्ड रामनगर है। क्षेत्रफल के आधार पर तहसील का बृहत्तम आबाद ग्राम अजगैवा जगल (896 हे०) आमा न्यायपचायत तथा न्यूनतम आबाद ग्राम बेनीपुर (8 हे०), पिपराजप्ती न्यायपचायत जो कि सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड में स्थित है।

## 2.2 उच्चावच्च एवं संरचना : —

अध्ययन क्षेत्र एक समतल मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग का निर्माण टर्शियरी कल्प में गोण्डवाना लैण्ड के उत्तराभिमुख दबाव के कारण निर्मित हिमालय पर्वत के दक्षिणवर्ती अग्रगर्त में राप्ती एवं घाघरा नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। इस भाग में सरिताओं के प्रवाह मार्ग, जलाशय तथा छोटे-छोटे नाले आदि सामान्य धरातलीय विषमता प्रकट करते हैं। सामान्यतः इस अध्ययन क्षेत्र का क्षेत्रीय ढलान उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पूर्व को है। इस क्षेत्र की सभी नदियाँ एवं नाले इसी ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। अध्ययन क्षेत्र की समुद्रतल से औसत ऊँचाई 88 मी० आँकी गयी है।



# TAHSIL BHANPUR DISTRICT BASTI DRAINAGE

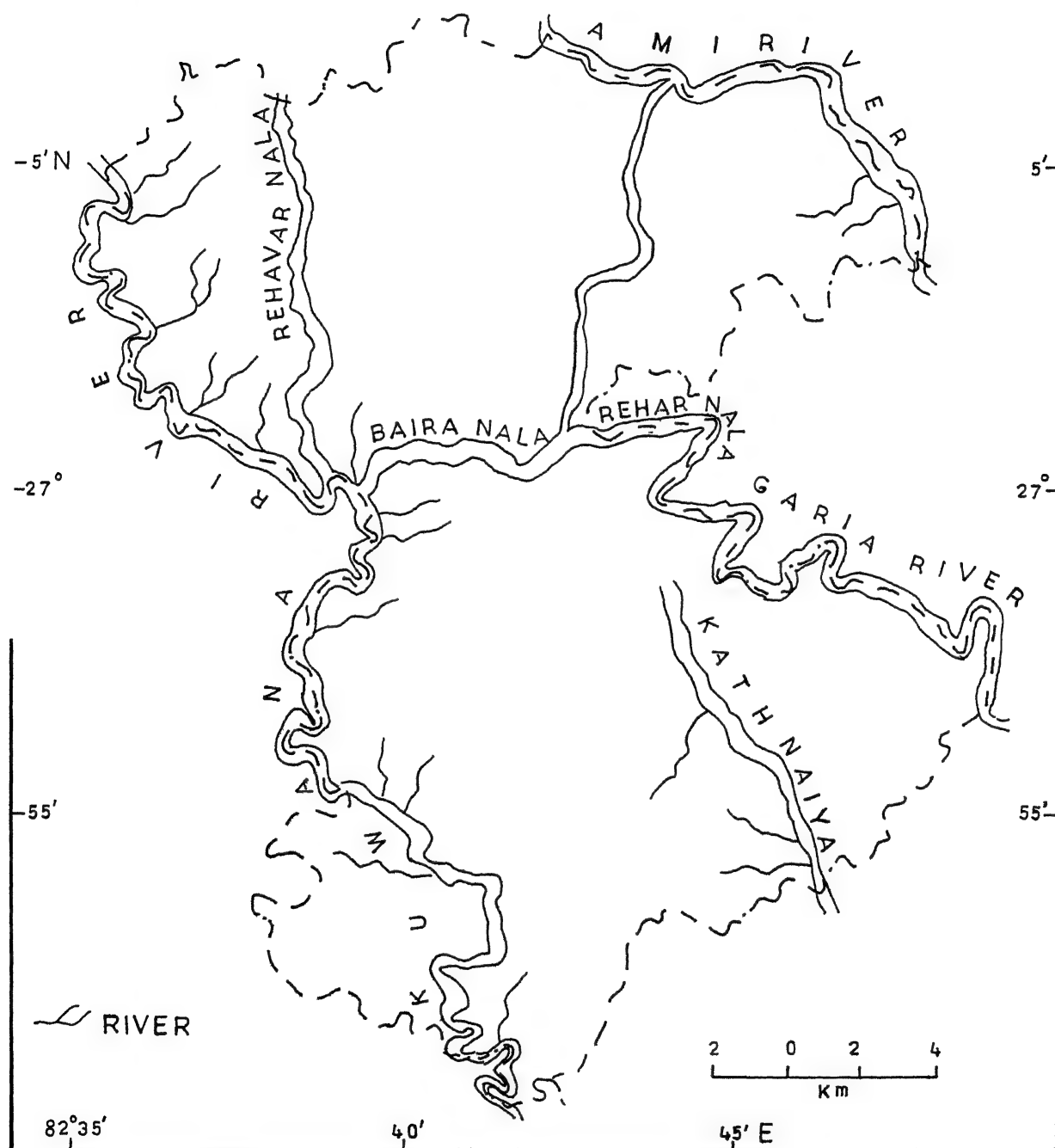


FIG.2-2

मे थोड़ा सा जल दिख जाता है। कुआनो कठिनइया घाघरा की सहायक नदी ही कही जा सकती है।

### 2.3 1 कुआनों नदी :-

कुआनो नदी बहराइच जनपद के पूर्वी निचले हिस्से से निकलने वाली कुआना (जो कि कुआनो के नाम से जानी जाती है और फिर यह गोण्डा जनपद के बीच से होकर प्रवाहित होती है यह रसूलपुर के पश्चिम से जनपद में प्रवेश करती है) चन्दोखा (शकरपुर न्यायपचायत-रामनगर ) के पास अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश कर रामनगर विकास खण्ड के पश्चिमी सीमा से प्रवाहित होती हुई भानपुर न्यायपचायत एवं कोठिला खास न्यायपचायत की सीमा के पास कुआनो नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक सहायक शाखा दोनों विकास खण्डों की सीमा बनाती हुई बैडवा नाला के नाम से प्रसिद्ध है जो कि सल्टौआ विकासखण्ड की उत्तरी पूर्वी सीमा पर रेहावर नाला के नाम से आगे प्रवाहित होती है।

मुख्य शाखा दक्षिण में सल्टौआ विकास खण्ड के पश्चिम प्रवाहित होती हुई आमा न्यायपचायत की सीमा बनाती हुई, अपनी शाखाओं के साथ बस्ती जनपद मुख्यालय के पश्चिम से दक्षिण होते हुये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह बस्ती पूरब परगना को बस्ती पश्चिम से, नगर पश्चिम को नगर पूरब से अलग करते हुये, महुली पश्चिम एवं पूरब होते हुये यह जनपद के दक्षिणी पूर्वी हिस्से से होते हुये छोड़ देती है।

यह सिकरी गज से आगे बरान के निकट गोरखपुर की सीमा में प्रवेश करती है तथा शाहपुर नामक स्थान पर घाघरा से मिल जाती है। इसकी बहुत सी प्रशाखाएँ हैं जिनमें से कुछ हैं रेवई, मनोवर और कठिनाईया। रेवई अमोढ़ा के

उत्तर से निकलकर एक छोटी दूरी तय कर बस्ती के निकट कुआनों में मिल जाती है।

### 2.3.2 कठिनइया नदी :—

कठिनाइया नाले के रूप में निकलकर सल्टौवा गोपालपुर विकासखण्ड के उत्तर पश्चिम भाग से परसा खाल, छनवतिया के दक्षिण से प्रवाहित होती हुई बसडीला के पास बस्ती तहसील में प्रवेश करती है। बस्ती के पूरब के कछारों से निकलकर नगर पूरब होते हुए दक्षिण पूरब दिशा में प्रवाहित होती है जो कि रसूलपुर के दक्षिण में स्थित गरैइया में जाकर मिल जाती है।

### 2.3.3 आमी नदी :—

आमी नदी बस्ती जिले के सिकहरा ताल से निकलकर रेरुवा, बरार, बूधा एव कुडवा नाला के जल को लेकर प्रवाहित होती है। आमी रसूलपुर में राप्ती से कुछ दूरी पर प्रवाहित होती है जोकि धान की खेती योग्य भूमि के विस्तृत भूभाग को घेरती है। शुरुआत में यह सकरी है लेकिन आगे चलकर यह एक धारा के रूप में है जोकि चिकनी दोमट व ऊसर जमीन से होकर बहती है। कुछ दूरी तक बॉसी पश्चिम से रसूलपुर को पृथक करके यह मगहर के पश्चिम में बहती है। जहाँ बसखर के निकट के दाहिने छोर पर यह एक सहायक शाखा से मिल जाती है। जो रेरुवा के नाम से जानी जाती है और जो रुघौली के पश्चिम में निकलती है।

मगहर परगना के पूर्वी सीमा पर आमी बरार से संयुक्त हो जाती है जो कि राप्ती की पुरानी शाखा है जो बनकटा की दिशा में एक विस्तृत भूभाग में बहती हुई बुद्धानाम से जानी जाती है जोकि बॉसी तहसील के पश्चिम से निकलती है। बरार से मिलने के बाद आमी की गहराई व चौड़ाई में बढ़ोत्तरी



होती है, जबकि जमीन का क्षय तथा बहाव होता है। इस तरह केन्द्र से आमी मगहर पूरब से गुजरती है तथा जनपद की कुछ किमी का परिसीमन भी करती है। बाहर निकलने के समय यह दक्षिण में कुढवा नाले के पास संयुक्त हो जाती है तथा मीरगज होते हुये इन दोनों का संयुक्त जल गोरखपुर में राप्ती से मिल जाती है। आमी नदी तहसील के उत्तरीपूर्वी भाग में सगराखास न्यायपचायत की उत्तरीपूर्वी सीमा पर प्रवाहित होती है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की समस्त नदियों का प्रवाह पूर्वाभिमुख (पश्चिम से पूरब की ओर) है। अध्ययन क्षेत्र में कुआनों, आमी नदी के अतिरिक्त सभी नदियों मौसमी हैं। ग्रीष्म काल में नदियाँ प्रायः जल विहीन हो जाती हैं। क्योंकि इनके उदगम का कोई स्थायी जलराशि केन्द्र नहीं है। अपितु इनका निर्माण निम्न क्षेत्रों में वर्षा काल में जल संग्रहण से होता है।

#### **2.3.4 नालें एवं तालाब :-**

अध्ययन क्षेत्र में बैडवा तथा रेहावर प्रमुख नाला है। हरना, खरदुमा एवं सल्टौआ जैसे कई सरोवर (ताल) हैं। तहसील में झील, तालाबों से सिंचाई के अतिरिक्त मछलियाँ भी बहुत संख्या में पकड़ी जाती हैं। मछलियों के अलावा झील तथा तालाब से सिंघाड़ा, कमलगट्टा, नरई, सीप आदि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। तालाबों के अलावा कुआनों, आमी एवं कठिनइया आदि नदियों से मछलियाँ निकाली जाती हैं। इस उद्योग में तहसील की लगभग 06 प्रतिशत जनसंख्या लगी है। जो मछलियों को मारकर बाजारों में बेचने का कार्य करते हैं। मछलियों में पढिन, भाकुर, रोहू, टेगर, नैनी, गिरई, सिधरी, चल्हवा आदि प्रमुख हैं। स्थानीय खपत के अलावा यहाँ से मछलियाँ जनपद मुख्यालय पर तथा अन्य जिलों पर भी भेजी जाती हैं।

## 2.4 जलवायु :-

मानुपर तहसील मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबन्ध के अन्तर्गत आता है। सामान्यतः इस तहसील की जलवायु नम तथा स्वास्थ्यकर है। जलवायु का किसी भी क्षेत्र की मृदा-संरचना, प्राकृतिक वनस्पति और कृषि-विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययन क्षेत्र में फसलों के प्रारूप को निर्धारित करने में जलवायु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्यगंगा मैदान के पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित होने के कारण अध्ययन क्षेत्र मई-जून में 'लू' तथा दिसम्बर जनवरी में कपन भार 'शीतलहर' से उतना प्रभावित नहीं होता है जितना मध्य गंगा का पश्चिमी व मध्य भाग होता है। यही कारण है कि अपवादों को छोड़कर शीत ऋतु में भानपुर तहसील का औसत तापमान उत्तर प्रदेश के मैदानों में सर्वाधिक तथा ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम अंकित होता है। तहसील में मुख्यतः ऋतुएं पायी जाती हैं।

- 1 ग्रीष्म काल (मध्य मार्च से मध्य जून तक)
- 2 दक्षिणी-पश्चिमी मानसून काल या वर्षाकाल-(मध्य जून से मध्य सितम्बर तक)
- 3 उत्तर मानसून काल या सक्रमण काल - (मध्य सितम्बर से अक्टूबर तक)
- 4 शीतकाल - (नवम्बर से फरवरी तक)

### 2.4.1 तापमान :-

अध्ययन क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान लगभग  $18.5^{\circ}$  से  $20^{\circ}$  व अधिकतम तापमान  $31.66^{\circ}$  से  $27^{\circ}$  रहता है। वर्षा ऋतु में न्यूनतम तापमान  $26.27^{\circ}$  से  $20^{\circ}$  एवं अधिकतम तापमान  $31.16^{\circ}$  से  $20^{\circ}$  रहता है। शीत ऋतु में अधिकतम तापमान  $26.20^{\circ}$  से  $20^{\circ}$  एवं न्यूनतम  $15.98^{\circ}$  से  $20^{\circ}$  तक पहुँच जाता है।

## तालिका क्रमांक 2.2

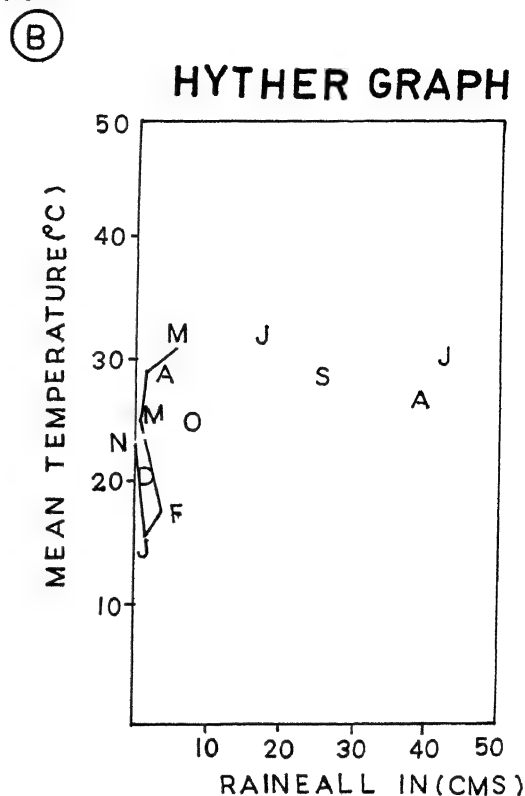
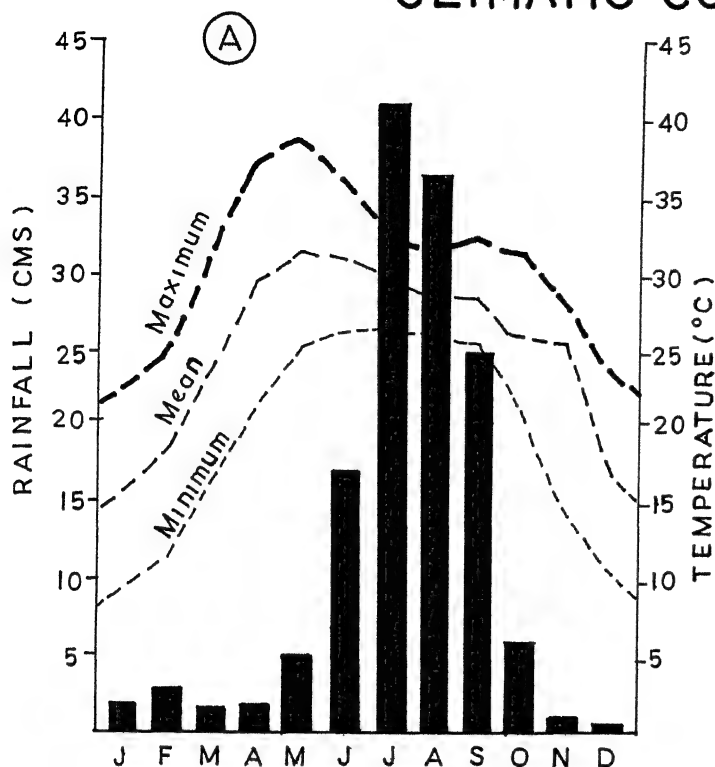
भानुपर तहसील : सामान्य तापमान (डिग्री से०ग्रे०)

(औसत दैनिक तापमान)

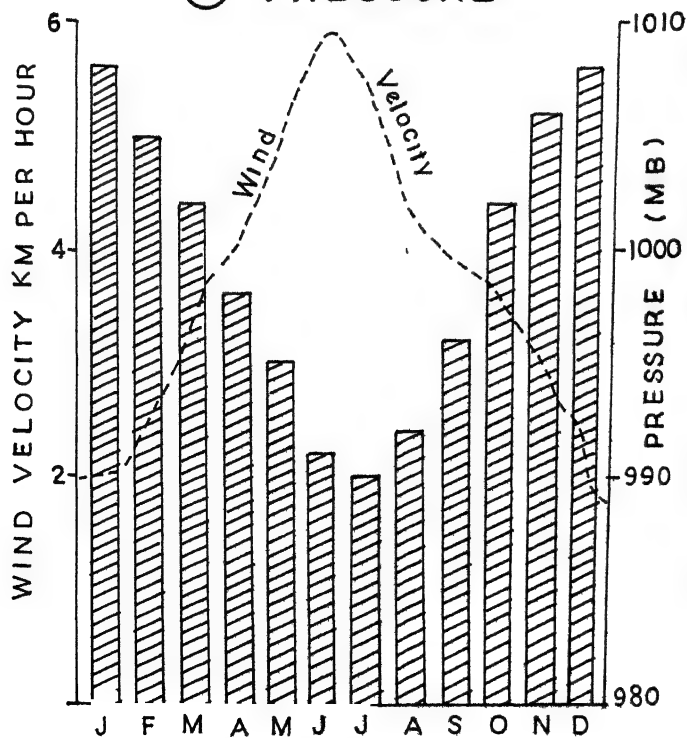
माह	अधिकतम	न्यूनतम	औसत
जनवरी	22.8	9.3	15.98
फरवरी	25.4	11.3	18.33
मार्च	32.3	16.5	24.30
अप्रैल	37.3	21.9	29.63
मई	38.4	25.1	31.66
जून	36.1	26.3	31.16
जुलाई	32.8	26.2	29.47
अगस्त	32.1	25.9	28.99
सितम्बर	32.4	25.2	28.80
अक्टूबर	31.9	20.8	26.27
नवम्बर	27.9	14.2	25.96
दिसम्बर	23.7	10.9	16.76
वार्षिक औसत	31.1	19.4	25.18

स्रोत : उत्तर प्रदेश गजेटियर, बस्ती व जिलाधिकारी कार्यालय, बस्ती।

# TAHSIL BHANPUR CLIMATIC CONDITION



## **(D) PRESSURE**



## **(C) CLIMOGRAPH**

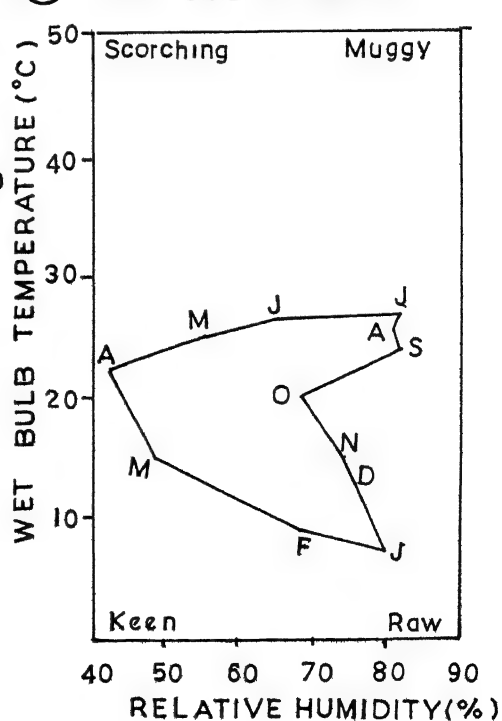


Fig-2,3

वर्ष 1995 में मई माह में अधिकतम तापमान  $45^{\circ}$  से  $0^{\circ}$  तक पहुँच गया जो एक रिकार्ड है। वर्ष 1998–99 में तहसील में अधिकतम तापमान  $44.8^{\circ}$  से  $0^{\circ}$  तथा न्यूनतम तापमान  $5.2^{\circ}$  से  $0^{\circ}$  रिकार्ड किया गया। मार्च अप्रैल व जून का माह गर्म रहता है। सामान्य जलवायु वाले इस क्षेत्र में कोहरा तथा पाला शीतकाल की विशेषता है। जनवरी माह में सर्वाधिक ठण्डी पड़ती है।

#### 2.4.2 वर्षा :—

वर्षा मानसूनी होती है। जनपद में वर्षा का वार्षिक औसत 110 सेमी से 130 सेमी के मध्य है। जाड़े के दिनों में भी कभी-कभी लौटते मानसून से इस क्षेत्र में बरसात हो जाती है। वर्षा का क्षेत्रीय वितरण बड़ा ही असमान है। बरसात पूरी तरह से अनिश्चित है। कभी-कभी मुख्य मौसम के मध्य ही सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्ष 1998–99 में तहसील में वास्तविक वर्षा 851 मिमी हुई। वर्षा उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग में अधिक होती है। तहसील की 1999 में सामान्य वर्षा 1156 मिमी रही है। जो कि स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है।

#### 2.4.3 सापेक्षिक आर्द्रता :—

अध्ययन क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ (अप्रैल माह) में न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 41.5% रहती है जो जून माह तक क्रमशः बढ़कर 67.10% तक पहुँच जाती है। जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर तक यहाँ आर्द्रता 80% के आस-पास बनी रहती है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ-साथ यह आर्द्रता क्रमशः घटने लगती है। शीत ऋतु के प्रारम्भ (नवम्बर माह) में यह सापेक्षिक आर्द्रता 70.90% के आसपास होती है। तत्पश्चात् क्रमशः वृद्धि की तरफ अग्रसरित होते हुए जनवरी में 74% तक पहुँच जाती है तथा फरवरी माह से यह पुनः तेजी से घटने लगती है।

### तल्लललल कुरललंक - 2.3.

#### डलनडुर तहसील : वलडुदलड

डलह	वलडुदलड (डललीडलर डें)
ऑनवरी	1008 30
डरवरी	1005 90
डलरुऑ	1002 20
अडुरैल	998 60
डई	995 40
ऑून	991 40
ऑुललई	990 70
अगसुत	992 70
सलतडुडर	996 80
अकुदूडर	1002.60
नवडुडर	1006 70
दलसडुडर	1008.70
वलरुषलक औसत	1000.00

सुत - ऑलललधलकलरी कलरुललड डसुती।

#### 2.4.4 वायुदाब एवं पवन :-

अध्ययन क्षेत्र में शीत ऋतु के समय दिसम्बर व जनवरी में तापमान अत्यन्त कम हो जाने पर वायुदाब सर्वाधिक 1008 70 मिली बार हो जाता है तथा न्यूनतम वायुदाब वर्षा ऋतु के जुलाई माह में 990 70 मिलीबार रहता है। शीत ऋतु में वायुदाब सामान्य हो जाता है। वर्ष के सर्वाधिक दिनों में पश्चिम की तरफ से वायु बहती है। जिसकी गति ऋतु के अनुसार 50-70 किमी के आस-पास रहती है। शीत ऋतु में पश्चिम की तरफ से आये चक्रवात मौसम की एक रसता को भग करने में सहायक होते हैं।

कभी-कभी इनकी गति 120 किमी प्रति घण्टा तक होती है। इनके द्वारा अध्ययन क्षेत्र में अपार धन-जन की क्षति होती है। दक्षिण पूरब की तरफ से सबसे कम लगभग 8 से 10 दिन ही पवन चलती है। वर्ष में लगभग 29 दिन ऐसे भी होते हैं जिन्हें 'शान्त दिवस' की सज़ा दी जा सकती है। जुलाई में वायु न चलने के दिन काफी उमस भरे होते हैं। जाड़े की ऋतु में मुख्य रूप से पश्चिमी पवन बहती है गर्मी के दिनों में पूर्वी एवं उत्तरी-पूर्वी हवाओं का भी प्रभाव होता है फिर भी प्रधानता पश्चिमी पवन की ही होती है। अक्टूबर ऐसा माह होता है। जब मुख्य रूप से पूर्वी या उत्तर-पूर्वी पवन चलती है। शीत ऋतु में वायु की गति 15 से 20 किमी<sup>0</sup> प्रति घण्टा अर्थात् न्यूनतम होती है। वर्षा ऋतु में यह गति औसतन 30 से 40 किमी<sup>0</sup> प्रति घण्टा के मध्य होती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में वायु की गति बढ़कर 55 से 60 किमी<sup>0</sup> प्रति घण्टा तक पहुँच जाती है।

#### 2.5 मृदा : -

मृदा ससाधन कृषि अर्थ-तन्त्र का आधार है। कृषि अर्थ-तन्त्र प्रधान क्षेत्रों में जब जनघनत्व एवं मृदा ससाधन उत्पादकता में प्रगाढ़ सम्बन्ध पाया जाता है।

# TAHSIL BHANPUR DISTRICT BASTI SOILS

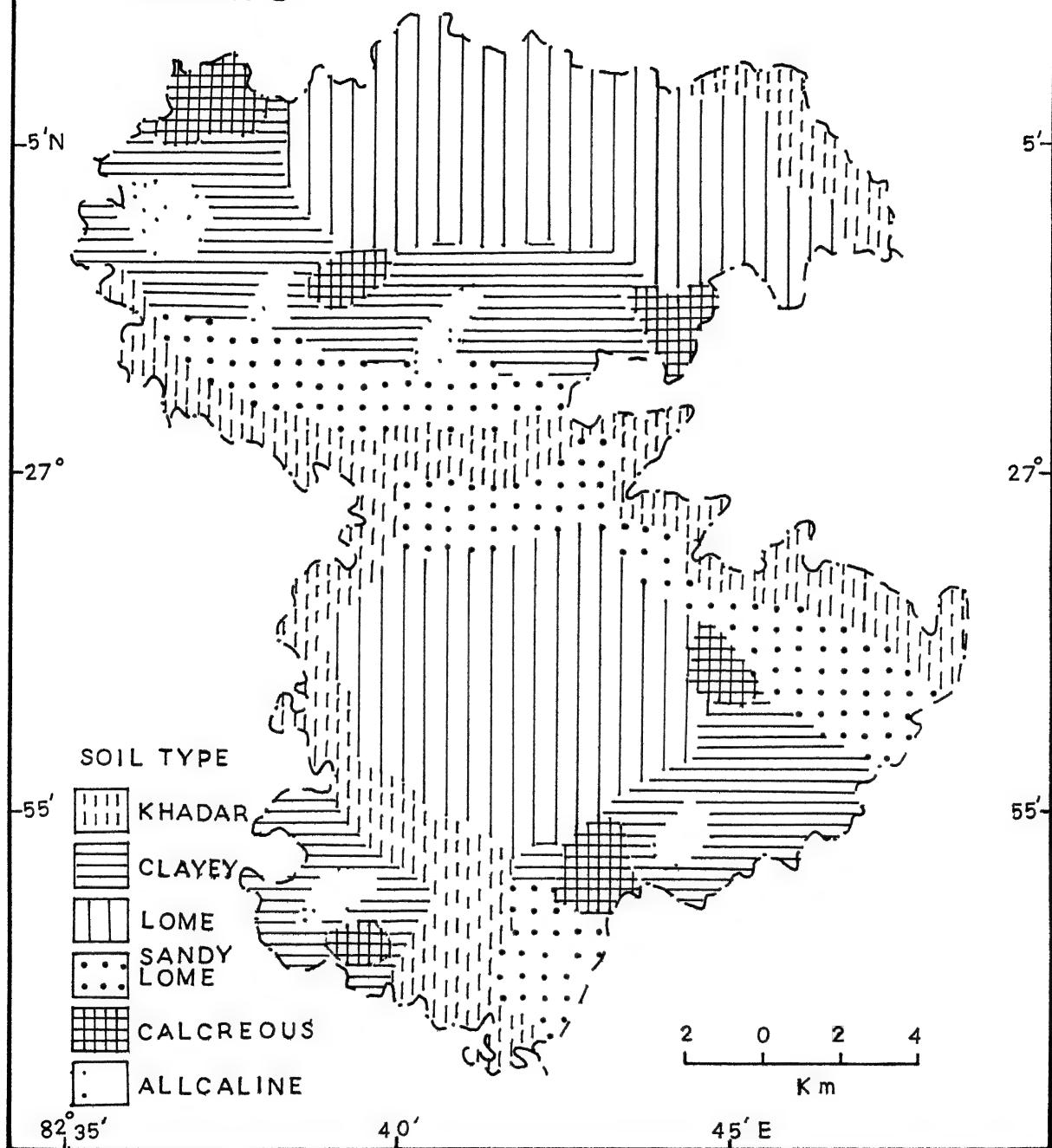


Fig. 2.4



दोनो के सहसम्बन्ध का सूक्ष्म अध्ययन, अनुशीलन यह प्रमाणित करता है कि मृदा ससाधन की क्षेत्रीय विशेषताओं ने मानव गत्यात्मकता को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप के कारण मृदा की विशेषता में पर्याप्त समानता पायी जाती है। फिर भी सूक्ष्म अध्ययन के लिये सम्पूर्ण क्षेत्र को मृदाकण एवं उर्वराशक्ति को आधार मानकर निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

### 2.5.1 बलुई मिट्टी :-

इस प्रकार की मृदा नदियों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पायी जाती है। इसमें बालू के कणों की मात्रा लगभग 40% होती है। कणों के अपेक्षित बड़े आकार के कारण इसमें जलशोषण क्षमता अधिक होती है, जो आलू, मूंगफली, शकरकन्द आदि की कृषि के लिए उपयुक्त है। कुआनों, आमी नदियों के बेसिन इस मृदा के क्षेत्र हैं जिन्हें खादर भूमि भी कहा जा सकता है। यह मिट्टी सामान्यतया बालू, सिलिका और चीका मिट्टी का मिश्रित रूप है। यह मिट्टी, धान एवं गन्ना उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। गेहूँ, मक्का, उड़द आदि की भी अच्छी कृषि होती है। नदियों की भीषण बाढ़ के कारण किसी न किसी वर्ष खरीफ फसल बुरी तरह प्रभावित होती है।

### 2.5.2 बलुई दोमट मिट्टी :-

इस प्रकार की भूमि अध्ययन क्षेत्र के मध्य तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में बालू के कण सूक्ष्म एवं अल्पमात्रा में होते हैं और इसके साथ रेत और चीका मिट्टी के कण पाये जाते हैं। यह बलुई, दोमट मिट्टी, खादर मिट्टी के समीपवर्ती भागों में मिलती है। इसका रंग प्रायः भूरा

होता है। गेहूँ और गन्ना प्रधान फसल है। मक्का, धान, चना, मटर अरहर, ज्वार, बाजरा, उडद आदि अन्य मुख्य फसले इस भूमि में उगाई जाती हैं।

### 2.5.3 मटियार दोमट मिट्टी :-

यह भूमि बलुई दोमट के उत्तर में पायी जाती है तहसील के रामनगर विकास खण्ड की अधिकांश भूमि पर इसी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सिलिका कणों से युक्त यह मिट्टी धान की उपज के लिये प्रसिद्ध है। यद्यपि बलुई दोमट एवं मटियार दोमट में कोई स्पष्ट विभाजन नजर नहीं आता लेकिन तहसील उत्तरी भाग में हम ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं। मिट्टी में बालू की कमी होती जाती है और मिट्टी में चिकनी मिट्टी की अधिकता होती जाती है। इस भूमि में धान एवं गन्ना प्रमुख रूप से उगाया जाता है। गेहूँ द्वितीय स्थान पर उगायी जाने वाली फसल है।

### 2.5.4. लवणयुक्त 'रेह' या उसर मिट्टी :-

भानपुर तहसील के उत्तरी पश्चिम भाग के समीप कुछ क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी पायी जाती है। कोशिका क्रिया के कारण इसमें लवण के अश धरातल पर प्रकट हो जाते हैं कृषि के दृष्टि से यह मिट्टी अनुपयोगी है। इस प्रकार की मिट्टी तहसील के लगभग सभी-न्याय पंचायतों में जगह-जगह कुछ क्षेत्रों में पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी के साथ ही साथ बीहड़ भूमि भी दिखने को मिलती है।

### 2.5.5. भूमिगत जल :-

भूमि के अन्दर बोरिंग की सतह भूमि के सतह से 150 फीट नीचे तक है। तहसील के ऊपरी भाग में पानी का सतह बहुत गहराई पर प्राप्त होता है और

कुछ स्थान पर सरलता से यह प्राप्त नहीं होता है। तहसील बस्ती तथा हरैया में यह सतह प्राप्त होने में कठिनाई नहीं है।

## 2.6 भ्वाकृतिक प्रदेश :-

उच्चावच्च, अपवाह एवं मृदा के आधार पर तहसील भानपुर को दो सभागों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) उत्तरी सभाग

(2) दक्षिणी सभाग

जो क्रमशः दोनों विकास खण्डों (रामनगर, सल्टौवा गोपालपुर) के द्योतक है।

उत्तरी सभाग को तीन भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) कुआनों नदी बेसिन

(2) आमी नदी बेसिन

(3) कुआनों आमी का मैदान

वही दक्षिणी सभाग में

(1) कुआनों-कठिनाइया का मैदान एवं

(2) कठिनाइया-गरैइया के मैदान को सम्मिलित किया जा सकता है।

कुआनों आमी मैदान का विस्तार उत्तरी दक्षिण में है उत्तर से दक्षिण की ओर ऊँचाई क्रमशः घटती जाती है उत्तर में रामनगर से लेकर दक्षिण में सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड के पश्चिमी भाग तक यह क्षेत्र फैला है। तमाम छोटे-छोटे नाले एवं ताल-पोखरे इस भाग में पाये जाते हैं।

TAHSIL BHANPUR  
DISTRICT BASTI  
**PHYSIOGRAPHIC DIVISION**

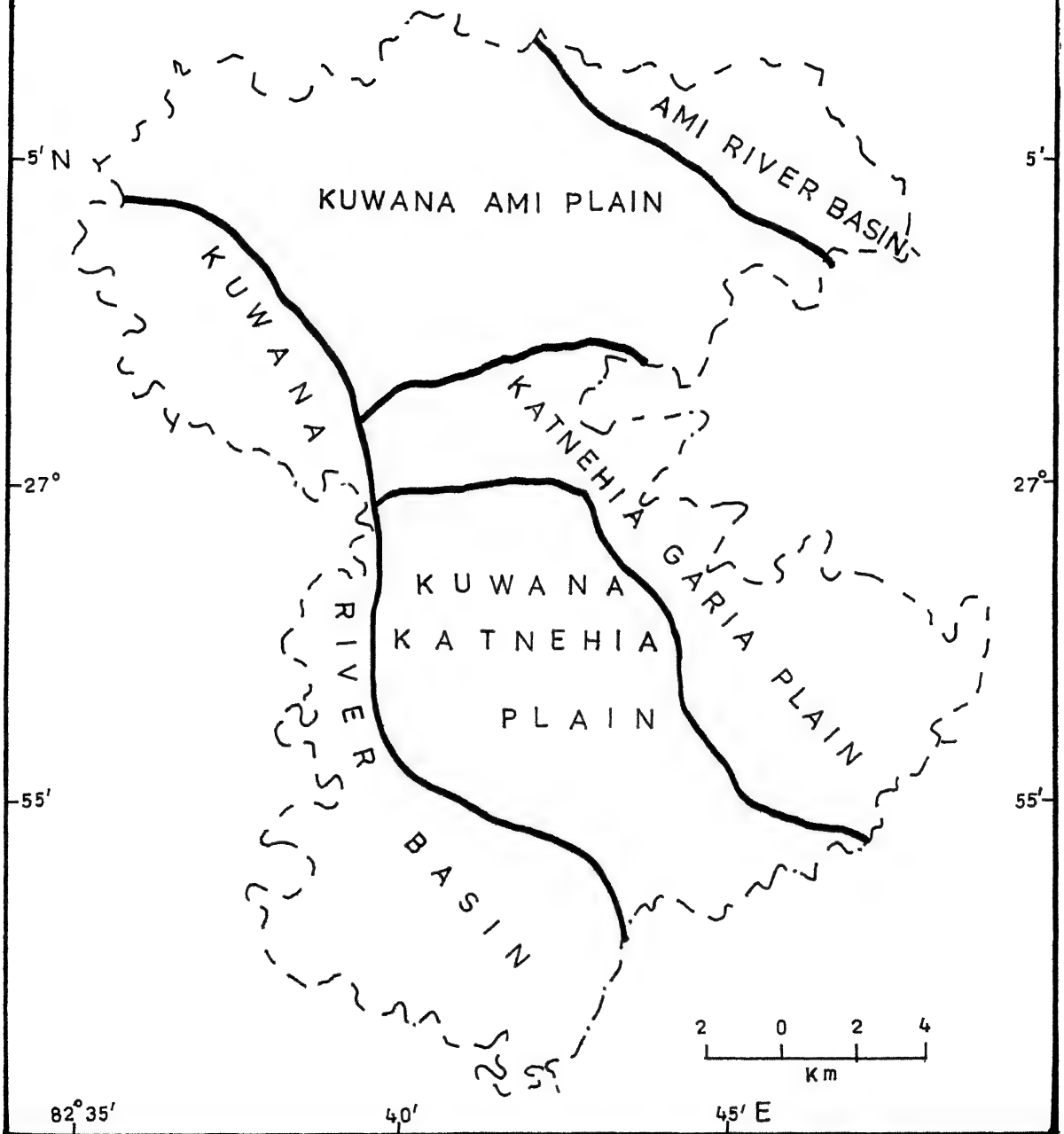


Fig. 2.5

कठिनाइया गरैइया मैदान का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। रूघौली विकास खण्ड के आधे से अधिक भाग को समेटे हुये यह सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड के पूर्वी भाग को समाहित करता है। भूमि का ढाल उत्तर से दक्षिण-पूर्व की ओर है। इस भाग में छोटे-छोटे जलाशयों की प्रधानता है। यहाँ सर्वत्र बागर मिट्टी का विस्तार है। कुआनों कठिनाइया मैदान का विस्तार तहसील के दक्षिणी सभाग में है। जिसमें सल्टौवा गोपालपुर के पूरब के सभी न्यायपचायत सम्मिलित किये जा सकते हैं।

## 2.7 प्राकृतिक वनस्पति :-

किसी भी भू-भाग की वनस्पति वहाँ की जलवायु के विविध तत्वों विशेषकर तापक्रम एवं वर्षा, मिट्टी और भू-पृष्ठ के वैज्ञानिक इतिहास से प्रभावित होती है (वी०पी० सुब्रमणियम, 1958)।

‘वन मानव एवं पशुओं के जीवन से सम्बन्धित रहे हैं जो कृषि-विकास के पूर्व मानव द्वारा खाद्य एवं वस्त्र आदि ससाधनों के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं,’ ट्रीवार्थ (1947)।

अध्ययन क्षेत्र पूर्णतया मानसनी जलवायु के प्रभाव में पड़ता है। अतः यहाँ की वनस्पतियाँ ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियों को गिराकर पतझड़ नाम को सिद्ध करती हैं। वनस्पतियाँ, चारागाह बाग-बगीचे अथवा बिखरे हुए वृक्षों के रूप में पायी जाती हैं। कहीं-कहीं छोटी नदियों के किनारे बेत, नरकट एवं अन्य कटीली वनस्पतियाँ झाड़ियों के रूप में पायी जाती हैं। आम, जामुन, महुआ, शीशम, पीपल बरगद बॉस, नीम, कटहल आदि प्रमुख वनस्पतियाँ अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इनकी औसत ऊँचाई 30-35 मी० तक होती है।

वर्तमान में सरकार द्वारा सड़को के किनारे सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत नये किस्म के पेड़ यूकेलिप्टस अर्जुन, सूबबूल, गुलमोहर तथा कुछ शीशम के वृक्ष भी लगाये जा रहे हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में बबूल वृक्षों की बहुतायत है।

पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर आदि बहुत कम संख्या में मिलते हैं। इसका मुख्य कारण लकड़ी का मजबूत न होना है। अतः ये अधिकांश धार्मिक स्थानों पर ही पाये जाते हैं। सामान्यतया वनस्पति क्षेत्रों में नीलगाय, लोमड़ी, गीदड़, नेवले आदि बहुतायत पाये जाते हैं। नदियों के किनारे झाड़ियों में गीदड़ एवं भेड़िये भी पाये जाते हैं। कुछ जहरीले साँप यदा-कदा देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर पूरे जनपद में काफी संख्या में मिलते हैं। तहसील के वनोत्पाद के विकास में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

## 28 खनिज सम्पदा :-

तहसील में अद्यतन भूमि सर्वेक्षण का अभाव पाया गया है। अतः भूमि के गर्भ में कितने रत्न छिपे हैं। इसका निश्चित आकलन नहीं किया जा सकता है। जनपद सिद्धार्थनगर से लगे भू-भाग में तेल की उपलब्धता है। बालू ककड़ की प्रचुर उपलब्धता होने के कारण उन्हें भवन निर्माण में प्रयुक्त किया जा रहा है।



## REFERENCE

District Census Hand Book, BASTI 1981

Gazetter of India, Uttar Pradesh District Basti 3-8 Page

Singh R L 1991 India of Regional Geography N.S S I Varanasi p 190

Trewartha F and Hammand, 1947 Elements of Geography p 407.

U P Census of India Administrative Atlas Volume 11- Series 21, Part IX A,  
(D M Sinha of the India Administrative Service Director of Census  
operations U P )

Sant Ram 1974 . A sociological study of occupational preferences of  
Intermediate students of Basti U P Thesis submitted in Partial  
Fulfillment of the Degree of master of Arts (Sociology) Department of  
sociology university of gorakhpur page 41-57

जनपदीय सामाजार्थिक समीक्षा, जनपद बस्ती 2000-01, राज्य नियोजन सस्थान, अर्थ एव  
सख्या प्रभाग, अर्थ एव सख्याधिकारी कार्यालय बस्ती।

जिलाधिकारी कार्यालय बस्ती।

साख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 1990 एव 2000-01, कार्यालय एव अर्थ सख्या  
अधिकारी बस्ती, अर्थ एव सख्या प्रभाग, राज्य नियोजन सस्थान, उ0प्र0

बस्ती विकास, 2001-2002 अतीत और वर्तमान।



### अध्याय—3

## जनसंख्या प्रतिरूप

प्रस्तावना .—

जनसंख्या जनशक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण ससाधन है। प्राकृतिक सम्पदा के समुचित विकास एवं उपभोग के लिये एक सक्षम जनशक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि विकास और परिवर्तन के सभी साधनों का केन्द्र बिन्दु मानव ही है। किसी क्षेत्र की उन्नति इस पर निर्भर करती है कि वहाँ की जनसंख्या और भौतिक ससाधनों में कितना सहसम्बन्ध है। मानव समयानुसार प्रकृति—प्रदत्त भौतिक ससाधनों से समायोजन कर उनका भरपूर उपयोग करता रहा है।

“मानव विविध प्रक्रियाओं द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को सांस्कृतिक भूदृश्य में परिवर्तित करता है,” (सिगिसभण्ड—1948, पृ० 278)।

अतः जनससाधन विकास एवं परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। “जनसंख्या —आकार, मानव विकास की प्रकृतिक एवं प्रतिरूप को निर्धारित करता है” जबकि इसका वितरण मानव के भौतिक ससाधनों के साथ समायोजन के बदलते स्वरूप को प्रदर्शित करता है” (राणा पी०बी० सिंह— 1977, पृ० 21)।

जनसंख्या की परिवर्तनशील प्रकृति (वृद्धि अथवा ह्रास) से दोनों परिस्थितियों में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। जहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, पारिवारिक विखण्डन की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा समाज में विभिन्न प्रकार की अव्यवस्था होती है। वही अल्पता की स्थिति में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।



## तालिका क्रमांक 3.1

### भानपुर तहसील में आबाद ग्रामों का विवरण

	तालिका	विकास खण्ड		तहसील	
		रामनगर	सल्टौआ गोपालपुर	भानपुर	जनपद
1	200 से कम आबादी के ग्राम	20	49	69	727
2	200 से 499 तक	66	100	166	1261
3	500 से 999 तक	54	62	116	766
4	1000 से 1999 तक	24	22	46	269
5	2000 से 4999 तक	6	5	11	37
6	5000 से ऊपर		1		6
	<b>योग</b>	<b>170</b>	<b>239</b>	<b>409</b>	<b>3066</b>

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 2000, एवं जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, जनपद बस्ती 2000-01 से संगणित।

नोट : आबाद एवं गैर आबाद ग्रामों को परिशिष्ट मानचित्र 1 में दर्शाया गया है।

जनसंख्या-आकार में सतुलन ही विकास के पथ को सुगम बनाये रख सकेगा। 'ग्रामीण जनसंख्या में हो रही पर्याप्त वृद्धि का दबाव केवल ग्रामीण ससाधनों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसका प्रभाव शहरों को भीडयुक्त बनाने में भी हुआ है, जिससे नगरों में अनेक प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं (यादव 1988 पृ० 51)। अतः आर्थिक विकास के लक्ष्यों के लिए किसी राष्ट्र या क्षेत्र का जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक होता है जिससे कि योजना के आकार एवं लक्ष्य को समझने में मदद मिल सके तथा वांछित प्रगति प्राप्त की जा सके। किसी भी क्षेत्र की अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो उस क्षेत्र के समस्त भौतिक ससाधनों का सतुलित उपभोग करके अपने जीवन स्तर को उच्च बनाये रखे।

अध्ययन क्षेत्र नदी-निर्मित पूर्णतः मानसूनी मैदानी एवं मानवानुकूल जलवायु क्षेत्र है, अतः जनसंख्या और जनघनत्व दोनों निरन्तर वृद्धिमान हैं। विकास सम्बन्धी समग्र योजनाएँ जनसंख्या को आधार मानकर बनायी जाती हैं। अतः प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिरूप, जन घनत्व, यौनानुपात, साक्षरता आदि की विवेचना के साथ-साथ वर्तमान सदी के पूर्वार्ध तक जनसंख्या की स्थिति का आँकलन तथा ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या की भूमिका को निरूपित करने का प्रयास किया गया है।

### 3.1. जनसंख्या विवरण :-

अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण तालिका क्रमांक 3.2 में दिया गया है। उसका वर्णन न्यायपंचायतवार 1981, 1991 तथा 2001 जनगणना के परिपेक्ष्य में किया गया है। जिसे चित्र सं० 3.1 में दर्शाया गया है।

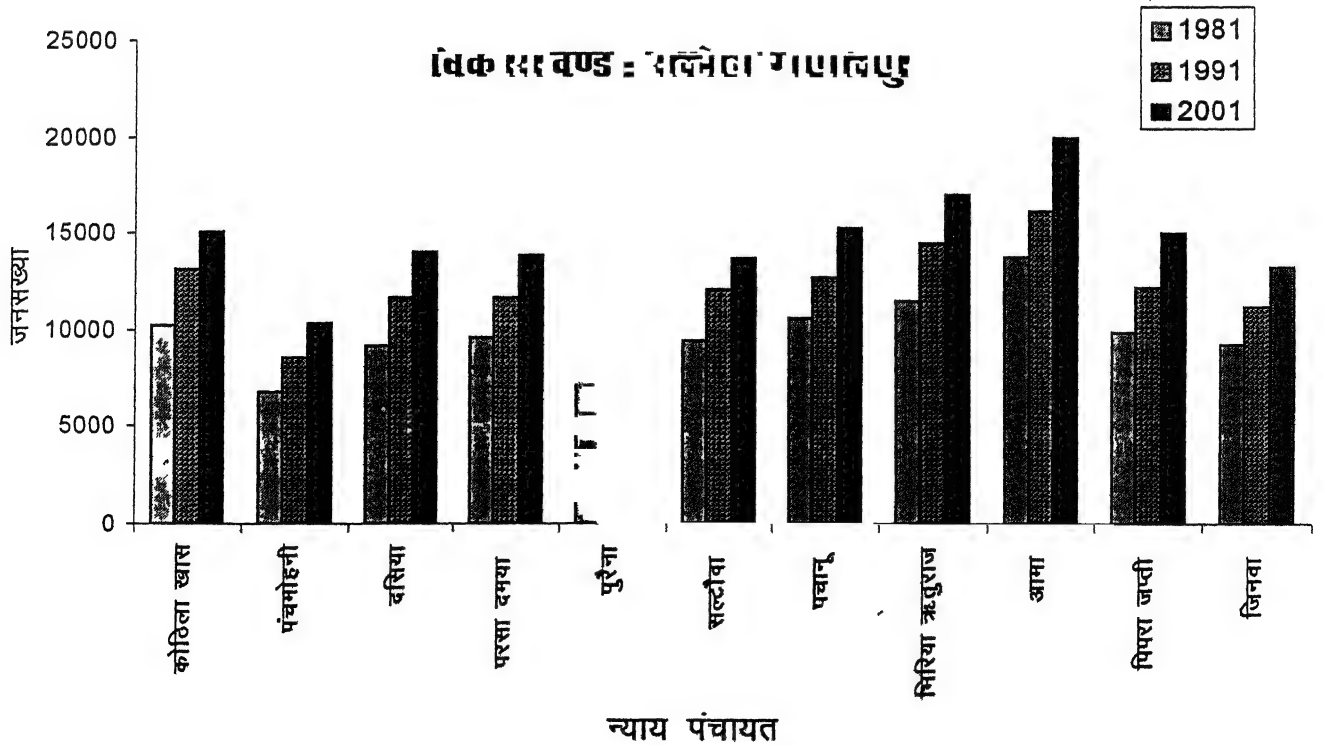
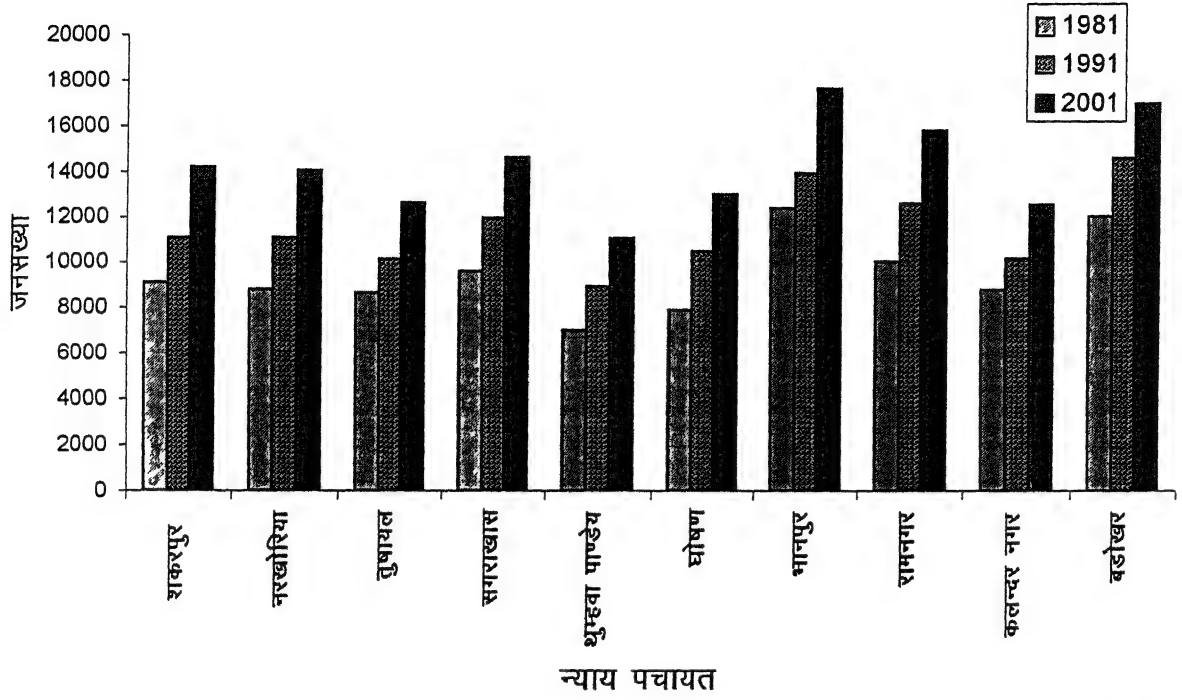
## तालिका क्रमांक – 3.2.

### तहसील भानपुर : जनसंख्या विवरण

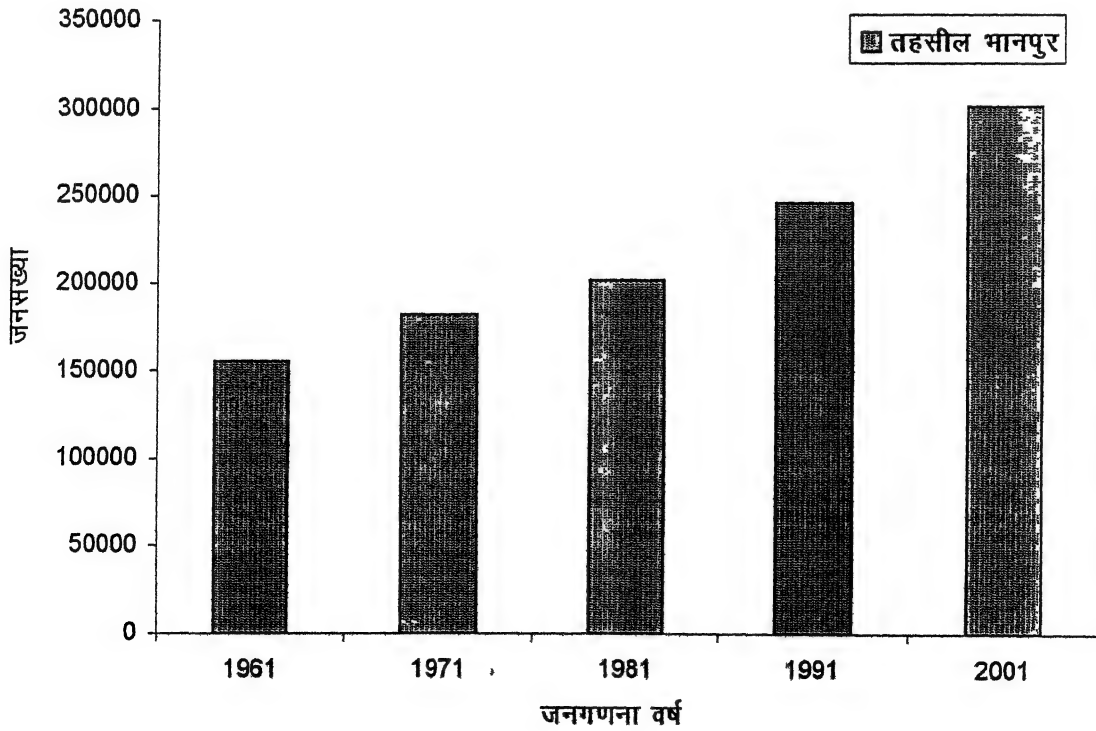
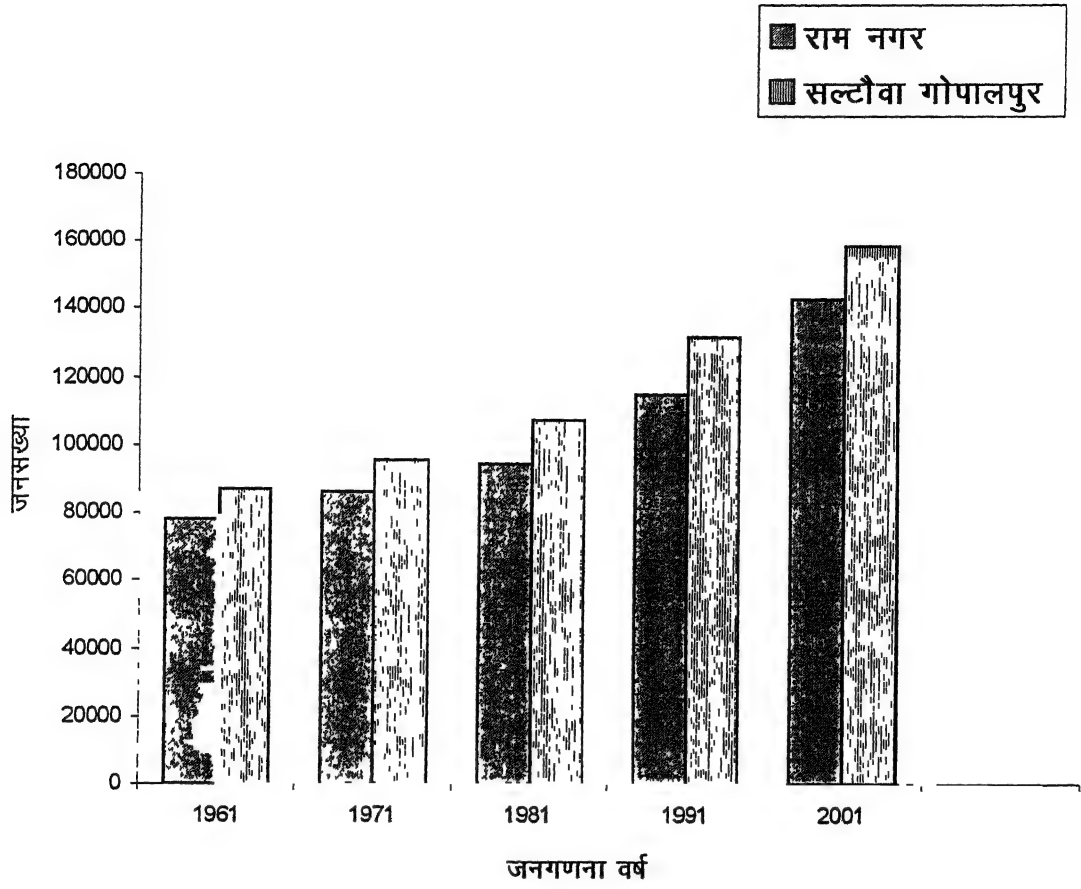
	न्यायपंचायत	क्षेत्रफल (हे०में)	1981	1991	2001
1	शकरपुर	1580 00	9121	11135	14205
2	नरखोरिया	1709 00	8820	11107	14048
3	तुषायल	2315 00	8657	10144	12639
4	सगराखास	2171 00	9608	11974	14683
5	थुम्हवा पाण्डेय	1466 00	7014	8960	11101
6	घोषण	2269 00	7941	10503	13038
7	भानपुर	2958 00	12462	14026	17671
8	रामनगर	4058 00	10080	12649	15818
9	कलन्दर नगर	2164 00	8832	10225	12594
10	बडोखर	2819 00	12097	14632	17038
11	कोठिला खास	2169 00	10223	13151	15115
12	पचमोहनी	1214 00	6782	8584	10348
13	दसिया	2146 00	9182	11662	14011
14	परसा दमया	2123 00	9666	11682	13871
15	पुरैना	1291 00	7385	8293	10622
16	सल्टौआ	1947 00	9487	12099	13656
17	पचानू	1994.00	10625	12753	15266
18	भिरिया ऋतुराज	2469.00	11496	14472	17041
19	आमा	2563 00	13738	16204	19987
20.	पिपरा जप्ती	2077 00	9906	12163	14998
21	जिनवा	1697.00	9241	11225	13268

## भानपुर तहसील : जनसंख्या विवरण

### विकासखण्ड : रामनगर



## भानपु तहसील : जनसंख्या वृद्धि



### सारणी : 3.3. A

भानपुर तहसील में जनसंख्या वृद्धि (%में)

विकास खण्ड	जनगणना वर्ष					
	1961	1971	1981	1991	2001	सम्भावित 2011
रामनगर	78566	86430 (10 1)	94676 (9 5)	115355 (21 84%)	142981 (23 94%)	177210
सल्टौवा गोपालपुर	87350	95835 9 7	107731 12 4	132288 (22 8%)	159060 (20 23%)	197138
तहसील भानपुर	155916	182265 (16 9)	202407 (11 1)	247643 (22 34)	302041 (21 96)	374348

स्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971 एवं 1981  
जनगणना निदेशालय लखनऊ (अप्रकाशित 1991 की जनगणना)  
सेन्सस आफ इण्डिया, 2001 (प्रोविजनल)

वर्तमान समय (2001) में तहसील की कुल जनसंख्या 3,02,040 है जिसमें 1,54,702 पुरुष तथा 1,47,339 स्त्री हैं।

इस प्रकार सन् 1961–2001 की अवधि में तहसील की जनसंख्या में (93.6%) लगभग दो गुनी वृद्धि हुई। चित्र संख्या 3.2 एवं तालिका क्रमांक 3.3A से स्पष्ट है कि भानपुर तहसील में जनसंख्या क्रमिक रूप से बढ़ रही है। साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि दर में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन 2001 में वृद्धि दर में कुछ कमी आयी है। जनसंख्या वृद्धि दर 1981–91 की अवधि में 22.34% तथा 1991–2001 की अवधि में 21.96% रही है। यह वृद्धिदर जनपद की तुलना में कम रही है।

विकास खण्ड स्तर पर जनसंख्या और वृद्धिदर दोनों दृष्टिकोणों से सल्टौवागोपालपुर का प्रथम स्थान है। सल्टौवागोपालपुर विकास खण्ड में 1961 से वर्तमान (2001) समय तक जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सन् 1961–71 एवं 1971–81 के मध्य तक वृद्धि क्रमशः 9.7% तथा 12.4% थी। 1981–91 में यह 22.79% रही और यह 1991–2001 में 20.25% रही लेकिन वृद्धि दर में कमी का संकेत मिलता है।

सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड में 1961–1971 में क्रमशः 87,350 एवं 95,835 जनसंख्या निवास करती थी जोकि 1981 में बढ़कर 1,07,731 हो गयी। 1991 में इसकी जनसंख्या 1,32,288 हो गयी जो कि 2001 में बढ़कर 1,59,060 हो गयी। 50 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में लगभग दो गुनी वृद्धि हुई है। सल्टौवा गोपालपुर के सापेक्ष रामनगर विकास खण्ड की वृद्धि दर बढ़ती रही है। रामनगर में 1961 में जनसंख्या 78,566 थी जो 1971 में बढ़कर 86,430 तथा 1981 में बढ़कर 94,676 हो गयी दो दशक में जनसंख्या में वृद्धि 20.50% रही। 1991 में

## तालिका क्रमांक 3.3 B

### जनपद बस्ती-जनसंख्या वृद्धि : 1901-2001

वर्ष	जनसंख्या	% वृद्धि प्रति दशक			% वृद्धि उ०प्र०	% वृद्धि भारत
		कुल	ग्रामीण	नगरीय		
1901	1845104	—	—	—	—	—
1911	1829381	-0.9	-0.5	-18.7	-0.97	5.73
1921	1924134	5.2	5.1	10.8	3.08	-0.30
1931	2076843	-7.9	7.7	27.7	6.66	11.00
1941	2184399	-5.2	-5.5	-11.7	13.57	14.22
1951	2386246	9.2	8.9	30.9	-11.82	-13.31
1961	2625755	10.04	10.5	-15.9	16.66	25.51
1971	2984090	13.69	12.4	9.6	19.80	24.80
1981	2173912	17.10	17.1	28.3	25.52	24.75
1991	2738522	25.97	25.45	42.78	25.16	23.50
2001	2068922	22.69	—	—	25.80	21.34
2001 की जनसंख्या, जनपद की नवीन सीमा के अनुसार प्रदर्शित की गयी है।						

- स्रोत :
- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971 तथा 1981।
  - जनसंख्या निदेशालय लखनऊ द्वारा प्राप्त जनगणना 1991
  - डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जनपद बस्ती।
  - सेन्सस आफ इण्डिया 2001 (प्रोविजनल)



जनसंख्या 1,15,355 पहुँच गयी। इस दशक वृद्धि दर 21.84% रही। 1991 से 2001 में रामनगर की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ी जोकि 1,42,981 पहुँच गयी। इस दशक में जनसंख्या वृद्धि भी (23.94%) अधिक रही। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। और इस वृद्धि पर अकुश नहीं लगाया गया तो जनसंख्या बढ़ती जायेगी और ग्रामीण विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आजादी के बाद जनसंख्या वृद्धि में तेजी आयी है। 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या एक अरब पार कर गयी है। तालिका क्रमांक 3.3 बी में बस्ती जनपद की जनसंख्या वृद्धि को उत्तर प्रदेश तथा भारत के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। तेज गति से बढ़ती जनसंख्या सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। यदि यही वृद्धि जारी रही तो 2045 तक भारत की आजादी चीन से अधिक होगी। अनियन्त्रित रूप से बढ़ रही आबादी हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये सबसे बड़ी चुनौती है।

### 3.3 जनसंख्या वितरण :-

जनसंख्या वितरण प्रारूप न सिर्फ मनुष्य के किसी क्षेत्र विशेष में बसाव सम्बन्धी अभिरुचि एवं अरुचि का घटक होता है अपितु क्षेत्र में कार्यरत भौगोलिक कारकों के सश्लेषण का स्पष्ट प्रदर्शक भी होता है। जनसंख्या वितरण से मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है। जनसंख्या का वितरण क्षेत्र के भौतिक एवं आर्थिक, संसाधनों तथा स्थानिक व्यवस्था से पूर्णतः सम्बन्धित एवं नियन्त्रित होता है (जेलिस्की, 1966 पृ० 14)। जनसंख्या का आकार मानव-विकास की प्रकृति एवं प्रतिरूप को निर्धारित करता है, जबकि इसका वितरण भौतिक संसाधनों से मानव के समायोजन की प्रकृति की विविधता को

TAHSIL BHANPUR  
DISTRICT BASTI  
DISTRIBUTION OF POPULATION  
2001

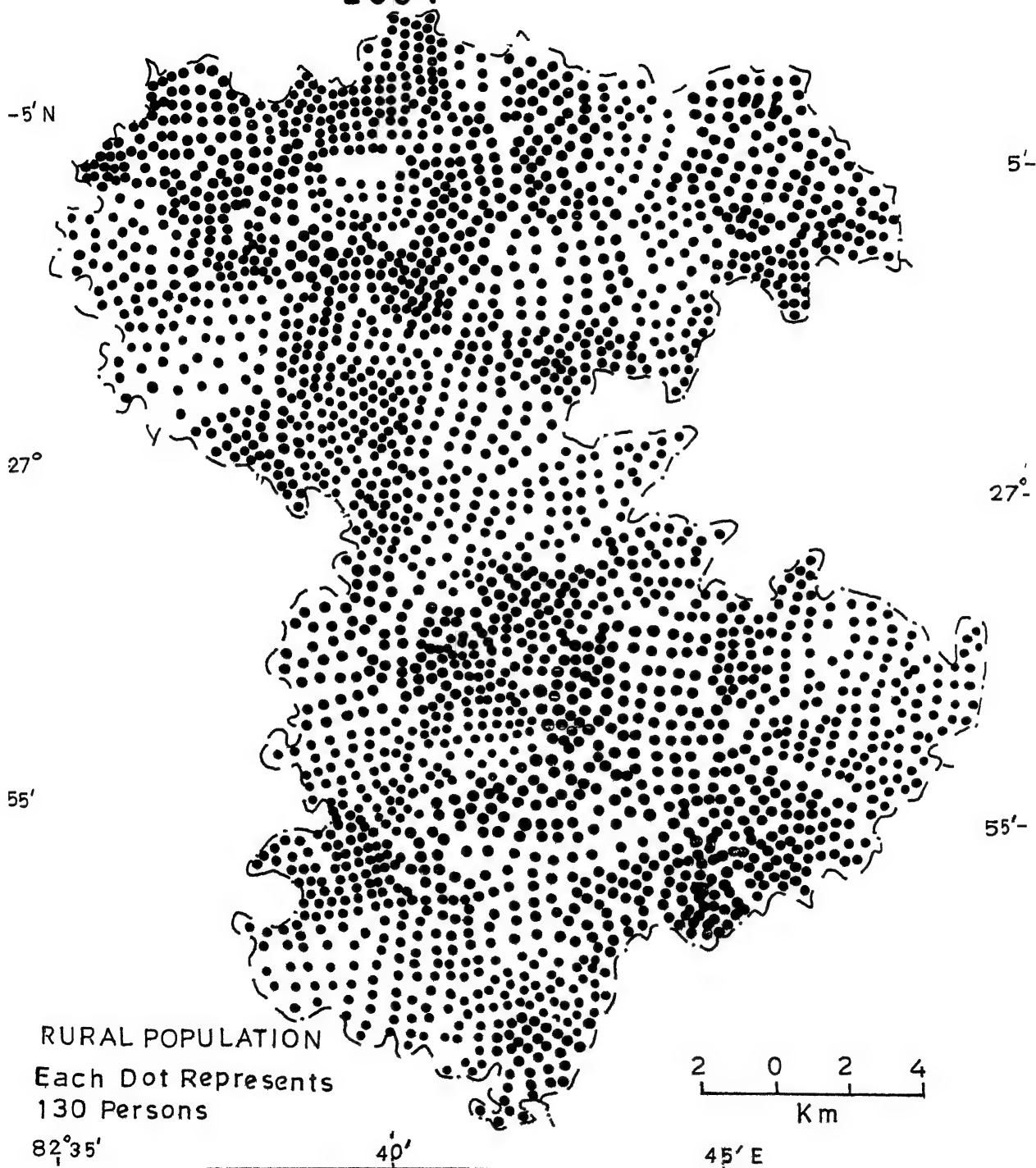


Fig. 3-3

### तालिका क्रमांक-3.4.

#### भानपुर तहसील में जनसंख्या का वितरण : 2001

जनसंख्या आकार वर्ग	बारम्बारता	न्यायपंचायत
< 11000	2	पंचमोहनी, पुरैना
11000—11999	1	थुम्हवा पाण्डेय
12000—12999	2	तुषायल, कलन्दरनगर
13000—13999	4	घोषण, परसादमया, सल्टौवा, जिनवा
14000—14999	5	शंकरपुर, नरखोरिया, सगराखास, दसिया, पिपराजप्ती
15000—15999	3	रामनगर, कोठिलाखास, पचानू
16000—16999	—	—
17000—17999	3	भानपुर, बडोखर, भिरिया ऋतुराज
18000—18999	—	—
> 19000	1	आमा

प्रदर्शित करता है, (सिंह, 1977 पृ० 21)। सन् 2001 की जनगणना पर आधारित बहुल बिन्दु मानचित्र 33 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में वितरण प्रायः समरूप है।

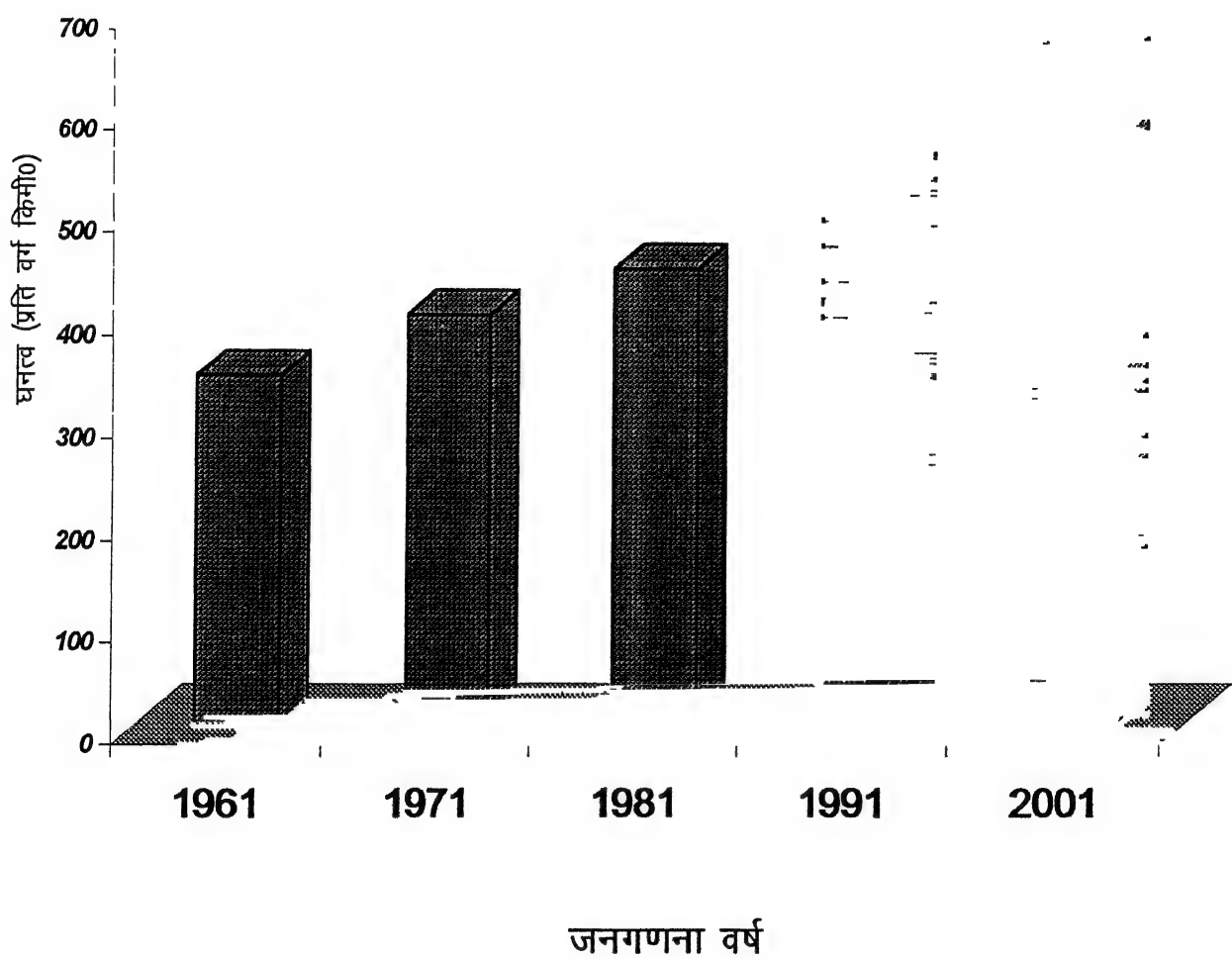
सन् 2001 की जनगणना के अनुसार अधिकतर न्याय पचायतों की जनसंख्या 14,000 से 15000 के मध्य है (तालिका क्रमांक-34)। आमा न्याय पचायत (1,99,87) सर्वाधिक और पचमोहनी न्याय पचायत (10,348) न्यूनतम जनसंख्या धारक है। तहसील में जनसंख्या आकार के आधार पर यदि न्याय पचायतों को वर्गीकृत किया जाय तो अध्ययन क्षेत्र में 11,000 से कम जनसंख्या की मात्रा दो न्याय पचायतों पचमोहनी और पुरैना है। 11000-12000 के बीच में केवल एक न्याय पचायत थुम्हवा पाण्डेय है। 12000-13000 के बीच में तुषायल तथा कलन्दरनगर न्यायपचायत आती है।

13000 से 15000 के बीच में सर्वाधिक न्यायपचायत हैं। इनकी संख्या 9 है जिनमें घोषण, परसा-दमया, सल्टौवा, जिनवा, शकरपुर, नरखोरिया, सगरा खास, दसिया, पिपराजप्ती न्यायपचायत हैं। 15000 से 16000 के बीच रामनगर, कोठिला खास तथा पचानू है। 17000 से 18000 के बीच में भानपुर, बडोखर तथा भिरिया ऋतुराज न्याय पचायत आते हैं। 19000 से अधिक जनसंख्या केवल आमा न्याय पचायत में पायी जाती है।

### 3.4 जनसंख्या घनत्व :-

जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। यह जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन है जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वितरण की अधिक

## भानपुर तहसील : जनसंख्या घनत्व



### तालिका क्रमांक-3.5

#### भानपुर तहसील में जनसंख्या घनत्व

वर्ष	जनसंख्या घनत्व/किमी <sup>2</sup>
1961	344
1971	403
1981	448
1991	548
2001	668

- स्रोत : 1 जिला-जनगणना हस्तपुस्तिका जनपद बस्ती, 1961, 1971, 1981
- 2 जनसंख्या निदेशालय लखनऊ द्वारा प्राप्त 1991 की जनगणना रिपोर्ट एवं
- 3 तहसील मुख्यालय भानपुर से प्राप्त 2001 की अप्रकाशित प्राथमिक जनगणना रिपोर्ट से संगणित।
- 4 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जनपद बस्ती 1984

अर्थपूर्ण स्थिति इसको क्षेत्रफल अथवा जीवन यापन के उपलब्ध साधनों के अनुपात में व्यक्त करने से मालूम होती है।

जनसंख्या घनत्व, संसाधनों पर जनसंख्या के वास्तविक दबाव को घोषित करता है, (ट्रिवार्था – 1953, पृष्ठ 94) अध्ययन क्षेत्र में एव 1961 से 2001 तक जनसंख्या घनत्व निरन्तर बढ़ता ही रहा है 1961 में यह जनघनत्व 344 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> था। जो उत्तरोत्तर 1971 में 403 से बढ़ते हुये 1981 में 448 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> हो गया है। 1991 में तहसील का जनघनत्व जहाँ 548 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> था वही 2001 की जनगणनानुसार घनत्व में लगभग दो गुने की वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ने से संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है (तालिका क्रमांक 3.5, चित्र संख्या 3.4)। वर्तमान समय में (2001) सर्वाधिक जनघनत्व सल्टौवा गोपालपुर विकासखण्ड (733 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup>) है। रामनगर का जनघनत्व 608 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> है।

जनसंख्या के गणितीय घनत्व के आधार पर तहसील को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (मानचित्र 3.6)।

#### 3.4.1 अति निम्न घनत्व क्षेत्र :-

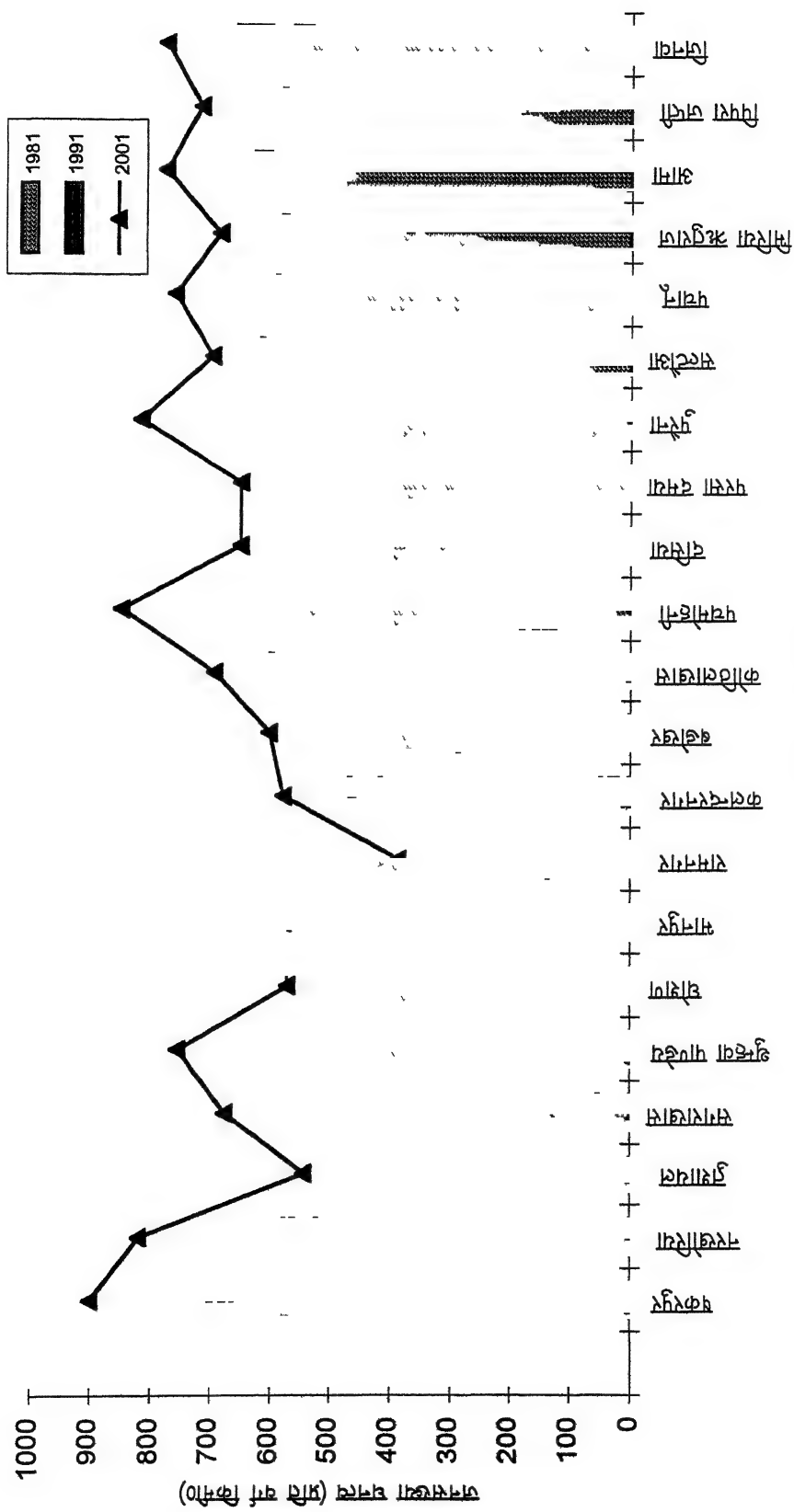
तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 1% भूभाग से भी कम भूमि पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> से भी कम है। जिसमें रामनगर न्याय पंचायत आता है। यही 1991 में तुसायल घोषण, भानपुर कलन्दरनगर न्याय पंचायत की भी जनघनत्व 500 व्यक्ति/वर्ग किमी से कम थी। 1981 में तो शकरपुर, नरखोरिया, पचमोहिनी पुरैना, पचानू और जिनवा को अतिरिक्त सभी न्यायपंचायतों का जनघनत्व 500 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> से कम था।

### तालिका क्रमांक-3.6

क्र० स०	न्यायपंचायत का नाम	जनसंख्या घनत्व/वर्ग किमी <sup>2</sup>			दशकीय वृद्धि (%में)
		जनसंख्या घनत्व 1981	जनसंख्या घनत्व 1991	जनसंख्या घनत्व 2001	
1	शकरपुर	589	704	899	27.7
2	नरखोरिया	525	649	822	26.7
3	तूषायल	426	438	545	24.2
4	सगराखास	289	551	676	22.7
5	थुम्हवा पाण्डेय	447	661	757	14.5
6	घोषण	389	462	574	24.2
7	भानपुर	450	473	579	22.4
8	रामनगर	460	311	389	25.1
9	कलन्दरनगर	425	472	581	23.1
10	बडोखर	455	519	604	16.4
11	कोठिला खास	460	606	696	14.9
12	पचमोहनी	543	707	852	20.5
13	दसिया	400	549	652	18.8
14	परसा दमया	475	550	653	18.7
15	पुरैना	563	642	822	28.0
16	सल्टौआ	453	621	701	12.9
17	पचानू	533	639	765	19.7
18	भिरिया ऋतुराज	411	586	690	17.7
19	आमा	498	632	779	23.3
20	पिपरा जप्ती	489	585	722	23.4
21	जिनवा	539	661	781	18.2



## भानपुर तहसील : जनसंख्या घनत्व



न्याय पंचायत

चित्र संख्या 35

### 3.4.2 निम्न घनत्व क्षेत्र :-

इसके अन्तर्गत 500–600 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> घनत्व वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस वर्ग में तुषायल, घोषण, भानपुर तथा कलन्दरनगर न्यायपचायते आती हैं। 1981 में सम्पूर्ण तहसील का जनघनत्व 600 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> से अधिक नहीं था। जबकि 1991 में इस वर्ग में सगरा खास, बडोखर, दसिया, परसा दमया, भिरिया ऋतुराज तथा पिपराजप्ती न्याय पचायते सम्मिलित थीं।

### 3.4.3 मध्यम घनत्व क्षेत्र :-

तालिका क्रमांक एव मानचित्र से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग का घनत्व 600–700 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> के मध्य है इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाली सगरा खास, बडोखर, कोठिला खास, दसिया, परसा दमया तथा भिरिया ऋतुराज न्यायपचायते आती हैं। जो सम्पूर्ण तहसील की 26.30% क्षेत्र आवृत किये हुये हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की कुल 21 न्यायपचायते में से 6 का जनघनत्व 600–700 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> के मध्य है।

### 3.4.4 उच्च जनघनत्व क्षेत्र :-

तहसील के लगभग 20% क्षेत्र का जनघनत्व 700–800 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> है। इस वर्ग में थुम्हवा पाण्डेय, सल्टौवा, पचानू, आमा, पिपराजप्ती, जिनवा न्यायपचायते सम्मिलित हैं। 1991 में केवल शकरपुर एव पचमोहनी न्यायपचायते थीं जो कि सर्वोच्च जनघनत्व का प्रतिनिधित्व करती थीं।

### 3.4.5 अति उच्च घनत्व क्षेत्र :-

तहसील की चार न्यायपचायते का घनत्व 800 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> से अधिक है। कुल 12.40% क्षेत्र पर व्याप्त इस वर्ग में शकरपुर, नरखोरिया, पचमोहनी और पुरैना न्यायपचायते सम्मिलित हैं। शकरपुर न्यायपचायत का घनत्व 899 व्यक्ति/

# TAHSIL BHANPUR DISTRICT BASTI POPULATION DENSITY 2001

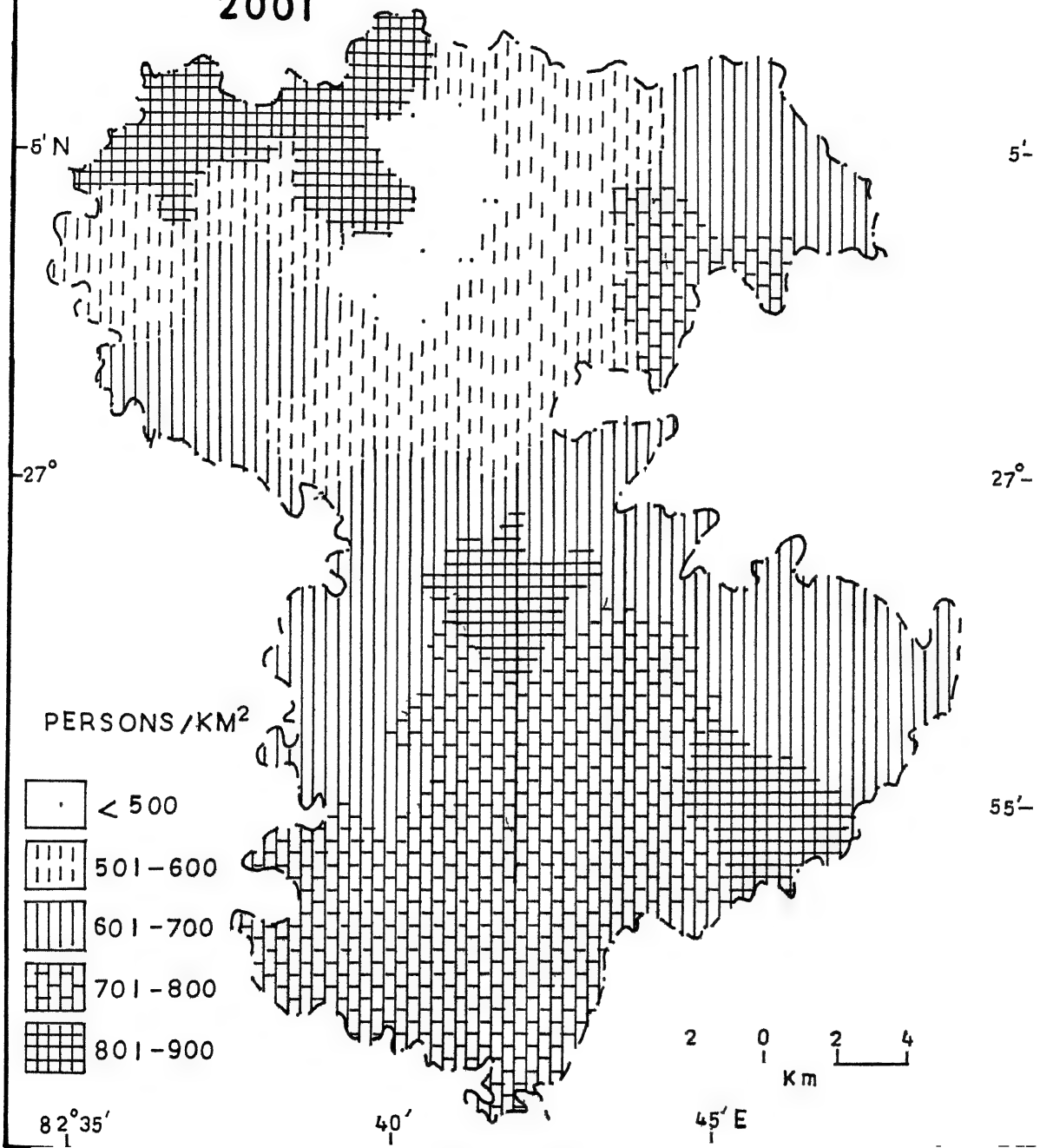


Fig. 3.6

किमी<sup>2</sup> है जो तहसील का सर्वोच्च जनघनत्व है। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के अति उच्च होने के कारण समतल मैदान, जलोढ़, उर्वरामृदा, सिंचाई के साधनों की प्रचुरता, परिवहन की अच्छी सुविधा विगत दशक (1991-2001) जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि, पुरैना तथा नरखोरिया न्याय पंचायतों में हुई।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या का यह वितरण प्रतिरूप मुख्यतः घरातलीय संरचना, मिट्टी की उर्वरता सिंचाई की सुविधाएँ, कृषि विकास एवं परिवहन की सुगमता आदि से प्रभावित पाया जाता है।

### 3.5 आयु-लिंग संरचना :-

किसी भी जनसंख्या की आयु-संरचना सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं जैसे-सामाजिक तथा राजनैतिक प्रवृत्तियों, आर्थिक, क्रियाकलापों, शारीरिक-क्षमता आदि को प्रभावित करती है। मनुष्य की आयु उसकी आवश्यकताओं, कार्यक्षमता तथा विचारों को प्रभावित करती है। अतः आयु मनुष्य की क्षमता का सूचकांक है (चान्दना-1981 पृष्ठ 126)। इससे यह प्रतीत होता है कि जनसंख्या का कौन सा भाग ऐसा है जो भविष्य में पुनरोत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेगा तथा कितना भाग ऐसा है जो पुनरोत्पादन तथा जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान कर रहा है। तहसील की कार्यशील जनसंख्या में क्रियाशील वर्ग (15-59 वर्ष) की मात्रा दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। युवा वर्ग नौकरी तथा काम के तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं।

यौनानुपात सामाजिक प्रारूप के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारक है तालिका क्रमांक 3.2 में न्यायपंचायत वार तहसील में पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या दी गयी है। तहसील के सृजन के बाद 1991 में भानपुर तहसील में प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 902 थी जो कि नयी जनगणना

### तालिका क्रमांक-3.7

भानपुर तहसील में यौनानुपात  
(प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या)

क्र० स०	न्यायपंचायत	1981	1991	2001
1	शकरपुर	922	886	938
2	नरखोरिया	981	970	1016
3	तुषायल	954	937	985
4	सगराखास	944	933	997
5	थुम्हवा पाण्डेय	914	919	917
6	घोषण	898	907	990
7	भानपुर	877	908	964
8	रामनगर	888	884	959
9	कलन्दरनगर	888	851	922
10	बडोखर	872	871	929
11	कोटिला खास	892	878	945
12	पचमोहनी	850	845	917
13	दसिया	864	895	930
14	परसादमया	894	910	965
15	पुरैना	880	941	976
16	सल्टौआ	925	911	952
17	पचानू	928	925	931
18	भिरिया ऋतुराज	882	886	944
19	आमा	881	899	947
20	पिपरा जप्ती	871	882	904
21	जिनवा	920	919	929

2001 में बढ़कर 952 हो गयी। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर भी यौनानुपात में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। 1991 में सल्टौआ गोपालपुर में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात 899 था जो 2001 में बढ़कर 943 हो गया। रामनगर विकास खण्ड में भी वृद्धि के संकेत मिलते हैं। जो 1991 में 905 थी जो 2001 में बढ़कर 962 हो गयी इस प्रकार दोनों विकास खण्डों में अनुपात में वृद्धि ही हुई है।

इस प्रकार तहसील भानपुर का यौगानुपात जनपद के 1991 (908), 2001 (916) के अनुपात से अधिक है जो कि तहसील में स्त्रियों के अनुपात में वृद्धि का घटक है। इसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा बालिकाओं की जन्म दर का अधिक होना है।

न्यायपचायत स्तर पर प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या पर दृष्टि डाला जाय तो इसमें ह्रास तथा वृद्धि के संकेत मिलते हैं। 1981 में जहाँ न्यायपचायत नरखोरिया का यौनानुपात सर्वाधिक (981) था। वही सबसे कम पचमोहनी (850) न्यायपचायत का है। जबकि 1991 में दोनों न्यायपचायतों में कमी आयी है। 2001 में नरखोरिया न्यायपचायत का अनुपात सर्वाधिक 1016 हो गया। सारणी से यह स्पष्ट है कि केवल नरखोरिया न्यायपचायत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। सगरा खास में (997) भी स्थिति अच्छी है। 2001 की जनसंख्या के आधार पर सबसे कम यौनानुपात पिपरा जप्ती (904) का मिलता है। इस प्रकार लगभग सभी न्यायपचायतों में अनुपात में वृद्धि परिलक्षित होता है। तहसील को यौनानुपात 962 से अधिक अनुपात केवल 6 न्याय पचायतों में है। जिसमें क्रमिक रूप से नरखोरिया (1016), सगराखास (997), घोषण (990) तुसायल (985), परसा दमया (965), तथा भानपुर (964) आते हैं।

### 3.6 साक्षरता :—

शिक्षा मनुष्य के बौद्धिक और भावनात्मक विकास का एक अनवरत प्रयास है। साक्षरता और विकास एक दूसरे से जुड़े हुये है। ग्राम्य विकास के लिये बनायी गयी प्रमुख परियोजनाओ मे शिक्षा के प्रचार, प्रसार को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। शिक्षा का अभाव समाज के सर्वांगीण विकास मे बाधक है। गावो मे इसकी कमी मे कारण अभी भी सामाजिक कुप्रथाये, कुरीतियाँ देखने को मिलती है। गरीबी, अभावग्रस्तता, जनसख्या वृद्धि, अधविश्वास जैसी समस्याये शिक्षा की कमी के मूल कारण है।

भारत सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 15 से 35 वष्र के आयु वर्ग के लोगो के लिये सन 2005 तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। सम्पूर्ण साक्षरता का अर्थ 75% साक्षरता से है और साक्षरता की परिभाषा यह है कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा मे लिखना, पढना और गणित की दृष्टि से 1 से 100 तक गिनना और सरल, जोड, घटाव, गुणा और भाग जानता हो वह साक्षर है, (कुरुक्षेत्र अक्टूबर पृ0 18 2002)।

अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता 2001 की जगणनानुसार केवल 38.95% है। जिसमे 52.08 पुरुष एव 25.16% महिला साक्षर है। क्षेत्र की साक्षरता का प्रतिशत प्रादेशिक साक्षरता 57.36% एव राष्ट्रीय साक्षरता 65.38% की तुलना मे बहुत कम है। पुरुष और महिला साक्षरता भी राष्ट्रीय साक्षरता (75.85% एव 54.16%) से बहुत कम है।

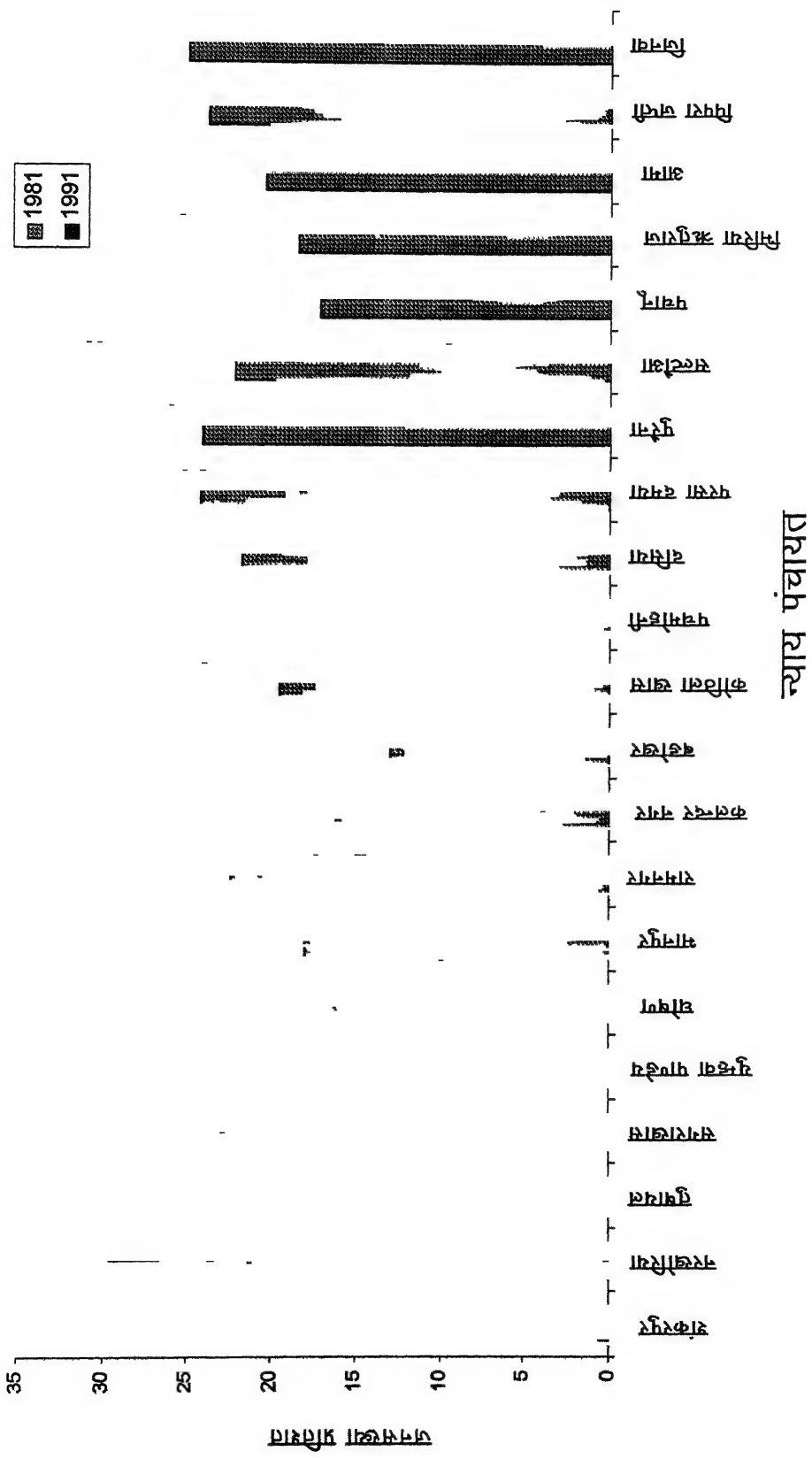
बस्ती जनपद मे भी साक्षरता 35.36% (1991) से बढ़कर 2001 में 54.28% हो गयी जिसमे उत्तरोत्तर वृद्धि के सकेत मिलते है। पुरुष साक्षरता 50.93% से

**तालिका क्रमांक-3.8**  
**भानपुर तहसील में साक्षरता**

क्र० स०	न्यायपंचायत	1981			1991		
		कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
1	शकरपुर	197	306	78	2026	30.87	829
2	नरखोरिया	213	354	69	2961	42.61	1517
3	तुषायल	178	288	63	2111	33.44	796
4	सगराखास	178	292	59	2297	36.17	918
5	थुम्हवा पाण्डेय	177	284	59	2539	38.18	1146
6	घोषण	165	280	36	2304	36.90	776
7	भानपुर	181	289	57	2680	38.41	14.01
8	रामनगर	225	358	76	2824	42.69	1190
9	कलन्दरनगर	162	268	42	1871	30.32	508
10	बडोखर	130	204	46	1795	16.81	700
11	कोठिलाखास	196	321	57	2715	40.52	11.93
12	पचमोहनी	219	344	72	2357	36.31	851
13	दसिया	219	348	70	2434	38.64	836
14	परसा दमया	243	371	100	2984	43.58	14.74
15	पुरैना	242	383	82	2615	41.38	997
16	सल्टौवा	223	361	75	3113	45.19	1423
17	पचानू	172	286	49	2486	37.73	1093
18	भिरिया ऋतुराज	186	301	56	2622	40.18	1049
19	आमा	205	330	68	2739	42.05	1110
20	पिपरा जप्ती	239	364	95	3205	46.45	1574
21	जिनवा	251	389	102	2722	42.32	1080



## भानपुर तहसील : साक्षरता



68.16% तथा महिला साक्षरता 18.08% से 39% हो पहुँच गयी। जो कि तहसील की साक्षरता से अधिक है।

1991 की जनगणना के अनुसार तहसील की केवल 25.06% जनसंख्या साक्षर थी। जो 2001 में बढ़कर 38.95% हो गयी जो कि शिक्षा के प्रति जागरूकता को इंगित करती है। 1991 में विकास खण्ड वार यदि साक्षरता पर दृष्टि डाला जाय तो सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड की साक्षरता 34.5% थी। जिसमें पुरुष 52.1% तथा स्त्री 14.9% थी। रामनगर की कुल साक्षरता 29.5% थी। जिसमें पुरुष की साक्षरता 44.8% तथा स्त्री की 12.8% थी। अधिकांश न्यायपचायतो का प्रतिशतांक 25 से 30% के मध्य है, (मानचित्र संख्या 39)। तहसील में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की साक्षरता अत्यन्त निम्न एवं चिन्तनीय है। 1981 में तहसील के न्यायपचायतो में सर्वाधिक कुल साक्षरता जिनवा (25.1) का था जबकि सबसे कम बड़ोखर न्याय पचायत का। जिनवा न्यायपचायत की पुरुष एवं स्त्री साक्षरता भी सर्वाधिक थी। 1981 में सबसे कम स्त्री साक्षरता 4.2% कलन्दरनगर न्यायपचायत की रही। 1991 में तहसील की न्यायपचायतो में सबसे कम साक्षरता बड़ोखर (17.95) तथा कलन्दरनगर (18.71) न्यायपचायत की है। जिसकी साक्षरता 20% से भी कम है।

सर्वाधिक साक्षरता सल्टौवा विकास खण्ड के सल्टौवा और पिपराजप्ती (32.08%) न्यायपचायत की है। इन न्यायपचायतो में महिला साक्षरता भी अधिक है। पिपराजप्ती में (15.74%) तथा सल्टौवा में (14.23%) साक्षरता अधिक होने का कारण नजदीक में विद्यालयों की सुलभता है। शंकरपुर, तुषायल, सगराखास, घोषण, पचमोहिनी दसिया, और पचानू न्यायपचायत की साक्षरता 20 से 25% के बीच में है। सबसे अधिक न्यायपचायतो की साक्षरता 25 से 30% के बीच में है।

TAHSIL BHANPUR  
DISTRICT BASTI  
**RURAL LITERACY**  
**1991**

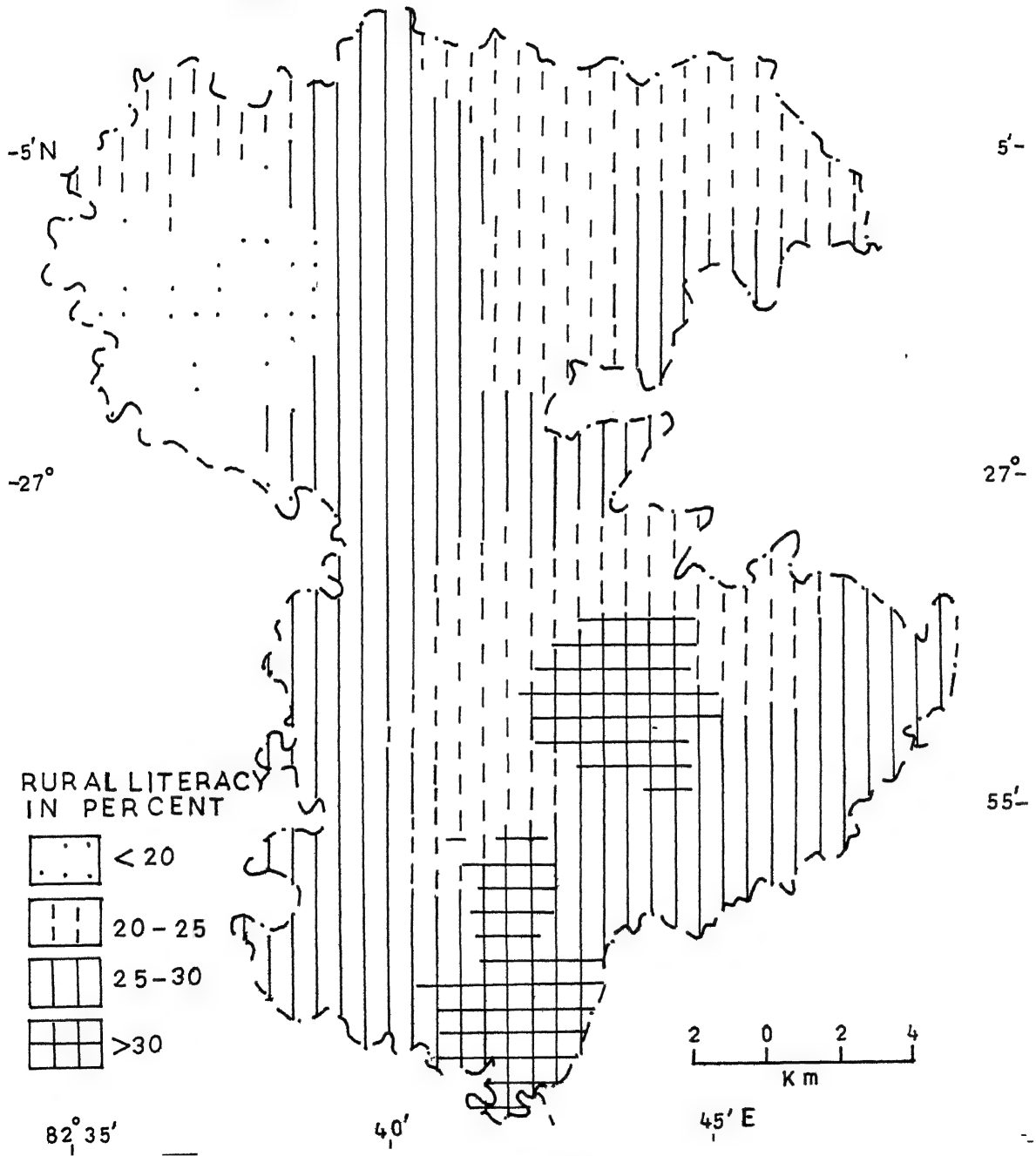


Fig. 3.9

इस वर्ग में नरखोरिया, थुम्हवा पाण्डेय, भानपुर, रामनगर, कोठिलाखास, परसादमया, पुरैना, भिरिया ऋतुराज, आमा तथा जिनवा न्यायपचायत आती है। न्यायपचायते स्तर पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पिपराजप्ती न्यायपचायत (46.45%) की है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कलन्दरनगर (30.32%) की है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता पिपराजप्ती (15.74%) तथा सबसे कम साक्षरता बडोखर (7%) न्यायपचायते की है।

तालिका क्रमांक 3.8 से स्पष्ट है कि 1981 की तुलना में 1991 में साक्षरता वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र की महिला साक्षरता 2001 जनगणनानुसार 25.16 है जो कि 1991 में 10.9% थी। तालिका तथा निजी सर्वेक्षण की सहायता से ऐसा प्रतीत होता है कि भानपुर तहसील में विभिन्न कक्षाओं में बालिकाओं की स्थिति समयानुसार परिवर्तित होती रही है। नामांकन के समय जहाँ 100% बालिकाएँ प्रवेश लेती हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पहुँचने में इनका प्रतिशत घटकर 20.15% आ जाता है तथा 9 से 12 कक्षा तक इनका प्रतिशत घटकर 8% से भी कम हो जाता है।

### अनुसूचित जाति/जनजाति :-

अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 17.6% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ पूरे तहसील में केवल ग्राम उकड़ा (भानपुर, न्यायपंचायत) में मिलती हैं। इनकी कुल जनसंख्या 20 है, जिसमें पुरुष 10 तथा महिलाएँ 5 हैं।

तालिका क्रमांक 3.9 एवं मानचित्र 3.9 से स्पष्ट होता है कि 12% से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूरे तहसील में केवल शकरपुर न्यायपंचायत का है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति (20% से अधिक) जिनवा, सल्टौवा, परसा-दमया,

### तालिका क्रमांक-3.10

#### भानपुर तहसील में अनुसूचित जाति का विवरण

क्र० स०	न्यायपंचायत	1981	1991
		कुल जनसंख्या से प्रतिशत	कुल जनसंख्या से प्रतिशत
1	शकरपुर	12 6	11 3
2	नरखोरिया	14 4	14 7
3	तुषायल	16 7	17 1
4	सगराखास	18 4	17 7
5	थुम्हवा पाण्डेय	21 0	18 0
6	घोषण	19 6	18 3
7	भानपुर	20 9	20 0
8	रामनगर	15 4	15 1
9	कलन्दरनगर	15 1	14 9
10	बडोखर	16 2	14 6
11	कोठिलाखास	28 8	20 9
12	पचमोहनी	19 3	19 3
13	दसिया	19 2	20 6
14	परसा दमया	21 2	21 7
15	पुरैना	19 8	17 7
16	सल्टौआ	14 1	20 6
17	पचानू	18 2	17 6
18	मिटिया ऋतुराज	18 5	17 7
19	आमा	16 4	14 9
20	पिपरा जप्ती	16 7	16 8
21	जिनवा	21 2	21 8

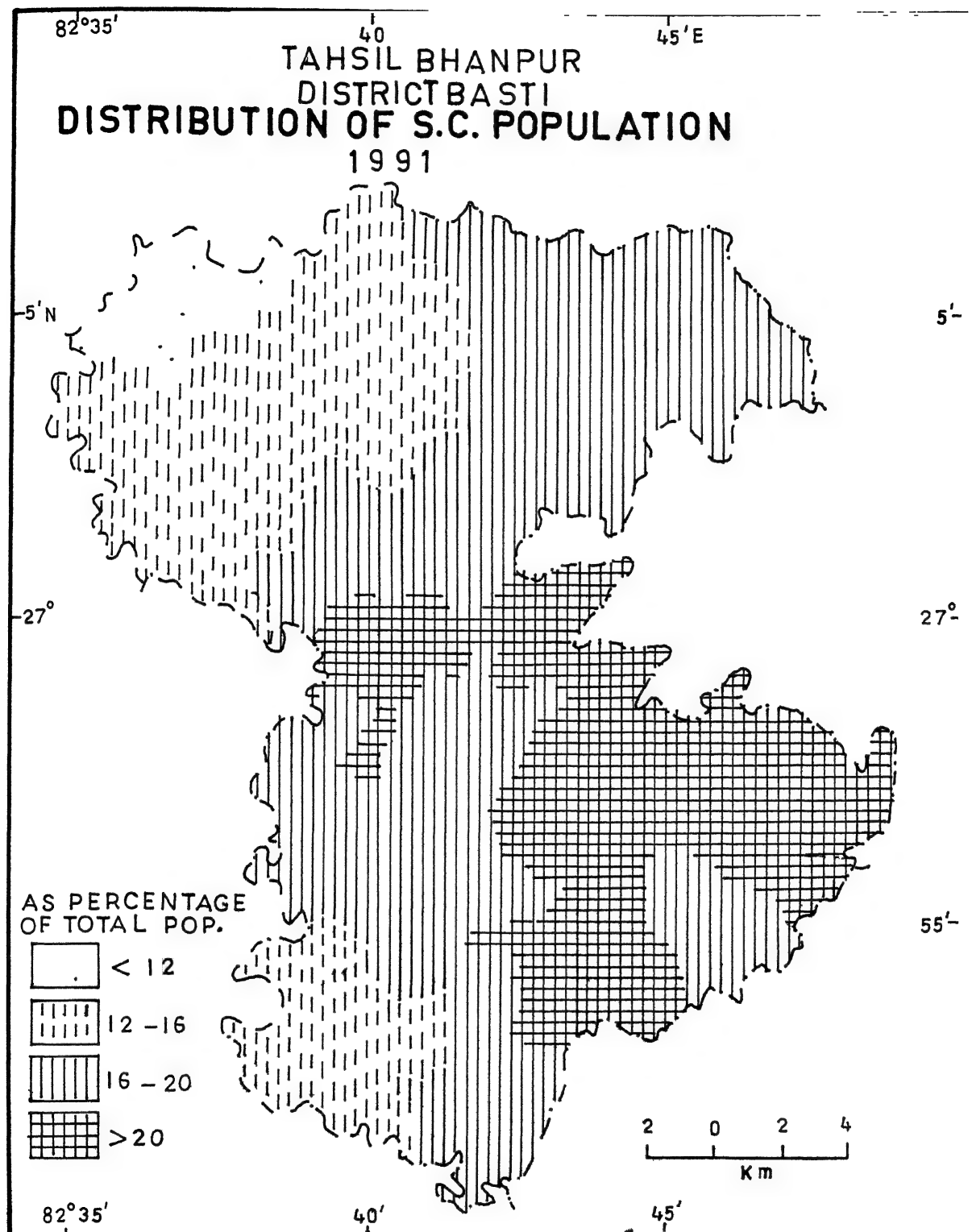


Fig.3.10

दसिया तथा कोठिला खास न्यायपचायतो मे निवास करती है। वही नरखोरिया, कलन्दरनगर, बडोखर, रामनगर एव आमा मे 12 से 16% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते है। सर्वाधिक न्यायपचायते 16 से 20% के बीच आती है।

मानचित्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसख्या सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे निवास करती है। इस प्रकार भानपुर तहसील मे छात्रो तथा छात्राओ की स्थिति को देखा जाय तो निसन्देह 1989-90 से 2000-01 मे वृद्धि हुई है जिसे तालिका क्रमांक 3 10 से देखा जा सकता है। जहाँ तहसील मे कुल छात्रो तथा छात्राओ की सख्या मे वृद्धि नजर आती है वही दोनो विकास खण्डो के अनुसूचित जाति के छात्र तथा छात्राओ की सख्या मे निरन्तर कमी आती जा रही है। कक्षा मे बढ़ते हुये वर्ग मे इनकी सख्या कम होती जा रही है। कक्षा 9 से 12 मे अनुसूचित जाति के छात्रो एव छात्राओ की सख्या मे वृद्धि के सकेत मिलते है।

अनुसूचित जाति की बालिकाओ की स्थिति माध्यमिक एवं उच्चतर कक्षाओ मे सल्टौवा विकास खण्ड मे कम है। अनुसूचित जाति की 92% बालिकाओ का शैक्षणिक जीवन जूनियर बेसिक स्कूल के बाद समाप्त हो जाता है। मात्र 6% छात्राये ही माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर पाती है। इधर कुछ वर्षो मे इनकी सख्या मे वृद्धि हो रही है। जो कि सामाजिक जनचेतना तथा जागरूकता का घोटक है।

प्रशासनिक और सामाजिक वर्जनाये बालिका शिक्षा के विकास मे अवरोधक बनी है। तहसील मे भानपुर तथा सल्टौवा गोपालपुर, मुहम्मदनगर, असनहरा मे विद्यालय है, जहा सह-शिक्षा मिलती है। बालिका विद्यालय (माध्यमिक विद्यालय) पूरे तहसील मे एक भी नही है। सह-शिक्षा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों मे अच्छा नही

**तालिका क्रमांक-3.10**

**भानपुर तहसील : विभिन्न कक्षाओं में छात्रों/छात्राओं की स्थिति**

	कक्षा 1 से 5 तक		कक्षा 6 से 8 तक		कक्षा 9 से 12 तक	
	सत्र 1989-90	2000-01	1989-1990	2000-2001	1989-1990	2000-2001
<b>विकास खण्ड</b>						
सल्टौआ गोपालपुर						
छात्रो	10050	16820	1614	5585	1442	2247
छात्राओ	5729	5325	348	582	165	95
<b>अनुसूचित जाति</b>						
छात्र	2305	1480	302	2162	81	530
छात्राओ	1074	855	53	139	28	5
<b>विकास खण्ड</b>						
रामनगर						
छात्र	8441	15320	538	2140	915	2033
छात्राओ	1971	6380	308	481	45	248
<b>अनुसूचित जाति</b>						
छात्र	1323	2936	302	640	105	399
छात्राओ	1071	1040	65	115	13	48

**स्रोत :-** सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 1989-90 एवं  
सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 2001 से सगणित



माना जाता है। इससे लड़कियों के सम्पूर्ण या सम्यक शैक्षिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। समाज में अधिकांश वर्ग के लोग असामाजिक तत्वों के भय से लड़कियों को दूर विद्यालय में भेजने से डरते हैं। नजदीक में विद्यालयों का अभाव लड़कियों की शिक्षा में अवरोधक है। समय से पहले (8-14 वर्ष) में ही 70% से अधिक लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद उनका शैक्षणिक कार्य वहीं बन्द हो जाता है। माध्यमिक कक्षा में बालिकाएँ किशोरावस्था में आ जाती हैं, उन पर माता-पिता द्वारा घरेलू कार्यों का भार अधिक कर देने से उनका अध्ययन काल कम हो जाता है। इसमें अनुसूचित जातियों की लड़कियाँ अर्थोपार्जन हेतु खेतों में या ईट में भट्टों में कार्य करना प्रारम्भ कर देती हैं तथा शैक्षणिक कार्य अधूरा छूट जाता है।

### 3.7. व्यावसायिक संरचना :-

जीविका निर्वाहन एवं अर्थोपार्जन हेतु की जाने वाली आर्थिक क्रियाकलाप को 'व्यवसाय' से अभिहित किया जाता है। जनसंख्या के इसी संरचना के द्वारा ही क्षेत्र क्रियाशील प्रारूप तथा विकास के स्तर की जानकारी होती है। जनसंख्या दबाव तथा आर्थिक संरचना का आकलन इसी के विश्लेषण से प्राप्त किया जा सकता है। व्यावसायिक संरचना को अध्ययन हेतु तीन भागों में बाटा जा सकता है - कार्यरत जनसंख्या (कुल मुख्य कर्मकर) सीमांत जनसंख्या (सीमांत कर्मकर) तथा बेरोजगार (अकर्मकर) जनसंख्या।

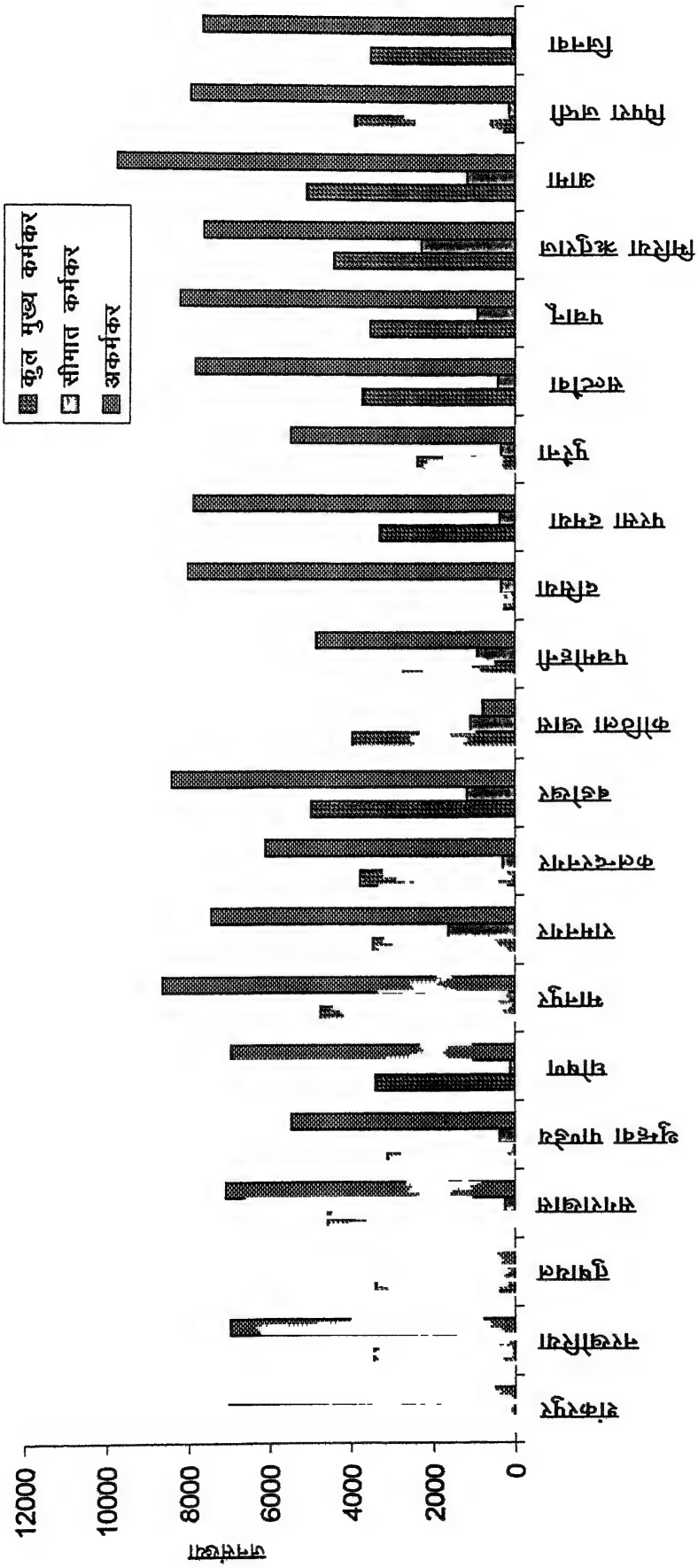
इस प्रकार एक व्यक्ति यदि वर्ष के अधिकांश समय में (कम से कम 180 दिन) किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है तो उसे कार्यरत या 'मुख्य कर्मकर' (कार्य करने वाला) माना जाता है। किन्तु यदि वह वर्ष के कुछ महीने में ही कार्य में लगा रहता है तो उसे सीमांत कर्मकर माना जाता है। इसके विपरीत वह

### तालिका क्रमांक-3.11

#### भानपुर तहसील : व्यावसायिक जनसंरचना

	न्यायपंचायत	कुल मुख्य कर्मकर		सीमांत कर्मकर		अकर्मकर	
		संख्या	(%)	संख्या	(%)	संख्या	(%)
1	शकरपुर	3915	35.2	187	1.7	7030	63.1
2	नरखोरिया	3480	31.3	662	5.9	6965	62.8
3	तुषायल	3429	33.8	714	7.0	6001	59.2
4	सगराखास	4610	38.5	254	2.1	7110	59.4
5	थुम्हवा पाण्डेय	3110	34.7	377	4.2	5473	61.1
6	घोषण	3416	32.5	118	1.1	6969	66.4
7	भानपुर	4775	34.0	589	4.2	8662	61.8
8	रामनगर	3528	27.9	1636	12.9	7485	59.2
9	कलन्दरनगर	3800	37.2	286	2.8	6139	60.0
10	बडोखर	5025	34.3	1176	8.0	8441	57.7
11	कोठिला खास	4035	30.7	1114	8.5	8002	60.8
12	पचमोहनी	2741	31.9	939	10.9	4904	57.1
13	दसिया	3692	31.7	354	3.1	8066	69.2
14	परसा दमया	3345	28.6	391	3.3	7946	68.1
15	पुरैना	2425	29.2	326	3.9	5542	66.9
16	सल्टौआ	3753	31.0	441	3.6	7905	65.4
17	पचानू	3576	28.0	912	7.2	8265	64.8
18	भिरिया ऋतुराज	4468	30.9	2309	15.9	7699	53.2
19	आमा	5176	31.9	1180	7.3	9848	60.8
20	पिपराजप्ती	3977	32.7	167	1.4	8019	65.9
21	जिनवा	3595	31.0	.85	80	7745	68.2
	<b>भानपुर</b>	<b>79271</b>	<b>32.0</b>	<b>14199</b>	<b>5.7</b>	<b>158206</b>	<b>62.3</b>

## भानपुर तहसील : व्यवसायिक जनसंरचना



न्याय पचायत

व्यक्ति जो वर्ष भर उत्पादन प्रक्रिया में नहीं रहा है उसे बेरोजगार या कार्य न करने की क्षेणी में रखा गया है, (मिश्रा इन्दू-1990, पृ0 135)।

### 3.7.1 कार्यरत एवं अकार्यरत जनसंख्या :-

अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का मात्र 32.5% ही कार्य करने वाले लोगों का है जिनमें पुरुषों का योगदान सर्वाधिक है। तालिका क्रमांक 3.11 द्वारा न्यायपचायत स्तर पर कर्मकर, सीमांत कर्मकर तथा अकर्मकर जनसंख्या के अनुपात को दिखाया गया है, जो प्रतिशत में है। तहसील में 62.3% जनसंख्या बेरोजगार है जबकि सीमांत रूप में कार्य करने वाले लोगों का योगदान 5.7% है।

सबसे अधिक बेरोजगार या अकर्मकर जनसंख्या दसिया (69.2%) तथा जिनवा (68.2%) न्यायपचायत की है। सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या सगराखास (38.5%) तथा कलन्दर नगर (37.2%) न्यायपचायत में पायी जाती है। सीमांत जनसंख्या सबसे अधिक भिरिया ऋतुराज (15.9%) तथा रामनगर (12.9%) में है। इस प्रकार सम्पूर्ण तहसील में 32% कार्यरत 5.7% सीमांत तथा 62.3% बेरोजगार या अकार्यरत जनसंख्या है।

### 3.7.2 कार्यरत जनसंख्या का वितरण :-

तहसील में सम्पूर्ण जनसंख्या की 32.5% जनसंख्या मुख्य कर्मकर के रूप में है। वर्ष 1991 की जनगणना में कार्यरत जनसंख्या को 9 प्रमुख वर्गों में बाटा गया है। यथा-कृषक, कृषि श्रमिक, पशुपालन वृक्षारोपण, खान एवं खदानों में कार्यरत लोग, पारिवारिक उद्योग, विनिर्माण कार्य व्यापार तथा परिवहन संचार एवं अन्य औद्योगिक कार्यों में सलग्न जनसंख्या (तालिका क्रमांक एवं चित्र स0 3.12)।

### 3.7.2.1 'कृषक' :-

वह व्यक्ति माना गया है जो अपनी स्वयं की भूमि पर अकेले या परिवार के साथ कृषि कार्य करता है। यह भूमि पट्टे की, बँटाई की, या किराये की किसी भी प्रकार की हो सकती है। सम्पूर्ण तहसील की 78.06% जनसंख्या कृषक है। विकास खण्ड वार कृषको पर दृष्टि डाली जाय तो रामनगर विकास खण्ड में कुल कृषक 82.08% है। जिनमें 81.3% पुरुष तथा 18.7% महिला है। सल्टौवा गोपालपुर में कृषको का प्रतिशत 75.2 है जिनमें 90.4% पुरुष कृषक तथा 9.6% महिला कृषक शामिल है।

सर्वाधिक कृषको की संख्या रामनगर विकासखण्ड में बडोखरा न्यायपचायत की है जिसमें लगभग 80% जनसंख्या कृषि में रूप में है। सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड में आमा न्यायपचायत में सर्वाधिक कृषको की संख्या है। सर्वाधिक स्त्री कृषक की जनसंख्या न्यायपचायत सगरा खास में है जो सभी न्यायपचायतों से अधिक है।

### 3.7.2.2 कृषि श्रमिक :-

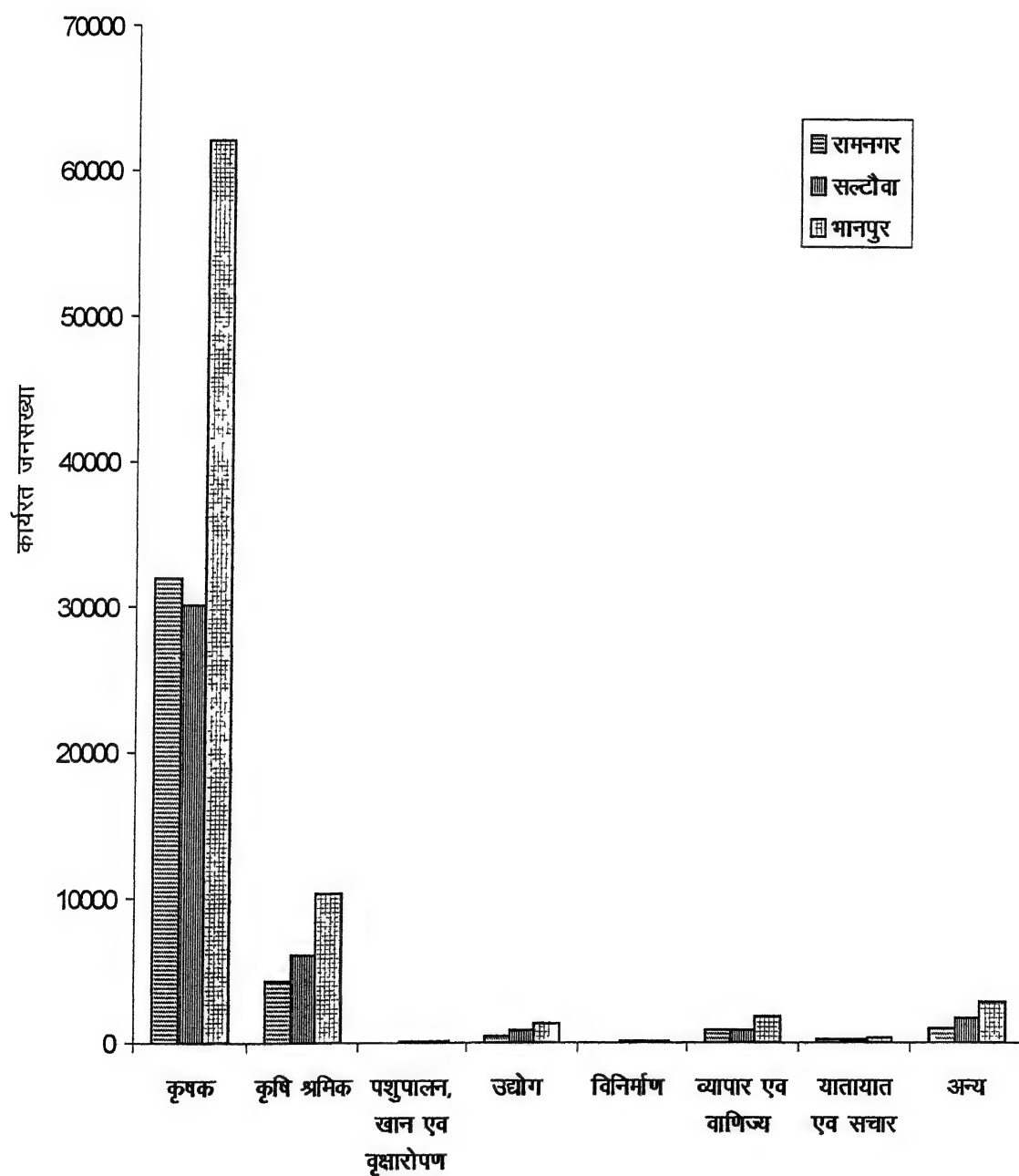
जो व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि पर कृषि करता है और नकद धनराशि प्राप्त करता है वह 'कृषि श्रमिक' या 'मजदूर' कहलाता है। तहसील में कुल क्रियाशील जनसंख्या में कृषि श्रमिक 13.6% है। रामनगर विकास खण्ड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 10.9 है। जिसमें 63.3% पुरुष तथा 36.7% महिला कृषि श्रमिक है। सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत रामनगर से अधिक (15.1%) है। रामनगर विकास खण्ड में कुल कृषि श्रमिकों में 71.6% पुरुष तथा 28.4% महिला कृषि श्रमिक सम्मिलित है।

## तालिका क्रमांक-3.12

### भानपुर तहसील में कार्यरत जनसंख्या का वितरण

क्र० स०	व्यवसाय विवरण	रामनगर क्रियाशील जनसंख्या	(%)	सल्टौआ गोपालपुर क्रियाशील जनसंख्या	(%)	तहसील भानपुर क्रियाशील जनसंख्या	(%)
1	कृषक	31936	82 08	30169	75 2	62105	78 06
	पुरुष	25961	81 3	27260	90 4	53261	85 7
	स्त्री	5975	18 7	2909	9 6	8884	14 3
2	कृषि श्रमिक	4248	10 9	6061	15 1	10309	13 6
	पुरुष	2691	63 3	4341	71 6	7032	68 2
	स्त्री	1557	36 7	1720	28 4	3277	31 8
3	पशुपालन, खान एवं वृक्षारोपण	57	15	86	20	143	0 18
	पुरुष	56	98 2	84	97 7	140	97 9
	स्त्री	1	1 8	2	2 3	3	2 1
4	उद्योग	527	1 4	838	2 1	1365	1 7
	पुरुष	478	90 7	773	92 2	1251	91 6
	स्त्री	49	9 3	65	7 8	114	8 4
5	विनिर्माण	39	10	85	20	124	0 15
	पुरुष	36	92 3	84	98 8	120	96 8
	स्त्री	3	7 7	1	1 2	4	3 2
6	व्यापार एवं वाणिज्य	912	2 3	911	2 3	1823	2 3
	पुरुष	867	95 1	884	97 0	1751	96 1
	स्त्री	45	4 9	27	3 0	72	3 9
7	यातायात एवं संचार	184	4 7	226	5 0	410	0 51
	पुरुष	152	82 6	223	98 7	375	91 5
	स्त्री	32	17 4	3	1 3	35	8 5
8	अन्य कर्म कर	1024	2 6	1753	4 4	2777	3 5
	पुरुष	956	93 4	1626	92 8	2582	93 0
	स्त्री	68	6 6	127	7 2	195	7 0
	<b>भानपुर</b>	<b>38927</b>		<b>40129</b>		<b>79056</b>	

## भानपुर तहसील : कार्यरत जनसंख्या



व्यवसाय की प्रकृति

चित्र संख्या 3.12

पशुपालन, खान एवं वृक्षारोपण हेतु कुल क्रियाशील जनसंख्या का मात्र 18% जनसंख्या ही तहसील में है। जिसमें रामनगर में 15 तथा सल्टौवा रामनगर में 20% है। दोनों विकास खण्डों में 97% से अधिक पुरुष इस व्यवसाय में सलग्न हैं।

### 3.7.2.3 उद्योग एवं निर्माण :-

किसी वस्तु के उत्पादन, मरम्मत तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित क्रियाकलाप को उद्योग की संज्ञा दी जाती है। तहसील की क्रियाशील जनसंख्या का लगभग 2% जनसंख्या इस कार्य में सलग्न है। वैसे तो उद्योग में कुछ जनसंख्या लगी हुई है। रामनगर विकास खण्ड में 14% जनसंख्या इस उद्योगों में लगी है, जिसमें 90.7% पुरुष तथा 9.3% महिला शामिल हैं।

इसी प्रकार सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्डों में भी 2.1% जनसंख्या लगी है। जिसमें 92.2% पुरुष तथा 7.8% महिला शामिल हैं। विनिर्माण क्षेत्र में सल्टौवा विकास खण्ड में महिलाओं का प्रतिशत कम है। जो केवल 1.2% ही है। जबकि रामनगर में 7% है।

### 3.7.2.4 अन्य कार्यों में लगी जनसंख्या :-

तहसील की कुल कार्यरत जनसंख्या की 2.3% जनसंख्या व्यापार एवं वाणिज्य में लगी है। जिसमें रामनगर में 3% तथा सल्टौवा गोपालपुर में 2.3% क्रियाशील जनसंख्या है दोनों विकास खण्डों की 95% से अधिक पुरुष जनसंख्या तथा 5% महिला जनसंख्या कार्यरत हैं। यातायात एवं संचार में भी कुल क्रियाशील जनसंख्या का 5% तहसील में लगा है। यातायात तथा संचार में जहाँ रामनगर विकास खण्ड के 82.6% पुरुष सलग्न हैं। वहीं सल्टौवा में यह प्रतिशत 98.7% है। यातायात एवं संचार में रामनगर की महिला प्रतिशत अधिक है जो



17.4 % है। व्यावसायिक क्रियाकलापों में अन्य कर्मकरों का प्रतिशत 3.5 है। रामनगर विकास खण्ड में 2.6% अन्य कर्मकर हैं। जबकि सल्टौवा गोपालपुर में 4.4% है।

इस प्रकार सम्पूर्ण तहसील में सर्वाधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में सलग्न है। कृषकों की संख्या सर्वाधिक है। उद्योग की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। कृषि से लोग हट रहे हैं। कृषि व्यवसाय की तरफ लोगों को ध्यान अब कम होकर विनिर्माण तथा उद्योग धंधों की तरफ अधिक हो रहा है।

### 3.8. जनसंख्या-ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन :-

किसी भी क्षेत्र के विकास के स्तर को वहाँ के जनसंख्या आकार, घनत्व, यौनानुपात तथा साक्षरता के द्वारा जाना जा सकता है जनसांख्यिकी के ये कारक सामाजिक ढाँचा को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। विकास तथा जनसंख्या एक दूसरे के विरोधी हैं। जनसंख्या वृद्धि जहाँ संसाधनों पर दबाव अधिक डालती है वही सामाजिक विकास को प्रभावित भी करती है। समाज पूर्णतः इससे प्रभावित होता है। जनसंख्या वृद्धि से जनशक्ति बढ़ती है जहाँ इसके लाभकारी परिणाम मिलते हैं कृषि व्यवसाय में उन्नति होती है जिससे समाज के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, सकल उत्पाद बढ़ता है, कृषि व्यवसाय में लाभ होता है लेकिन कृषि भूमि पर इनकी संख्या बढ़ने से कृषि जोत का आकार कम होता है आय कम हो जाती है तथा जनसंख्या अधिक होने से संयुक्त परिवार में विघटन प्रारम्भ हो जाते हैं। इस प्रकार समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जब संसाधन कम हो और जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र हो और जनसंख्या भी अधिक हो तो यह समाज के विकास के लिये हानिकारक है। उच्च साक्षरता शैक्षिक समाज तथा सुदृढ़ राष्ट्र का आधार है जनसंख्या की वृद्धि से साक्षरता में

गिरावट आती है जिसका प्रभाव आज भी गाँवों में कुरीतियों एवं बुराईयों के रूप में देखी जा सकता है।

ससाधनों के समुचित उपयोग हेतु तथा समाज के सर्वांगीण आर्थिक विकास हेतु सतुलित जनसंख्या का होना आवश्यक है तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है।



## REFERENCES

- Census of India 1961 District Census Handbook Basti District
- Census of India 1971 District Census Handbook Basti District
- Census of India 1981 District Census Handbook Basti District
- Chandana R C 1981 Introduction to Population Geography Kalyani Publication  
New Dehli p 126
- Census Abstract 1991 – Village/Town Primary, Population Directorate-U.P
- Census of India 2001 Series-10 U P Provisional Population Totals Dr Ranbir Singh  
Director of Census operations, Uttar Pradesh
- Mishra, Indu, 1990 Human Settelement system and Regional Development in  
Allahabad District The Problem and Poicies unpublished D Phil , Thesis of  
Allahabad University, Allahabad p p 120-135
- Signismond, D D 1948 Florida's Human Resources, Geographical Review, Vol 38,  
p 278
- Singh, R P B 1977 Clan Settlements in the saran Plain (Middle Ganga Valley) A  
Study in Cultural Geography, National Geographical Society of India,  
Varansi, p-21
- Sorokin, p, 1928 : Contemporary Sociological Theories – p 357
- Trewartha, G.T : A case for population Geography, Annals of Association of  
American Geographers, Vol 43, p -94
- Zelinski, W 1966 . A Prologue to population Geography (Englewood Cliff Prentice  
Hall) Quoted by Fielding, G J 1974 · Geography as a Social Sicnece (New  
York Harper and Row Publishers), p 14
- सांख्यिकीय प्रतिका 1990, 2000–जनपद बस्ती, 2001 की जनगणना का अप्रकाशित रिपोर्ट ।

## **कृषि विकास और सामाजिक परिवर्तन**

कृषि, आर्थिक विकास एवं ग्रामीण समाज का मूल आधार है। विकास की प्रक्रिया में कृषि ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव की मूलभूत तीनों अनिवार्य आवश्यकताएँ — भोजन, वस्त्र एवं मकान की पूर्ति कृषि द्वारा ही होती है। कृषि मानव के लिये खाद्य, वस्त्र तथा गृहनिर्माण का साधन मात्र ही नहीं है अपितु आवास, उद्योग, व्यापार तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर को निर्धारित करने का एक मापदण्ड भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि आधारभूत ग्रामीण सुविधाओं का समुन्नयन परोक्ष रूप से कृषि विकास से ही होता है। राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि, योजनाओं की सफलता, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, राजनैतिक स्थायित्व आदि सभी कुछ कृषि के विकास पर ही निर्भर है। जीविका का प्रमुख साधन होने के कारण कृषि पर लगभग 75% श्रमिक शक्ति आश्रित है, जो कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 40% का योगदान करती है। अध्ययन क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण आवासीय क्षेत्र है जिसमें लगभग 98% ग्रामीण जनसंख्या सम्पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है।

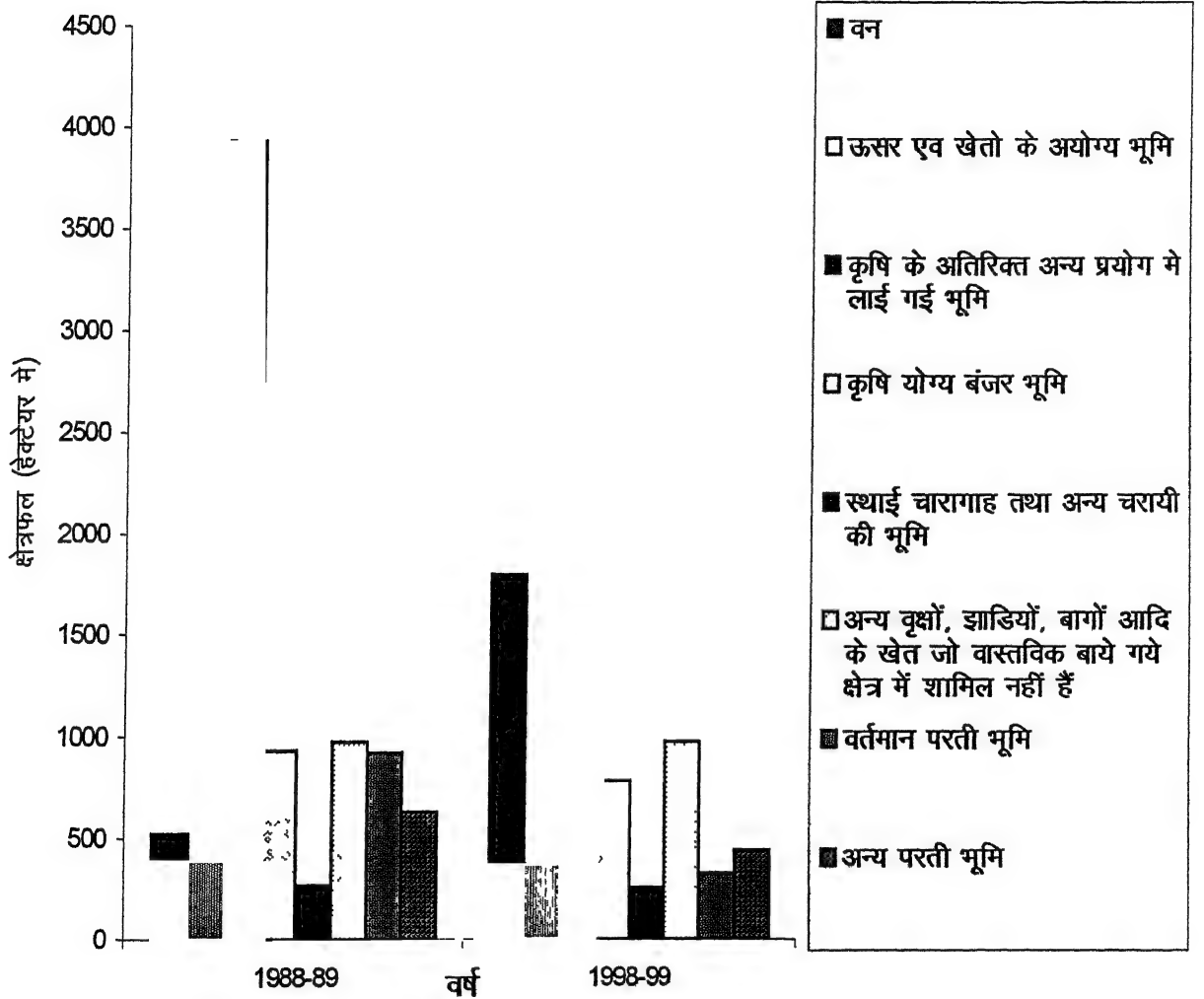
कृषि विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से ही ग्रामीण विकास के लिये आधार निर्मित होता है। ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्यों, अधिकतम रोजगार, आर्थिक विभिन्नता तथा स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग कृषि विकास पर ही आधारित है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा अध्ययन क्षेत्र की प्रगति हेतु कृषकों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की गयीं, जिन्हें आंशिक सफलता भी मिली है किन्तु क्षेत्र का वांछित विकास नहीं हुआ है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास और कृषि विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांख्यिकीय पत्रिका, समाजार्थिक समीक्षा तथा तहसील मुख्यालय आदि स्रोतों से प्राप्त ऑकड़ों एवं व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र में विद्यमान, कृषि के विकास तथा प्रवृत्तियों, सिंचाई के साधन, कृषि समस्याओं आदि का विवेचन किया गया है तथा कृषि विकास हेतु कतिपय सुझाव भी देने का प्रयत्न किया गया है।

#### 4.1 भूमि-उपयोग :-

भूमि उपयोग प्रतिरूप का अभिप्राय किसी प्रदेश की समस्त भूमि की विविध रूपों में उपयोगिता से है। चूंकि भूमि प्राकृतिक सम्पदा के रूप में एक महत्वपूर्ण साधन है इसलिये विविध रूपों में इसकी उपयोगिता है। भूमि उपयोग प्रतिरूप का विश्लेषण वन क्षेत्र, कृषित भूमि, परती भूमि, बजर भूमि, ऊसर भूमि आदि रूपों में किया जाता है। भूमि उपयोग का विविध रूपों में विश्लेषण करने वाले विद्वानों में जी०पी० मार्स (1864), कार्ल ओ० सौर (1919), डब्ल्यू०डी० जोन्स एव फ्रिन्च (1925), वक (1937), ने विशेष योगदान दिया है। भूमि उपयोग से सम्बन्धित विशद विवेचन का कार्य स्टाम्प (1962), इनायदी (1964) आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। एम० शफी द्वारा 1962-72 के मध्य भारत के विभिन्न प्रान्तों की भूमि उपयोगिता तथा भूमि संरक्षण, पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मानव अपने क्रियाकलापों से भूमि उपयोगिता में वृद्धि करता है। इस प्रकार भूमि उपयोग का स्वरूप मुख्य रूप से दो कारकों — प्राकृतिक (संरचना, उच्चावच, जलवायु), जो भूमि की क्षमता का निर्धारण करते हैं एवं सांस्कृतिक कारक जो क्षेत्र की कार्यावधि के साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक दशा का प्रतिनिधित्व करते हैं (बलराम 1986, पृष्ठ 36) से प्रभावित होता है। सर्वेक्षण और परीक्षण के उपरान्त

## भानपुर तहसील : भूमि उपयोग का पैटर्न



**तालिका क्रमांक-4.1**  
**भानपुर तहसील में**  
**भूमि उपयोग का विवरण**

क्र० स०	भूमि उपयोग	1988-89		1998-99	
		(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	प्रतिशत	(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल	46992	—	42451	
2	वन	525	1 1	1801	4 2
3	ऊसर एव खेतों के अयोग्य भूमि।	390	0 8	375	0 9
4	कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोग में लाई गई भूमि।	3935	8 4	3409	8 0
5	कृषि योग्य बजर भूमि	953	2 0	791	1 9
6	स्थायी चारागाह तथा अन्य चरायी की भूमि।	271	0 6	258	0 7
7	अन्य वृक्षों, झाड़ियों, बागों आदि के खेत जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।	978	2 3	981	2 3
8	वर्तमान परती भूमि	927	2 1	329	0.8
9	अन्य परती भूमि	636	1 4	444	1 0
10	शुद्ध बोया गया वास्तविक क्षेत्र	38087	81 3	34063	80 2

तहसील की समस्त भूमि उपयोग की दृष्टि से वन, ऊसर एव खेतों के आयोग्य भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोग में लायी गयी भूमि, कृषि योग्य बजर भूमि स्थायी चारागाह, परती भूमि के साथ ही शुद्ध बोया गया वास्तविक क्षेत्र आदि वर्गों में विभाजित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप का विवरण तालिका क्रमांक 4.1 एवं मानचित्र 4.1 में दृष्टव्य है।

अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 90% से अधिक भूमि का ही उपयोग होता है। भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्रफल 42,451 हेक्टेयर है। जिसमें समस्त क्षेत्रफल का 4.2% वन पाया जाता है। तहसील में वन भूमि का क्षेत्रफल सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड में रामनगर से अधिक है। सल्टौवा गोपालपुर में वन क्षेत्र समस्त भूमि उपयोग की 6% है, जबकि रामनगर में केवल 2.3% है।

अध्ययन क्षेत्र में स्थायी चारागाह के रूप में भूमि लगभग नगण्य है। सन् 1998-99 में कुल क्षेत्रफल का 0.7% भाग ही चारागाह के रूप में था। रामनगर विकास खण्ड के 213 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी चारागाह पाया जाता है जो कि पूरे क्षेत्रफल का 1.1% है जबकि सल्टौवा गोपालपुर में केवल 0.2% क्षेत्र पर ही चारागाह है। पशुओं के चारे के रूप में बरसीम, बाजारा, इत्यादि को बोया जाता है किन्तु चारागाह का स्पष्ट विभाजन नहीं दिखाई पड़ता है।

उत्तरोत्तर जनसंख्या की बढ़ती हुई वृद्धि तथा खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हुई हेतु कृषि योग्य बजर भूमि एवं परती भूमि पर, कृषि कार्य बढ़ने से इनके क्षेत्रफल में ह्रास हुआ है। भूमि उपयोग विवरण पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो कुल भूमि का मात्र 1.9% भूमि, बजर भूमि के अन्तर्गत आता है।



## तालिका क्रमांक-4.2

### भानपुर तहसील : विकास खण्ड से भूमि उपयोग का विवरण

क्र० स०	भूमि उपयोग विवरण (1998-99)	रामनगर	सल्टौआ गोपालपुर	भानपुर क्षेत्रफल हेक्टेयर में	बस्ती जनपद में)
1.	भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल	20272	22179	42451	276367
2.	वन	464 (2.3%)	1337 (6.0%)	1801 (4.2%)	4093
3.	ऊसर एवं खेतों के आयोग्य भूमि।	165 (0.8%)	210 (2.3%)	375 (0.9%)	3657
4.	कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोग में लाई गयी भूमि।	1839 (9.1%)	1570 (7.1%)	3409 (8.0%)	36873
5.	कृषि योग्य बंजर भूमि।	422 (2.1%)	369 (1.7%)	791 (1.9%)	5744
6.	स्थायी चारागाह तथा अन्य चरायी की भूमि।	213 (1.1%)	45 (0.2%)	258 (0.7%)	600
7.	अन्य वृक्षों, झाड़ियों, बागों आदि के क्षेत्र जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं हे।	594 (2.9%)	387 (1.8%)	981 (2.3%)	6674
8.	वर्तमान परती भूमि	176 (0.81%)	153 (0.7%)	329 (0.8%)	6741
9.	अन्य परती भूमि	216 (1.1%)	228 (1.0%)	444 (1.0%)	5217
10.	शुद्ध बोया गया वास्तविक क्षेत्र	16183 (79.8%)	17880 (8.0%)	34063 (80.2%)	206768
11.	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	6561	7349	13410	85533
12.	सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्र				
	अ - खरीफ	10735	13725	24460	152980
	ब - रबी	11532	11126	22658	134392
	स - जायद	465	364	829	4893
	द - गन्ने के लिए तैयार की गयी कृषि	12	14	26	36
13.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	10242	12533	22775	131427

स्रोत : जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा 2000-01, एवं  
सांख्यिकीयपत्रिका, जनपद बस्ती, 2000 से संगठित

(%) प्रतिशत

# TAHSIL BHANPUR LAND-USE PATTERN

1998-99

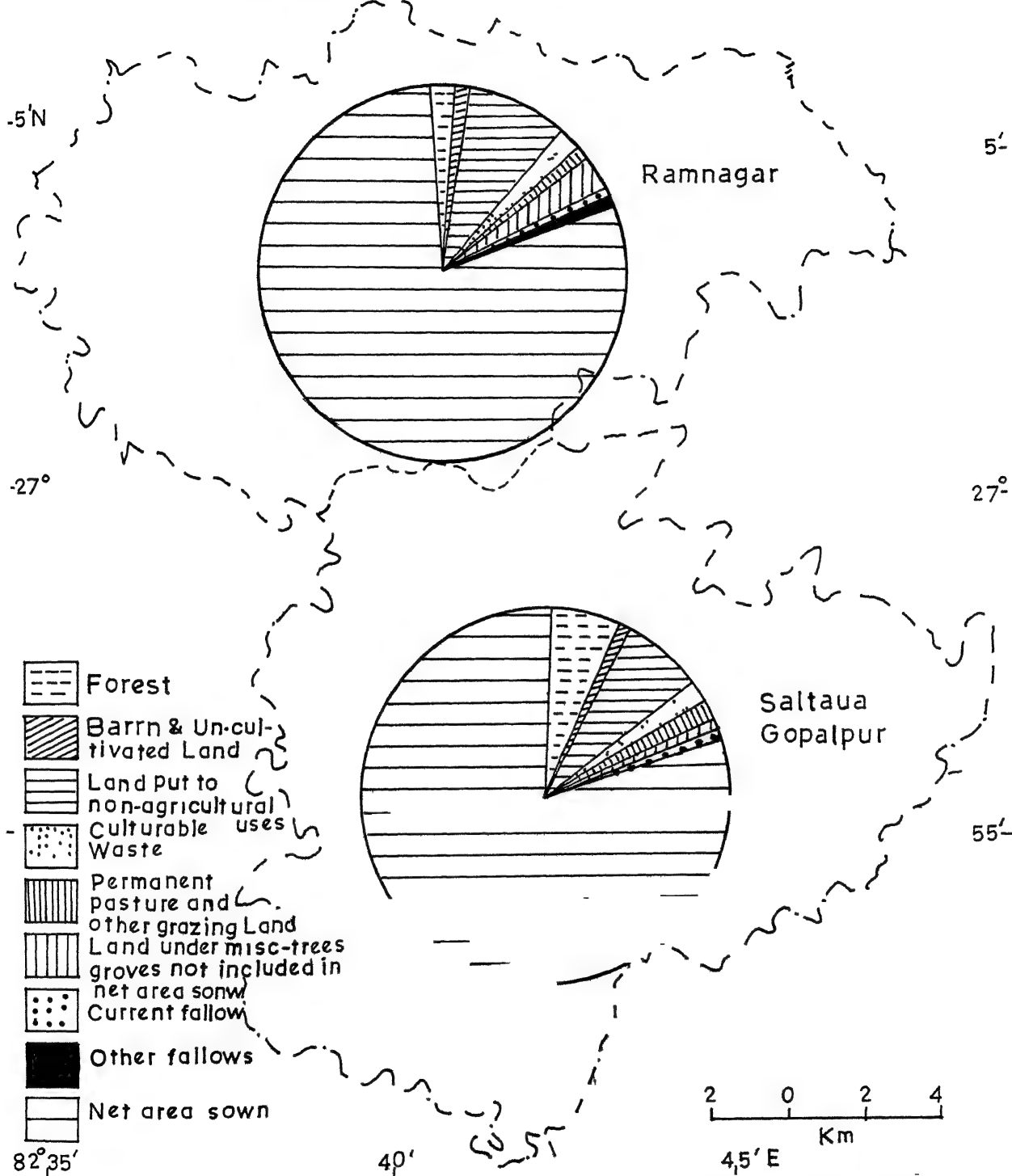


Fig. 4-2

After K. Roy, 1989

आर्थिक क्रियाकलापो में प्रगति के कारण वनोद्यान-भूमि का उपयोग अधिवास, कृषि-क्षेत्र, परिवहन एवं संचार साधनों के विकासार्थ आदि कार्यों में किया जाने लगा है। जिससे वृक्षो, झाड़ियों, बागीचों में प्रयुक्त भूमि के क्षेत्रफल में ह्रास हो रहा है। रामनगर तथा सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्डों में 1998 में वनोद्यान क्षेत्र में प्रयुक्त भूमि क्रमशः 29 तथा 18 प्रतिशत थी। पर्यावरण सतुलन हेतु सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी योजना सहित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सड़कों, पोखरों, नहरों के किनारे तथा अन्य रिक्त सरकारी भूमि पर सरकार द्वारा वृक्षारोपण कराया जा रहा है। तहसील में वनोद्यान भूमि के क्षेत्रफल में तीव्र ह्रास हो रहा है जिसके समाधान हेतु सरकार व्यक्तिगत वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दे रही है (तालिका क्रमांक 4.2, मानचित्र 4.2)।

अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 80.25% भाग कृषि योग्य तथा 19.75% भाग कृषि अयोग्य है। यद्यपि खाद्यान्नों की बढ़ती माँग की पूर्ति हेतु अधिकाधिक क्षेत्र पर कृषि कार्य अपेक्षित होता है। किन्तु वनोद्यान भूमि में कमी से पारिस्थितिकी संकट की समस्या उत्पन्न होती है। ऊसर सुधार उर्वरकों एवं अन्य नवीनतम वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोग से ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि पर भी कृषि कार्य विकसित हुआ है। अतः तहसील के विकासार्थ एक सुनियोजन की आवश्यकता है, जिससे न्यूनतम कृषि क्षेत्र में अधिकतम अन्नोत्पादन हो सके तथा भौतिक पर्यावरण भी शुद्ध एवं सतुलित बना रहे।

तहसील में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 13910 हेक्टेयर है जो कि कुल भूमि का 30% से भी अधिक है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की बढ़ती

जनसंख्या तथा खाद्यान्न आपूर्ति हेतु कृषि क्षेत्र में गहनता को प्राथमिकता दी जा रही है।

#### 4.2 शस्य प्रतिरूप :

एक निश्चित अवधि में विविध फसलों के आनुपातिक निरूपण को शस्य प्रतिरूप कहते हैं। इसमें किसी समयावधि में किसी क्षेत्र में बोये गये समस्त अथवा प्रमुख फसलों का विवेचन किया जाता है। शस्य प्रतिरूप किसी निश्चित समय में विभिन्न फसलों के क्षेत्रीय अनुपात को निरूपित करता है। इससे फसलों की स्थानिक व्यवस्था को एक दूसरे के परिपेक्ष्य में समझा जा सकता है (त्रिपाठी 1991, पृष्ठ 113)। अध्ययन क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। शस्य प्रतिरूप पूर्णतः पारम्परिक परिलक्षित होता है। अध्ययन क्षेत्र में शस्य प्रतिरूप तीन भागों में विभाजित है। (1) रबी की फसलें (2) खरीफ की फसलें (3) जायद की फसलें।

रबी की फसलों में गेहूँ प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसो, तम्बाकू, शकरकन्द, अलसी, पोस्ता, आदि आते हैं। गेहूँ की बुवाई कार्तिक (नवम्बर) में होती है जिसे बैसाख (अप्रैल/मई) में काट लिया जाता है। गेहूँ अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख फसल है। जिसकी कृषि सम्पूर्ण तहसील के 50% भाग पर की जाती है। इसी प्रकार क्रमशः मटर, चना, सरसो, मसूर, फसल आते हैं जो तहसील के दोनों विकास खण्डों में बोयी जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूँ की ही बुआई होती है (चित्र संख्या 4.3)।

रबी फसलों के अन्तर्गत बोये गये समस्त क्षेत्रफल का 88.27% गेहूँ की कृषि का ही रहा है जिसमें रामनगर ब्लॉक अपने सकल कृषि क्षेत्र का 90% तथा

### तालिका क्रमांक-4.3

#### रबी के अन्तर्गत फसल वार क्षेत्र

क्र० स०	फसल का नाम	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में		तहसील भानपुर	जनपद बस्ती
		रामनगर	सल्टौवा गोपालपुर		
1	गेहूँ	10855	12050	22905	111471
2	जौ	2	2	4	137
3	चना	267	600	867	4255
4	मटर	276	820	1096	7568
5	मसूर	19	20	39	1376
6	सरसो	241	261	502	2719
7	अलसी			-	13
8	आलू	345	189	534	3676
9	तम्बाकू			-	444
10	अन्य			-	71
	योग	12005	13942	25947	

# भानपुर तहसील : रबी के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र (1998-1999)

विकासखण्ड : रामनगर



- गेहूँ
- जौ
- चना
- मटर
- मसूर
- सरसों
- अलसी
- आलू
- तम्बाकू
- अन्य

विकासखण्ड : सान्ढोवा गोपालपुर



- गेहूँ
- जौ
- चना
- मटर
- मसूर
- सरसो
- अल्सी
- आलू
- तम्बाकू
- अन्य

सल्टौवा गोपालपुर 86% क्षेत्र पर गेहूँ की कृषि करता है।

अध्ययन क्षेत्र में जौ की कृषि मात्र 4 हेक्टेयर पर की जाती है तथा उत्पादन लगभग नगण्य है। रबी की फसलों में गेहूँ के उपरान्त क्रमशः मटर, चना, आलू तथा सरसो का स्थान आता है।

सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड में 600 हेक्टेयर भूमि पर चने की कृषि की जाती है जो कि सकल फसल क्षेत्र का 4.2% है जबकि रामनगर विकास खण्ड में मात्र 2.2% क्षेत्र पर चना की कृषि की जाती है। मटर की कृषि भी सल्टौवा विकास में अधिक से अधिक 5.9% भूमि पर रामनगर विकास खण्ड में कम से कम 2.3% भूमि पर की जाती है।

इस प्रकार तुलनात्मक रूप में सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड में चना और मटर दोनों की कृषि में रामनगर विकास खण्ड से अधिक क्षेत्र पर कृषि होता है।

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में आलू का उत्पादन मात्र 2.05% क्षेत्र पर किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ भोजन में सब्जी के रूप में आलू प्रमुख है अतः इसके क्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता है।

सम्पूर्ण तहसील में तिलहन का उत्पादन बहुत कम क्षेत्र पर (1.93%) किया जाता है। तिलहन की फसलों में सरसो, तीसी एवं लाही मुख्य हैं। तिलहन की फसलों का सर्वाधिक क्षेत्र सल्टौवा गोपालपुर में है।

इस प्रकार गेहूँ की कृषि के अतिरिक्त सभी फसलों में रामनगर विकास खण्ड का क्षेत्र सल्टौवा गोपालपुर से कम है। किन्तु नहरों के विकास तथा ट्यूबवेल की उपलब्धता ने रामनगर के उत्पादन स्तर को बनाये रखा है।

## तालिका 4.4

### खरीफ के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र

क्र० स०	फसल का नाम	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में		तहसील भानपुर	जनपद बस्ती
		रामनगर	सल्टौवा गोपालपुर		
1	धान	894	12118	13012	111767
2	मक्का	7	6	13	5238
3	बाजरा	—	—	—	8
4	उर्द	18	15	33	216
5	मूग	7	10	17	75
6	मूगफली	—	—	—	8
7	गन्ना	1420	2544	3964	24055
8	हल्दी	—	—	—	—
9	अरहर	318	608	926	8908
10	तिल	—	—	—	306
11	अन्य	—	—	—	37
	योग	2664	15301	17965	



## खरीफ :

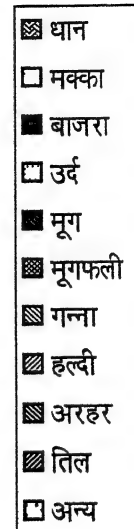
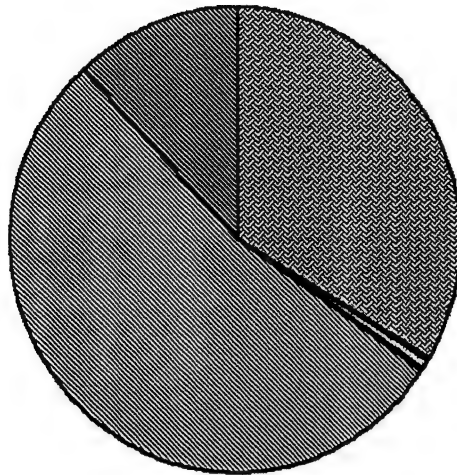
खरीफ के अन्तर्गत उगायी जाने वाली प्रमुख फसले धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा इत्यादि है। खरीफ की समस्त फसलो मे सर्वाधिक भाग धान का होता है। वर्ष 1998-99 मे भानपुर तहसील मे खरीफ फसल क्षेत्र के 74.42% भाग पर धान की कृषि की गयी। धान का सर्वाधिक क्षेत्र सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे (79.2%) पाया जाता है। वही रामनगर विकास खण्ड मे 33.5% भूमि क्षेत्र पर ही केवल धान की कृषि की जाती है। धान की कृषि क्षेत्र कम होने का कारण रामनगर विकास खण्ड मे गन्ने का अधिक कृषि क्षेत्र अधिक होना है।

फसल क्षेत्र के आधार पर द्वितीय क्रम मे प्रमुख मुद्रादायिनी फसल गन्ना है जो कि खरीफ के सकल कृषित भूमि के 22.08% भूमि पर की जाती है। जिस प्रकार सल्टौवा गोपालपुर धान उत्पादन हेतु अधिक क्षेत्र पर कृषि करता है। उसी प्रकार रामनगर मे 53.3 भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है। यह मौसमी फसल न होकर वर्षपर्यन्त उत्पादित होने वाली फसल है। अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी गन्ने की कृषि के लिये उपयुक्त है। जलवायु का विनाशकारी प्रभाव, बाढ़, सूखा तथा ओलावृष्टि का भी आनुपातिक दृष्टि से इस पर कम प्रभाव पडता है। किसी क्षेत्र मे (खेत) एक बार गन्ना बो देने पर तीन चार वर्षो तक लगातार अच्छा उत्पादन लिया जाता है (चित्र संख्या 4.4)।

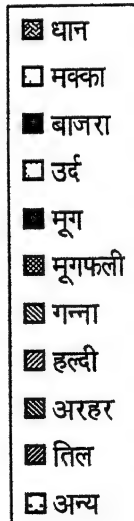
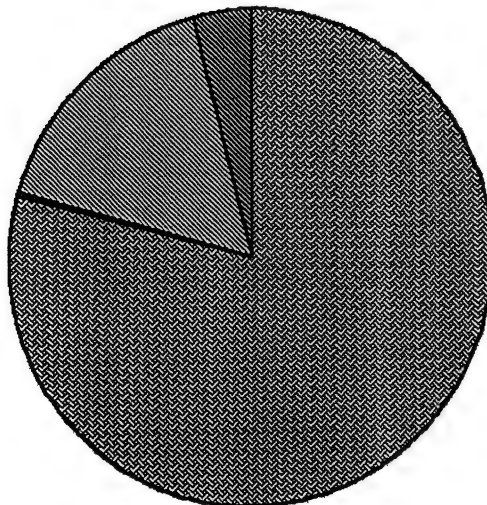
गन्ने की कटाई के उपरान्त पुन गन्ने की जड से नयी फसल उग आती है जिसे स्थानीय भाषा मे 'पेडी' कहा जाता है। इस प्रकार एक बार गन्ना बो देने के बाद 3.4 वर्ष तक पेडी होती रहती है और इससे कृषक को लाभ अधिक होता है।

# भानपुर तहसील : खरीफ के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र (1998-1999)

विकास खण्ड : रामनगर



विकास खण्ड : सल्टौवागोपालपुर



अध्ययन क्षेत्र में कोई चीनी मिल नहीं है लेकिन बस्ती शुगर मिल की अवस्थित इस क्षेत्र की गन्ने की कृषि के लिये वरदान सिद्ध हुई है।

खरीफ की फसलों में अरहर का दलहन के रूप में प्रमुख स्थान है। सम्पूर्ण तहसील में 55% भाग पर अरहर की कृषि की जाती है। सल्टौवा गोपालपुर में 608 हेक्टेयर तथा रामनगर में 318 (हेक्टेयर) भूमि पर अरहर की कृषि की जाती है। अन्य फसलों में चारा हेतु उगायी जाने वाली फसले, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, हल्दी, तिल आदि आती है। जिनका उत्पादन नगण्य है (तालिका क्रमांक-43)।

#### 4.3 शस्य-क्रम :

शस्य क्रम का अभिप्राय किसी क्षेत्र में उत्पादित फसलों की श्रेणी-बद्धता से है। इसमें क्षेत्र के आधार पर प्रत्येक फसल का समस्त बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत ज्ञात करके उनको अवरोही क्रम में दर्शाया जाता है जिससे प्रत्येक फसल का सापेक्षिक महत्व ज्ञात होता है।

भानपुर तहसील में शस्य क्रम में प्रथम स्थान गेहूँ का है। द्वितीय स्थान धान तथा तृतीय स्थान गन्ना का है। चतुर्थ तथा पंचम स्थान क्रमशः अरहर और मटर का है। अध्ययन क्षेत्र में रामनगर में गेहूँ प्रथम क्रम पर है जबकि धान में सल्टौवा गोपालपुर प्रथम क्रम में है वही दोनों विकास खण्ड गन्ना में द्वितीय क्रम पर है। अरहर में सल्टौवा तृतीय क्रम में जबकि मटर में चतुर्थ क्रम में आता है। आलू पंचम क्रम में आता है।

#### 4.4 अध्ययन क्षेत्र में कृषि की आधारभूत सुविधाओं की स्थिति :

कृषि के समुचित विकास के लिये, सिचाई, उर्वरक, पशु ससाधनो कीटनाशक दवाओ, विकसित कृषि यन्त्रो आदि की आवश्यकता होती है। इन सुविधाओ की उपलब्धता रहने पर कम उपजाऊ मृदा मे भी अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। इन सुविधाओ के अभाव मे बहुत अच्छी मृदा मे भी उत्पादन कम होता है।

##### 4.4.1 सिचाई :

जल जीवन का आधार है। जल मानव जीवन तथा समस्त जीवधारियो और वनस्पतियो के लिये परमावश्यक आधारभूत प्राकृतिक ससाधन है। देश की अर्थव्यवस्था मे भू-जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भू-जल का दोहन सीधे उपभोक्ताओ के नियन्त्रण मे होने से यह विभिन्न उपयोगो के लिये प्राथमिक साधन बन गया है। भू-जल ने पेयजल तथा सिचाई के साधन के रूप मे महत्व अर्जित किया है। वर्तमान मे सिचाई मे इसका योगदान लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रो मे, घरेलू कार्य के लिये 80% तथा शहरी व औद्योगिक क्षेत्रो हेतु 50% अनुमोदित है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद मे भू-जल का योगदान 9% है।

जनसख्या वृद्धि के कारण अनियन्त्रित और अन्धाधुन्ध इस्तेमाल तथा सरक्षण के अभाव मे भू-जल स्तर मे चार मीटर से अधिक गिरावट आयी है।

देश मे औसतन 4000 अरब घनमी० वर्षा एक वर्ष मे होती है। इसमे हिमपात भी शामिल है। इसमे से 3000 अरब घन मी० वर्षा मानसून के दौरान होती है। देश की विभिन्न नदियो मे औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 अरब घन मी०

ऑका गया है जिसमे से यदि उपयुक्त भण्डारण सुविधाये उपलब्ध कराई जाए तो केवल 690 अरब घन मी० सतही जल ही उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 432 अरब घन मी० भू-जल ससाधन है। इस प्रकार देश में कुल 1,142 अरब घनमी० जल उपयोग किये जाने योग्य है, जिसमे से वर्तमान में सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा तथा अन्य उद्देश्य के लिये 605 अरब घन मी० पानी का उपयोग किया जा रहा है।

वर्तमान में देश में कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता 177 अरब घनमी है। केन्द्रीय जल आयोग के आकलन के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता घट रही है। वर्ष 1951 में 5,177 घन मी उपलब्धता थी जो वर्तमान में घटकर 1,820 घन मी रह गयी है तथा वर्ष 2025 तक यह घटकर 1,820 घन मी रह गयी है तथा वर्ष 2025 तक यह घटकर 1,341 और 2050 तक घटकर 1140 तक जाने का अनुमान है (कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, 2002, पृ० 30)।

देश का लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्रफल और 76% जनसंख्या पूर्णतया जल की तंगी झेल रही है अर्थात् वार्षिक जल उपलब्धता 500 घन मी० है। इस प्रकार भूजल का आवश्यकता से ज्यादा दोहन किया गया है जिससे अब अर्थतन्त्र के प्रमुख आधार कृषि के लिये भी समुचित मात्रा में जल उपलब्ध करा पाना कठिन प्रतीत हो रहा है। यहाँ तक कि पेयजल की समस्या भी पैदा हो गयी है। जनसंख्या बढ़ रही है। जल वृष्टि अनिश्चित हो रही है। भू-जल स्तर घट रहा है, जल की मात्रा में वृद्धि करना सम्भव नहीं है अतः उपलब्ध जल का सही प्रबन्ध ही उचित विकल्प है। इस स्थिति में सरकार द्वारा हाल ही में अपनायी गयी

# TAHSIL BHANPUR SOURCE OF IRRIGATION

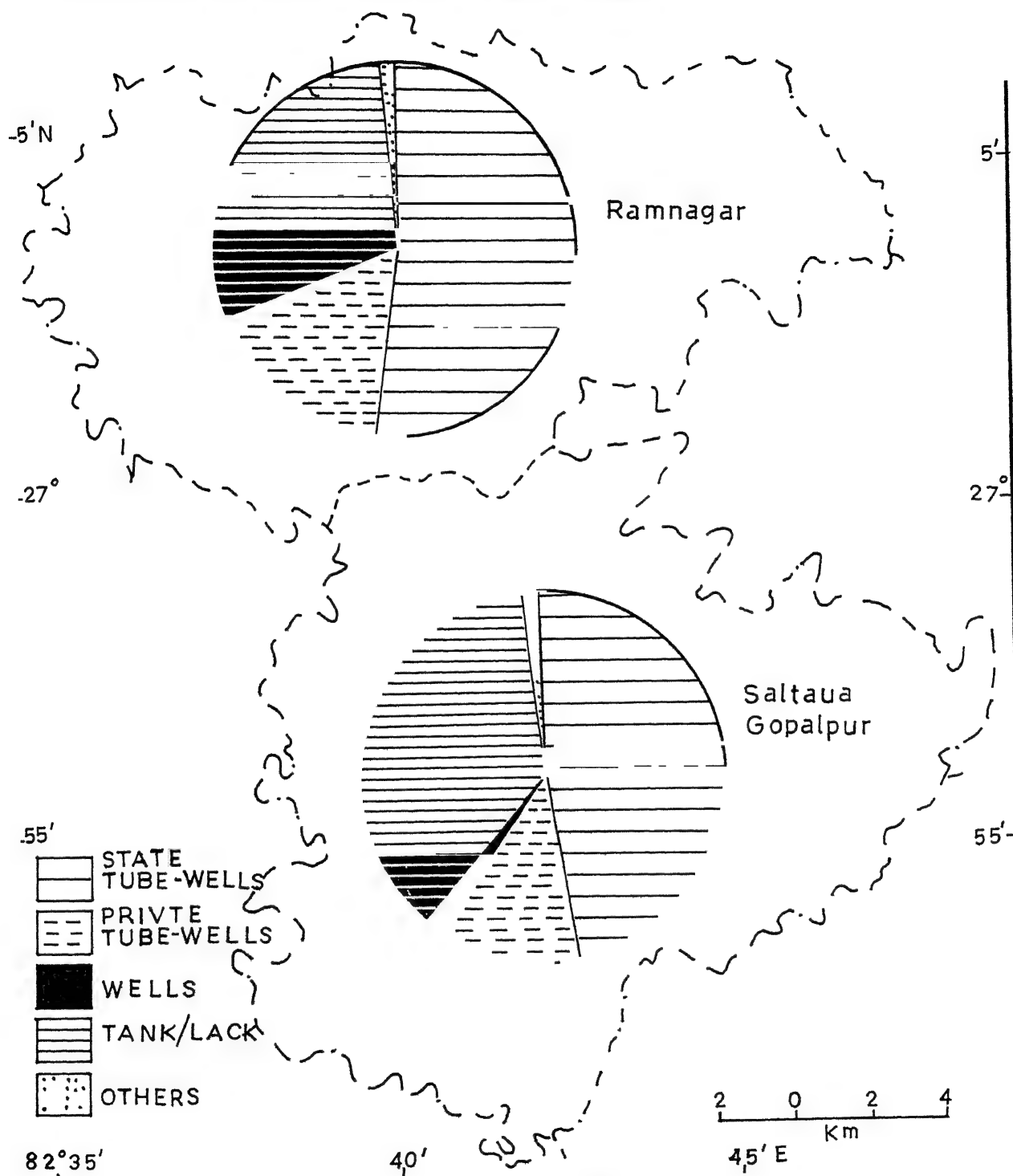


Fig.4.5

## तालिका क्रमांक-4.5

भानपुर तहसील : स्रोतानुसार सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)  
(1999-2000)

क्र० स०	श्रोत	विकास खण्ड के नाम			
		रामनगर	प्रतिशत	सल्टौआ गोपालपुर	प्रतिशत
1	नहरे	—	—	—	—
2	नलकूप — राजकीय	5340	52 7	5932	47 6
3	नलकूप — निजी	1572	15 5	1580	12 7
4	कूप	70	7	128	1 1
5	तालाब/झील/पोखरा	3052	30 1	4630	37 4
6	अन्य	106	1 1	130	1 2
	योग	10140		12450	

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 2001 के संगठित।

सशोधित जलनीति, 2002 सही समय पर उठाया गया कदम है।

इस नीति में ससाधनो को सरक्षित करने के साथ-साथ प्रदूषण समाप्त करने, जल परिवहन मार्ग को पक्का करने, तालाबो सहित वर्तमान प्रणालियो के आधुनिकीकरण तथा उसकी पुर्नस्थापना करने की व्यवस्था (मानचित्र सख्या 45)।

#### 4 4 1 (अ) नहर

अध्ययन क्षेत्र में सिचाई साधनो एव स्रोतो पर दृष्टि डाला जाय तो इनकी उपलब्धता स्वतः स्पष्ट हो जायेगी। पूरे जनपद में नहर की लम्बाई 10 किमी० मात्र बहादुरपुर विकास खण्ड में है। सरयू नहर उपखण्ड परियोजना की नहरो का निर्माण अध्ययन क्षेत्र में किया जा रहा है। पूरे तहसील में नहरो का जाल बिछाया जा रहा है। सभी नहरे निमार्णाधीन हैं। बस्ती शाखा तथा खलीलाबाद शाखा नहरो की मुख्य शाखाये हैं। रामनगर विकास खण्ड में अपेक्षाकृत नहरो का अधिक निर्माण हुआ है। कोठिला खास न्याय पचायत तथा परसा-दमया न्यायपचायत में नहर निर्माण हेतु भूमि की पैमाइश कर ली गयी है तथा निर्माण कार्य भी चल रहा है (मानचित्र सख्या 46)।

#### (ब) नलकूप :

भूमिगत जल को किसी यान्त्रिक मशीन की सहायता से धरातल पर लाने की क्रिया नलकूप द्वारा की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में दो प्रकार के नलकूप हैं। राजकीय नलकूप तथा निजी नलकूप। पूरे जनपद के 527 नलकूपों में भानपुर तहसील में 120 राजकीय नलकूप हैं। जिसमें सर्वाधिक 73 नलकूप रामनगर विकास खण्ड में हैं। क्षेत्र में कृषि भूमि की सर्वाधिक सिचाई निजी नलकूपों द्वारा होती है। राजकीय नलकूपों की क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार प्रचुर संख्या नहीं है।



82°35'

40

45' E

# TAHSIL BHANPUR DISTRICT BASTI DISTRIBUTION OF CANALS AND GOVERNMENT TUBE-WELLS

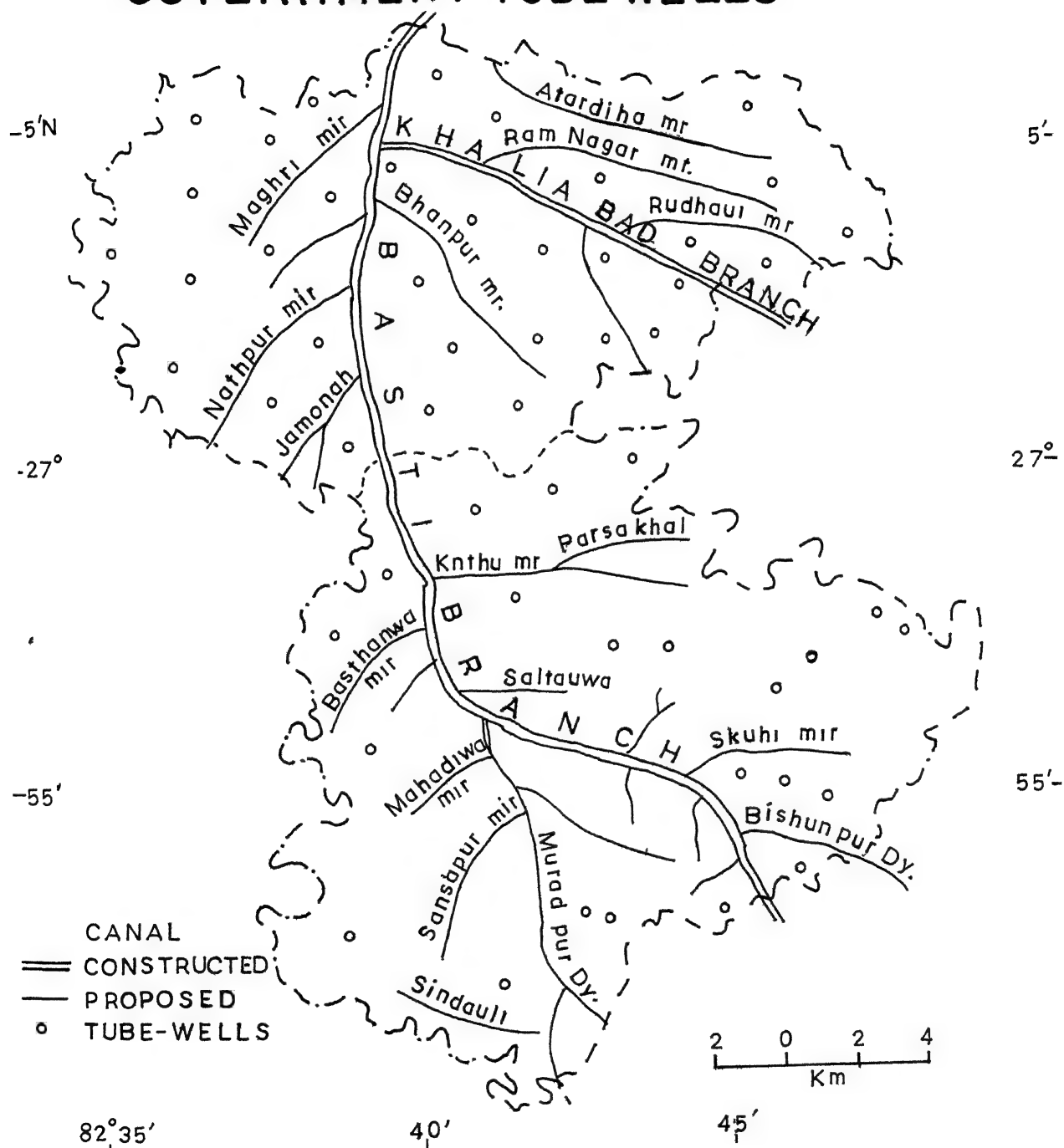


Fig. 4-6

(स) कुएँ :

तहसील में सिंचाई हेतु कूप-जल का प्रयोग चरखी, रहट, ढेकुली आदि के माध्यम से किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में पक्के कुएँ की संख्या 1220 है जो कि जनपद की संख्या 7675 का लगभग 18% प्रतिशत है। रहटों की संख्या 918 है। भूस्तरीय पम्पसेटों की संख्या अध्ययन क्षेत्र में 76 है। पूरे जनपद में बोरिंग पर लगे पम्पसेटों की संख्या 1998-99 में 1,18,128 थी जो बढ़कर 2000-01 में 1,21,491 हो गयी। जिसमें पदानुक्रम के आधार पर एक दृष्टि जनपद के समस्त विकास खण्डों पर रखा जाय तो तहसील का रामनगर विकास खण्ड 10,334 पम्पसेटों के साथ विकास खण्ड रुघौली तथा विक्रम जोत के बाद है। तहसील में 2000-01 में 19,675 पम्पसेट हैं जबकि निजी नलकूपों को देखा जाय तो पूरे जनपद में 5,843 है जिसमें तहसील में इनकी संख्या 738 है।

(ढ) तालाब एवं अन्य साधन :

तहसील के सिंचाई साधनों में नलकूप की तथा कुएँ की उपलब्धता के बावजूद भी तालाब द्वारा सिंचाई सल्टौआ विकास खण्ड के कई न्यायपचायतों में की जाती है। कृषि श्रमिक या मजदूर वर्ग अपने फसल की सिंचाई समीप स्थित तालाब से ही करते हैं। तालाबों से जल 'बेड़ी' द्वारा निकाला जाता है 'बेड़ी' तसले के आकार की बाँस निर्मित एक बड़ी सरचना होती है जिसे स्थानीय भाषा में 'दौरी' या 'दोगला' कहा जाता है। इसके दो विपरीत किनारों पर दो-दो रस्सियाँ लगाकर दो व्यक्ति मिलकर तालाब से जल निकालते हैं। चूँकि अध्ययन क्षेत्र में नदियों की कमी है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की कृषि सिंचाई में नदियों तथा नहरों का कम योगदान है। नलकूप तथा कुएँ वरदान साबित हो रहे हैं।

## तालिका क्रमांक-4.6

### तहसील भानपुर : सिंचाई साधन का विवरण (1999-2000)

क्र० स०	नाम साधन	इकाई	तहसील	जनपद उपलब्ध मात्रा
1	नहरो की लम्बाई	किमी	—	10
2	राजकीय नलकूप	सख्या	120	527
3	निजी नलकूप	"	738	5733
4	पक्का कूप	"	1220	7675
5	भूस्तरीय स्रोतो पर लगे पम्पसेट	"	76	488
6	पम्पिंग सेट	"	19675	119041
7	अन्य	"	918	5529

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती, वर्ष 2000 एवं  
जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, जनपद बस्ती, 2000-2001 से संगणित।

#### 4 4 2 उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं

फसलो के विकास के लिये उर्वरक उतना ही आवश्यक है जितना फसलो को जीवित रहने के लिये सिचाई। भानपुर तहसील में सर्वाधिक प्रयोग नाइट्रोजन खाद का होता है। द्वितीय स्थान फास्फोरस का है। पोटैश का स्थान तृतीय के साथ-साथ उत्तरोत्तर घट रहा है। तहसील में प्रयुक्त उर्वरको का लगभग 80% नाइट्रोजन, 17.50% फास्फोरस तथा 2.50% पोटैश का है। कृषि में उर्वरको का प्रयोग प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जो भूमि उर्वरता एवं अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये आवश्यक भी है। उर्वरको के प्रयोग में विगत दशक में सर्वाधिक वृद्धि सल्टौवा गोपालपुर में हुई है। 1988-89 में नाइट्रोजन उपयोग की मात्रा 1937 मीटरी टन थी जो कि 1998-99 में 2930 पहुँच गयी। जबकि रामनगर विकास खण्ड में पोटैश उर्वरक के प्रयोग में कमी आयी है जो कि 90 से 78 मीटरी टन हो गयी है।

इस तहसील के रामनगर विकास खण्ड में उर्वरक प्रयोग की दर निरन्तर बढ़ती जा रही है। रामनगर विकास खण्ड में जहाँ पर उपयोग 1988-89 में 3,106 मीटरी टन था, जो कि 1999-00 में बढ़कर 4,201 मीटरी टन हो गया है। वहीं सल्टौवा गोपालपुर में यह दृष्टि 1988-89 की अपेक्षा 1999-00 में 2,519 मीटरी टन से 3,820 मीटरी टन पहुँच गया है (मानचित्र संख्या 47)।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में उर्वरक पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पारम्परिक रूप से कृषक अब कम्पोस्ट खाद का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। रासायनिक खादों का प्रति हेक्टेयर उपभोग तहसील में धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

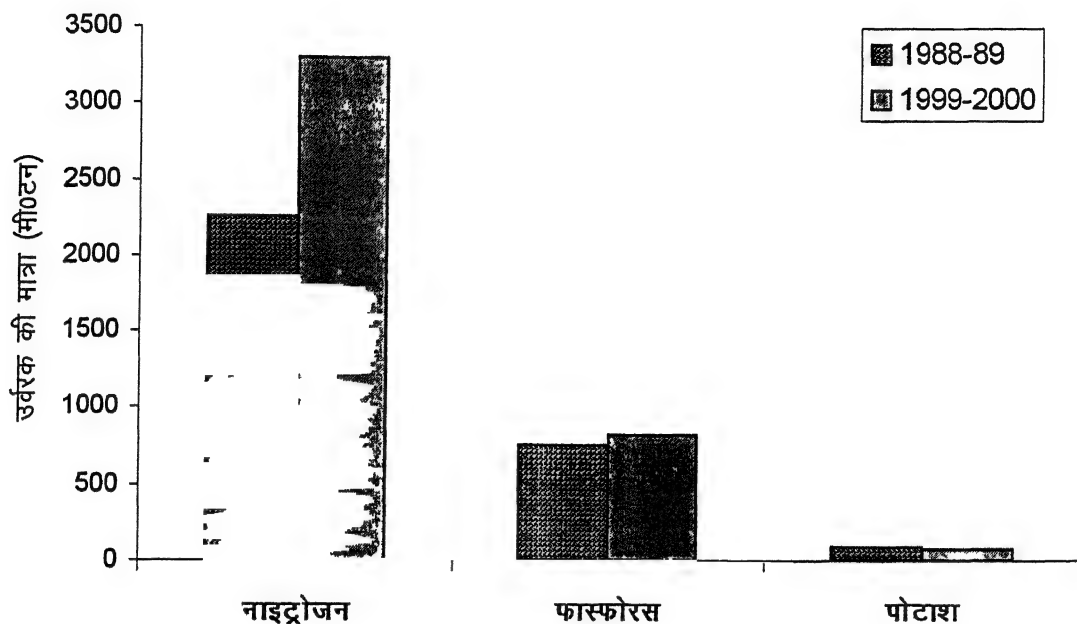
तालिका क्रमांक-4.7

भानपुर तहसील : उर्वरक वितरण (मी०टन०)

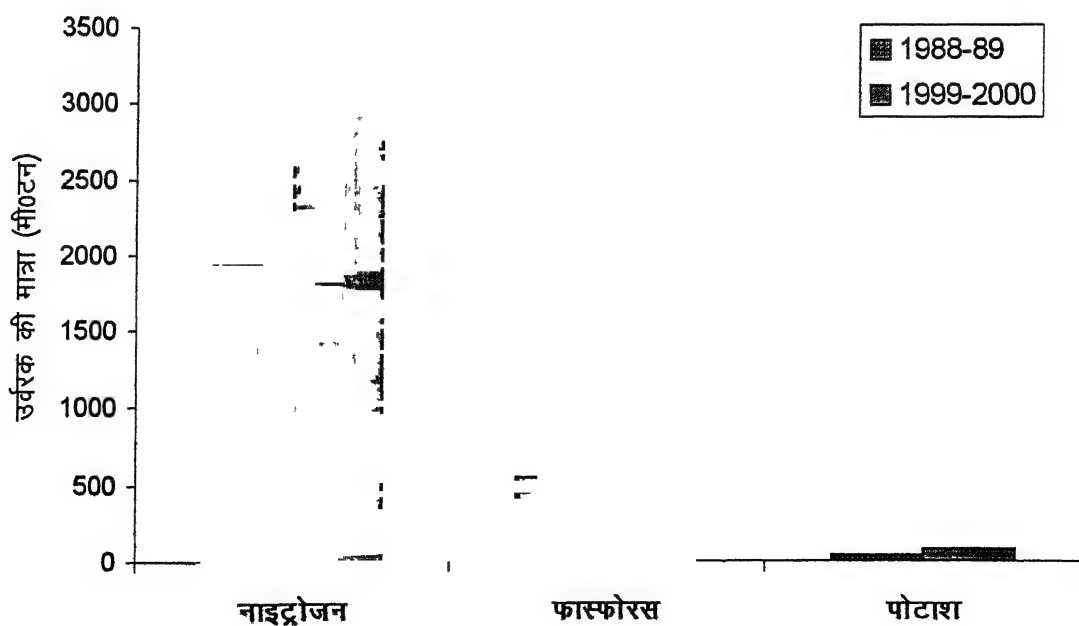
उर्वरक	रामनगर		सल्टौवा गोपालपुर	
	1988-89	1999-2000	1988-89	1999-2000
नाइट्रोजन	2257	3298	1937	2930
फास्फोरस	759	825	549	816
पोटाश	90	78	33	74
योग	3106	4201	2519	3820

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती, वर्ष 1990 एवं वर्ष 2000

## भानपुर तहसील : उर्वरक वितरण विकासखण्ड : रामनगर



## विकासखण्ड : सल्टीवा गोपालपुर



फसलो को रोगो से बचाने के लिये कीटनाशक दवाओं का प्रयोग आवश्यक है। इसके अभाव में फसलो के रोगग्रस्त होकर पूर्णतः नष्ट होने की सम्भावना रहती है। कीटनाशक दवाओं की प्राप्ति विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कार्यालयों एवं व्यक्तिगत विक्रेताओं के यहाँ से हो जाती है।

जनपद में सतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए 8436 नमूनों का विश्लेषण कराते हुये विभिन्न फसलो हेतु उर्वरक प्रयोग की सस्तुतिया किसानों को समय से उपलब्ध कराये गये। जनपद में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये बीज संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन प्रजातियों के आधारीय प्रमाणित बीजों के संवर्धन हेतु जनपद में राजकीय कृषि क्षेत्र सिसई, (हरैया तहसील) एवं अमरडीहा में स्थापित है, अमरडीहा भानपुर तहसील के रामनगर विकास खण्ड में अवस्थित है।

फसल सुरक्षा उपायों के सफल संचालन हेतु विकास खण्डों में कृषि रक्षा इकाई की स्थापना की गयी है। यदि अध्ययन क्षेत्र के समग्र भाग का अवलोकन किया जाय तो (2000-01 तक) स्थिति बहुत ही खराब मानी जायेगी। तहसील में मात्र दो बीज गोदाम केन्द्र हैं, जिनकी क्षमता 200 टन है ग्रामीण गोदाम की संख्या रामनगर में 6 तथा सल्टौवा गोपालपुर में 10 है। तहसील में कीटनाशक डिपो की संख्या 2 है। बीज वृद्धि के फार्म मात्र केवल एक ही अमरडीहा में है जो रामनगर विकास खण्ड में है। शीत भण्डार की एक भी संख्या अध्ययन क्षेत्र में नहीं है। रामनगर में एक एग्री कृषि सेवा केन्द्र है। कृषि उत्पादन मण्डी समिति तो पूरे जनपद में तो 6 है लेकिन इस तहसील में एक भी नहीं है।

#### 4.4.3 कृषि यन्त्र एवं उपकरण :

पशुगणना वर्ष 1988 के अनुसार तहसील में लकड़ी के हलों की संख्या

12,971 तथा लोहे के हलो की संख्या 6,937 थी, उन्नत हल तथा कल्टीवेटर 2,360 थे उन्नत थ्रेसिंग मशीन 1988 थी, ट्रैक्टरों की संख्या 394 थी यही संख्या पशुगणना वर्ष 1997 में लकड़ी के हलो की 10,627 रही जो कि कृषि के पारम्परिक तकनीक से हटकर आधुनिक कृषि यन्त्रों के प्रति झुकाव को इंगित करता है। लोहे के हलो की संख्या 5,430 ही रही। उन्नत हैरो तथा कल्टीवेटर में भी कमी आयी जबकि थ्रेसिंग मशीन की संख्या बढ़कर 3,294 हो गयी। ट्रैक्टरों की संख्या में भी काफी वृद्धि परिलक्षित होती है। इसकी संख्या लगभग 672 है। जोकि 50% की वृद्धि को इंगित करता है। कृषि के सम्यक विकास तथा कृषि को उद्योग के स्तर तक लाने में जिन कृषि यन्त्रों की आवश्यकता किसी क्षेत्र को होती है, उसका अभाव पाया जाता है। उन्नत किस्म के बुवाई यन्त्रों तथा कम्बाइन मशीनों की कमी कृषि के सम्पूर्ण विकास में बाधक है। जिसका प्रभाव अध्ययन क्षेत्र में देखा जा सकता है।

#### 4.4.4 पशु संसाधन :

पशुपालन कृषि का एक प्रधान एवं अपरिहार्य अंग है। इसकी महत्ता को देखते हुये हमारे देश में जनगणना की भाँति पशुगणना का कार्य भी प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के लिये पशु संसाधन के रूप में प्रमुखतया बैल का प्रयोग किया जाता है। कृषि कर्म मुख्यतः बैल होने के कारण ट्रैक्टरों की बहुलता के बाद भी क्षेत्र में बैलों की संख्या बढ़ी है। अध्ययन क्षेत्र के बडोखर नामक गाव के पास पशु मेला (बाजार) प्रत्येक मंगलवार को लगता है। जहाँ से कृषि उपयोगी पशु खरीदे एवं बेचे जाते हैं।



**तालिका क्रमांक-4.8**  
**भानपुर तहसील : पशुसंसाधन**  
**(पशुओं की संख्या)**

क्र० स०	पशु प्रजातियों	विकास खण्ड		तहसील
		रामनगर	सल्टौवा गोपालपुर	भानपुर
1	गोजातीय	22600	19706	42306
2	महर्षि जातीय	11498	15115	26613
3	भेड	1966	413	2379
4	बकरिया	13203	10788	23991
5	घोडा एव टट्टू	35	25	60
6	सुअर	1524	2013	3537
	अन्य पशु	50941	48170	99111

स्रोत : जनपदीय सामाजार्थिक समीक्षा 2000-2001 तथा  
साख्यकीय पत्रिका जनपद, बस्ती 2000 से सगणित

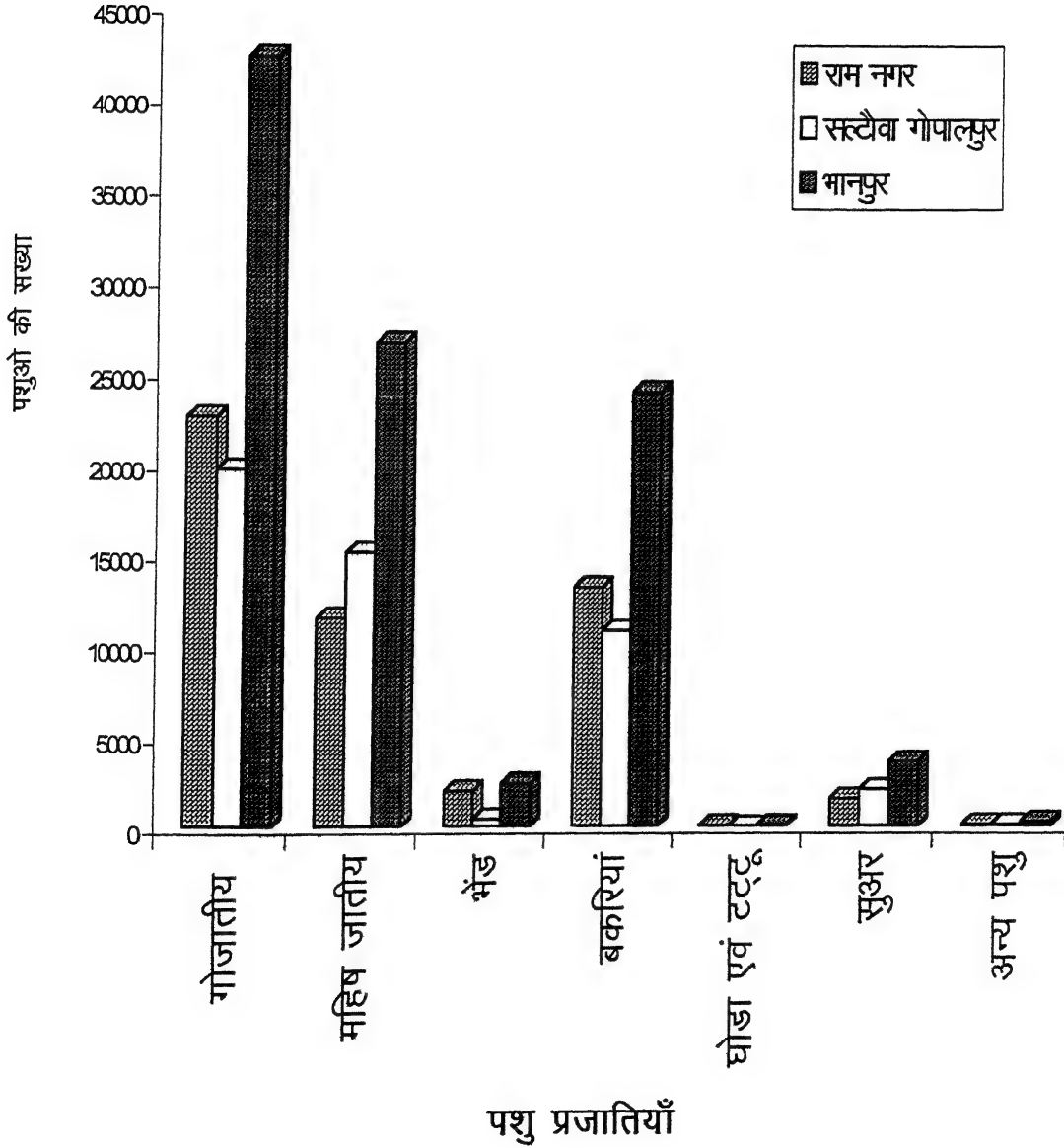
पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन का सर्वांगीण विकास करने हेतु पशु चिकित्सा, रोगनियन्त्रण, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। पशुपालन विभाग अपनी योजनाओं द्वारा कृषकों के आर्थिक विकास के लिये सतत प्रयासरत है।

तहसील में पशुधन विभाग द्वारा रोगी पशुओं की चिकित्सा, नर तथा छुट्टा पशुओं का बध्नाकरण विभिन्न सक्रामक रोगों से बचाव हेतु निरोधात्मक टीकाकरण, दुधारु पशुओं में प्रजाति संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से नस्ल सुधार, बरबरी बकरो द्वारा नस्ल सुधार, कुक्कुट पालकों को कुक्कुट उपलब्ध कराने का कार्य, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत प्रत्येक विकास खण्डों में ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह गठित कराकर उन्हें बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर भैंस, गाय, बकरी, सूअर तथा कुक्कुट इकाई की स्थापना का कार्य कराया जाता है।

#### 4.4.5 पशु चिकित्सालय एवं अन्य सेवाएँ :

1989-90 में तहसील में कुल दो पशु चिकित्सालय थे। पशुधन विकास केन्द्र की संख्या 6 थी। चार पशु चिकित्सालय केन्द्र हैं। पशुधन विकास केन्द्र में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की संख्या 1 एवं इसकी उपकेन्द्र की संख्या 3 है जिसमें सल्टौवा गोपालपुर में केवल एक केन्द्र है तथा दो उपकेन्द्र रामनगर में हैं। पशु प्रजनन एवं भेड़ विकास केन्द्र एक भी नहीं है। तहसील में वर्तमान समय में कुल पशुओं की संख्या 1,30,951 है। जिसमें गोजातीय 42,306 महीष जातीय 26,613, भेड़ 2376, बकरियाँ 23991, घोड़ा एवं टट्टू 60, सुअर 3,537 तथा अन्य पशु 225 हैं (चित्र संख्या 4.8)।

## भानपुर तहसील : पशु संसाधन (2000-2001)



पशुओं की दशा सुधारने एवं उन्हें आर्थिक उपादेय बनाने में पशुचारा विकास कार्यक्रम का विशेष महत्व है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उन्नतशील चारा जैसे एम0पी0चरी, जई, बरसीम तथा लोबिया आदि की बीज सस्ते दरो पर उपलब्ध कराये जाते हैं। इनकी कमी का दुग्ध व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

#### 4.5. कृषि में अभिनव विकास की प्रवृत्तियाँ :

मानव की बढ़ती आवश्यकता, रूचि परिवर्तन, नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों आदि कारणों से कृषि की प्रवृत्ति में परिवर्तन होता रहता है। अध्ययन क्षेत्र की कृषि में भी विगत दशकों में कुछ परिवर्तन हुये हैं तथा कुछ प्राचीन परम्पराएँ आज भी विद्यमान हैं।

##### 4.5.1 वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि :

अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। धान की कृषि 74% क्षेत्र पर तथा गेहूँ की 88% क्षेत्र पर की जाती है। गन्ना का उत्पादन 22.08% क्षेत्र पर किया जाता है। किन्तु जनाधिक्य के कारण यह स्थानीय माग की पूर्ति से अतिरिक्त नहीं हो पाता, गन्ना की कृषि कम श्रम-शक्ति एवं कम लागत से की जा सकती है। फलस्वरूप गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। जोकि 1988-89 में तहसील के 2851 हेक्टेयर से 1998-99 में 3964 हेक्टेयर हो गया है। क्षेत्र के कृषकों के आय का मुख्य साधन होने के कारण इसके क्षेत्रफल तथा प्रतिहेक्टेयर उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

#### 4.5.2. बागवानी में वृद्धि .

वन विभाग का प्रमुख दायित्व जिले में वन क्षेत्रों का संरक्षण, संवर्धन विकास एवं विस्तार है। ग्रामीण क्षेत्रों में हरे वृक्षों का कटान, आरा मशीनों का संचालन वनोपजन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। तहसील में यूकेलिप्टस के वृक्ष सर्वाधिक संख्या में लगाये जा रहे थे लेकिन पारिस्थितिक असंतुलन, मृदा उर्वरता में कमी तथा ऊसरीकरण की भयावह स्थिति होने की आशंका से इस वृक्ष पर रोक लगा दिया गया है। कृषि कृत क्षेत्रों में बबूल, अर्जुन, आम, अमरुद, केला, पपीता, नीबू, कटहल आदि के वृक्ष अधिक संख्या में लगाये जा रहे हैं। वृक्षों से पर्यावरण की स्वच्छता बनी रहती है तथा फलों एवं लकड़ियों से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास तथा योजनाएँ वृक्षारोपण के लिये चलायी जा रही हैं।

#### 4.5.3. नलकूपों की संख्या में वृद्धि .

नहरों में जल की अनुपलब्धता, नदी जलाभाव, वर्षा की अनिश्चितता, राजकीय नलकूपों की कमी, सामाजिक एवं पारिवारिक विघटन तथा कृषि क्षेत्र का विस्तार आदि कारणों से अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत नलकूपों की संख्या में तीव्रगति से वृद्धि हो रही है। 1989-90 में तहसील में कुल निजी नलकूपों की संख्या 1054 थी जोकि 1999-2000 में बढ़कर 1572 हो गयी। सूखे की स्थिति तथा खाद्यान्न समस्या ने कृषकों को सिंचाई साधन में आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रोत्साहित किया है।

#### 4.5.2. रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग :

कम्पोस्ट खाद तथा पशुओं के गोबर की खाद के प्रयोग में निरन्तर कमी

हो रही है। दो तीन दशक पूर्व फसलो की वृद्धि के लिये खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग सर्वाधिक 95% होता था। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिये कृषक, खेतों में बड़ी संख्या में भेड़ रूकवाते थे, जिनके शरीर से प्रसारित तत्वों से उर्वराशक्ति बढ़ती है किन्तु वर्तमान समय में स्थिति पूर्णतः विपरीत हो गयी है। उर्वरकों के प्रयोग में 95% भाग रसायनिक उर्वरकों के रूप में होता है।

#### 4 5.5 कृषि का यन्त्रीकरण :

कृषि में यन्त्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कृषि श्रमिकों की संख्या में कमी, बढ़ती मजदूरी, आधुनिक कृषि यन्त्रों द्वारा कम समय में अधिक एवं सुव्यवस्थित कार्य, जैसे अन्यान्य कारण हैं। बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति अध्ययन क्षेत्र में सुलभ रोजगार से पूर्ण नहीं हो पाती है। परिणामस्वरूप नवयुवा वर्ग (15-35 आयु वर्ग) सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले श्रमिक, धनार्जन हेतु दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, पंजाब, राजस्थान आदि अन्य औद्योगिक नगरों में चले जाते हैं। वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में उनकी संख्या अधिक है जिनकी कार्यक्षमता कम होती है। जिनमें बच्चे तथा वृद्ध वर्ग आते हैं। अध्ययन क्षेत्र में निजी सर्वेक्षण के दौरान यह देखने को मिला कि युवा वर्ग जो हाईस्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है और जीविका के लिये कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य साधन भी नहीं है तो वे अपने कृषि भूमि में कृषि कर्म करना अपमान समझते हैं तथा कृषि मजदूरी का कम होना भी इनके प्रवास का प्रमुख कारण है। ट्रैक्टर सहित अनेक आधुनिक कृषि यन्त्र श्रमिक कमी को पूरा कर रहे हैं। अतः कृषि यन्त्रों द्वारा कम व्यय होने से कृषि में यन्त्रीकरण बढ़ रहा है।

#### 4 5.6 कृषि जोत आकार में ह्रास :

कृषि गणना 1995-96 के अनुसार तहसील में सर्वाधिक जोत वर्ग सख्या 1 हेक्टेयर से कम रही जो कि तालिका क्रमांक 49 से स्पष्ट होता है, कि तहसील में लगभग 90% जोते 7 हेक्टेयर के अन्तर्गत आती है। इसके अन्तर्गत 58% क्षेत्र है जोतो की सख्या में गत, कृषि गणना में कमी आयी है जो यह तथ्य दर्शाता है कि जनसख्या का झुकाव धीरे-धीरे कृषि से हटकर अन्य उद्योग-धन्धों की तरफ अग्रसर हो रहा है।

#### 4 6 कृषि समस्याएँ :

कृषि का अभीष्ट विकास अभी तक अध्ययन क्षेत्र में नहीं हो पाया है। इसके प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों कारक उत्तरदायी हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं।

##### 4.6.1. मौसमी परिवर्तन :

अध्ययन क्षेत्र की जलवायु पूर्णतः मानसूनी है। यहाँ का मौसम पूर्णतः अनिश्चित रहता है। वर्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता है कभी मानसून आने के पूर्व ही काफी वर्षा हो जाती है तो कभी फसल सूख जाने के बाद होती है। फसलीय समय पर वर्षा-जल नहीं प्राप्त हो पाता है। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि या सूखा तथा पाला से कृषि को व्यापक हानि होती है। जिसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

##### 4.6.2. भूक्षरण :

भूमि का ढाल, मृदा संरचना, वर्षा की मात्रा, अपवाह प्रणाली, तथा पवन प्रवाह जैसे कई कारक हैं। जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी मुलायम होने तथा उचित ढग से मेढबन्दी न

## तालिका क्रमांक-4.9

### भानपुर तहसील

#### क्रियात्मक भूमि जोत का विवरण 95-96

क्र०स०	जोत वर्ग	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	1 हेक्टेयर	101605	30865
2	1-2 हेक्टेयर	7528	10369
3	2-4 हेक्टेयर	3031	7636
4	4-10 हेक्टेयर	510	3137
5	10 से अधिक	32	421
	<b>कुल</b>	<b>112706</b>	<b>52428</b>



करने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण बढ़ रहा है। मृदा की ऊपरी परत ही फसलो के विकास के लिये महत्वपूर्ण होती है जोकि भू-जैविकीय ससाधनो से परिपूर्ण होती है।

#### 4 6.3. अव्यवस्थित विद्युत आपूर्ति :

राजकीय नलकूप, निजी नलकूप अध्ययन क्षेत्र की सिचाई के प्रमुख आधार है। नलकूपो द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रो पर सिचाई की जाती है। इजनों (डीजल) की तुलना मे तहसील मे विद्युतशक्ति चालित नलकूपो का बाहुल्य है। चूकि विद्युत चालित नलकूप तहसील के सिचाई के आधार है परन्तु प्राय अव्यवस्थित रहने वाली विद्युत-आपूर्ति इस आधार को ही पगु बना देती है।

#### 4.6.4. अज्ञानता एवं निर्धनता

अधिकांश ग्रामीण वासी निरक्षर अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े है जिसके कारण उन्हें नूतन वैज्ञानिक कृषि प्रविधियो एवं सरकारी सुविधाओ, योजनाओ का पूर्ण ज्ञान नही हो पाता है। अज्ञानतावश वे प्रयत्नशील भी नही रहते। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार तहसील की 62.12% जनसंख्या अशिक्षित है। कुछ शिक्षित व जागरूक कृषक यदि आधुनिक कृषि यन्त्रो की जानकारी होने पर उनको क्रय करना चाहते है तो निर्धनता उनके सामने समस्या बन जाती है। इस प्रकार कृषको की कम साक्षरता एवं गरीबी, वर्तमान समय मे अध्ययन क्षेत्र के कृषि विकास मे अवरोधक बनी हुई है।

#### 4 6.5. कृषि-उत्पाद विपणन एवं कृषि-ऋण :

31 मार्च 2001 की स्थिति तक तहसील मे कृषि ऋण सहकारी समितियों की संख्या 15 है जिनमें 6 रामनगर तथा 9 सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे

है। सदस्यों की कुल संख्या 28937 है। जिसमें रामनगर 15,468 तथा सल्टौवा गोपालपुर में 13,469 है। अशपूजी हजार रुपये में कुल 3,432 है, जिसमें 1,416 रामनगर तथा 2,016 सल्टौवा गोपालपुर का है। कार्यशील पूजी 15,739 हजार रुपये हैं। जमा की हुयी धनराशि 1053 हजार रुपये है।

वर्ष 2001 में कुल अल्पकालीन वितरित ऋण 3,440 हजार रुपये रामनगर एवं 2087 हजार रुपये सल्टौवा गोपालपुर के साथ कुल 5527 हजार रुपये हैं। कृषि समितियों के अन्तर्गत रामनगर के 170 ग्राम तथा सल्टौवा गोपालपुर के 239 ग्राम हैं। दोनों विकास खण्डों में एक-एक सहकारी बैंक की शाखा है। सहकारी बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 3538 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया।

कृषि विकास में उत्पादन का उतना ही महत्व है जितना कि उसके विपणन का। जब तक कृषि उत्पादों पर लाभ नहीं मिलता तब तक अधिक उत्पादन उत्साहवर्धक परिणाम नहीं दे पाता। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में बीज, सिचाई, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं हेतु कृषकों को काफी लागत लगानी पड़ती है किन्तु इसकी तुलना में उत्पादित वस्तु का मूल्य समुचित न होने से लाभ नहीं मिल पाता है। कृषि उत्पादन कम होने पर वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तथा अधिक होने पर कम हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में कृषक को हानि होती है। सरकार की उदासीनता कृषक व्यवसाय के विकास में तथा कृषि उत्पादन से प्राप्त लाभ में बाधक है।

#### 4.7 कृषि विकासार्थ नियोजन :

कृषि नियोजन के अन्तर्गत कृषि भूमि नियोजन, कृषि की उत्पादकता में

वृद्धि तथा कृषि पर आधारित आर्थिक कार्यों, जैसे—पशुपालन एवं सम्बन्धित उद्योगों का उन्नयन सम्मिलित है। कृषि भूमि नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भूमि दुरुपयोग रोककर उसका उचित एवं आदर्श उपयोग करना है। भूमि का दुरुपयोग भौतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा होता है। डडले स्टाम्प के अनुसार भूमि नियोजन प्रत्येक एकड़ भूमि के आदर्श उपयोग का निर्धारण है। इसे लचीला होना चाहिये जिससे समयानुसार इसके प्रतिरूप में परिवर्तन हो सके। आदर्श उपयोग का तात्पर्य अनुकूलतम उपयोग से है। भूमि के आदर्श उपयोग को भूमि की क्षमता तथा मानवीय आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अधिकाधिक उत्पादन, फसल प्रतिरूपों में सुगमता, ग्रामीण बेरोजगारी की समाप्ति एवं ग्रामीण आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है कि एक व्यवस्थित योजना तैयार किया जाय जिसके क्रियान्वयन से क्षेत्र की कृषि विकास को गति प्रदान की जा सके। कृषि विकास के लिये विस्तृत कृषि क्षेत्र का होना आवश्यक है कृषि विकास का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यदि कृषि क्षेत्र के लिये योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाय तो कृषि का महत्तम विकास किया जा सकता है। कृषि सम्बन्धी योजना सभी आर्थिक विकास कार्यक्रमों का आधार स्तम्भ है। ऐसी योजना में निम्नलिखित पक्षों को समावेशित किया जा सकता है।

- (1) कृषिगत आधारभूत संरचना के लिये सिंचाई, जल, बीज, उर्वरक, पौध सुरक्षा, कृषि यन्त्र परिवहन, भण्डारण, विपणन और साख सुविधाओं को समुन्नत करना।
- (2) भूमि उपयोग नियोजन में भूमि सुधार, अवनयित भूमि विकास, भूमि उर्वरता, सुवैज्ञानिक फसल प्रतिरूप और मुद्रादायिनी कृषि पर बल देना है।
- (3) बागवानी विकास के साथ-साथ फूलों एवं सब्जियों की कृषि को विकसित करने

हेतु सुनिश्चित कार्यक्रम बनाना।

- (4) कृषि के साथ-साथ कृषि सम्बन्धित व्यवसायो-पशुपालन, एव दुग्ध उद्योग, तथा मत्स्य पालन आदि को प्रोत्साहित करना।
- (5) अवस्थावनात्मक सुविधाओ-विद्युतीकरण, भण्डारगृह, ग्रामीण गोदाम आदि विस्तार करना।
- (6) फसल बीमा योजना के साथ कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- (7) कृषि विकास के साथ-साथ पर्यावरण को असतुलित होने से बचाना।

कृषि अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या का जीवन आधार है। कुल जनसंख्या का लगभग 80% जनसंख्या कृषि-कर्म में लगी है। स्थानीय जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त खाद्यान्नोत्पादन नहीं हो पा रहा है। निर्धनता अभिशाप स्वरूप कृषको को ग्रसित किये हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कृषि एव कृषको के विकास को प्रथम अधिमान्यता दी जा रही है, फिर भी इनका अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित कृषि समस्याओ तथा प्रदत्त प्रशासनिक सुविधाओ को दृष्टि में रखते हुये कृषि विकास हेतु कतिपय सुझाव दिये जा रहे हैं। जो अग्रलिखित हैं -

अब कुछ उन समस्याओ पर प्रकाश डालना आवश्यक है जो अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीणो कृषको द्वारा बतायी गयी है, जिनमें प्रमुख है।

- (1) 25 80% लोगो ने ग्रामीण क्षेत्रो में पर्याप्त परिवहन एव यातायात के साधनो का न होना और विद्युत आपूर्ति में बाधा को प्रमुख समस्या के रूप में गिनाया।

- (2) 20% से अधिक लोगो ने वर्षा की अनिश्चितता, सिंचाई की सुविधा के अभाव तथा भूक्षरण की समस्या को प्रमुखता दी।
- (3) 32.50% लोगो ने अकुशल श्रमिकों और नये ससाधनों तथा तकनीकी ज्ञान से अपने आप को अनभिज्ञ बताया।
- (4) उर्वरकों की बढ़ती मिलावट तथा समय पर अच्छे बीजों का न उपलब्ध होना प्रमुख समस्या के रूप में 15% ग्रामीणों ने बताया।
- (5) कृषि ऋण, फसलों की चोरी, कृषक संगठन का अभाव, सरकारी संरक्षण का न प्राप्त होना आदि को प्रमुख समस्या के रूप में 10% ग्रामीणों ने महत्व दिया।
- (6) लगभग सभी ग्रामीणों ने कृषि उपज विपणन व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण तथा उच्चवर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण की समस्या को प्रमुखता दी।

कृषि में वाणिज्यीकरण की तरफ झुकाव के कारण कृषक फसल प्रतिरूप में धीरे-धीरे परिवर्तन कर रहे हैं। वे खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में कमी कर मुद्रादायिनी फसलों के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की कमी को उन्नतशील बीजों, सिंचाई, सुविधाओं तथा उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं आदि के प्रयोग से पूरा किया जा रहा है।

### सुझाव :-

- (1) तहसील में कृषि साक्षरता कम होने के कारण कृषकों को सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं की जानकारी नहीं हो पाती है यद्यपि रेडियो, टेलीविजन द्वारा भी कृषकों को कृषि विकास के लिये नवीनतम कृषि तकनीकों तथा सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। किन्तु अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता के कारण कृषक इसका लाभ नहीं उठा पाते। अतः कृषि विकास के लिये प्रथम आवश्यकता

कृषको को शिक्षित करने की है। जिससे कि वे नवीनतम कृषि तकनीक को स्वीकार करे और कृषि विकास की योजनाओं, सुविधाओं की जानकारी करके उनसे अधिकतम लाभार्जन प्राप्त करे।

- (2) मुद्रादायिनी फसलों के क्षेत्र को विस्तृत किया जाय।
- (3) नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में चावल के अधिक उत्पादन के साथ-साथ मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित किया जाये।
- (4) कुआनों तथा आमी नदी के खादर मिट्टी के क्षेत्रों में दलहन, तिलहन आदि फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाय।
- (5) कृषि की आधारभूत सुविधाओं, उन्नतशील बीज, कृषियन्त्र, विद्युत, सिंचाई, उर्वरक, परिवहन, भण्डारण, विपणन, साख, सुविधा आदि में वृद्धि की जाये।
- (6) कृषि सम्बद्ध उद्यमों जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन आदि को समुन्नत किया जाये।
- (7) फलदार वृक्षों को अधिकाधिक लगाया जाय तथा पौष्टिक सब्जियों की कृषि को विकसित किया जाय। इसके कृषको को सतुलित भोजन की प्राप्ति होगी जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता बढ़ेगी।
- (8) कृषि को उद्योग की तरह मान्यता प्रदान की जाये।
- (9) अनुपयोगी, बजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय तथा वृक्षों को खेतों के चारों तरफ लगाया जाय। इससे भूक्षरण पर विराम लगेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा और जलाने के लिये लकड़ी की प्रचुर प्राप्ति होगी।
- (10) सरकारी सुविधाओं तथा कृषको में सीधा सम्पर्क कायम हो, बिचौलियों का अन्त किया जाये।

- (11) माह में कम से कम एक दिन, कृषि विकास अधिकारी द्वारा न्याय-पंचायत स्तर पर कृषकों की आम-सभा आहूत करके उन्हें नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा सरकारी योजनाओं, सुविधाओं की जानकारी दी जाय।
  - (12) ग्रामसभा स्तर पर यह प्रक्रिया प्रत्येक फसल मौसम में एक बार अवश्य हो।
  - (13) कृषि से सम्बन्धित सभी विभागों में ईमानदार तथा क्षेत्रीय कृषि-समस्याओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये।
- उपरोक्त सुझावों के क्रियान्वयन से फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर अध्ययन क्षेत्र की कृषि को एक नवीन आयाम दिया जा सकता है और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

### कृषि विकास एवं ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन

कृषि विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। कृषि में होने वाला कोई भी परिवर्तन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन ग्रामीण सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा। समाज में होने वाले परिवर्तनों से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और अर्थव्यवस्था से कृषि। यही कारण है कि विकसित समाज के ध्येय की प्राप्ति के लिये वर्तमान समय में समस्त योजनायें ग्रामोन्मुख एवं कृषि विकास से सम्बन्धित लक्ष्य मानकर बनायी जा रही है। खाद्यान्नों में अत्यन्त कमी हो जाने पर सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाती है एवं सामाजिक मानवीय मूल्यों का पतन होने लगता है।

जीविका हेतु खाद्यान्न न प्राप्त करने के लिये मानव विविध प्रकार के असामाजिक कार्य करने लगता है परिणाम स्वरूप समाज में चोरी हत्या, कलह, स्वार्थ इत्यादि बुराइयाँ पनपती है। इसके विपरीत कृषि उत्पादों में वृद्धि से

संतुलित भोज्य पदार्थ की उपलब्धता होने पर स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, परिवहन तन्त्र, मानव मूल्य का विकास आदि होता है। इस प्रकार कृषि के विकास से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होता है।

सामाजिक परिवर्तन से कृषि प्रभावित होती है। भोजन प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन से पशुससाधन एवं कृषि में भी परिवर्तन होता है। यदि भोजन में मासाहारों की मात्रा बढ़ती है तो कुक्कुट, मत्स्य, बकरी इत्यादि तथा शाकाहारों की मात्रा बढ़ने पर दुधारु पशुओं, फलदार वृक्षों एवं सब्जियों के अनुपात में वृद्धि होती है। अर्थप्रधान समाज में आर्थिक समुन्नति हेतु वाणिज्यिक फसलों के अनुपात में बढ़ोत्तरी होती है जिसका उदाहरण गन्ना की कृषि में विस्तार से देखा जा सकता है।





## REFERENCE

- Athawale, A G 1966 Some New Methods of Crop Combination,  
Geographical Review of India, Vol 28 No 4, pp 29-30
- Balram, 1986 Spatial System of Rural Settlements in Hammirpur District  
(U P ), Unpublished D Phil Thesis of Allahabad University Allahabad,  
p 36
- Buck, J L 1967 · Land Utilization in China, Vol. 1 University of Nanking
- Coppock, J T 1964 Crop, Live stock Enterprise Combination in England and  
Wales, Economic Geography, Vol 40, pp 65-81.
- Datt, D 1988 Changing Pattern of Landuse in the Bino-Basin U P Himalya,  
National Geographar, Vol 23, No 2 p 157
- Enayedl, G Y. 1964 · Geographical types of Agriculture Applied Geogrphy in  
Hungary, Budapest.
- Jones, W D. and Finch 1925 . Detailed Field Mapping of American, Cities,  
Geographer, Vol. 15
- Marsh, G.P 1864 · Man and Nature, Physical Geography as Modified by  
Human Action, New York
- Pownall, L.L 1953 The Functions of Newzealand Towns, Annals of the  
Association of American Geographers Vol. 23, pp 332-350.
- Reddy, M.V and Reddy, N.B K. 1988 · Changing Pattern of Crop-  
combinations in chittoor District, Andhra Pradesh, National Geographer,  
Vol 23 No 2, p. 89.

- Roy, B K 1967 Crop- Association and changing Pattern of crops in the Ganga-Ghagara Doab East, National Geographer Journal of India, Vol 13 No 4, p 198.
- Shafi, M 1962-72 Measurement of Agricultural Productivity of Great Plains, The Geographer Vol 36, pp 296-305
- Sharma, S C 1980 Land Capability, Classification and Landuse Planning-A case study of Padrouna Block of Deoria District Geographical Review of India, Vol. 42, pp 32-40
- Singh, B N 1984 · Agricultural Landuse of Deoria Tahsil, District Deoria (U P ), Unpublished D Phil Thesis of Allahabad University, Allahabad, p. 196
- Singh, Jasbir and Dhillon, S.S 1984 Agricultural Geography, Tata Mc Graw Hill Publishing Company Limited, p. 124.
- Stamp, D 1962 · The land of Britain, Its use and misuse, III Edition, London.
- Sover, C O 1919 . The Utilization of Land, Geographical Review, Vol 4, Newyark.
- Thomas, D. 1963 . Agriculture in Wales During the Napoleonic war, Wales University Press pp 80-81.
- Tiwari, R C. 1984 : Settlement system in Rural India A case study of the lower Ganga-Yamuna Doab, The Allahabad Geographical Society : Allahabad, p. 13.
- Tripathi, S. 1991 : Integrated Rural Development : A Case study of Gorakhpur

District, Unpublished D Phil Theiss, Allahabad University, Allahabad

p 113

Yadav, H S 1988 Integrated Rural Development A case study of Allahabad

District, Unpublished D Phil Thesis, Allahabad university, Allahabad,

p 132

सिंह, ब्रजभूषण 1988 कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन गोरखपुर, पृ० 151



## अध्याय-5

### ग्रामीण यातायात, संचार व्यवस्था एवं सेवाकेन्द्र

प्रस्तावना :-

किसी भी स्थान विशेष का विकास एवं प्रगति उस क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर होता है। इन सुविधाओं में विद्युत, परिवहन, यातायात एवं संचार सेवाओं तथा सेवाकेन्द्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवहन एवं संचार व्यवस्था प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के वाहक माने जाते हैं। यातायात से अभिप्राय व्यक्तियों एवं वस्तुओं के गमनागमन से होता है, तथा विचार अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का कार्य संचार माध्यमों से किया जाता है। मानव उद्भव काल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिये विभिन्न साधनों का प्रयोग करता रहा है। नये स्थान पर अपने समायोजन हेतु मानव को विचार-विनिमय की भी आवश्यकता पड़ती रही इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता एवं यातायात, संचार साधनों का विकास एक क्रमिक रूप से एक दूसरे के समानान्तर होता रहा है।

किसी भी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के विकास में परिवहन के साधन एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। अतः विकास और परिवहन एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान सभ्यता और अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ स्वरूप परिवहन साधनों का प्रतिफल है (रिछरिया-1990, पृ० 18)। परिवहन साधनों के विकास का ही प्रतिफल है कि कृषि, उद्योग तथा कारखानों की उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। परिवहन के अतिरिक्त दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण साधन नहीं है जो किसी भी

अविकसित क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में तीव्र विकास ला सके (कोनान, 1965)।

इस प्रकार परिवहन सेवाएँ क्षेत्र दूरी को कम करने तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करती हैं। यदि कृषि तथा उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था में शरीर एवं अस्थिमज्जा के समान हैं तो परिवहन के साधन भी शिराएँ एवं धमनियाँ का कार्य करती हैं (मिश्र, पृ० 205)।

परिवहन एवं संचार व्यवस्था भाषा, प्रथाएँ एवं पर्यावरणीय दीवारों को तोड़कर सामाजिक समरसता को सुलभ करती बनाती हैं (स्ट्रार्ट – 1934)। उस तरह न केवल परिवहन सेवाओं द्वारा आवागमन का कार्य होता है बल्कि विचार एवं कौशल का सम्प्रेषण भी किया जा सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएँ अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। ये राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय एकता और अखण्डता, सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, कानून और व्यवस्था आदि में उल्लेखनीय रूप से सहायक होती हैं (तिवारी – 1984)। सुव्यवस्थित परिवहन तन्त्र के माध्यम से ही किसी स्थान पर उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव नहीं होने पाता है एवं इससे समूचे देश या उसके एक बड़े क्षेत्र में समान मूल्य रखने में सहायता मिलती है (तिवारी एवं त्रिपाठी 1987, पृ० 66–67)।

इस प्रकार परिवहन व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान एवं विचारों के विस्तार में, प्रौद्योगिकी अनुसंधान के प्रसार में, जीवन स्तर के विकास में एवं सामाजिक उपलब्धियों के वितरण में सहायक होती हैं। प्रस्तुत अध्याय में बस्ती जनपद के भानपुर तहसील में यातायात के प्रमुख माध्यमों तथा संचार सुविधाओं की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण एवं संश्लेषण के अतिरिक्त, क्षेत्र की आवश्यकतानुसार,

ग्रामीणों के विकास तथा सामाजिक उन्नयन हेतु उनका नियोजन प्रस्तुत किया गया है।

#### 5.1. परिवहन तन्त्र का स्थायिक प्रतिरूप :-

सामान्यतः यातायात के तीन प्रमुख माध्यम होते हैं, जल, स्थल एवं वायु। अध्ययन क्षेत्र में केवल स्थल माध्यम द्वारा ही परिवहन होता है। सतत वाही नदियों का अभाव होने के कारण जलमार्ग द्वारा परिवहन नहीं होता। सम्पूर्ण बस्ती जनपद में वायुमार्गों का विकास सम्भव नहीं हो पाया है। तहसील में कोई एअर पोर्ट न होने का कारण वायु यातायात भी सम्भव नहीं है। अध्ययन क्षेत्र के समतल मैदानी भाग होने के कारण स्थल मार्गों का विकास हुआ है। तहसील में स्थल मार्गों का स्थानिक प्रतिरूप निम्नवत है।

##### 5.1.1 सड़क मार्ग :-

सड़क मार्ग व्यापार, व्यवस्था, संस्कृति और विचारों के निर्बाध आदान-प्रदान को सम्भव बनाकर मानव सभ्यता को जीवित रखती है और प्रगति पथ गामिनी होती है। जिस प्रकार धमनियाँ मानव शरीर को जीवन प्रदान करती हैं उसी प्रकार देश का विकास, सभ्यता का विकास, सड़क रूपी धमनियों के माध्यम से होता है। सड़क मार्ग और रेलमार्ग स्थल यातायात के दो प्रमुख साधन हैं। सड़क सम्बन्धी समस्याओं के निवारणार्थ एवं इसके सम्यक विकास हेतु योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना में भारतीय सड़क मार्ग को 3 वर्गों में रखा गया है।

भारत दुनिया के सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। देश में सड़कों की कुल लम्बाई 33 लाख किमी० है।

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्तर्गत आने वाली प्राथमिक सड़क प्रणाली (2) राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़को प्रणाली तथा (3) गावों की सड़को और अन्य जिला सड़को के तहत शामिल ग्रामीण सड़के, (भारत 2002 पृ० 627)।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली 57,735 किमी सड़को की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। जबकि राज्यमार्गों तथा जिला और ग्रामीण सड़को की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़को का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 1500 तक की आबादी वाले सभी गाँवों को बारहमासी सड़को से जोड़ना है।

मार्च 1997 में भारत में जवाहर रोजगार योजना वाली सड़को को छोड़कर अन्य सभी (पक्की तथा कच्ची दोनों) सड़को की कुल लम्बाई 24,65,877 किमी० थी जिसमें उत्तर प्रदेश में कुल लम्बाई 2,55,467 किमी० थी। ग्रामवासियों के आर्थिक विकास हेतु इस जनपद में मुख्यतः राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग सड़को के निर्माण एवं उसके सुधार का उत्तरदायित्व सभालता है। वर्ष 1988 की सांख्यिकीय पत्रिका के अनुसार जनपद में पक्की सड़को की लम्बाई इस प्रकार थी—राष्ट्रीय राजमार्ग 74 किमी, प्रादेशिक राजमार्ग 90 किमी० प्रमुख जिला मार्ग 95 किमी० तथा अन्य जिला एवं सामान्य सड़के 652 किमी० हैं। ये सड़के लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं।

मार्गों की बनावट के आधार पर तहसील के मार्गों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है।

- (1) पक्की सड़क
- (2) खडजा मार्ग।
- (3) कच्चा मार्ग।

# TAHSIL BHANPUR DISTRICT BASTI TRANSPORT NETWORK

2001

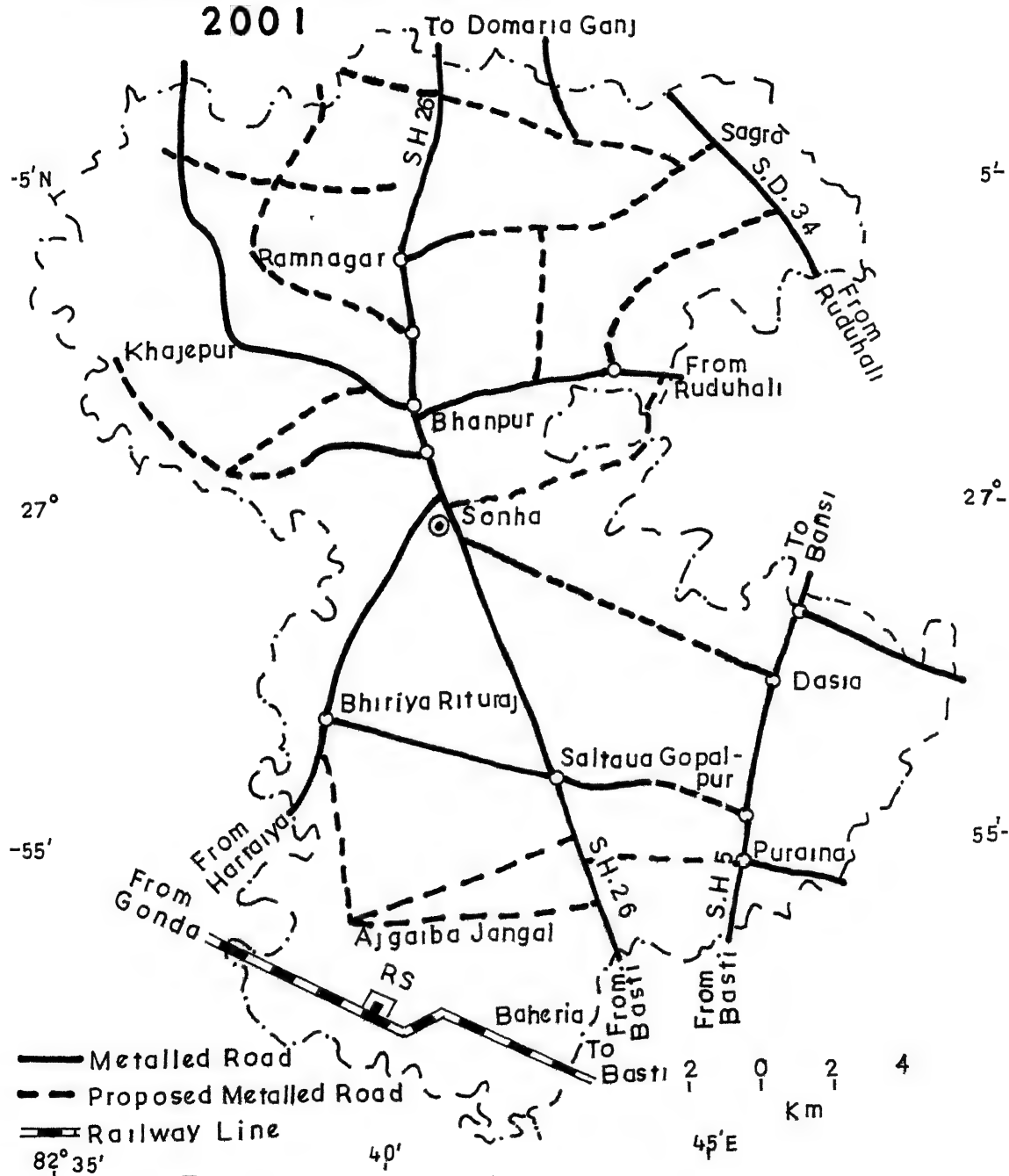


Fig. 5.1



## तालिका क्रमांक-5.1

### भानपुर तहसील : प्रमुख सड़क मार्ग

प्रान्तीय मार्ग	(1) बस्ती-बासी मार्ग स0 5
	(2) बस्ती-डुमरियागज मार्ग स0 26
प्रान्तीय जिला मार्ग	(3) रूघौली - डुमरियागज मार्ग स0 34
अन्य मार्ग	(4) रूघौली भानपुर मार्ग
	(5) सोनहा शिवाघाट, हैरेया मार्ग
	(6) भिरिया-सल्टौवा मार्ग
	(7) भानपुर - खाजेपुर मार्ग
	(8) भानपुर-शकरपुर मार्ग
	(9) सगरा-मझारी-नरखोरिया मार्ग
	(10) सगरा-दुबौली मार्ग
	(11) सोनहा-बरगदवा मार्ग
	(12) दसिया-महनुआ मार्ग
	(13) मानिक चन्द-सल्टौवा मार्ग
	(14) पुरैना-जिनवा मार्ग
	(15) अजगैइबा जंगल-भिरिया मार्ग
	(16) बरहुआ-अजगैइबा जंगल मार्ग
	(17) आमा-अजगैइबा जंगल मार्ग
	(18) बरगदवा-बजरिया बुजुर्ग मार्ग
	(19) भानपुर-भैसहिया-घौरहरा मार्ग
	(20) विशुनपुरवा - हनुमानगज मार्ग

अध्ययन क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। प्रान्तीय मार्गों की संख्या भी तहसील में मात्र दो ही है। प्रान्तीय मार्ग संख्या 5 (जो जनपद मुख्यालय से सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय को जोड़ती है) लुम्बनी से दुददी तक जाता है) की तहसील में कुल लम्बाई मात्र 10 किमी० है। प्रान्तीयमार्ग सं० 26 (बस्ती – डुमरियागज मार्ग) की तहसील में लम्बाई 24 किमी है। भानपुर तहसील में स्थित प्रमुख सड़क मार्गों को तालिका क्रमांक 5.1 तथा उनकी स्थिति को मानचित्र संख्या 5.1 से प्रदर्शित किया गया है।

वर्तमान समय में (1999–2000) भानपुर तहसील में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 172 किमी है। जो कि जनपद की कुल लम्बाई का 18.10% है। सारणी 5.2 से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि (1988–89 से 1999–2000) तहसील में पक्की सड़कों की लम्बाई में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सारणी में दिये गये जनपद की सड़क की लम्बाई (1988–89) अविभाजित सिद्धार्थनगर और सन्त कबीर नगर संयुक्त रूप की है। रामनगर विकास खण्ड में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 90 किमी० है जिसमें 83 किमी० लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। सल्टौवा गोपालपुर में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 82 किमी० है कुल लम्बाई 172 किमी० में 157 किमी० पक्की सड़क लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है।

तहसील में यदि सब ऋतु योग्य सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या पर दृष्टि डाला जाय तो 1000 से कम जनसंख्या वाले ग्राम 177 हैं। वहीं 1000 से 1500 वाले ग्रामों की संख्या 20 है जबकि 1500 से अधिक वाले ग्राम मात्र 12 हैं।

वर्ष 1989–90 में अध्ययन क्षेत्र में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 83 किमी थी जो 10 वर्ष के अन्तराल पर 1999–2000 में बढ़कर 172 किमी हो गयी। रामनगर विकास खण्ड में इसकी लम्बाई 45 से 90 तथा सल्टौवा गोपालपुर में 38

## तालिका क्रमांक-5.2

### भानपुर तहसील : पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी०) (1989-90 एवं 1999-20000)

विकास खण्ड	पक्की सड़को की लम्बाई			सब ऋतु योग्य सड़को से जुड़े ग्रामों की संख्या							
	कुल		लोक निर्माण विभाग		1000 से कम वाले ग्राम		1000 से 1499 वाले ग्राम		1500 से अधिक वाले ग्राम		
	वर्ष	1999-00	1989-90	1999-2000	1989-90	1999-2000	1989-90	1999-2000	1989-90	1999-2000	
1 रामनगर		90	45	83	45	95	90	11	10	7	6
2 सल्टौवा		82	38	74	38	82	76	9	7	5	4
तहसील भानपुर		172	83	157	83	177	166	20	17	12	10
जनपद बस्ती		950	977	800	853	1276	1808	86	141	82	121

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 1900 एव  
2000 से संगणित।

से 82 हो गयी। इस प्रकार भानपुर तहसील के 31.18% आबाद ग्राम पक्की सड़को से सयोजित है।

#### 5.1.1.1 सड़क यातयात—प्रवाह :-

यातयात—प्रवाह से सड़क विशेष का अन्य सड़को की तुलना में उसका महत्व देखा जाता है। इसकी गणना एक समय विशेष में चलने वाले कतिपय अथवा समस्त वाहनो की संख्या के आधार पर की जाती है, जो कि एक पूर्णतः व्यक्ति निष्ठ किया है। प्रस्तुत अध्ययन में सड़क यातायात—प्रवाह का परिगणन, मार्ग विशेष, पर दिन भर पर आने जाने वाले समस्त वाहनो की संख्या के आधार पर किया गया है। सर्वाधिक यातयात प्रवाह प्रान्तीय मार्ग—संख्या 5 तथा 26 पर होता है। अध्ययन क्षेत्र में प्रान्तीय मार्ग संख्या 5 जनपद से पुरैना, दसिया होते हुए जनपद सिद्धार्थनगर में प्रवेश करता है। वहीं प्रान्तीय मार्ग संख्या 26 जनपद को सल्टौवा विकास खण्ड के मुख्यालय से जोड़ते हुये तहसील मुख्यालय पर जाता है। यह मार्ग डुमरियागंज को जाता है। तहसील का रामनगर विकास खण्ड भी इस मार्ग पर होने के कारण—तहसील में इस मार्ग का यातायात प्रवाह सर्वाधिक है। प्रान्तीय जिला मार्ग सं० 34 रूघौली विकास खण्ड को डुमरियागंज तहसील से जोड़ता है। सगरा खास के पास नरखोरिया तथा दुबौली से आने वाले मार्ग मिलते हैं। जो इस मार्ग के यातायात प्रवाह में वृद्धि करते हैं।

#### 5.1.2 सड़क—घनत्व :-

सड़क घनत्व के सगणन से किसी क्षेत्र में सड़को का तुलनात्मक प्रतिरूप निरूपित होता है। प्रस्तुत अध्ययन में सड़को की सघनता को दो रूपों में प्रति 100 वर्ग किमी और प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर परिगणित कर तालिका क्रमांक—5.3 में दर्शाया गया है। सर्वाधिक सड़क घनत्व रामनगर विकास खण्ड में

### तालिका क्रमांक-5.3

#### भानपुर तहसील : सड़क घनत्व (सड़कों की लम्बाई किमी०)

विकास खण्ड	1988-89			1999-2000		
	कुल	प्रति 100 वर्ग किमी० पर	प्रति लाख जनसंख्या पर	कुल	प्रति 100 वर्ग किमी० पर	प्रति लाख जनसंख्या पर
रामनगर	45	19.14	47.53	90	38.29	78.02
सल्टौवा गोपालपुर	38	17.59	35.27	82	37.96	61.98
भानपुर	83	18.40	40.93	172	38.13	69.45

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 1999 एवं  
सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 2000 से संगणित।

38 29/100 किमी<sup>2</sup> तथा 79 02 किमी<sup>0</sup>/लाख जनसंख्या है। जहाँ वर्ष 1988-89 में सड़क घनत्व प्रति प्रति 100 वर्ग किमी पर 18 40 था वह 1999-2000 में बढ़कर 38 13 हो गया। वर्ष 1988-89 में भानपुर तहसील का औसत 40 93 किमी<sup>0</sup>/लाख जनसंख्या थी जो 1999-2000 में 69 45 किमी/लाख जनसंख्या हो गयी।

### 5.1.3 सड़क सम्बद्धता :-

सड़क-सम्बद्धता मापन से किसी मुख्य ग्राम या सेवा केन्द्र से अन्य सेवाकेन्द्रों से सयोजकता तथा इसकी केन्द्रीयता का बोध होता है। प्रस्तुत अध्ययन में सड़क सम्बद्धता ज्ञात करने के लिये दो चरों '0' और '1' का प्रयोग किया गया है। चर '0' दो केन्द्रों के मध्य अप्रत्यक्ष और चर '1' दो सेवा केन्द्रों के मध्य प्रस्ताव सड़क सम्बन्ध का घटक है। तालिका क्रमांक-54 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक सम्बद्धता, सयोजकता अंक 5 है जो भानपुर तथा सोनहा का है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में सोनहा तथा भानपुर सर्वाधिक सेवा केन्द्रों से प्रत्यक्षत सयोजित है। द्वितीय क्रम में सल्टौवा तथा रामनगर सेवाकेन्द्र आते हैं। न्यूनतम सम्बद्धता अंक '1' अजगैइबा जंगल का है जो एकल सेवा केन्द्र से सम्बद्ध है।

### 5.2.2 रेलमार्ग :-

रेल देश में माल और यात्री परिवहन का मुख्य साधन है। यह देश के दूर दराज इलाकों में सभी लोगों को करीब लाने और व्यापार, देशाटन, तीर्थयात्रा तथा शिक्षा के कार्यों में मदद करती है। भारतीय रेल पिछले 148 वर्षों से राष्ट्रीय एकता बनाये हुये है। इसने देश आर्थिक विकास को एक सूत्र में पिरोया है और कृषि तथा उद्योग के विकास को तीव्रगति प्रदान की है।

तालिका क्रमांक-5.4

भानपुर तहसील : सड़क सम्बद्धता

	S	A	T	S	R	B	B	B	B	S	S	B	A	A	D	P	T	
	S	A	T	S	R	B	B	B	B	S	S	B	A	A	D	P	T	
SHA	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	SHA = SHANKARPUR
ASN	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ASN = ASNHARA
TUS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	TUS=TUSIAL
SAG	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	SAG=SAGRAKHAS
RAM	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	RAM=RAMNAGER
BHAN	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	BHAN=BHANPUR
BARO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BARO=BAROKHAR
BARG	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	BARG=BARGADWA
SON	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	5	SON=SONHA
SAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4	SAL=SALTAUA
BHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	BHI=BHIRIYARITURAI
AJG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	AIG=AJGAIBA JANGAL
AMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	AMA=AMA
DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	DAS=DASIA
PUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	PUR=PURAINA
T	3	3	2	3	4	5	1	3	5	4	3	3	3	1	2	2		

भारत में रेल की शुरुआत 1853 में मुम्बई से थाने तक के बीच 34 किमी० मार्ग पर हुई। आज देश भर में रेलों का एक व्यापक जाल बिछा हुआ है। रेलवे स्टेशनों की संख्या 6,877 और रेलमार्गों की कुल लम्बाई 62,789 किमी० है। 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलों के पास 7,517 इंजन, 36,510 यात्री डिब्बे 4,838 अन्य सवारियों गाड़ियों के डिब्बे और 2,44,419 माल डिब्बे थे। अब तक लगभग 32.5% कुल रेल पटरी का विद्युतीकरण हो चुका है।

आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में रेलों का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। बस्ती जनपद में बड़ी लाइनें उपलब्ध हैं। बड़ी लाइन मुण्डेरवा से बभनान तक है। जिसके अन्तर्गत 6 स्टेशन हैं जिसकी कुल लम्बाई 54 किमी० है। तहसील की आमा स्टेशन इसी लाइन पर है। तहसील में इसकी लम्बाई लगभग 10 किमी० है। अन्य किसी भी तरफ तहसील को रेल की सुविधा नहीं मिलती है। जनपद मुख्यालय से पर तहसील वासियों के रेल यातायात की पूर्ति होती है।

## 5.2 यातायात-नियोजन :-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भानपुर तहसील में लगभग 55% गाँव पक्की सड़क से 5 किमी दूर हैं। जबकि 30.18% गाँव सड़क हैं या 1 किमी० से भी कम दूरी पर हैं। तहसील में जो राजकीय जिला एवं ग्रामीण पक्की सड़कें हैं। निर्माणाधीन हो या पूरी बन गयी हो उनकी स्थिति दयनीय है।

प्रान्तीय सड़कों को जोड़ने वाले मार्ग की स्थिति का आकलन दसिया-महुआ मार्ग तथा मानिक चन्द-सल्टौवा मार्ग से देखा जा सकता है दसिया-महुआ मार्ग सन 1988-89 के पहले से ही निर्माणाधीन है। दोनों प्रान्तीय मार्गों से कुछ ही किलोमीटर तक पक्की हुई है। अन्य क्षेत्र खडन्जा तथा कच्ची सड़कों के हैं। मानिकचन्द्र सल्टौवा मार्ग की स्थिति भी दयनीय है।



तहसील के विकास खण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है। ग्रामीण मार्गों पर कहीं भी भारी वाहनों के यातायात वर्ष पर्यन्त असम्भव है।

अतः क्षेत्र के विकासार्थ प्रथम आवश्यकता वर्तमान सड़कों की स्थिति में सुधार की है, जिससे सुरक्षित एवं तीव्र यातायात तथा सुविधाओं का आदान प्रदान हो सके। अभी भी क्षेत्र के बहुत से गांव ऐसे हैं, जो कि कच्ची सड़क से भी नहीं जुड़े हैं या जुड़ भी गये हैं तो खड़जा नहीं पहुँचा है। अतः क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यकता है खड़जा मार्ग को पक्की सड़कों में परिवर्तित किया जाय तथा कच्ची सड़कों पर खड़जा का निर्माण किया जाय।

किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु उच्च एवं सघन सड़क जाल के साथ-साथ उत्तम रेलमार्ग भी अपेक्षित हैं। अध्ययन क्षेत्र में मात्र 10 किमी० लम्बा (ब्राडगेज का) रेलमार्ग है। आया स्टेशन ही इसका स्टेशन है। कोई रेलमार्ग बस्ती से सिद्धार्थनगर न होने के कारण यात्री सुविधाओं तथा आवागमन में कठिनाई होती है इस प्रकार तहसील के सम्यक विकास हेतु कम से कम एक नूतन रेलमार्ग के विकास की महती आवश्यकता है, आमा-रूघौली-बासी रेलमार्ग।

### 5.3. संचार प्रतिरूप :-

भारत में डाक सेवाओं की शुरुआत 1837 में हुई। कराची में 1852 में पहला डाक टिकट जारी किया गया। जो केवल सिन्धू सूबे में वैध था। वर्ष 1854 में भारतीय डाक विभाग का एक सस्था के रूप में पुनर्गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष एक महानिदेशक थे। इसके बाद से डाक नेटवर्क का विस्तार हुआ और अनेक नई सेवाओं के जरिये इसमें विविधता आयी। भारत में डाक सेवाएँ 1989 के भारतीय डाकघर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित होती हैं। यह अधिनियम

सरकार को देश में पत्रों को जमा करने, ले जाने और पहुँचाने का एकाधिकार देता है।

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में संचार माध्यमों की विशिष्ट भूमिका होती है। जिसके द्वारा समय तथा अर्थ दोनों की बचत होती है। इनके द्वारा भी क्षेत्र में त्वरित कार्य सम्भव होता है। संचार माध्यमों द्वारा नवीन विचारों, नवाचारों तथा अन्वेषणों को दूरस्थ ग्रामों तक पहुँचाया जाता है। संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघर, दूरभाष, तारघर, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि केन्द्रों को सम्मिलित किया जाता है। बस्ती जनपद के भानपुर तहसील में विद्यमान प्रमुख संचार सेवाओं का विवरण तालिका क्रमांक-5.5 में दर्शाया गया है।

#### 5.3.1. डाकघर :-

भारतीय डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश में डाकघरों की संख्या अब 1,54,551 है। इनमें 16,402 शहरी और 1,38,149 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। स्वाधीनता प्राप्त होने के समय देश में कुल 23,344 डाकघर थे। इनमें से 19,184 डाकघर ग्रामीण और 4,160 शहरी इलाकों में थे। उसके बाद से डाक नेटवर्क में करीब सात गुना वृद्धि हो चुकी है। (भारत 2002 पृष्ठ 648)।

डाक नेटवर्क का विस्तार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभोग्तर डाकघरों की प्रणाली के जरिये हुआ है। डाक नेटवर्क में चार प्रकार के डाक घर आते हैं ये हैं। मुख्य डाकघर, उप-डाकघर, विभागोत्तर उप-डाकघर और विभागोत्तर शाखा डाकघर। सदेश वाहक कार्यक्रमों के अन्तर्गत डाकघरों का प्रमुख स्थान है इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान तथा वित्तीय संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में काफी सुविधा मिलती है। जो स्थान इस सुविधा से सम्पन्न है। वहाँ की जनता अपने को साधन सम्पन्न मानती है।

## तालिका क्रमांक-5.5

भानपुर तहसील में यातायात एवं संचार सेवाओं का प्रतिकार

(1989-90 एवं 2000-01)

कास खण्ड	डाकघर		तारघर		टेलीफोन		पब्लिक काल आफिस		रेलवे स्टेशन		बस स्टेशन/ बसस्टाप	
	1989-90	2000-01	1989-90	2000-01	1989-90	2000-01	1989-90	2000-01	1989-90	2000-01	1989-90	2000-01
रामनगर	19	11	2	2	—	350	2	10	—	—	12	12
सल्टौआ	20	21	1	1	—	20	2	2	1	1	5	5
हसील भानपुर	39	32	3	3	—	370	4	12	1	1	17	17
नपद-बस्ती	385	266	45	33	1248	10083	50	699	10	7	1665	105

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 1990 पेज 99

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 2001 पेज से सगणित निजी सर्वेक्षण

सन 1989-90 में रामनगर विकास खण्ड में 19 तथा सल्टौवा में 20 डाकघर थे। यानि भानपुर तहसील में कुल डाकघरों की संख्या 39 थी। 2000-01 में रामनगर में यह संख्या घटकर 11 तथा सल्टौवा में 21 हो जाने से इसकी संख्या 32 हो गयी। इसके कमी के कारण में नयी तहसीलों तथा जिलों के निर्माण शामिल हैं। मानचित्र संख्या 52 में डाकघरों को स्पष्ट किया गया है।

बस्ती डाक मण्डल बस्ती के डाकघरों की अद्यतन सूची (31/3/2001) निम्नवत है।

असनहरा उपडाकघर में, अमारेडीहा, धौराहरा, धवाय, घोषण, करमहिया, पिरैलागरीब, रामनगर, टडवा तथा तुसायल आते हैं। हनुमानगज उपडाकघर में आमवारी, दसिया, मझौवा, बैकुण्ठ तथा परसा-दमया आते हैं। आमा में सरदहा शुक्ल सुकरौली, शिवपुर तथा टिनिच आते हैं। सल्टौवा उप डाकघर में अमरौली सुमाली, बरगदवा, बिशुनपुरवा, चौकवा, जहलीपुर, जिनवा, लपसी, मझौवा खुर्द, सोनहा, सिहारी सरदहा, तेलियाडीह प्रमुख हैं।

### 5.3.2. तारघर :-

तारघर शीघ्रातिशीघ्र सूचना सम्प्रेषण की इकाई है। इस समय अध्ययन क्षेत्र में तीन तारघर हैं, जिसमें से दो रामनगर में तथा एक सल्टौवा गोपालपुर में हैं। जबकि सम्पूर्ण जनपद में इनकी 33 हैं। रामनगर में यह असनहरा में तथा सल्टौवा में है। क्षेत्रीय विस्तार तथा साधन की बढ़ती माँग ने क्षेत्र के विकास में तारघरों की संख्या में और वृद्धि की आवश्यकता है। तहसील में मात्र 11 ग्राम ऐसे हैं जिनको 1 किमी० की दूरी पर तारघर की सुविधा मिल पाती है। 352 गाँवों को तारघर की सुविधा 5 किमी० से भी अधिक दूरी पर मिलती है। (तालिका क्रमांक-56)।

# TAHSIL BHANPUR DISTRICT BASTI SPATIAL PATTERN OF P.O. P.S. AND P.T.O.

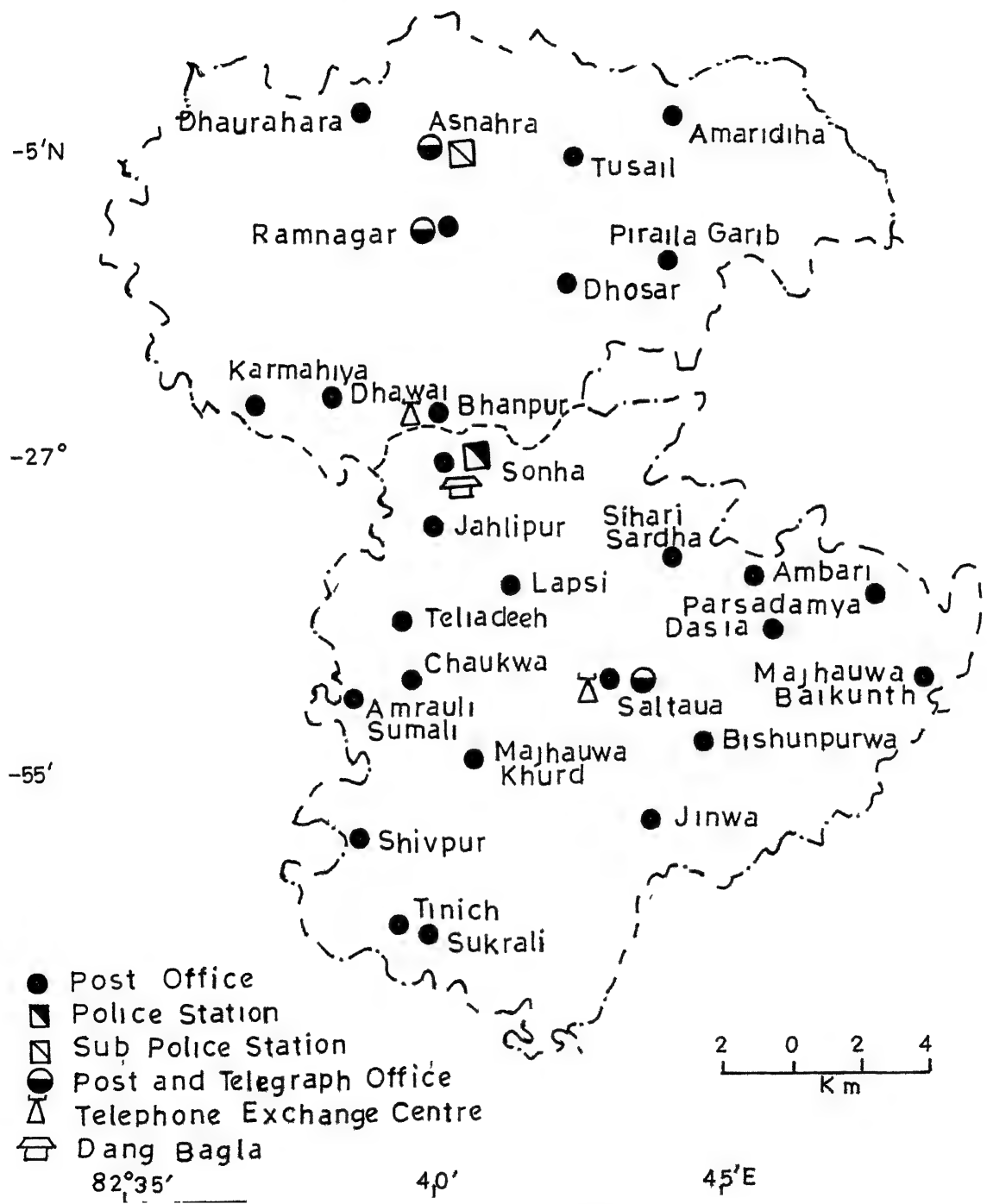


Fig. 5.2

तालिका क्रमांक-5.6

भानपुर तहसील : यातायात एवं संचार सुविधाओं का विवरण  
(1989-90 एवं 2000-01)

विकास खण्ड	ग्राम में	1 किमी० से कम	1-3 किमी०	3-5 किमी०	5 किमी० से अधिक	कुल
रामनगर	11	10	67	46	36	170
सल्टौवा गोपालपुर	21	32	118	47	21	239
भानपुर	32	42	185	93	57	409
तारघर :-						
रामनगर	2	5	9	15	139	170
सल्टौआ गोपालपुर	1	6	6	8	218	239
भानपुर	3	11	15	23	357	409

स्रोत : सांख्यिकीयपत्रिका जनपद बस्ती 2000 से संगणित

### 5.3.3. दूरभाष :—

आज दूरभाष की सुविधा जनसंचार माध्यमों में सर्वाधिक नवीन तथा द्रुतगामी है। सुदूरवर्ती भागों में स्थित अन्य व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में वैचारिक आदान-प्रदान कर सकता है। आज कृषि, शिक्षा, उद्योग, परिवहन राजनीति जैसे क्षेत्रों में दूरभाष संचार माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है।

दूरभाष के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों की दूरियां कम लगने लगी हैं। आर्थिक क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव रहा है। यह आज जनसामान्य की आवश्यक आवश्यकता हो गयी है। अध्ययन क्षेत्र में सल्टौवा विकास खण्ड में एक दूर संचार केन्द्र है। तहसील भानपुर मुख्यालय में भी एक दूर भाष केन्द्र है। जिनके माध्यम से तहसील के कई ग्राम तथा बाजार संयोजित हैं। 1989-90 में जहाँ टेलीफोन नगण्य था वही 2001 में 350 राम नगर में तथा 20 सल्टौवा गोपालपुर में साथ 370 टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या रही। तहसील में पीओसीओ की संख्या जहाँ 1989-90 में 4 थी जो कि 2001 में 12 हो गयी है।

### 5.3.4. अन्य संचार साधन :—

आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण सर्वत्र व्याप्त है शायद ही कोई ऐसा ग्राम हो जहाँ चाहे विद्युत की आपूर्ति न हो या दूरदर्शन न हो। तहसील में कोई आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन केन्द्र नहीं है। रेडियो, टेपरिकार्डर, तो लगभग समस्त ग्रामों से हैं अन्य संचार साधनों में समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आती हैं। तहसील में आज, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान आदि दैनिक समाचार पत्रों का अध्ययन होता है। अंग्रेजी समाचार पत्रों का प्रचार नहीं के बराबर है।

#### 5.4 संचार नियोजन :-

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि अध्ययन क्षेत्र में संचार साधनों की सुलभता सर्वत्र नहीं है जहाँ सुलभ है भी वहाँ उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शनो प्रसारण को लोग मनोरजन की दृष्टि से देखते हैं। उनके द्वारा कृषि विकास योजना, तथा समाचार, सन्देशों पर कम ध्यान देते हैं।

सर्वेक्षण के दौरान शोधार्थी को यह ज्ञात हुआ कि 95% जनसंख्या रेडियो, टेपरिकार्डर और टेलीविजन सेट का प्रयोग सुगम संगीत तथा मनोरजन हेतु करती है। टेलीविजन पर लगी बच्चों की भीड़ ग्रामीण जनमानस की बदलती प्रवृत्ति का घोटक है। निजी सर्वेक्षण के दौरान कुछ ग्राम ऐसे मिले (उदाहरणार्थ, बरडाड नानकार) जहाँ विद्युत की आपूर्ति नहीं है लेकिन लोगों के पास बैटरी है जिससे वे मनोरजन समाज के सभी वर्गों में देखने को मिला है।

सर्वेक्षण के दौरान पूछे गये प्रश्नावलियों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि 8%से कम लोग रेडियो तथा दूरदर्शन से समाचार सुनते हैं। राजनीतिक गतिविधियों या चुनाव के समय समाचार पत्र रेडियो एवं दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है। ज्ञानात्मक अभिरुचि या जिज्ञासा हेतु किसी कार्यक्रम को सुनने या देखने वाले मात्र 1% हैं।

अतः तहसील के विकास हेतु संचार सुविधाओं में परिमाणात्मक विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता को ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।



## 5.5 ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन पर परिवहन—संचार का प्रभाव :—

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार माध्यमों का विशेष योगदान रहा है। परिवहन एवं संचार तन्त्र के अभाव के कारण ही भारत के गावों में सामाजिक कुरीतियाँ, आर्थिक, पिछड़ापन तथा रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं। गावों में जनजागृति एवं जनचेतना के विकास में सड़कों, रेलमार्गों, दूरदर्शन, रेडियो, तार, दूरभाष, सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ग्रामीण समाज नगरीय संस्कृति का अन्धानुकरण कर रहा है। सामाजिक समरसता में उत्तरोत्तर कमी आ रही है। विकास का कोई निश्चित सुव्यवस्थित मापदण्ड न होने के कारण ग्रामीण समाज को संसाधनों के विदोहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पश्चात्य संस्कृति का अन्धानुकरण कर हम बहुत सी अपनी अच्छी परम्पराओं एवं सामाजिक मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं जिसका प्रभाव स्वस्थ ग्राम्य परिवेश को दूषित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों को समुचित रख-रखाव हेतु संचार माध्यमों की आवश्यकता होती है।

अतः स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु स्वस्थ मानसिकता की जरूरत है। आज ऐसे समाज की आवश्यकता है। जो कि इन समस्याओं का निराकरण कर सके। भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास की परमावश्यकता है। आवागमन तथा संचार के साधन इसमें कड़ी का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों की सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण उनके आर्थिक विकास में सहायता मिली है, जो कि किसी भी विकासशील क्षेत्र के सम्बन्धित विकास हेतु आवश्यक है। जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके।

## 5.6 सेवा केन्द्र का अभिप्राय :—

आधुनिक विकास की सभी आधार भूत सुविधाओं से परिपूर्ण अधिवास पुज का जो अपने परितः स्थित बस्तियों को सेवा प्रदान करते हैं “सेवा केन्द्र” कहे जाते हैं। इनकी स्थिति केन्द्रीय होती है, जो सभी क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है। अधिवासों के आकार एवं उसके आर्थिक स्तर इनकी संख्या अधिक तथा कम होती रहती है। ये सेवा केन्द्र एक ग्राम से लेकर एक महानगर तक विविध पदानुक्रम के रूप में हो सकते हैं। ग्रामीण विकास ये केन्द्र मूलभूत सेवाएँ—यथा प्रशासनिक, शैक्षणिक, कृषि, चिकित्सा, परिवहन एवं संचार, मनोरंजन, व्यापार एवं वाणिज्य आदि प्रदान करते हैं। ये सेवा केन्द्र उस ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के भी प्रेरक होते हैं क्योंकि इन्हीं सेवा केन्द्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न धर्मों, समुदायों, वर्गों तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों के लोग एकत्रित होकर अपनी सामाजिक स्थिति, समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। जिससे वहाँ के सामाजिक विकास में परिवर्तन होता रहता है।

इस प्रकार ये केन्द्र क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुये हैं। ये अपने स्थान, कार्य तथा अन्य क्रिया कलापों से अन्तर्सम्बद्ध होते हैं। क्षेत्र के संतुलित आर्थिक सामाजिक विकास के लिये विकास सम्बन्धी नीतियों तकनीकों, आविष्कारों के प्रचार प्रसार में इन सेवा केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकांशतः ये सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के क्रोड के रूप में कार्य करते हैं।

किसी क्षेत्र या प्रदेश में सामाजिक व आर्थिक विकास की प्रगति दर एवं उसका स्थानिक वितरण सदैव एक समान नहीं रहता है। यह असमानता स्थान काल दोनों ही सन्दर्भों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। किसी भी क्षेत्र में चाहे वह

छोटा हो या बड़ा, कुछ स्थान विशेष, दूसरों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं, जो मानवीय क्रियाओं के स्थानिक प्रतिरूप को जन्म देते हैं। इसी सन्दर्भ में ग्रामीण सेवा केन्द्र कृषि आधारित ग्रामीण क्रिया कलापो एवं उद्योगों तथा सेवा पर आधारित नगरीय क्रिया कलापो को अन्तर्सम्बन्धित करते हैं। इस प्रकार ये केन्द्र नगरीय एवं ग्रामीण क्रिया कलापो को समन्वित करते हैं (शेर्ली-1981, पृष्ठ 60)। जिससे केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया सदैव सक्रिय रहती है।

‘सेवा केन्द्र’ को भूगोलविदों एवं अन्य विद्वानों द्वारा विविध संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। मार्क जेफरसन (1931) ने इस प्रकार के अधिवासों के लिये ‘केन्द्रीय स्थल’ शब्द का प्रयोग किया था। जर्मन भूगोलविद क्रिस्टालर ने 1933 ई० में ‘केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त’ का प्रतिपादन किया जिसमें केन्द्रीय स्थल अवधारणा का विशद विश्लेषण शामिल है।

‘विकास ध्रुव सिद्धान्त’ का प्रतिपादन फ्रांसिसी विद्वान पेरॉक्स ने 1955 ई० में किया। जिन्होंने केन्द्रीय स्थल के स्थान पर विकास ध्रुव शब्द का प्रयोग किया जो मूलतः एक आर्थिक संकल्पना है। बेरी ने 1958, मोरिल ने 1962, बोडबिलो ने 1966 में इसे एक भौगोलिक विचारधारा का रूप देने का प्रयास किया, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास घरातल पर होता है, शून्य में नहीं। भारतीय भूगोल वेत्ताओं में डॉ० आर०एल० सिंह ने इन्हें ग्रागर बस्ती, एच०एच०सिंह ने ग्रामर केन्द्र और काशीनाथ सिंह, के०वी० सुन्दरम् आदि ने ‘सेवा केन्द्र’ की संज्ञा दी है।

1975 में प्रो० आर०पी० मिश्रा ने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की संरचना के आधार पर विकास केन्द्रों को निम्न 6 वर्गों में विभक्त किया है।

(1) विकास ध्रुव

(2) विकास केन्द्र

- (3) विकास बिन्दु
- (4) सेवा केन्द्र
- (5) बाजार केन्द्र
- (6) ग्रामीण केन्द्र

इस प्रकार इन सभी विकास जनक केन्द्रों को 'विकास केन्द्र' कहते हैं। ये सेवा केन्द्र ऐसे अधिवास या अधिष्ठान होते हैं जो अपनी सीमा के अन्दर स्थित विभिन्न कार्यों द्वारा आस पास की व्यक्तियों को सेवाये प्रदान करते हैं।

प्रस्तुत अध्याय में बस्ती जनपद की भानपुर तहसील में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीयता सेवा क्षेत्र तथा पदानुक्रम को निरूपित करने के साथ साथ कतिपय सेवा केन्द्रों पर अतिआवश्यक कार्यों को प्रतिस्थापित करने का सुझाव भी देने का प्रयत्न किया गया है जिससे तहसील का सर्वांगीण विकास हो सके तथा तहसीलवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

#### 5.7 सेवा कार्य एवं केन्द्रीयता मान :-

सेवा केन्द्रों के निर्धारण की प्रक्रिया में प्रथम सोपान सेवा कार्यों के चयन का होता है। सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक सेवा को 100 अंक का अभिमान दिया जाता है पुनः प्रत्येक कार्य की सम्पादित होने वाली कुल संख्या से अभिमान को विभाजित कर दिया जाता है इस प्रकार जो भागफल प्राप्त हुआ वही उस सेवा कार्य का केन्द्रीयता मान है जिसे तालिका क्रमांक 57 में दर्शाया गया है। उदाहरण . प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या तहसील में 9 है तथा अभिमान 100 है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का केन्द्रीयता मान  $100/9 = 11.11$  होगा। सेवाकार्य का चयन एक व्यक्ति निष्ठ प्रक्रिया है। अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रशासन, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा

यातायात, संचार, वाणिज्य और व्यापार तथा मनोरंजन से सम्बन्धित कार्यों का चयन किया गया है। सारणी इस प्रति इकाई महत्व स्पष्ट होता है इसके माध्यम से कार्यों के महत्व के अनुसार विभिन्न कार्यों का मान स्पष्ट किया गया है।

#### 5.8 सेवा केन्द्रों का निर्धारण :-

सामान्यतः केन्द्रीय सेवाओं की उपस्थिति, केन्द्रीयता सूचकांक, जनसंख्या आकार, कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात, जनसंख्या आकार में परिवर्तन, यातायात के साधनों की उपलब्धता, कार्यघर जनसंख्या तथा बस्तियों के सेवा क्षेत्र के आधार पर या इन आधारों में से किसी एक आधार को लेकर सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है। अनेक भारतीय विद्वानों में सेवा केन्द्रों के निर्धारण में इन्हीं आधारों का प्रयोग किया है जिसमें सेन (1971), मिश्रा, सुन्दरम् और राय (1979),

आर०एल० सिंह और रागा पी०बी० सिंह (1978), के एन० सिंह (1966), एल० बनमाली (1970), एल०के० सेन (1971), कुमार और शर्मा (1977), आर०सी० तिवारी (1980), बलराम (1986) एच०एन० यादव (1988), के० राय (1990) राधेश्याम मिश्र (1992), एस०के० तिवारी (1993) आदि प्रमुख हैं।

#### 5.9 सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता :-

केन्द्रीयता सेवा केन्द्रों के तुलनात्मक महत्व को प्रदर्शित करती है। यह सेवा केन्द्रों पर सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों की परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विशिष्टता को प्रदर्शित करती है यदि किसी सेवा केन्द्र का केन्द्रीयता मान अधिक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह केन्द्र अन्य केन्द्रों की तुलना में क्षेत्रीय जनसंख्या को अधिक सेवा प्रदान कर रहा है तथा ये केन्द्र महत्वपूर्ण हैं। सेवा

## तालिका क्रमांक-5.7

### भानपुर तहसील : सेवा कार्यों का तुलनात्मक मान

क्र० स०	सेवा कार्य	उपलब्ध कुल संख्या	कुल महत्व	प्रति इकाई महत्व का मान
1	तहसील मुख्यालय	1	100	100 00
2	रेलवे स्टेशन	1	100	100 00
3	कृषि सेवा केन्द्र	1	100	100 00
4	बीज वृद्धि के कार्य	1	100	100 00
5	पुलिस स्टेशन	1	100	100 00
6	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	1	100	100 00
7	विकास खण्ड	2	100	50 00
8	सहकारी बैंक शाखा	2	100	50 00
9	बीज गोदाम	2	100	50 00
10	कीटनाशक डिपो	2	100	50 00
11	परिवार एवं कल्याण केन्द्र	2	100	50 00
12	डाक एवं तार घर	3	100	33 34
13	पशु चिकित्सालय	4	100	25 00
14	पशुधन विकास केन्द्र	6	100	16 67
15	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाये	6	100	16 67
16	राष्ट्रीय कृत बैंक शाखायें	7	100	14 28
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	9	100	11 11
18	हायर सेकेण्डरी स्कूल	9	100	11 11
19	सार्वजनिक टेलीफोन	12	100	8 33
20	ग्रामीण/सहकारी बैंक	15	100	6 66
21	ग्रामीण गोदाम	16	100	6 25
22	बस स्टेशन/स्टाप	17	100	5 88
23	सीनियर बेसिक स्कूल	17	100	5 88
24	बाजार घाट	25	100	4 00
25	डाकघर	32	100	3 12
26	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	44	100	2 27
27	सस्ते गन्ने की दुकान	166	100	0 60
28	जूनियर बेसिक स्कूल	190	100	0 52

केन्द्रों के चयन की भाँति केन्द्रीयता परिगणन भी एक व्यक्ति निष्ठ प्रक्रिया है। जिसे अनेक विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर समाकलित किया है। सर्वप्रथम क्रिस्टालर (1933) ने दक्षिण जर्मनी में टेलीफोन कनेक्शन के आधार पर केन्द्र स्थलों की केन्द्रीयता का मापन किया था स्लैम्स (1944), ब्रुश (1953), कार्टर (1955), उलमैन (1960), और कार (1962), आदि ने किसी स्थान पर पाये जाने वाले सम्पूर्ण कार्यों के आधार पर केन्द्रीयता ज्ञात की है। बैरी और गैरीसन (1958) ने विशिष्ट कार्यों तथा उनकी कार्याधार जनसंख्या और पदानुक्रम कार्यों को आधार मानकर केन्द्रीयता का परिकलन किया है। जिनमें विश्वनाथ (1967), प्रकाश राव (1974), जगदीश सिंह (1976), आदि प्रमुख हैं।

साधारणतः केन्द्रीयता का मापन केन्द्र स्थल में उपलब्ध केन्द्रीय कार्यों के आधार पर किया जाता है। जिसे विभिन्न कार्यों के विवेकानुसार 1,2,3,4,5, आदि अंक प्रदान किये जाते हैं।

#### 5.10. सेवा केन्द्रों का स्थानिक प्रतिरूप :-

मानचित्र सेवा केन्द्रों के स्थलीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है, इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अध्ययन क्षेत्र में इनका वितरण पूर्णतः असमान है। सबसे अधिक सेवा केन्द्र रामनगर विकास खण्ड में है। जहाँ इनकी संख्या 9 है। सल्टौवा में 8 प्रमुख सेवा केन्द्र हैं। जो क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। सेवा केन्द्रों का अधिकांश प्रमुख राजमार्गों पक्की सड़कों के आस-पास पाया जाता है। भारत में सेवा केन्द्रों का वर्तमान प्रतिरूप एक तरफ तो इतिहास और संस्कृति का परिणाम है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था और राजनैतिक कारणों का भी प्रतीक है (सिंह एवं पाठक-1979, पृष्ठ 157)।

अध्ययन क्षेत्र में दो प्रमुख सेवा केन्द्र हैं। जो प्रथम स्तर के माने जा सकते हैं। जिसमें भानपुर तथा सल्टौवा सेवा केन्द्र आता है जो भानपुर परितः क्षेत्र के विभिन्न सेवाओं का अवसर प्रदान करता है। भानपुर में तहसील का मुख्यालय (निर्माणाधीन) है। वर्तमान में भानपुर में अस्पताल, इन्टर कालेज, दूर संचार केन्द्र, पेट्रोल पम्प, बैंक, ट्रैक्टर एजेन्सी, बर्फ तथा लकड़ी चीरने का मशीन स्थापित है। जो क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। इसी प्रकार सल्टौवा सेवा केन्द्र, कृषि, रक्षा केन्द्र, दूर संचार केन्द्र इसका तारघर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्टर कालेज, पशु स्वास्थ्य केन्द्र, तथा ब्लॉक से सम्बन्धित सभी सेवाएँ क्षेत्र को प्रदान करता है। रामनगर सेवा केन्द्र में ब्लॉक, बैंक तथा महिला अस्पताल सेवा क्षेत्र को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। असनहरा सेवा केन्द्र में पेट्रोल पम्प, बाजार, तारघर, बैंक एवं पुलिस स्टेशन (पुलिस चौकी), आदि विद्यालय क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं (मानचित्र 53)।

मोहम्मद नगर में राइसमिल, शुगर मिल, इन्टर कालेज तथा पौधशाला है जो क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। बडोखरा में पौधशाला है बडोखरा पशु बाजार पूरे जनपद में प्रसिद्ध है। जहाँ प्रत्येक मंगलवार को पशु बाजार लगती है। अमरौली सुमाली में महिला अस्पताल तथा हाईस्कूल विद्यालय तथा पुरैना में स्टेट बैंक तथा ग्रामीण बैंक क्षेत्र को सुविधा या सेवा प्रदान करते हैं।

भिरिया ऋतुराज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्टर कालेज तथा पशु बाजार क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। भिरिया में भी पशु बाजार प्रत्येक सोमवार को लगता है। जबकि सोनहा, ग्रामीण बैंक, पुलिस स्टेशन, ट्रैक्टर एजेन्सी तथा वर्तमान में तहसील मुख्यालय के रूप से क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है।



82°35' 40' 45'

# TAHSIL BHANPUR DISTRICT BASTI SERVICE CENTRES

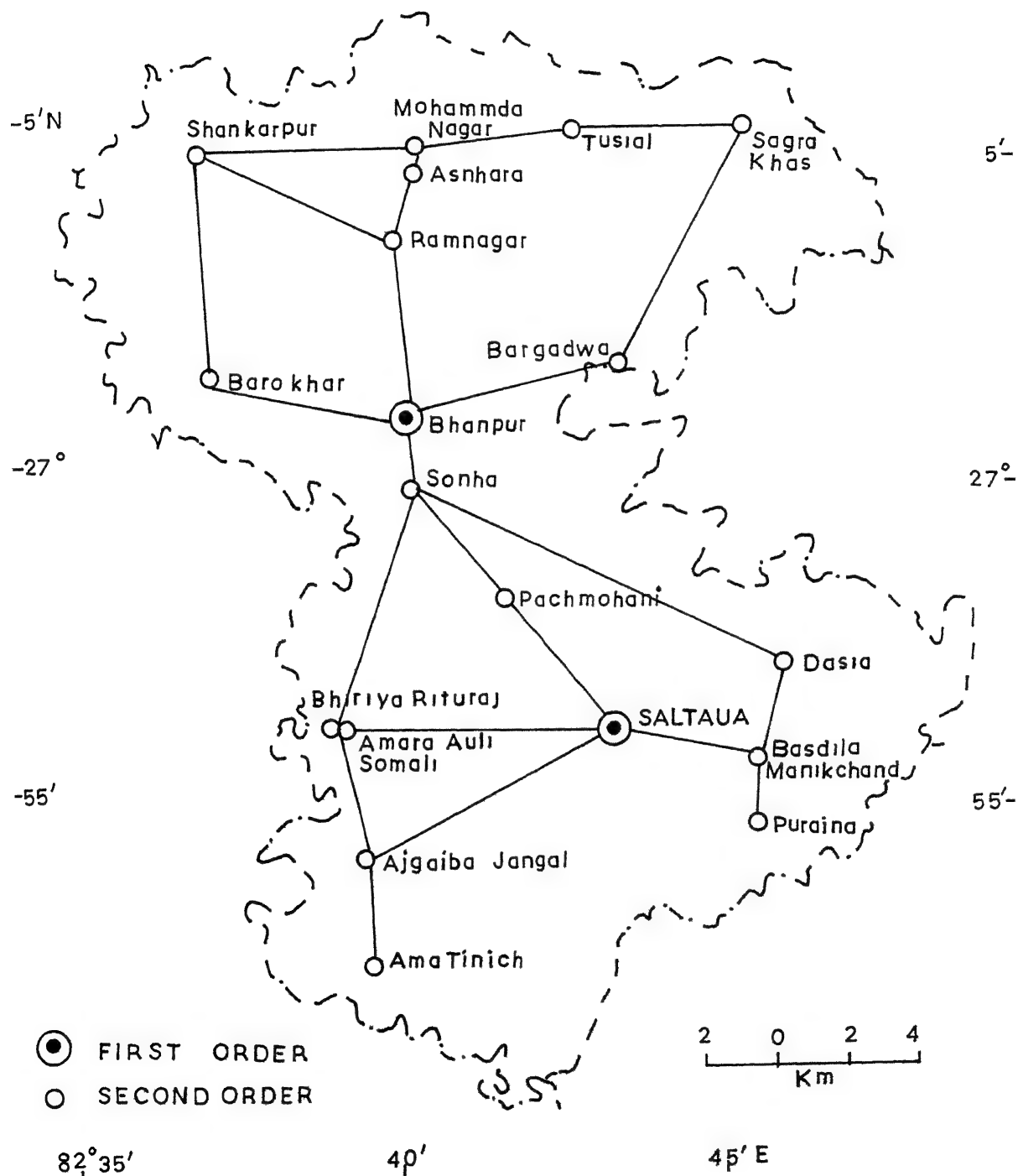


Fig.5-3

दसिया ग्रामीण बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जूनियर हाईस्कूल एवं बाजार के माध्यम से क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। तुषायल में पंजाब नेशनल बैंक तथा बूचडखाना है। सगराखास ग्रामीण बैंक तथा बाजारों के माध्यम से क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है।

#### 5.10.1 सेवा क्षेत्र :-

वह क्षेत्र जो विकास केन्द्रों की सेवा करता है तथा विकास केन्द्रों पर स्थित केन्द्रीय सेवाओं से युक्त होता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। किसी भी विकास केन्द्र के चारों ओर का क्षेत्र जो उस केन्द्र के साथ सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सम्बद्ध होता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है, चूंकि प्रत्येक कार्यक्रम कार्यात्मक इकाई का रेज अलग-अलग होता है अतः किसी विकास केन्द्र पर कार्यों की जितनी ही संख्या होती है। उसका उतना ही बड़ा सेवा क्षेत्र भी होगा (सिंह 1973, पृष्ठ 348)। किसी केन्द्र का किसी स्थान पर बने रहना उन कार्यों तथा सेवाओं पर निर्भर करता है जिसके द्वारा वह उत्पन्न समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है (डिकिन्सन 1934, पृष्ठ 19-31)।

ग्रामीण नियोजन सामाजिक तथा प्रादेशिक विकास की रूपरेखा तैयार करने में भी इन सेवा क्षेत्रों से सहायता मिलती है (सेन, इत्यादि 1972, पृष्ठ 5)।

इस प्रकार सल्टौवा गोपालपुर तथा भानपुर प्रथम स्तर के सेवा क्षेत्र माने जा सकते हैं द्वितीय स्तर पर असनहरा, सोनहा, रामनगर, सेवाकेन्द्र आते हैं अन्य सेवा केन्द्र तृतीय क्षेत्र में रखे जा सकते हैं। छोटे-छोटे बाजार केन्द्रों तथा चौराहों द्वारा क्षेत्र की काफी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। रामनगर विकास खण्ड के पूर्वी क्षेत्र को सर्वाधिक सेवा रूघौली विकास खण्ड मुख्यालय से

प्राप्त होता है। सगराखास तथा बरगदवा को मिलाती हुई सीमा रेखा मान लिया जाए तो उसके सीमा के पूरब के क्षेत्र को सेवा रूघौली सेवाकेन्द्र से मिलती है।

मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में न तो सेवा केन्द्रों का समान वितरण है और नही प्रत्येक सेवा केन्द्र अपने समीपवर्ती क्षेत्र का सुचारु रूप से सेवा ही कर रहा है। इस प्रकार अधिवासो और सेवा केन्द्रों के मध्य एक आवश्यकता से अधिक बड़ी दूरी पायी जाती है जिसे स्थानिक-कार्यात्मक रिक्तता की सज्ञा दी जाती है। इस रिक्तता के क्षेत्रों को समाप्त करने के लिये सर्वप्रथम परिवहन एवं संचार की सुविधाओं के विकास की योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे सभी स्तर के सेवा केन्द्र आपस में जुड़ सकें।

#### 5.10.2 प्रस्तावित सेवा कार्य :-

किसी भी क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक समुन्नति तभी सम्भव होती है। जब वहाँ क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार सेवा कार्यों की समुचित उपस्थिति रहे। वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में मात्र 7 सेवा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। किन्तु सेवा कार्य क्षेत्रीय जनसंख्या के अनुरूप प्रचुर संख्या में नहीं है। कुछ और सेवाकेन्द्रों की आवश्यकता तथा कुछ में नवीनता लाने की जरूरत है।

कोई भी राष्ट्र क्षेत्र या समाप्त तभी पूर्ण रूपेण विकसित हो सकता है जब उसमें पूर्ण साक्षरता हो भानपुर तहसील में वर्ष 2001 में मात्र 38% जनसंख्या साक्षर थी। जिसमें 68% पुरुष तथा 32% महिलाओं की थी। क्षेत्र के सामाजिक उन्नति तथा विकास के लिये महिलाओं को पूर्ण साक्षर बनाने की मुख्य आवश्यकता है। वर्तमान समय में तहसील में बालिका विद्यालय एक भी नहीं है। एक मात्र प्रस्तावित बालिका विद्यालय सोनहा में है।

जबकि इन्टर कालेजो मे (सल्टौवा, भानपुर, मुहम्मदनगर मे बालको के साथ बालिकाओ को शिक्षा दी जाती है। बालिका विद्यालय का अभाव शिक्षा के क्षेत्र मे क्षेत्रीय विकास मे बाध्य है। बरगदवा जो कि भानपुर तथा रूघौली (विकास खण्ड) के मध्य मे अवस्थित है। क्षेत्र की बालिकाओ को 8 किमी० दूर चाहे रूघौली या भानपुर जाना पडता है। बरगदवा मे एक माध्यमिक विद्यालय है। लेकिन बालिका विद्यालय की आवश्यकता है। दसिया मे भी बालिका माध्यमिक विद्यालय की महती आवश्यकता है, क्योंकि बालिका शिक्षा का केन्द्र सल्टौआ या रूघौली है जो करीब 8 किमी० दूर पडता है। ग्रामीण बालिकाओ की शिक्षा कक्षा 8 के बाद इसलिये यही समाप्त हो जाती है इसके साथ ही साथ भिरिया ऋतुराज, सगराखास तथा रामनगर मे भी बालिका इन्टर कालेज की आवश्यकता है।

लगभग 450 वर्ग किमी० क्षेत्र पर 3 लाख से अधिक जनसंख्या धारक तहसील भानपुर मे एक भी डिग्री कालेज नहीं है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मृदा प्रशिक्षण केन्द्र जैसी आवश्यक सेवाये भी उपलब्ध नहीं है।

क्षेत्र के सम्यक् विकास हेतु कुछ क्षेत्रो मे सेवा कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है। जो इस प्रकार है।

प्रस्तावित सेवा कार्य — भानपुर में डिग्री कालेज, पालीटेक्नीक, मृदा परीक्षण केन्द्र, रोडवेज, तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सेवाये प्रस्तावित की जा रही है। दसिया मे बालिका इन्टर कालेज, पुलिस सब स्टेशन, पशु उत्पादन तथा सल्टौवा मे महिला चिकित्सालय, बालिका विद्यालय तथा हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र तथा शकरपुर में एवं सगरा खास मे बालिका (हाईस्कूल) विद्यालय एवं पुरैना मे कोल्ड स्टोरज तथा महिला अस्पताल का प्रस्ताव है।

तहसील के सम्यक् विकास के लिये आवश्यक है कि प्रस्तावित सेवा कार्यों को शीघ्रताशीघ्र विकसित किया जाय और वर्तमान सेवा कार्यों में गुणात्मक उन्नयन किया जाय।

#### 5.11. सेवा केन्द्र : ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन :-

सेवा केन्द्र ग्रामीण और नगरीय सभ्यता के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। जिस पर दोनों क्षेत्रों के उत्पादों का आदान प्रदान होता है। ग्रामीणों को राजगार सेवा केन्द्रों पर मिलता है। साथ ही नूतन प्राविधिक आविष्कारों का ग्रामीण क्षेत्रों तक संचारण सेवा केन्द्रों से ग्राम वासी कृषि विकास हेतु उन्नतिशील बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं तथा कृषि यन्त्रों को प्राप्त करते हैं।

सेवा केन्द्रों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन परिहवन, आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संचार माध्यमों के द्वारा समाचार पत्रों का प्रसारण ग्रामीण क्षेत्रों तक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की दैनिक घरेलू उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति सेवा केन्द्रों द्वारा होती है।

क्षेत्रीय बाजारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र से सम्बद्ध कोई न कोई बाजार होता है जो सप्ताह में एक या दो बार जरूर लगती है। इन्हीं सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता आयी है और समाज का नवीन विचारों से सम्पर्क स्थापित हुआ है।

नवीन अविष्कार, नई प्रक्रिया, नई तकनीक का प्रसारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारण की सुविधा के अतिरिक्त सेवा केन्द्रों के माध्यम से पहुँचता है जिसका उपयोग समाज अपने विकास के लिये करता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में न तो सेवा केन्द्रों का एक सुसंगठित तन्त्र का विकास हो सकता है और न ही ये सामाजिक आर्थिक

रूपान्तरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने मे एव गरीबी के कारण अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रो मे जो आज के सभ्य समाज मे अमानवीय माना जाता है। जाति प्रथा, दहेज, बाल-विवाह, दलित उत्पीडन, बालश्रम, भिक्षावृत्ति, धार्मिक, कट्टरता आदि ऐसी समस्याये हे जिनसे समाज दूषित हो रहा है। इस स्थिति मे भारतीय समाज को सेवा केन्द्रो, जनसचार माध्यमो आदि साधनो द्वारा इन समस्याओ पर प्रभाव डालना चाहिये जिससे समाज का सम्यक विकास हो सके।



## REFERENCES

- Berry, B J L 1958 . A Note on Central Place Theory and Range of Goods,  
Economic Geography, Vol 34, p p 304-311
- Christaller, W 1933 Die Zentralen orte in suddeutschland, Jena Translated by  
C W Baskin (1966) central places in Southern Germany, Engle wood  
cliffs, New Jersey
- Cannon A M 1965 New Railways construction and the pattern of Economic  
Development of East Africa, Transactions an Institute of British  
Geograpshers'd No 36, page 21
- Dickinson, R E 1934 The Distribution of Functions of the smaller urban  
settlement in East Anglia, Geography, Vol 19.p 19
- Morril, R L 1962 . Simulation of Cenral Place Pattern over time, Land studies  
in Geography, Series B, Human Geography, no. 24.
- Mishra, R P 1975 · The Process of Regional Development Theoretical  
Foundation in Regional Development planning in India, Vikash  
Publishing House, New Delhi
- Mishra, R S , 1992 · Rural Development and Social change in Allahabad  
District p.p. 84-113.
- Perroux, F 1955 Note Surlanotion de pole de translated by Mishra, Sundaram  
and Rao ( eds.) Regional Development Planning in India : A New  
Strategy, New Delhi 1976, p.p. 180-218

- Prakasa Rao, V L S 1974 Planning for an Agricultural Region, in R P Mishra (et al) 1974 Regional Development Planning in India A New strategy, New Delhi
- Richachariya, H C. 1990 Transport Bases of Development University Prakashan, New Delhi p. 18
- Roy, K., 1989 Fathehpur District : A study in Rural Settlement Geography, unpublished Thesis, Geography Department, Allahabad University
- Start Daggett, 1934 Principles of Inland Transportation, Geographical Review Vol. 25 p 227
- Singh, R N and Pathak, R K. 1979 Integrated area Development Planning, Concept and Backgroud, National Geographer, Vol 15, No. 2, p p 157-173.
- Singh, R.L and Singh, R P B. 1978 . Spatial Planning in Indian perspective, Varanasi, N.G.S.I Research Publication No. 28.
- Sen, L.K 1971 : Planning Rural Growth Centres for Integrated Area Development – A Study in Miryalguda Taluka, NICD, Hyderabad p. 92
- Shelly, E R 1981 · Rural Development Programm Population Decentralization policy in Development planning U.N Newyark p 160
- Singh, J 1976 · Nodal Accessibility and Central Place Hierarchy : A case study in Gorakhpur Region, National Geographer, Vol. 11 No.2 p.p. 101-102.
- Singh, J. 1984 Central Place and spatial organisation in a Backward Economy, Gorakhpur Region, Uttar Bhoogol Parishad, Gorakhpur. p. 5



- Singh, K N 1966 Spatial Patterns of Central Places in the Middle – Ganga Valley, India, N G L I Vol 12, p p 218-226
- Tiwari, R C and Tripathi, S 1987 Role of Transport in Development, Avadh, Journal of Social Sciences Vol , 1 p.p 66-67
- Tiwari, R C 1980 Spatial organisation of Service centres in the lower Ganga Yamuna Doab, National Geographer, Vol 15 No 2, p p. 103-124
- Tiwari, R C 1984 . Settlement system in Rural India – A case study of the lower Ganga- Yamuna Doab, Allahabad Geographical Society Allahabad p p 161, 162
- Tiwari R C and Yadav H S 1990 : Spatial characteristic of Transport Net work in Allahabad District, U.P National Geographer, Vol 25, No. 1 June 1990, p p. 17-29
- Tiwari, S K 1993 . Rural Development and Social change in Independent India A case study of Phulpur Tahsil of Azamgarh District p p 97-119
- Ullman, E.L 1960 Trade Centres and Tributary Areas of Phillippines, Georgaphical Review, Vol 50 p.p 203-218
- Wanmali, S 1970 . Regional Planning for Social facilities, A case study of Eastern Maharastra, NICD, Hyderabad p 19
- Yadav H.S 1988 · Integrated rural Development programm in Allahabad District, unpublished D.Phil Thesis of Allahabad University, p.p. 72-707

## अध्याय-6

### ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में उद्योग एवं

### प्रौद्योगिकी की भूमिका

#### प्रस्तावना :-

वर्तमान में विश्व के बदलते परिदृश्य में देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में उद्योग की निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के बाद संभवतः लघु उद्योग सेक्टर ही ऐसा क्षेत्र है। जहाँ रोजगार उपलब्ध कराने की प्रबल सम्भावनाएँ हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए लघु उद्योगों के विकास में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सुनियोजित ढंग से नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालित करने पर प्राथमिकता दी जाती है तथा राज्य सरकारों द्वारा उद्योगों में अधिकाधिक पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश का अपना पृथक् स्थान है। गुजरात व महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक आई0ई0एम0 तथा एल0ओ0ई0 उत्तर प्रदेश को प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

जनसंख्या एवं साधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। उद्योग नीति वर्ष 1998 के अन्तर्गत प्रदेश को गतिशील आर्थिक परिदृश्य, औद्योगिक विकास में प्रचुर सम्भावनाएँ, ससाधनों की उपलब्धता, उदारीकरण की प्रक्रिया एवं बाजार सुधारों से उद्योगों की समृद्धि के लिए अत्यधिक अवसर सृजित हुए हैं। नियोजित ढंग से औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतियों की योजनाएँ बनायी गयी हैं जिनमें निर्यात नीति एवं खनिज नीति प्रमुख हैं।

वर्तमान में बदलते परिवेश के अनुसार सरकारी नीतियों में समय-समय पर परिवर्तन कराये गये ताकि उद्योग इन चुनौतियों का निर्भीक एवं प्रभावी ढंग से सामना कर सके। अधिकाधिक पूँजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अनिवासी भारतीयों को विशेष रियायतें दिये जाने का निश्चय किया गया है। प्रदेश में बड़ी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने, औद्योगिक गलियारों के विकास, प्रदेश में लघु उद्योगों द्वारा किये जा रहे उत्पादों के विपणन हेतु प्राइवेट कंपनियों की संरचना, कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि, एकल मेज व्यवस्था तथा टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक समूहों को विकसित किये जाने पर इस प्रदेश के औद्योगिक स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। जिससे न केवल वर्तमान औद्योगिक वातावरण सुदृढ़ होगा अपितु भविष्य में भी अधिकाधिक पूँजी निवेश की संभावनाओं प्रबल होंगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से कतिपय उद्योगों के महत्वपूर्ण क्लस्टर कार्यरत हैं। इन क्लस्टरों के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा समन्वित परियोजनाएँ भी तैयार किये जा रहे हैं। जिसमें आगरा की फाउण्ड्री, कानपुर का चमड़ा उद्योग, फिरोजाबाद का काँच उद्योग तथा खुरजा का पॉटरी उद्योग हैं। इस अध्ययन से जहाँ इस क्षेत्र में लगे उद्योगों का वर्तमान स्तर बढ़ेगा वहीं इन उद्योगों का अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक बाजार में भी प्रवेश होगा।

प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक एवं सस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट ब्यूरो का गठन किया गया तथा उद्योग निदेशालय का निर्यात बिक्री सुदृढ़ किया जा रहा है। निर्यात में उपयोग होने वाले कच्चे माल आदि में व्यापार रखने, ग्रीन कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था, श्रम कानूनों के पुनरीक्षण आदि से प्रदेश का निर्यात निश्चित रूप से

गतिशीलता प्राप्त करेगा। वर्तमान समय में विश्व के वही देश विकास कर रहे हैं जो औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी हैं। औद्योगीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने एवं उसमें सतुलन स्थापित करने में सहायक होता है (बुचानन एवं इलिस 1980)। अतः तीव्र औद्योगिकीकरण ग्रामीण विकास के लिये परमावश्यक है।

उद्योग का अभिप्राय वस्तु उत्पादन से है। मशीन अथवा हस्तकौशल द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन या उसको एक रूप प्रदान करना ही उद्योग है। इस प्रकार इसके अन्तर्गत सूक्ष्म यन्त्रों, खिलौना से इकाई जहाज एवं जलपोतो जैसे वृहत्तम तथा मिट्टी के पात्र जैसे अतिसाधारण से जटिलतम मशीनरी उपकरणों तक का निर्माण समाहित किया जाता है।

ग्रामीण गरीबी, एवं बेरोजगारी निवारण हेतु तथा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के मध्य सतुलन स्थापित करने एवं सामाजिक स्तर के उन्नयन के लिये उद्योगों को निरन्तर विकास किया जा रहा है। प्रस्तुत अध्याय में बस्ती जनपद की भानपुर तहसील में उद्यमियों को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं आदि की प्रस्तुति के साथ-साथ औद्योगीकरण एवं प्रौद्योगिकी से ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तनों का भी विवेचन किया गया है।

#### **6.1. उद्योग का वर्गीकरण :-**

उद्योग की परिभाषा समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। औद्योगिक नीति (1990 में प्रस्तुत) के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार है।

##### **6.1.1. बृहद स्तरीय उद्योग :-**

यन्त्र एवं सयन्त्र पर दो करोड़ से अधिक पूंजी विनियोजित करने वाली इकाइयों को बृहदस्तरीय उद्योग की श्रेणी में आते हैं तथा जिनमें 60 लाख से अधिक और दो करोड़ रुपये तक की पूंजी की विनिवेश हो मध्यम स्तरीय उद्योग

के अर्न्तगत आते हैं। ऐसी इकाईया डायरेक्टर जनरल, टेक्निकल डेवलपमेन्ट एव केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकारी में आती हैं। इनका नियमन केन्द्रीय सरकार की नीतियों तथा समय-समय पर घोषित लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं द्वारा होता है।

#### **6.1.2. लघु स्तरीय उद्योग :-**

ऐसे प्रतिष्ठान एव इकाइयों जिनकी मशीनरी 60 लाख रुपये से कम की लागत के हो, लघुस्तरीय उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इसका पंजीकरण महाप्रबन्धक जिला औद्योगिक केन्द्र/खादी ग्रामोद्योग सगठन द्वारा किया जाता है।

#### **6.1.3. पूरक उद्योग :-**

ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें स्थिर परिसम्पत्तियों के रूप में यन्त्र एव सयन्त्र पर कुल 75 लाख रुपये से कम की पूंजी निपेशित हो तथा जो कल पुर्जों, सघटनों या यन्त्रों के निर्माण में लगे हैं अथवा सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये उद्योग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु दूसरी इकाइयों को अपने कुल उत्पादन या सेवाओं का 50% भाग दे रहे हैं, बशर्ते कि ऐसा उपक्रम किसी अन्य अधिष्ठान का सहायक उपक्रम या उसके नियन्त्रण में न हो, पूरक उद्योग कहलाते हैं। यह भी लघु उद्योग के ही अर्न्तगत आते हैं।

#### **6.1.4. अति लघु उद्योग :-**

सयन्त्र एव मशीनरी पर दो लाख रुपये से कम की पूंजी विनिवेश करने वाले उपक्रमों को इसके अर्न्तगत रखा जाता है।

#### **6.1.5. खादी एवं ग्रामोद्योग :-**

इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का नियमन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा होता है ये 10,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में लगाये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कमेटियो, सस्थाओ तथा व्यक्तिगत इकाइयो को 4% वार्षिक ब्याज दर पर आर्थिक सहायता ऋण/अनुदान परीक्षण एव विपणन की सुविधा प्रदान की गयी है। जनपद स्तर पर बिक्री भण्डार के माध्यम से ग्रामोद्योगी सामानो की बिक्री का कार्य भी किया जाता है।

निम्नलिखित ग्रामोद्योगो को सहायता प्रदान की जाती है -

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| (1) अनाज दाल प्रशोधन       | (11) हाथ कागज             |
| (2) गुड खाडसारी            | (12) रेशा                 |
| (3) ताडगुड एव ताल वस्तु    | (13) कुटीर चूना           |
| (4) ग्रामीण तेल            | (14) फल सरक्षण एव उपयोग   |
| (5) अखाघ तेल, साबुन        | (15) बास, बेत का कार्य    |
| (6) ग्रामीण चर्म           | (16) जडी बूटी सकलन        |
| (7) ग्रामीण कुम्हारी       | (17) एल्युमिनियम के बर्तन |
| (8) कुटीर दियासलाई         | (18) शीशा                 |
| (9) मधुमक्खी पालन          | (19) लाख उत्पादन          |
| (10) लोहारगीरी तथा बढईगीरी | (20) कत्था उत्पादन        |

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 1996-97 तक सहकारी समितिया सस्था को तथा व्यक्तिगत इकाईयो को 4% वार्षिक ब्याज की दर से आर्थिक सहायता सुलभ कराई जाती रही है। धन के अभाव में विभाग द्वारा बजट न उपलब्ध होने के कारण वर्ष 1995-96 से शासन स्तर से ब्याज उपादान योजना चलाई गयी जिसमे उद्यमियों को बैंक के माध्यम से आर्थिक सहायता सुलभ है एव अधिकतम 10% ब्याज जिला प्लान से ब्याज उपादान मद से प्राप्त धनराशि से की जाती है अधिकाशत. इस जनपद में मिनी राइस मिल, काष्ठ

कला, लौहकला, रस्सी बढाई, डलिया, टोकरी, बनाना आदि उद्योगो मे सहायता प्रदान की जाती है।

तहसील की क्रियाशील जनसख्या की 17 प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न प्रकार के उद्योगो मे की है। जिसमे पुरुष 91.6% तथा स्त्रिया केवल 8.4% ही विकास खण्ड स्तर पर रामनगर के क्रियाशील जनसख्या का 1.4% तथा सल्टौवा के 2.1% जनसख्या उद्योग-धन्धे मे लगी हुई है।

## 6.2 औद्योगिक प्रतिरूप :-

भानपुर तहसील यद्यपि कृषि प्रधान तहसील है यहाँ पर 98% जनसख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। यह तहसील बड़े उद्योगो के क्षेत्र मे बहुत ही पीछे है। तहसील का विकास या तहसील मे उद्योगो का विकास जिला उद्योग के विकास के सापेक्ष ही होगा। पूरे जनपद मे मात्र मुख्य रूप से दो चीनी मिले है जिसमे एक बस्ती जनपद मुख्यालय तथा दूसरी पाल्टरगज मे कार्यरत है। जबकि मुण्डेरवा चीनी मिल बन्द हो गयी है अर्थात पूरे जनपद मे गन्ना पेराई हेतु केवल दो मिले है। तहसील मे कोई भी चीनी मिल नहीं है। रामनगर विकास खण्ड मे मुहम्मदनगर मे एक छोटी इकाई चीनी मिल की है। तहसील के सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड का गन्ना कृषको को बस्ती मिल तथा वाल्टरगज मिल पर ले जाना पडता है। रामनगर तथा सल्टौवा दोनो विकास खण्डो मे इसके विभिन्न स्थानो पर कई गन्ना क्रय केन्द्र पेराई सत्र मे स्थापित कर दिये जाते है।

उपरोक्त के अतिरिक्त लघु उद्योगो के क्षेत्र के अर्न्तगत जनपद मे 2276 इकाइया स्थापित है जिसमें से 27 इकाइयां ऐसी है जो कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत है। इन इकाईयों में 4521 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर

सुलभ है स्थापित लघुस्तरीय इकाइयों में कृषि आधारित, वन आधारित, इंजीनियरिंग एण्ड एलाइड, वस्त्र आधारित, रसायन आधारित आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग भी स्थापित हैं। अध्ययन क्षेत्र में राइस मिल, सुगर मिल, आइसक्रीम तथा लकड़ी से सम्बन्धित उत्पादन वस्तुओं की बहुलता पायी जाती है।

वर्ष 1999-2000 तक नवसृजित जनपद सन्तकबीर नगर की इकाइयों को घटा देने के पश्चात जनपद बस्ती में 1565 व्यक्तिगत इकाइयों, 27 सहकारी समितियां तथा 16 सस्थाओं को निम्न उद्योगों के अर्न्तगत 350 17 लाख रुपया की सहायता विभाग से तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सुलभ करायी जा चुकी है। उक्त इकाइयों में से 670 व्यक्तिगत इकाइयों, 4 सहकारी समितियां तथा एक सस्था कार्यरत हैं। जिसके माध्यम से वर्ष 99-2000 में 205 60 लाख का उत्पादन तथा 272 70 लाख की बिक्री की गयी है। जिसमें 1265 लोगों को पूर्णकालिक एवं आंशिक रोजगार प्राप्त हुआ है।

वर्तमान समय में निम्नलिखित ग्रामोद्योगों को सहायता प्रदान करायी जाती है —

- (1) खनिज आधारित उद्योग — कुम्हारी उद्योग, स्टूडियो पटरी, ईट, भट्ठी आदि
- (2) वन आधारित उद्योग .— हाथ कागज उद्योग, अगरबत्ती, निर्माण, बांस बेत आदि।
- (3) कृषि एवं खाद आधारित उद्योग :— बेकरी, मसाला, राइस मिल, दालमिल आदि।
- (4) बहुलक रसायन उद्योग :— शवच्छेदन, चर्मशोधन, चर्मवस्तु एवं फुट वियर आदि।
- (5) इंजीनियरिंग एवं परम्परागत ऊर्जा — लोहारी एवं बढईगिरी एल्युमिनियम उद्योग आदि।



- (6) वस्त्र उद्योग एवं खादी को छोड़कर – लोक वस्त्र का निर्माण, रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण, खिलौना और गुड़िया निर्माण आदि।
- (7) क्षेत्र सेवा उद्योग – कपड़ों की धुलाई, नलसाजी, बिजली की वायरिंग आदि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत।

बस्ती जनपद के उद्योग विभाग के एक अध्ययन के अनुसार जनपद में सम्भावित उद्योग के प्रबल अवसर हैं। जिनका उपयोग क्षेत्र के विकास के दृष्टि से करना वाछनीय है। भानपुर तहसील में कुछ प्रमुख उद्योगों का विकास हुआ है। जिन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है।

**1. दो लाख रुपये से अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग :-**

इस उद्योग के अन्तर्गत जनरल इन्जीनियरिंग, चर्मशोधन कृषि यन्त्र, पशु आहार, सुखी चूना, बेकरी, रेडीमेड गारमेन्ट्स, चावल, दाल की मिल आदि प्रमुख उद्योग आते हैं।

**2. लघुस्तर ग्राम्य तथा कुटीर उद्योग :-**

उसके अन्तर्गत लकड़ी, फर्नीचर, हवनसामग्री, कुम्हारगरी, अगरबत्ती निर्माण सौन्दर्य प्रसाधन, प्रिन्टिंग प्रेस, स्टील (बाक्स एवं आलमारी) वर्क्स, मछली जाल निर्माण आदि प्रमुख उद्योग आते हैं।

उपरोक्त उद्योगों के निमित्त तहसील में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र तथा बिक्री केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के लोग अलग-अलग कुटीर उद्योगों में सलग्न हैं, जो कि सामाजिक वर्ग का रूप धारण किये हुये हैं। ये वर्ग कृषि करता है और साथ ही साथ अपनी छोटी दूकान भी चलाते हैं जिसमें कृषि से सम्बन्धित तथा विभिन्न घरेलू आवश्यकताओं सम्बन्धित सामान होते हैं जैसे लोहार : हंसिया,

खुरपी, कुदाल, फावड़ा, आदि बनाकर बेचता है। बढई फर्नीचर, जुलाहा गमछा चद्दर तथा कुम्हार कुल्हड़, हडिया, नाद और मिट्टी के खिलौने बनाता है। तेली, धोबी, नाई, दर्जी आदि समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज के सांस्कृतिक विकास में इनकी अहम भूमिका होती है।

तहसील में जहाँ कुटीर उद्योग में लगे लोगों की संख्या अधिक है वहीं बड़े उद्योग नगण्य हैं। जनपद में तो बड़े उद्योग चीनी, कागज, वस्त्र, पीतल के बर्तन, वनस्पति घी, रस्सी तथा चमड़ा उद्योग आदि शामिल हैं। तहसील में किसी बड़े उद्योग का विकास नहीं हुआ है कुटीर उद्योगों की संख्या अधिक है। उन्हीं में बढ़ोत्तरी हो रही है। चीनी उद्योग के विकास में ग्रामीणों की विवशता स्पष्ट परिलक्षित होती है। चीनी मिल की नजदीक में अनुपलब्धता किसानों को गन्ना उत्पादन में कम प्रोत्साहित करती है। खरीफ के समस्त फसल क्षेत्रों में 22.08% गन्ना का क्षेत्र है। तहसील के 3964 हेक्टेयर भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। लेकिन तहसील में रामनगर विकास खण्ड में एक छोटी इकाई सुगर मिल की (मुहम्मदनगर) में है। तहसील के गन्ना पेराई हेतु बस्ती या वाल्टरगंज मिल पर जाता है। इसके लिये तहसील के विभिन्न न्यायपचायतों में गन्ना क्रय केन्द्र पेराई सत्र में स्थापित किये जाते हैं।

### 6.3. उद्योग अवस्थापन तथा कार्यक्रम :-

औद्योगिक अवस्थापना योजना का शुभारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। देश की औद्योगीकरण की गति के साथ प्रदेश में भी इस योजना की महत्ता को देखते हुये उपयोगी परिवर्तन किये जाते रहे हैं। औद्योगिक अवस्थापन के विकास का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लघु उद्योगों की भूमि तथा सर्विस सुविधा आदि उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ उनकी स्थापना, विस्तारीकरण एवं

उनके आधुनिकीकरण आदि के लिये प्रोत्साहित करना था। इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को निर्मित रोड/प्लॉट के साथ सभी प्रकार की अवस्थापनात्मक सुविधाये जैसे सड़क, जलव्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था, औद्योगिक फीडर लाइन, व्यवस्था करायी जाती है।

प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति एवं औद्योगिक अवस्थापनों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए लगभग प्रत्येक जनपद में औद्योगिक अवस्थापनों की स्थापना की गई। इस प्रकार प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस योजना का विस्तार का विभिन्न जनपदों में विकेंद्रीकरण कर उनकी स्थापना की गयी। वर्तमान समय में अनेक सस्थाये सहायता प्रदान कर रही हैं जिनमें प्रमुख हैं।

#### 6.3.1. जिला उद्योग केन्द्र योजना :-

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978-79 में किया गया है इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है:-

- (1) लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगार में अधिकाधिक औद्योगिकीकरण की गति में अधिक तीव्रता लाना।
- (2) उद्यमियों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधाये उपलब्ध कराना।
- (3) लघु एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिए अवस्थापना का प्रबन्ध, तकनीकी जानकारी, उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना।
- (4) लघु उद्यमियों को विभिन्न स्तरों पर अनुभूतियों/स्वीकृतियों शीघ्र जारी करने के उद्देश्य से जिला प्राधिकृत समिति की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की है। इन जिला उद्योग केन्द्रों में लघु उद्योगों के पंजीकरण भूमि व भवन, कच्चा माल, मशीन यंत्र उपकरण, सयंत्र, तकनीकी मार्गदर्शन, ऋण एवं विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जिला उद्योग केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी महाप्रबन्धक होता है जिसके अधीन सुचारु रूप से कार्य संचालन हेतु प्रबन्धन (विपणन) परियोजना प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (ऋण) आदि कार्यरत हैं। तहसील/ब्लाक स्तर उद्यमियों की जानकारी एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सहायक कार्यरत हैं। ग्रामीण अंचलों में कार्यक्रम के प्रचार/प्रसार हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक सहायक विकास अधिकारी उद्योग सेवा व्यवसाय की व्यवस्था भी राज्य सरकार के नियोजन विभाग द्वारा की गयी है।

### 6.3.2. एकल मेज व्यवस्था :-

‘एक छत के नीचे’ एक मेज व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों की विभिन्न विभागों से अनुमोदन, स्वीकृतियाँ, आपत्तियों, लाइसेन्स इत्यादि के सबंध में आवेदन-पत्र का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराना है, ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों में उपरोक्त कार्य हेतु बार-बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके। एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया है।

### 6.3.3. स्वरोजगार बन्धु योजना :-

शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगमों द्वारा बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए स्वरोजगार से संबंधित चलाई जा रही समस्त

योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर उनके ससाधन अनुरक्षण एवं समीक्षा के उद्देश्य से इस योजना के अधीन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता जनपदीय कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से जनपदीय कार्य योजना का प्रचार-प्रसार, पात्रता का चयन एवं प्रोजेक्ट तैयार करना, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, बैंक ऋण स्वीकृत कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं के निदान तथा इकाई द्वारा किये गये उत्पादन के समुचित विपणन में सहयोग देना इत्यादि कार्यों का निस्तारण इस योजना के द्वारा फलीभूत होता है।

#### **6.3.4. उद्यमिता विकास कार्यक्रम :-**

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास में गति देने तथा बेरोजगार व्यक्तियों को अपना उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने हेतु स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1978-79 से संचालित की गयी। औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने तथा सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह गति आवश्यक है कि उद्यमी को सभी प्रकार की जानकारी हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न 23 प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला सेक्टर के अन्तर्गत चलायी जा रही है। इस प्रशिक्षण हेतु योजनाबद्ध ढंग से नव उद्यमियों को चयनित किया जाता है। संस्थाओं द्वारा कतिपय प्रशिक्षण जैसे इलेक्ट्रानिक,

प्लास्टिक, फूड प्रोडक्ट्स, साबुन बनाना, आयल आदि पर दिये जाते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर में 25 से 50 तक प्रशिक्षार्थी शामिल किये जाते हैं। जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए 20% आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला/अल्पसंख्यकों को चयन में वरीयता दी जाती है।

#### 6.3.5. उद्योग बन्धु :-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने के उद्देश्य से 1981 में उद्योग बन्धु की स्थापना एक उद्योग बन्धु संचालन समिति के रूप में की गयी थी जिससे औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित सहायता प्रदान की जा सके। प्रगतिशील औद्योगिक वातावरण के सृजन के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उत्प्रेरित करने तथा आधारभूत सुविधाओं जैसे भूमि, विद्युत, वित्त, तथा अनुमन्य प्रोत्साहन एवं सुविधाओं को यह संस्था जानकारी उपलब्ध करा रही है।

उद्योग बन्धु के अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त उ०प्र० है तथा इसके दैनिक कार्यों का दायित्व अधिशाषी निदेशक द्वारा किया जाता है। उद्योग बन्धु की गहन भूमिका को देखते हुए शासन ने 28 फरवरी 1989 को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु तथा मण्डल स्तर पर 23 जून 1990 को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु के रूप में गठन किया गया था एवं समितियों के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का समाधान जिला/मण्डल स्तर की समितियों में नहीं हो पा रहा है, उनका समाधान उद्योग बन्धु द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में जिला उद्योग बन्धु की बैठकें प्रत्येक माह

के द्वितीय मंगलवार को उद्योग बन्धु जनपद के प्रभारी मन्त्री जी की अध्यक्षता में की जाती है। प्रभारी मन्त्री के उपलब्ध न रहने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठके आयोजित की जाती है। लघु उद्योगों को विद्युत स्वीकृति, विद्युत कनेक्शन, बिक्री कर छूट, सुविधा ऋण, कार्यशील पूजा, भूमि पर कब्जा दिलाया जाना आदि विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियाँ प्रदान कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु द्वारा संबंधित विभागों के साथ त्रिपक्षीय बैठकों का नियमित आयोजन प्रत्येक माह किया जाता है जिससे संबंधित विभाग व उद्यमी आमने सामने बैठकर समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। जिन समस्याओं का समाधान त्रिपक्षीय बैठकों के माध्यम से नहीं होता है उन्हें विशेष रूप से गठित वर्किंग ग्रुप के समक्ष रखकर समाधान का प्रयास किया जाता है।

#### **6.3.6. उ०प्र० लघु उद्योग आधुनिकीकरण योजना :-**

प्रदेश की लघु औद्योगिकी इकाइयों की क्षमता एवं कार्यशीलता, उत्पादन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में कमी एवं रूग्णता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए उ०प्र० शासन ने औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु इस योजना का शुभारम्भ किया।

योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य इकाइयों का आधुनिकीकरण करके उनके उत्पादन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि, ऊर्जा की बचत, प्रदूषण, नियंत्रण दुर्लभ कच्चे माल को नष्ट होने से बचाना, निर्यात मूलक उत्पादों का उत्पादन, आयात को रोकने हेतु अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद तैयार करना है।

### 6.3.7. बीमार एवं लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वासन :-

प्रदेश की अनेक औद्योगिक इकाइयों बढ़ती हुई रूग्णता स्थिति में हैं। यदि इस समस्या का प्रभावशाली ढंग से निपटाया नहीं गया तो औद्योगिकीकरण की वर्तमान नीति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक उद्योग की रूग्णता दूसरे उद्योग को भी प्रभावित करती है। औद्योगिक इकाइयों स्थापित होने के बाद कुछ अपरिहार्य कारणों से बीमार हो जाती हैं जैसे कार्यशील पूँजी न मिलना, अनियमित विद्युत आपूर्ति, इकाई को समय से विद्युत कनेक्शन न दिया जाना, समय से वित्तीय सस्थाओं द्वारा सावधि ऋण का भुगतान न किया जाना एवं प्रबन्धकीय प्रभाव आदि। बीमार होने के कारण इकाई अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है। जहाँ एक ओर औद्योगिक इकाइयों को पुनर्स्थापित कराया जाना भी अति आवश्यक है। यदि बीमार इकाइयों को पुनर्स्थापित नहीं कराया जाता है तो शासन द्वारा वित्तीय सस्थाओं के माध्यम से दिया गया ऋण वसूल हो सकेगा। उद्योग में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की कमी होगी तथा बीमार इकाइयों में लगी पूँजी अनुत्पादक हो जायेगी इसलिए बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करना अति आवश्यक है।

रूग्ण इकाइयों को सुविधा प्रदान करने और समस्याओं का निराकरण करने हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय पुनर्वासन समिति कार्यरत है। जिसके द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर बीमार इकाइयों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। मण्डलीय पुनर्वासन समिति के कार्यकलापों का अनुश्रवण करने हेतु सचिव लघु उद्योगों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कोन्डिंग कमेटी का गठन किया गया है।



योजनान्तर्गत दिसम्बर 2000 तक प्रगति का विवरण निम्नवत है -

अ-	चिन्हित रूग्ण इकाइयों की संख्या	1799
ब-	रूग्ण घोषित इकाइयों की संख्या	252
स-	तैयार कराये गये पुर्नवासन पैकेज	78
द-	पुनर्वासित इकाइयों की संख्या	34

### 6 3.8 क्लस्टर योजना :-

उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा त्वरित औद्योगिकीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एव रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से नयी औद्योगिक नीति में 'क्लस्टर योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के संचालन हेतु प्रदेश के 26 औद्योगिक क्षेत्रों में जिन पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० तथा 4 औद्योगिक आस्थानों जो उद्योग निदेशालय के नियन्त्रण में हैं, को चयनित किया गया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में उपलब्ध भूखण्डों को लघु औद्योगिक इकाइयों के मध्य आवंटित कर औद्योगिक नीति के क्षेत्र में नयी औद्योगिक इकाइयों को क्लस्टर के रूप में लगाया जाना है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र/आस्थानों में माग कम से कम 30 भूखण्ड नये उद्यमियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। कुल योजनावधि में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लि० द्वारा शासन से उपलब्ध बजट के अनुसार लगभग 100 इकाइयाँ वित्त पोषित की जायेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा द्रुतगामी औद्योगिक क्षेत्र की मूल दर में 10 प्रतिशत तथा मन्थरगामी औद्योगिक क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जायेगी। शर्त यह होगी कि इकाई एक वर्ष में स्थापित हो जाये उद्योग निदेशालय के औद्योगिक आस्थानों

मे वर्तमान दरो पर भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेगे, जिनका भुगतान आसान किस्तो मे देय होगा।

#### 6.4 उद्योग सम्बन्धी प्रमुख संस्थायें एव विभाग :-

वर्तमान समय मे औद्योगिक विकास मे निम्न सस्थाये कार्यरत है

- जिला उद्योग केन्द्र
- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
- दि स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्टल कारपोरेशन आफ यू0पी0
- उत्तर प्रदेश वित्त निगम।
- उद्योग निदेशालय।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन।
- उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम।
- उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम।
- उत्तर प्रदेश चर्म विकास एव विपणन विकास लिमिटेड
- उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड
- उत्तर प्रदेश खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड
- उपरोक्त सस्थाओ के अतिरिक्त ग्रामीण औद्योगीकरण मे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप मे सहायक केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रमुख विभाग निम्न है।

- (1) सी0एस0आई0आर0
- (2) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
- (3) कृषि, फलोत्पादन एव मत्स्य विभाग
- (4) खाद्य एव आपूर्ति विभाग
- (5) गन्ना विकास

- (6) केन्द्रीय खाद्य अनुसंधान तकनीकी संस्थान
- (7) पर्यावरण निगम
- (8) कुटीर एवं रेशम उद्योग विभाग
- (9) अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- (10) हरिजन एवं समाज कल्याण निगम
- (11) खाद एवं संरक्षण विभाग
- (12) तकनीकी शिक्षा विभाग (तिवारी एस0 के0 1993)

#### 6.5 औद्योगिक समस्याएँ :-

अध्ययन क्षेत्र भानपुर तहसील के औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जिनमें कुछ इस प्रकार हैं।

##### 6.5.1 खनिजों का अभाव :-

अध्ययन क्षेत्र में कहीं भी कोई घात्विक या अधात्विक खनिज नहीं पाया जाता है। इसलिये गन्ना, तिलहन, दलहन, वनोत्पाद, तथा पशुधन उत्पाद आदि को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले लघु तथा कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ है। कृषि जनित फसलों या उत्पादों पर आधारित सर्वाधिक लघु तथा कुटीर उद्योग हैं।

##### 6.5.2. तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव :-

किसी भी क्षेत्र में उद्योग के विकास हेतु तकनीकी ज्ञानयुक्त प्रशिक्षित, परिश्रमी, कार्यक्षमताओं तथा कुशल प्रबन्धक का होना आवश्यक है क्योंकि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन क्षेत्र में उद्यमी प्रायः अप्रशिक्षित तथा प्रबन्धकीय कुशलता से अनभिज्ञ हैं। परिणामतः परम्परागत एवं प्राचीन तकनीक के अनुसार उत्पादन लागत अधिक पड़ती है तथा

उच्च कोटि का न होने से उन्नत तकनीक द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। वस्तुओं के उत्पाद से इनको समुचित लाभ भी नहीं मिल पाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान का अभाव क्षेत्र की जनता के प्रशिक्षण में प्रमुख बाधा है। जनपद में केवल एक औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान है जो कि क्षेत्र के समुचित विकास में योगदान करने वाले उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिये कम है

#### 6.5.3. औद्योगिक उत्पादों का वितरण —

अध्ययन क्षेत्र में लघु तथा कुटीर उद्योगों की बहुलता है जिसमें पूँजी निवेश, श्रम और समय अधिक लगता है और उत्पादन लघु स्तर पर होता है।

इनकी गुणवत्ता अच्छी न होने से ये उत्पाद उच्च तकनीक द्वारा निर्मित सामानों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन में सगठित व्यवस्था न होने से उद्यमियों को इनका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। पूँजी तथा समुचित साधनों के अभाव में उद्यमी अपनी वस्तुओं का विज्ञापन नहीं करा पाते हैं। जबकि विज्ञापन प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम है इससे उत्पादित वस्तु की विशिष्टता तथा उपभोक्ता के बीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। जिसका समुचित लाभ उद्यमी को मिलता है।

#### 6.5.4. ऊर्जा, परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव :-

तहसील में ऊर्जा के रूप में विद्युत की आपूर्ति रूढ़ौली विद्युत उपकेन्द्र से प्राप्त होती है। विद्युत वितरण प्रणाली न केवल उद्योगों को पूर्ण करने के लिये आवश्यक है बल्कि कृषि तथा कुटीर उद्योग के विकास में विद्युत उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है अब जब कृषि का यन्त्रीकरण हो रहा है तो विद्युत के महत्व को किसी भी दशा में उपेक्षित नहीं किया जा सकता है 31-3-2000 तक पूरे जनपद में दो विद्युतीकरण नगर हो गये थे। 2,642 ग्रामों तथा 929 हरिजन

बस्तियों में बिजली उपलब्ध करायी गई है। तहसील में विद्युत केन्द्रों का अभाव पाया जाता है 85% से अधिक गांव विद्युतीकृत हो गये हैं। किन्तु विद्युत आपूर्ति बहुत अनियमित रहती है। कृषि से सम्बन्धित विभिन्न लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास में परिवहन मार्गों तथा उन्नत संचार व्यवस्था का होना आवश्यक है परिवहन उद्योग की धमनियों के समान है। अध्ययन क्षेत्र में दो प्रमुख प्रान्तीय मार्ग हैं जिनकी लम्बाई लगभग 35 किमी है जिसमें प्रान्तीय मार्ग स0 26 (बस्ती में डुमरियागंज) की लम्बाई तहसील में लगभग 25 किमी तथा प्रान्तीय मार्ग स0 5 (बस्ती से बासी) की लम्बाई लगभग 10किमी है अध्ययन क्षेत्र में मात्र 12 किमी लम्बा रेलमार्ग (बस्ती से गोण्डा तक) है। अभी तहसील के अधिकांश ग्राम पक्की सड़कों से काफी दूरी पर है। जिससे बरसात के मौसम में वहां आवागमन में काफी असुविधा होती है। इन गांवों तक पहुंचने के लिये यातायात के साधनों का पूर्णतः अभाव है। पक्की सड़कों की पूर्ण उपलब्धता न होने से भी यातायात अवरुद्ध होता है। जो औद्योगिक विकास में बाधक है। अध्ययन क्षेत्र में मात्र 2 दूर संचार केन्द्र हैं। मुद्रण की सुविधा न उपलब्ध होने के कारण उद्यमियों के विज्ञापन का प्रचार-प्रसार कम हो पाता है।

#### 6.5.5. साक्षरता का कमी :-

साक्षरता किसी भी क्षेत्र के विकास की प्रथम एवं अनिवार्य आवश्यकता है। क्षेत्र की लगभग 65% जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त औद्योगिक सुविधाओं से अनभिज्ञ होते हैं, जिससे वे उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार की वित्तीय सुविधाओं को विचौलिये खा जाते हैं। दूरदर्शिता की कमी से उद्यमी उपभोक्ताओं की अभिरुचि तथा बाजार की मांग का अनुमान

नहीं लगा पाते हैं। पूँजी निवेश के प्रति आशंका भी उनके उद्यम को प्रभावित करता है। एक कुशल उद्यमी का गुण है कि वह क्षेत्रीय, प्रादेशिक एवं अन्तराष्ट्रीय बाजारों की वर्तमान और भावी माँगों का समुचित आकलन करके तदनुरूप उत्पादन करे। यदि भविष्य में लाभ की आशा है तो तात्कालिक हानि को दरकिनारा कर पूँजी निवेश उद्यमी को करना चाहिये न कि औद्योगिक इकाई को बन्द कर देना चाहिये। कुशल उद्यमी के गुण किसी साक्षर व्यक्ति से ही अपेक्षित हैं।

#### 6.5.6. सरकारी नीति :-

औद्योगिक विकास में सरकारी नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। सरकार उद्योग की स्थापना हेतु धन उपलब्ध करवाती है किन्तु औद्योगिक इकाइयों के वित्त की आवश्यकता के समय सरकारी औपचारिकताएँ इसमें बाधक बनती हैं।

लघु तथा कुटीर उद्यमियों को कभी-कभी उच्च ब्याज दर पर व्यक्तिगत ऋण लेना पड़ता है जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और लाभ भी कम हो जाता है। ग्रामीण जनता का बृहद भाग अशिक्षित है, जबकि सरकारी सुविधाओं की सूचना औद्योगिक विभागों के कार्यालयों तक ही सीमित रहती है। सरकार इसका व्यापक-प्रचार-प्रसार नहीं करती कि प्रत्येक ग्रामीण को इन सुविधाओं की जानकारी ग्राम स्तर पर ही मिल जाय। इसके लिये सरकारी नीतियाँ ही दोषी हैं।

इस प्रकार खनिजों का अभाव, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव उत्पादों के विपणन की समस्या, ऊर्जा परिवहन तथा संचार माध्यमों का अभाव, साक्षरता की कमी, दोषी सरकारी नीतियाँ आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो

अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास में बाधक है। जिसका परिणाम है कि यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा है।

#### 6.6 औद्योगीकरण की अभिनव प्रवृत्तियाँ एवं औद्योगिक नियोजन :-

स्वतन्त्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी गयी और समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन कर इसको दूर करने का प्रयास किया गया। निर्धन ग्रामीणों और बेरोजगारों का समुचित सुनियोजन ही इन योजनाओं का प्रमुख आधार रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं।

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर, स्थानीय संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना।
- (2) ग्रामीण बेरोजगारों के लिये रोजगार के लाभकारी अवसर उपलब्ध करना।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित लघु कुटीर उद्योगों की मांग की पूर्ति हेतु सामग्रियों तथा बड़े उद्योगों के लिये कच्चा माल तैयार करना।
- (4) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योग धंधों का विकास करना जो ग्राम्य आधारित हो तथा ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाय और उन पर आधारित नयी औद्योगिकीकरण नीति के तहत ग्रामीण सेवा में नये उद्योग लगाये जाय जो रोजगार परक तथा उनके उन्नयन में सहायक हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक निश्चित और विकेन्द्रीकरण नीति अपनायी जाय और उद्योगपतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापन हेतु प्रोत्साहित किया जाय। सरकार लघु उद्योगों के उत्पन्न माल को

विपणन की व्यवस्था करे। छोटे उद्योगों के क्षेत्र में बड़े उद्योगों को लाइसेंस न दे। कुछ ग्रामीण समूहों का चयनकर उन्हें समस्त आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय जिनमें प्रशिक्षण, तकनीकी सुविधा तथा वित्तीय सुविधा आदि शामिल हों।

क्षेत्र में लघु उद्योगों को जनपद से एक सम्बद्ध शृंखला के माध्यम से जोड़ा जाय और उन्हें सरकारी संरक्षण, वित्त, परिवहन तथा संचार साधनों द्वारा जोड़ा जाय।

यदि इन योजनाओं को अंगीकृत किया जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, रूग्ण उद्योगों में सुधार होगा ग्रामीण औद्योगिक केन्द्र विकसित होंगे, निर्धनता समाप्त होगी। साथ ही उन उद्देश्यों की पूर्ति से स्थानीय संसाधन कच्चे मालों में परिवर्तित होंगे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, समाज का सम्यक विकास होगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसकी प्राप्ति हेतु सरकारी एजेंसियों, बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं और विकासखण्डों को उचित सलाह देकर जिला उद्योग केन्द्र को सक्रिय करे।

## 6.7 औद्योगिक सम्भाव्यता एवं प्रस्तावित उद्योग :-

कच्चे माल की सुलभता, ऊर्जा आपूर्ति एवं उच्च यातायात अधिगम्यता आदि ऐसे आधारभूत तत्व हैं जो किसी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक हैं अध्ययन क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या का मात्र 1.7% ही उद्योगों में सलग्न है। (जनगणना 1991) उद्योगों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -

- (1) संसाधनों पर आधारित उद्योग।
- (2) मांग पर आधारित उद्योग।



तहसील में कच्चेमाल के रूप में कृषि उत्पाद, वनोत्पाद, पशु उत्पादों, रेह जलोढ मृदा आदि की प्रचुरता है, जिन पर आधारित उद्योग विकसित हो सकते हैं। स्थानीय मांग के आधार पर उर्वरक, कृषि यन्त्र सम्बन्धी, सिलाई कढ़ाई, प्रिन्टिंग प्रेस, आदि उद्योगों के सफल होने के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं। अध्ययन क्षेत्र में वृहद या मध्यम स्तर की कोई भी इकाई भी नहीं है। अतः क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है कि यहाँ मध्यम वृहद स्तरीय औद्योगिक अधिष्ठानों की स्थापना की जाय।

#### 6.7.1 कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग :-

भानपुर तहसील के सकल क्षेत्र के दो तिहाई भाग से भी अधिक क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तहसील में चावल, गेहूँ, अरहर, चना, मटर, आलू, गन्ना आदि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। इन उत्पादों पर आधारित चावल मिल, दाल मिल, चीनी मिल, तेल मिल, फल संरक्षण एवं इनके अनुसंगी उद्योगों का विकास अध्ययन क्षेत्र में तीव्रता से हो सकता है क्योंकि कच्चे माल की सुलभता तथा सस्ता श्रम इसके लाभार्जन में सहायक होगा।

परिवहन विद्युत एवं संचार संयोजन तथा भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये भानपुर में चीनी मिल, भिरिया में उर्वरक उद्योग, रामनगर तथा सल्टौवा गोपालपुर में प्रशीतक गृह, बरगदवा, दसिया तथा सोनहा में चावल, दाल तथा आटा मिल, दसिया तथा रामनगर में खाडसारी, पुरैना तथा बरगदवा में दालमोट उद्योग स्थापित किया जाना चाहिये।

#### 6.7.2 पशु एवं पशु आधारित उद्योग :-

पशुगणना 1988 के अनुसार भानपुर तहसील में गोजातीय 42,306 महिष जातीय 26,613, भेड़ 2,379, बकरिया 23,991, घोड़े टट्टू 60, सुअर 3,537 तथा

अन्य पशु 225 थे। पशु उत्पाद के अर्न्तगत मत्स्य, अमिष, अस्थि, बाल श्रम चर्म आदि सम्मिलित किये जाते हैं। पशु विकास हेतु सतुलित पशु आहार की माग बढ रही है। अत इसकी स्थापना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त कुपोषण से बचाव हेतु तहसील मे प्रचुर मात्रा मे दुग्धापूर्ति आवश्यक है अत शकरपुर, तुषायल, बडोखर आमा, पुरैना मे लघुस्तरीय एव सोनहा तथा सल्टौवा मे बृहदस्तरीय दुग्धोत्पादन इकाइयो को स्थापित करने की आवश्यकता है। पुच्छ एव बाल से तूलिका बनाने, चर्म से बेल्ट, बैग, जूता, चप्पल आदि के विनिर्माण मे तहसील मे सभी आधारभूत सुविधाये सुलभ है। मास निर्यात से भी उद्यमी लाभार्जन कर सकते है।

#### 6.7.3 बनोत्पाद : आधारित उद्योग :-

वनो से हमे शुद्ध वायु औषधियों, विभिन्न प्रकार के फल, पुष्प एव कीमती लकडियों प्राप्त होती है। इस प्रकार वृक्ष तथा वनस्पतियों हमारे जीवन के अग है।

वन, उद्योग के विकास मे सहायक होते है। साथ साथ ये औद्योगीकरण से प्रदूषित पर्यावरण का शुद्धीकरण भी करते है।

अध्ययन क्षेत्र मे बबूल, बास, आम, मछुआ, नीम, शीशम, पीपल, खजूर, ताड, सागौन आदि अनेक प्रकार की झाडियों तथा वनस्पतियों मिलती है। बास का प्रयोग गृह, कृषि कागज तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओ के निर्माण मे होता है। औषधि निर्माण मे विभिन्न वनस्पतियो का योगदान होता है। वृक्षों की लकडियो से फर्नीचर, दरवाजा, चौखट आदि का विनिर्माण होता है।

शिक्षा के प्रति अध्ययन क्षेत्र की जागरूकता से कागज की माग निरन्तर बढती जा रही है। तहसील के आस पास कोई भी कागज निर्माण की इकाई नही है। अत सोनहा मे एक बृहदस्तरीय कागज निर्माण उपक्रम की स्थापना आवश्यक है। इसके लिये कच्चा माल क्षेत्र के प्राकृतिक ससाधनो एव वाल्टरगंज चीनी मिल

से उत्पादित खोई से सुलभ हो जायेगा। अध्ययन क्षेत्र में प्रस्तावित चीनी मिल के कार्यरत हो जाने पर यह इकाई पूर्णतः अपनी तहसील के ससाधनों पर निर्भर हो जायेगी। काष्ठ कला उद्योग के रूप में कई स्थानों पर कार्यरत हैं जिनके आधार को विस्तारित करने की आवश्यक है। अगरबत्ती तथा माचिस उद्योग को लघु तथा कुटीर उद्योग के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रचलित किया जाना चाहिये।

#### 6.7.4. मांग पर आधारित उद्योग :-

कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कच्चे माल की तुलना में स्थानीय मांग अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे कृषियन्त्र, मोमबत्ती, मुद्रण, रेडीमेड वस्त्र उद्योग आदि।

यद्यपि इन उद्योगों हेतु आवश्यक ससाधनों का सम्भरण क्षेत्रीय ससाधनों से पूर्ण नहीं हो पाता लेकिन तीव्र स्थानीय मांग के कारण लागत अधिक होने के बाद भी उद्यमी को पर्याप्त लाभ होता है तथा क्षेत्रीय जनता के आवश्यकता की पूर्ति होती है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि यन्त्रों, कृषि रसायनों, विद्युत उपकरणों, पुस्तकों चूड़ियों आदि की मांग काफी है। अतः इन वस्तुओं के सम्भरण हेतु तहसील में इनसे सम्बन्धित विविध उपक्रमों की स्थापना अपेक्षित है।

अध्ययन क्षेत्र की त्वरित आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है कि उपरोक्त वार्षिक तथा मानचित्र 6.1 में प्रदर्शित प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रमों की शीघ्र स्थापना की जाय। सरकार को चाहिये कि कुटीर उद्योग के साथ-साथ मध्यम एवं बृहदस्तरीय उद्योग को प्रोत्साहन दे, क्योंकि इससे न केवल क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा अपितु अधिकारिक रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। सरकार का यह दायित्व है कि सरकारी प्रकृत सुविधाओं से उद्यमियों को अवगत कराये।

82°35'

45'

TAHSIL BHANPUR  
DISTRICT BASTI

## PROPOSED INDUSTRIES

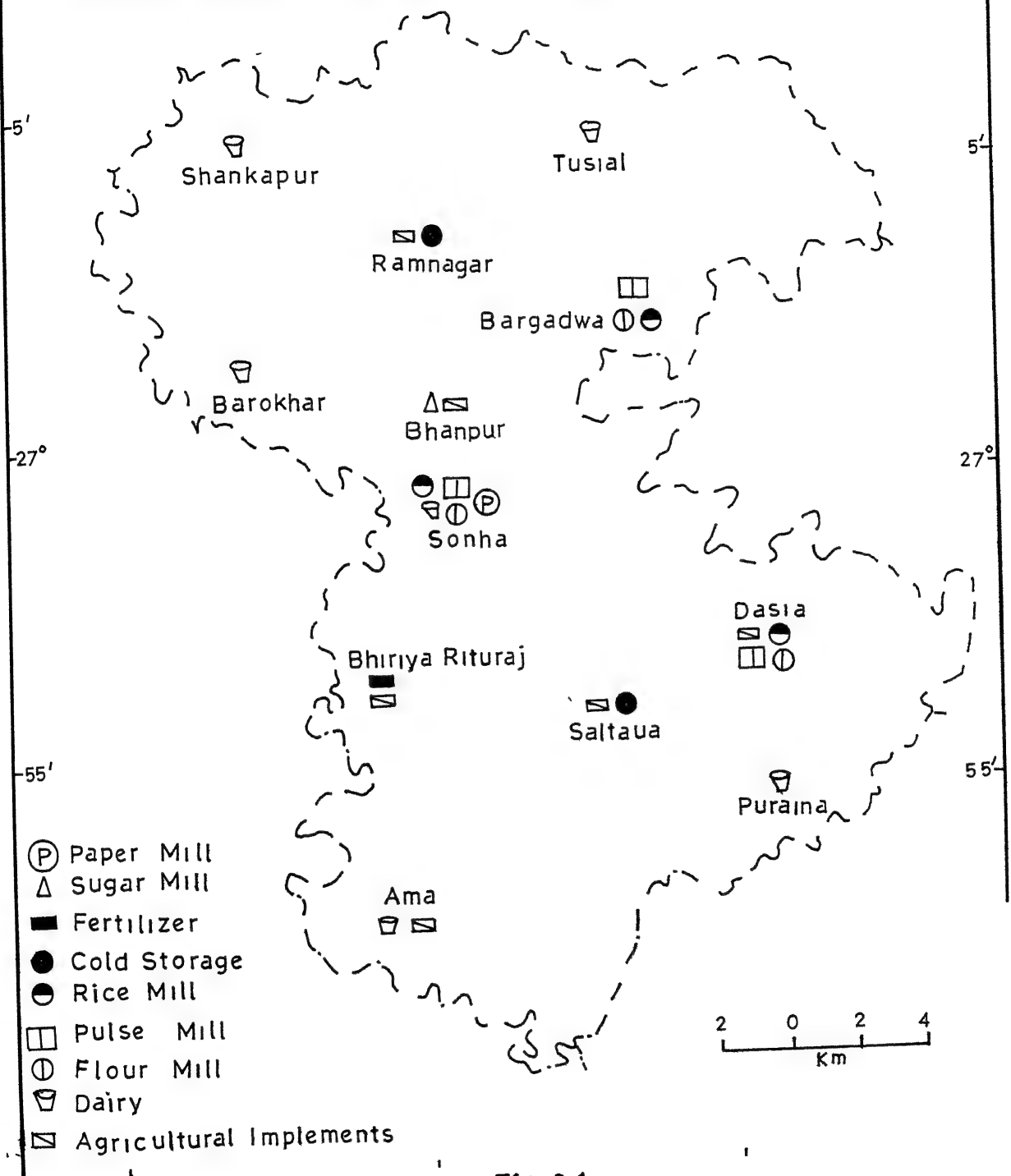


Fig.6-1

## 6.8. औद्योगिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन :-

औद्योगीकरण का नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु उद्योगों का विकास अनिवार्य है। औद्योगिक विकास से व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन होता है।

### 6.8.1 सामाजिक जीवन में परिवर्तन :-

सामाजिक संगठन तथा सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। औद्योगीकरण से स्वार्थपरता में वृद्धि हुई है। भौतिक समृद्धि को बल मिला है।

जाति प्रथा का प्रभाव कम हो गया है इसका स्थान उसकी उपलब्धियों ने ले लिया है। नगरीकरण से गन्दी बस्तियों का विकास हुआ है, जहाँ सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं। औद्योगीकरण से असमानता बढ़ी है तथा जीवन संघर्षपूर्ण हो गया है। औद्योगिक विकास से मानव की कार्यक्षमता एवं आयु में घटोत्तरी हुई है।

### 6.8.2 पारिवारिक जीवन में परिवर्तन :-

भौतिकता तथा व्यक्तिवादिता में वृद्धि से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है तथा एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ी है। पहले जहाँ माता-पिता भाई-बहन चाचा-चाची सबको सम्मिलित रूप से परिवार माना जाता था वही आज परिवार का अभिप्राय मात्र पति-पत्नी एवं बच्चों से हो गया है। स्त्री-पुरुषों में समानता के अधिकार की प्रवृत्तियों का विकास आर्थिक उच्चता में परिवर्तित हो गया है। उसकी महत्ता का मापदण्ड उसके अर्थोपार्जन से होता है। पारिवारिक जीवन की अनिवार्यता विवाह है। अतः समाज में परिवार के पारम्परिक संगठन में व्यापक फेरबदल देखने को मिलता है।

### 6.8.3. धार्मिक जीवन में परिवर्तन :-

उद्योग का प्रभाव धार्मिक विश्वास एवं मानवीय मूल्यों पर पड़ रहा है। धार्मिक रूढ़िवादिता परम्परागत अन्धविश्वास के स्थान पर तर्क, विवेक एवं व्यावहारिकता को प्रश्रय मिला है। वर्तमान विकास के युग में मानवीय मूल्यों एवं नैतिकता में गिरावट आयी है।

### 6.8.4. राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन :-

औद्योगिक विकसित देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कार्यरत है। जो सामाजिक समानता का द्योतक है। सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों—मनोवृत्ति, मनोरंजन तथा मानवीय मूल्य पर औद्योगीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। मनोरंजन के साधनों का व्यावसायीकरण हो गया है। इनका उद्देश्य स्वस्थ मनोरंजन न होकर धनोपार्जन का होता है, जिसका प्रभाव समाज में अपराधों एवं अनैतिकता में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हो रहा है।

इस प्रकार उद्योग ग्रामीण विकास के विविध तत्वों में परिवर्तन को अभिप्रेरित करता है औद्योगिक विकास से जहाँ आर्थिक उन्नति हुई है वहीं सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यों की अवनति भी हुई है। अतः आवश्यकता ऐसे नियोजन की है जिससे भौतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास भी हो।



## REFERENCES

Buchanan, N S and Ellis, H S 1980 Approaches to economic development,  
S Chand Co Ltd , New Delhi, p – 105

Tiwari, S K Rural Development and Social change in Independent India “A  
case study of Phulpur Tahsil of Azamgarh District” Unpublished D  
Phil thesis of Allahabad University, p p. 183-191

साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 2000

साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 1990

भारत 2002, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश 2002, सूचना एव जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश।

जनपदीय सामार्थिक समीक्षा, जनपद बस्ती 2000–2001

बस्ती–विकास 2001–2002 जिला सूचना कार्यालय, बस्ती उ०प्र० (भारत)।

विकास मार्ग विशेषांक 1996–97 जनपद बस्ती, जिला सूचना कार्यालय, बस्ती द्वारा  
प्रकाशित



## ग्रामीण विकास की प्रमुख सामाजिक सुविधायें एवं समस्याएँ

प्रस्तावना :-

भोजन वस्त्र एवं आवास मानव की मूलभूत आवश्यकताये हैं, किन्तु मानव केन्द्र सम्पूर्ण सामाजिक विकास के लिये कुछ आधारभूत सामाजिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक सामाजिक सुविधाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आवास जलापूर्ति, सफाई, रोजगार, परिवहन संचार, बैंक, विद्युत आपूर्ति आदि प्रमुख हैं। इन आधारभूत सामाजिक सुविधाओं से सामाजिक क्षेत्र के जीवन स्तर में सुधार होता है, निर्धनता में कमी आती है। प्रस्तुत अध्याय में बस्ती जनपद की भानपुर तहसील में उक्त प्रमुख सामाजिक सुविधाओं के स्थानिक प्रतिरूप तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास और सामाजिक परिवर्तन में इनके योगदान को मूल्यांकित करने का प्रयास किया गया है तथा शोधार्थी द्वारा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार इसके सम्यक विकास हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

### 7.1 शिक्षा :-

शिक्षा मनुष्य के बौद्धिक और भावनात्मक विकास का एक अनवरत प्रयास है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़े, दृष्टिकोण सन्तुलित तथा सकारात्मक बने और वह एक उपयोगी और उत्तरदायी व्यक्ति बनकर समाज, परिवार, समाज और देश के जीवन में अपनी भूमिका निभा सके। गांधी जी ने कहा “शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे या प्रौढ़ के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुण का सर्वांगीण विकास करना है (कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2002 पृ0 17)।



मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यहाँ शिक्षा का अभिप्राय विद्यालयी शिक्षा से है। किसी राष्ट्र की सम्पन्नता या विकास का आकलन राजस्व की प्रचुरता, सार्वजनिक इमारतों की भव्यता से नहीं होता यह तो इस बात पर निर्भर है कि इसके नागरिक कितने स्वस्थ, कितने शिक्षित और कितने प्रगतिवादी हैं (ओड- 1986 पृ० 103)।

“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।” अरस्तू का यह कथन स्वास्थ्य और शिक्षा में पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर करता है। शिक्षा मानव समाज की अमूल्य विधि है। यह न केवल मानव समाज को ज्ञान के प्रकाश पुज से प्रकाशित करती है अपितु यह सम्पूर्ण राष्ट्र एवं समाज के सम्यक विकास का परिचायक भी है। शिक्षा देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक विकास के लिये महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा का प्रभाव कृषि उत्पादकता तथा औद्योगिक विकास में देखा जा सकता है। शिक्षा से ज्ञान के विकास के साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता तथा सामाजिक संरचना में सुधार होता रहता है। नवीन, नैतिक, मूल्यों का संरक्षण तथा पुरानी कुरीतियों अधविश्वासों के उन्मूलन में शिक्षा महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है।

विकास के मजिल की आधारशिला शिक्षा है। अधिकतम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम शिक्षा ही है प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी जो मुस्लिम काल में ‘मदरस’ के रूप में सामने आयी। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा की उन्नति हेतु भारत सरकार ने डा० एस० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा समिति (1948-49), डॉ० मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), संस्कृत आयोग (1956-57), स्त्री शिक्षा समिति (1957-59), नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा समिति

(1959), बाल कल्याण समिति (1961-62), शारीरिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय सेवा योजना समिति (1964), कन्या शिक्षा समिति, (1963-65), डॉ० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग (1964-66), आदि का गठन किया तथा उनसे प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों का अनुकरण करने का प्रयास किया (एस०के० तिवारी 1992)।

#### 7.1.1 वर्तमान शिक्षा का प्रतिरूप :-

अंग्रेजों के आगमन के बाद क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। वर्तमान शिक्षा का प्रतिरूप इसी का परिणाम है जिसके तहत बालक का विद्यालय जाना प्राथमिक शिक्षा से प्रारम्भ होता है और विश्वविद्यालय स्तर पर समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉ० कोठारी (1964-66) के अनुसार शिक्षा एक भवन है जिसकी तीन मजिले हैं - प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का भार प्राथमिक शिक्षा पर है अतः सरकार प्राथमिक शिक्षा के विकास पर तथा उसके सुधार पर अधिक ध्यान देती है।

#### 7.1.2 प्राथमिक शिक्षा :-

कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं जिसे सामान्यतः दो स्तरों में विभाजित किया जाता है जूनियर बेसिक स्कूल (कक्षा 1 से कक्षा 5 तक) और सीनियर बेसिक स्कूल (कक्षा 6 से कक्षा 8 तक) सन 1972 के पूर्व इसका नियन्त्रण स्थानीय निकायों द्वारा होता था। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नियन्त्रण अपने हाथों में ले लिया। सम्प्रति अध्ययन क्षेत्र में दो प्रकार के प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं (1) सरकारी विद्यालय (2) स्वायत्तशासी एवं स्थानीय निकायों द्वारा शामिल स्वपोषित विद्यालय। इस समय तहसील में कुल 190 जूनियर बेसिक स्कूल हैं जिनमें 100 सल्टौवा

**तालिका क्रमांक-7.1**  
**भानपुर तहसील : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें**

क्र० स०	विकास खण्ड	1989-90					2000-01				
		जूनियर स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल		हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट		जूनियर स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल		हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट	
			कुल	बालिका	कुल	बालिका		कुल	बालिका	कुल	बालिका
1	रामनगर	65	13	2	3	—	90	8	1	4	—
2	सल्टौआ	67	13	4	4	—	100	12	1	5	—
	तहसील भानपुर	132	26	6	7	—	190	20	2	9	—
	जनपद बस्ती	1354	295	65	104	7	1338	171	34	80	7

स्रोत : सांख्यिकीय प्रत्रिका जनपद बस्ती, 1990 एवं 2000 से संगठित।

गोपालपुर तथा 90 रामनगर विकास खण्ड में स्थित है। (सांख्यिकीय पत्रिका 2000) तहसील में प्रति जूनियर बेसिक स्कूल द्वारा सेवित जनसंख्या (2001 में) 1589 है। जबकि सल्टौवा विकास खण्ड में 1590 तथा रामनगर विकास खण्ड में 1588 जनसंख्या सेवित रही है। जूनियर बेसिक स्कूल में 129 जूनियर बेसिक स्कूल सरकारी (सरकार द्वारा वित्त पोषित) है। जिसमें 83 सल्टौवा विकासखण्ड में तथा 46 रामनगर विकास खण्ड में स्थित है जिसका उल्लेख शिक्षण संस्थाओं की सूची में किया गया है। अन्य जूनियर बेसिक स्कूल स्ववित्त पोषित एवं मान्यता प्राप्त है।

## तालिका क्रमांक 7.2

### भानपुर तहसील : शिक्षण संस्थाओं का विवरण-2002

(1) प्राथमिक शिक्षण संस्थाएँ

(1) (A) जूनियर बेसिक स्कूल (प्राइमरी)

रामनगर विकास खण्ड -

(1) परसा कुतुब	(17) भिटीमाफी	(33) औसानकुडवा
(2) चेसार	(18) शकरपुर	(34) असनहरा
(3) बसडिलिया	(19) पिरैलागरीब	(35) आदमपुर
(4) गन्धरिया	(20) डसावल	(36) धवाय
(5) चन्दोखवा	(21) इब्राहिम	(37) खैरा
(6) कोहडा	(22) रामनगर	(38) खरियापुर जगल
(7) बस्ती अलावल	(23) कुसुम्ही कुँवर	(39) खांगपुर
(8) पटवारिया	(24) परसा भिवर	(40) बेदौला
(9) भैसहिया	(25) नवौँ गाँवा	(41) करमहिया
(10) मझौवाखास	(26) जमोहना	(42) परसाकुडवा
(11) छितरगावा	(27) परसौहिया	(43) छठौडी
(12) अमोडीहा	(28) नरखोरिया	(44) भानपुर
(13) बेगनी	(29) बनवधिया	(45) बडोखर
(14) नरखोरिया	(30) उमरझरिया	(46) बरगदवा
(15) नथवापुर	(31) देईडीहा	
(16) बडौगी	(32) सगरा	

## जूनियर बेसिक स्कूल (प्राइमरी)

### सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड

(1) सल्टौआ (प्रथम)	(20) कनेथू	(39) घोरियाडीह
(2) बभनगावा	(21) मुडबरा	(40) पकरी भीखी
(3) कोठिला	(22) कोठिला	(41) भगवानपुर
(4) पचमोहनी	(23) भिवा	(42) दसिया
(5) परसालगडा	(24) तेनुआ	(43) मुनियॉव
(6) पिटापुर	(25) करमापाठक	(44) पिपराजप्ती
(7) सिसवाँ	(26) बघोडी	(45) दमया
(8) सेहबरा	(27) बनरही	(46) मझौवाकलॉ
(9) बस्तिया	(28) सेसुइया	(47) मिऊरा
(10) चौचवा	(29) सल्टौआ	(48) शिवपुर (आमा)
(11) शाहपुर	(30) बाघनवा	(49) आमवा
(12) खरहरा	(31) नरायनपुर	(50) जिनवा
(13) बिशुनपुरवा	(32) एकडगवा	(51) उमरा खास
(14) अमरौली	(33) रमवापुर	(52) मझौवा बाबू
(15) देईडीहा	(34) तुरकौलिया	(53) बदलापुर घनघटी
(16) बढया सदरहा	(35) डोरिकाचल	(54) बिछियॉव
(17) दुर्गापुर	(36) करमा	(55) मझौआ बैकुण्ठ
(18) महनुँआ	(37) धवरपारा	(56) बहरामपुर
(19) परसा झुगियॉ	(38) कल्यानपुर	(57) वासापार

(58) बहादुरपुर	(67) भादीखुर्द	(76) डेडवा
(59) पचरौलिया	(68) टिनिच शुक्ल	(77) लक्ष्मणपुर
(60) परसाखुर्द	(69) कडही	(78) परसा
(61) पडरी	(70) पुरैना	(79) सिसवारी
(62) पडरिया	(71) बिशुनपुरवा	(80) चेतारा
(63) हरदिया दिलौडी	(72) बखरिया	(81) बेलौहा
(64) जगदीशपुर	(73) मझौवा	(82) बसडिलिया
(65) अर्जुनवीरा	(74) जमलपुर	(83) हटवा
(66) बहेरिया	(75) सुभईराम	

**सीनियर बेसिक स्कूल (जू0हा0 स्कूल)**  
**रामनगर सल्टौआ गोपालपुर**

(1) नरखोरिया	(1) कोठिला
(2) बढोखर	(2) सल्टौआ
(3) शकरपुर	(3) शाहपुर
(4) भानपुर	(4) हसनपुर
(5) कलन्दरनगर	(5) सल्टौआ
	(6) दसिया
	(7) मझौवा बाबू
	(8) पिपराजप्ती
	(9) बिछियागज
	(10) अजगँवा जगल
	(11) परसा दमया

(2) माध्यमिक शिक्षण सस्थाये

हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट

## रामनगर

(1) किसान इन्टर कालेज, भानपुर

(2) मेहीलाल उच्चतर विद्यालय असनहरा

(3) सन्त कबीर राम विलास उ०मा०वि० मुहम्दाबाद (मुहम्मदनगर)

(4) आदर्श उ०मा०वि० बरगदवा

## सल्टौवा गोपालपुर

(1) जनता उच्चतर मा०वि० भिरिया ऋतुराज

(2) आदर्श इन्टर कालेज सल्टौवा गोपालपुर



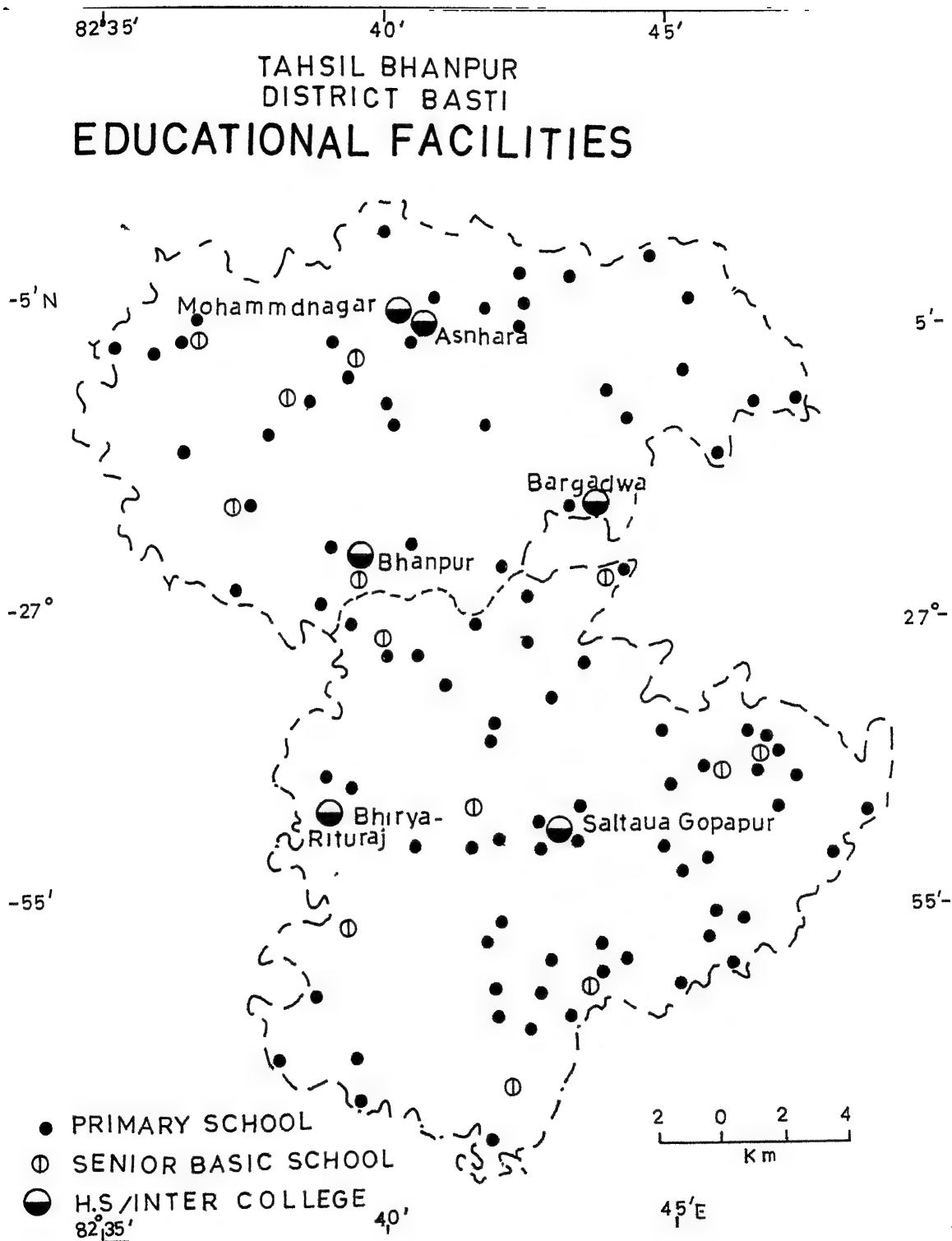


Fig. 7-1

तालिका 7.1 से स्पष्ट है कि तहसील में जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जहाँ 1989-90 में तहसील में कुल 132 जूनियर बेसिक स्कूल थे 2000-01 में बढ़कर 190 हो गयी।

अध्ययन क्षेत्र में कुल सीनियर बेसिक स्कूल की संख्या वर्तमान समय में 20 है जिसमें 12 सल्टौवा तथा 8 रामनगर विकास खण्ड में स्थित है। 1989-90 में सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 26 थी। इसकी संख्या कम होने का कारण नवीन तहसील का सृजन होना है क्योंकि रामनगर विकास खण्ड में तहसील के सृजन के पूर्व 11 न्यायपचायतें थीं। वर्तमान समय में इनकी संख्या 10 है। परसाइमाद न्यायपचायत डुमरियागंज तहसील में जाने से इसकी संख्या कम हो गयी (मानचित्र संख्या 7.1)

सीनियर बेसिक स्कूलों की कुल संख्या तहसील में 16 है। जिसमें सल्टौवा गोपालपुर में 11 तथा रामनगर में 5 है। जिनका उल्लेख शिक्षण संस्थाओं की सूची (तालिका 7.2) में किया गया है। तहसील में बालिका बेसिक स्कूलों की संख्या 2000-01 में मात्र दो है। ये विद्यालय भी मान्यता प्राप्त नहीं हैं। तहसील में शिक्षा के सम्यक विकास हेतु अभी कुछ नये विद्यालयों की आवश्यकता है।

### 7.1.3 माध्यमिक शिक्षा :-

प्राथमिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा के मध्य सेतु का कार्य माध्यमिक शिक्षा द्वारा होता है। बालक के विकास की किशोरावास्था से सम्बन्धित होने के कारण यह शिक्षा क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। उच्च शिक्षा के लिये माध्यमिक शिक्षा आधार शिला का कार्य करती है। इस शिक्षा के बाद बहुत के छात्र व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। माध्यमिक शिक्षा की भूमिका समाज के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रही

है। 1921 ई0 में माध्यमिक स्तर की परीक्षा संचालन हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। 1989-90 में तहसील में हाईस्कूल/इंटरमीडिएट कालेजों की संख्या 7 थी जो 2001 में बढ़कर 9 हो गयी। बालिका इंटरकालेज की एक भी संख्या तहसील में नहीं है। वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त सरकारी 6 माध्यमिक विद्यालय हैं। जिसमें 4 रामनगर तथा 2 सल्टौवा गोपालपुर में हैं।

तहसील की जनसंख्या तथा शिक्षा के स्तर को देखते हुए इनकी संख्या बहुत कम है। इस प्रकार तहसील में लगभग 33560 जनसंख्या पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है जो कि सल्टौवा गोपालपुर में 79,350 जनसंख्या पर एक माध्यमिक विद्यालय है। जो कि क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिये बहुत कम है। माध्यमिक विद्यालयों का अभाव शिक्षा के स्तर में गिरावट का मूल्य कारण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश विद्यालयों को 5 किमी तथा उससे अधिक दूरी पर ही माध्यमिक विद्यालय की सेवा मिल पाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में प्रति शिक्षक पर भारित छात्रों की संख्या भी सामान्य से अधिक है। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः क्षेत्र के शैक्षणिक विकास हेतु अधिक माध्यमिक स्तरीय बालिकाओं तथा बालकों के विद्यालयों की स्थापना की महती आवश्यकता है जिससे शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य सुगमता से प्राप्त किया जा सके। केवल एक बालिका माध्यमिक विद्यालय सोनहा में प्रस्तावित है। जबकि भानपुर, दसिया में भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु यह आवश्यक है कि सरकार क्षेत्र के समुचित विकास हेतु प्रस्तावित विद्यालयों को स्थापित करे, शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाये।

#### 7.1.4 उच्च शिक्षा :-

उच्च शिक्षा का अभिप्राय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा से है अध्ययन क्षेत्र में इसका अभाव है। एक भी उच्च शिक्षा का केन्द्र नहीं है। जनपद में 4 डिग्री कालेज है दो जनपद मुख्यालय घर ही है। शोधार्थी ने भानपुर तहसील मुख्यालय पर एक महाविद्यालय की आवश्यकता को महसूस किया है जिसको प्रस्तावित रखा है।

#### 7.1.5. प्राविधिक शिक्षा :-

तकनीकी व व्यासायिक शिक्षा के विकास के सुदृढ आधार पर ही कृषि उद्योग, परिवहन, अभियान्त्रिकी स्वास्थ्य आदि का विकास होता है।

तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से ही आर्थिक विपन्नता तथा सामाजिक विषमता को समाप्त किया जा सकता है किन्तु तहसील में एक भी तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा केन्द्र नहीं है। पूरे जनपद में एक राजकीय पालीटेक्निक, एक औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान तथा एक शिक्षण प्रशिक्षण सस्थान है। अध्ययन क्षेत्र के सम्यक विकास हेतु इस प्रकार के विद्यालयों की भी नितान्त आवश्यकता है, क्योंकि कृषि विकास तथा लघु उद्योग हेतु तकनीशियनों तथा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

#### 7.1.6. अनुसूचित जाति शिक्षा :-

अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक स्तर के विद्यालय के कुल छात्रों की संख्या में अनुसूचित जाति के छात्रों का भाग 1370 एवं इसी स्तर पर कुल छात्राओं में अनुसूचित जाति की छात्राओं का अंश 1632 रहा है। वर्तमान समय में तहसील में माध्यमिक स्तर के कुल छात्रों की संख्या 2170 है जबकि अनुसूचित जाति छात्राओं की संख्या 155% है। जबकि सीनियर बेसिक स्कूल में अनुसूचित जाति

के छात्रों की संख्या 36.27% तथा छात्राओं की संख्या 23.90% है। इस प्रकार छात्रों तथा छात्राओं दोनों वर्गों की संख्या सीनियर बेसिक स्कूल में अधिक है जिसका कारण नजदीक में विद्यालय की प्राप्ति तथा सरकार द्वारा दी गयी छात्रवृत्ति भी नामांकन की संख्या बढ़ाने में प्रेरणा का कार्य करती है। अनुसूचित जाति के छात्र नामांकन करवाकर मजदूरी करते हैं तथा सरकार की छात्रवृत्ति का उपयोग करते हैं उन्हें ज्ञानार्जन से कुछ नहीं लाभ होगा। माध्यमिक स्तर की शिक्षा छात्राओं की तो सल्टौवा विकास खण्ड की मात्र 0.52% है जो सबसे कम है। (2001 सांख्यिकीय पत्रिका)।

#### 7.1.7 स्त्री शिक्षा .-

स्त्री शिक्षा का अभाव भी ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन का एक कारण है। अध्ययन क्षेत्र में मात्र 31.50% महिलाओं की साक्षरता दर है जो क्षेत्र में स्त्री शिक्षा की निम्नतर स्थिति को प्रदर्शित करती है। सामाजिक विकास के लिये स्त्री शिक्षा का अधिक महत्व है।

राजनीतिक तथा रोजगार में महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित किये गये हैं जिससे महिलाओं का शिक्षा के प्रति झुकाव में वृद्धि हो परन्तु स्त्री शिक्षा की प्रगति बहुत सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक कुरीतियों का समाज में व्याप्त होना है। अभी भी पर्दाप्रथा का प्रचलन है तथा उनके आवागमन तथा मेल-मिलाप पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में यह जटिलताएँ कुछ अधिक प्रभावशाली हैं जिससे स्त्री शिक्षा के पर्याप्त विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।

विश्वास नहीं होता कि 21वीं सदी जिसे शिक्षा का युग कहा जाता है उसमें 21 गावों में हाईस्कूल उत्तीर्ण महिला नहीं है शिक्षा का यह स्तर जहाँ

सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति चलाये जा रहे अभियानों के लिये एक करारा तमाचा है वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2001 में मनाये गये नारी सशक्तीकरण वर्ष पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है।

विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के 21 गावों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की कोई भी महिला हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। यह बात सामने तब आयी जब स्थानीय बाल विकास परियोजना कार्यालय से आगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिका पद के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रकाशित किया गया। बाल विकास अधिकारी ने कथनानुसार विकास खण्ड के कोइलसा, हटवा, मुगरहा, शाहपुर, परसा-लगडा, भिरिया ऋतुराज, पचमोहनी, कोठिला, ससारपुर, हरदिया, साडी कलप, बेलवाडाड, पुरैना, पिपराजप्ती, बेलौहा, बसडिलिया, उमराखास, मुनिर्यौव, बनरही, लप्सी गोरखगाव, में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति में तीन व सामान्य में एक पद के लिये कोई भी महिला हाईस्कूल उत्तीर्ण नहीं मिली। जो बाल विकास परियोजना में बाधा पहुँचा रही है (28 अगस्त 2002, दैनिक जागरण, बस्ती जनपद)।

## **7.2. शिक्षा की समस्याएँ :-**

निम्न प्रमुख समस्याएँ हैं -

### **7.2.1 बेरोजगारी :-**

बेरोजगारी व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिये अभिशाप है इससे देश सामाजिक अस्थिरता व अशान्ति को प्रश्रय मिलता है। बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि किसी भी देश की सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता प्रदर्शित करता है। रोजगार अवसरों में कमी छात्रों को उपाधि हासिल में वृद्धि के संकेत देते हैं। नौकरी की लालसा में

छात्र आर्थिक सकट झेलते रहते हैं किन्तु स्वरोजगार की दिशा में कोई प्रयासरत नहीं करते हैं। हाल ही में सरकार ग्रामीण बेरोजगारों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की है जिसके माध्यम से शिक्षित तथा प्रशिक्षित बेरोजगार स्वयं रोजगार ढूँढ सकें। जवाहर रोजगार योजना का प्रयोग कर भी सरकार बहुत सफल नहीं हो पा रही है।

इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति में कुछ बुनियादी परिवर्तन किया जाय जिससे नवयुवकों में स्वालम्बन की भावना जागृति हो तथा सरकारी नौकरी का विकल्प निजी व्यवसाय बने। इसके लिये ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

#### **7.2.2. निर्धनता और अवसरों का अभाव :-**

प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक परिवार का धन बच्चों पर व्यय होता है। निर्धन परिवारों के बच्चों को शिक्षा कब और कहा मिले यही आज सरकार को जानने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे कस्बे से लेकर नगरों तथा महानगरों में आज पब्लिक स्कूलों के नाम पर शिक्षा के दूकानों की बाढ़ सी आ गयी है (उपाध्याय 1991 पृ० 20)

ग्रामीण स्कूलों में आवश्यक साधनों की अनुपलब्धता अभिभावकों की निरक्षरता व शिक्षा के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, लड़कियों की शिक्षा का विरोध, निर्धनता और जनसंख्या में विशाल वृद्धि में अनेक ऐसे कारण हैं जो शिक्षा के स्तर को गिराने में सहायक सिद्ध होते हैं।

#### **7.3. ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु नियोजन :-**

व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों का विकास शिक्षा का कार्य है। इससे व्यक्ति तथा समाज दोनों का उत्कर्ष होता है परन्तु वर्तमान शिक्षा अपने

उद्देश्यों में असफल रही है इसमें व्यवहारिकता का अभाव है। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार प्रदत्त होनी चाहिये। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि इसके निर्धारकों का सम्बन्ध तथा उद्देश्य शिक्षा के विकास से कम, राजनीतिक अधिक होता है अध्ययन क्षेत्र के शैक्षणिक उन्नयनार्थ आवश्यक है कि

- (1) तहसील की वर्तमान जनसंख्या तथा आकार को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के और अधिक विद्यालय स्थापित किये जाय।
- (2) उच्च शिक्षा के विकासार्थ तथा रोजगार हेतु कम से कम एक महाविद्यालय (तहसील मुख्यालय पर) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायें।
- (3) बालिका शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक स्तर के कम से कम तीन बालिका विद्यालयों की स्थापना की जायें।
- (4) शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जायें।
- (5) गरीब तथा विपन्न प्रतिभाशाली छात्रों को समुचित छात्रवृत्ति प्रदान की जायें।
- (6) शिक्षा की सभी योजना में समाज के सभी वर्गों के प्रबुद्ध लोगों का सहयोग लिया जाय।

ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक विकास में समाज के सभी वर्गों का यथोचित सहयोग लिया जाय।

इन सब जैसे कई कार्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है शिक्षा का विकास, विकास के सभी स्तर पर पहुँचाने का प्रयास किया जाय तथा क्षेत्र के विकास में सहयोग करे।



#### 7.4. ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्याएँ एवं निवारणार्थ सुझाव :-

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद नागरिकों की स्वास्थ्य में सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमों द्वारा काफी प्रयत्न किया है तथा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों स्वास्थ्य-वृद्धि अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है। जिसका कारण आधारभूत सुविधाएँ माने जा सकते हैं। अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य-उन्नति एवं अवरोधक विविध कारकों में प्रदूषित वातावरण, दूषित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं की परिमितता, शिक्षा की कमी आदि प्रमुख समस्याएँ हैं।

##### 7.4.1. प्रदूषित ग्रामीण पर्यावरण :-

ग्राम्य पर्यावरण में वह शुद्धता नहीं रह गयी है जो पहले थी। इस समस्या का प्रमुख कारण अशिक्षा, निर्धनता, वस्तुओं के अनियोजित प्रारूप आदि से है ग्रामीण बस्तियों के सर्वेक्षण के दौरान दृष्टिगोचर हुआ कि ग्रामीणलोग प्रायः आवासों के आस-पास कम दूरी पर ही खुले में मलत्याग कहते हैं जबकि जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। अधिवासों के चतुर्दिक व्याप्त गन्दगी से इन क्षेत्रों में विविध प्रकार के रोग-सवाहक कीटाणु उद्भूत होते हैं। जिनसे ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग व्याधिग्रस्त हो जाता है। वातावरण तथा स्वच्छता हेतु ग्रामीण जनता को अत्यधिक शिक्षित किया जाय।

##### 7.4.2. दूषित पेयजल :-

अध्ययन क्षेत्र में पेयजल के मुख्य क्षेत्र कुये एवं हस्तचालित नलकूप और हैंडपम्प हैं। भारत सरकार नीदरलैण्ड सरकार के सहयोग से सम्पूर्ण देश में शुद्ध जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु 'पाइलट प्रोजेक्ट' चला रही है। जिसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में पाइलट प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है।

### 7.4.3. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायें :-

किसी भी तरह के विकास के लिये उत्तम स्वास्थ्य आवश्यक है। स्वास्थ्य का अभिप्राय मात्र शारीरिक दुर्बलता एवं व्यक्तियों का परिवार ही नहीं, वरन् इसका तात्पर्य शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता से है इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अध्ययन क्षेत्र विविध प्रकार की व्याधियों, एवं चेचक, मलेरिया जैसे अनेक महामारियों से ग्रस्त था। भारत सरकार ने अलमा अटाप्रस्ताव (1978) द्वारा सन् 2000 तक "सबके लिये स्वास्थ्य" का लक्ष्य रखा गया है।

सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा पद्धति 'एलोपैथ' है। सन् 1989-90 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 8 थी जबकि 2000-01 में इसकी संख्या 9 हो गयी। समस्त उपलब्ध सेवाओं की संख्या 32 थी जो कि अब 56 पहुँच गयी है तहसील में 1989-90 में परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मात्र 2 था जबकि परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र 45 थे। डाक्टर की संख्या 6, पैरामेडिकल की संख्या 102 तथा अलग 12 है।

वर्तमान समय में (2000-01) में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 56 उपलब्ध शैयाओं की संख्या, 3 डाक्टर, 90 पैरामेडिकल, 9 अन्य हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल एक रामनगर में है। 2, परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं। परिवार एवं मातृ शिशु सेवा केन्द्र 42 है। इस प्रकार तहसील में उत्तम स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवाओं की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि किसी भी स्थान विशेष के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि उनके निवासियों के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है।

अध्ययन क्षेत्र में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। प्रत्येक कुंये, तालाब एवं तालाब स्थानों में वर्ष में कम से कम 3-4 बार

कीटाणु नाशक दवा डाली जाय और प्रत्येक गाव मे दवाओ का निशुल्क वितरण किया जाय।

#### 7.4.4. नशीले पदार्थों के प्रति बढ़ती अभिरुचि :-

स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या है नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों सुधारकों की तुलना में अनुषंगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि का होना है। शोधार्थी के द्वारा क्षेत्र के अध्ययन में विभिन्न आयु वर्ग लोगों से साक्षात्कार के समय उनकी मानसिकता के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि इसमें 68% लोग सुरापान को आधुनिकता और उच्च मानसिक का प्रतीक मानते हैं, लगभग 25% लोगों को शारीरिक थकान को दूर करने वाला साधन लगता है।

धूम्रपान करने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 2/3 लोग अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के होते हैं। तम्बाकू का सेवन सभी वर्ग तथा जाति के लोग करते हैं। विगत दशक में युवा वर्ग की तम्बाकू सेवन की प्रवृत्ति अत्यन्त तीव्रता से बढ़ी है। होली, दीपावली तथा कोई अन्य पर्व पर कुछ लोग उत्तेजक नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं जिसका प्रभाव व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्धों, परिवार आदि पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

#### 7.4.5. स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी :-

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अत्यन्त कमी है इसके अतिरिक्त जो कार्यरत हैं भी उनमें जीवन रक्षक औषधियों, चिकित्सकों, परिचारिकाओं निदान उपकरणों तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधा का अभाव है।

कुशल चिकित्सकों की नियुक्ति भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है। सरकारी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या काफी होती है।

अतः अध्ययन क्षेत्र के विकास तथा स्वास्थ्य सुधार हेतु और अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है तथा न्यूनतम खर्च पर ग्रामीण व्यक्ति को यह सुविधा मुहैया करवायी जाय।

#### 7.4.6. ग्रामीण रूढ़िवादिता :-

आधुनिक युग में भी ग्रामीण समाज का एक भाग आज भी अतिरूढ़िवादी है। इस प्रकार के लोग भूत, प्रेत, टोना, जादू में ज्यादा विश्वास करते हैं। झाड़-फूक से अपने आपको अनेक व्याधियों का शिकार बनाते हैं। बाद में ये रोग लाइलाज हो जाते हैं। अतः रूढ़िवादिता परम्पराओं का शिक्षा तथा उचित मार्गदर्शन द्वारा निवारण अनिवार्य है।

ग्रामीण स्वास्थ्य की प्रथम आवश्यकता ग्रामीण जनसंख्या को शिक्षित करके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। सरकार द्वारा नवीनतम सुविधा सम्पन्न चिकित्सालय स्थापित किये जाये और तीन-चार माह में चिकित्सक प्रत्येक ग्राम में जाकर ग्रामीण जनता को उत्तम सुविधा हेतु सामान्य जानकारी प्रदान करे।

#### 7.5. पेयजल सुविधा :-

जल जीवन का आधार है। जल मानव जीवन तथा समस्त जीवधारियों और वनस्पतियों के लिये परम आवश्यक आधारभूत साधन है देश की अर्थव्यवस्था में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूजल का दोहन सीधे उपभोक्ताओं के नियन्त्रण में होने से यह विभिन्न उपयोगों के लिये प्राथमिक साधन बन गया है। भूजल ने पेयजल तथा सिंचाई के साधन के रूप में महत्व अर्जित किया है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में भूजल का योग 9% है।

जनसख्या वृद्धि के कारण अनियन्त्रित और अन्धाधुन्ध इस्तेमाल तथा सरक्षण के अभाव में भूजल स्तर में चार मीटर से अधिक गिरावट आयी है। अध्ययन क्षेत्र में हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क-2 द्वारा पेयजल की सुविधा 65 गावों को मिलती है। इससे तहसील की 59,750 जनसख्या लाभान्वित हो रही है। रामनगर विकासखण्ड में इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प की संख्या 1,172 है। वहीं सल्टौआ विकास खण्ड में कुल हैण्ड पम्पों की संख्या 1,309 है। दोनों विकास खण्डों के लगभग सभी न्याय पंचायतों के ग्राम पंचायतों में सरकारी हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। सभी आबाद ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता हो गयी है।

#### 7.6. बैंक :-

ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु भारत सरकार ने 1969 ई० में बैंको ने राष्ट्रीय कारण के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित व्यावसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में 7 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की संख्या 6 है। जबकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक 2 हैं अर्थात् कुल बैंको की संख्या 15 है। इसकी संख्या को तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। मानचित्र में बैंको की स्थिति का निरूपण भी किया गया (मानचित्र 7.2)।

## तालिका क्रमांक-7.3

जनपद बस्ती — 2002

बैंक शाखाओं की संख्या एक दृष्टि में

			भानपुर
(1)	भारतीय स्टेट बैंक	23	2
(2)	पंजाब नेशनल बैंक	15	5
(3)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	06	—
(4)	इलाहाबाद बैंक	02	—
(5)	बैंक ऑफ बडौदा	01	—
(6)	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	02	—
(7)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	01	—
(8)	भूमि विकास बैंक	02	—
(9)	बस्ती ग्रामीण बैंक	40	6
(10)	जिला सहकारी बैंक	17	2
(11)	अरबन कोऑपरेटिव बैंक	1	
	योग	110	15

तहसील भानपुर : बैंक शाखाओं की सूची

बैंक	रामनगर	सल्टौवा
(1) भारतीय स्टेट बैंक	भानपुर बाबू	पुरैना
(2) पंजाब नेशनल बैंक	रामनगर, तुषायल	सल्टौवा, लक्ष्मिनपुर भिरिया ऋतुराज
(3) जिला सहकारी बैंक	भानपुर बाबू	सल्टौवा
(4) बस्ती ग्रामीण बैंक	असनहरा, शकरपुर, सगरा	टिनिच, सोनहा दसिया

स्रोत : भारतीय स्टेट बैंक मार्गदर्शी बैंक कार्यालय जनपद बस्ती

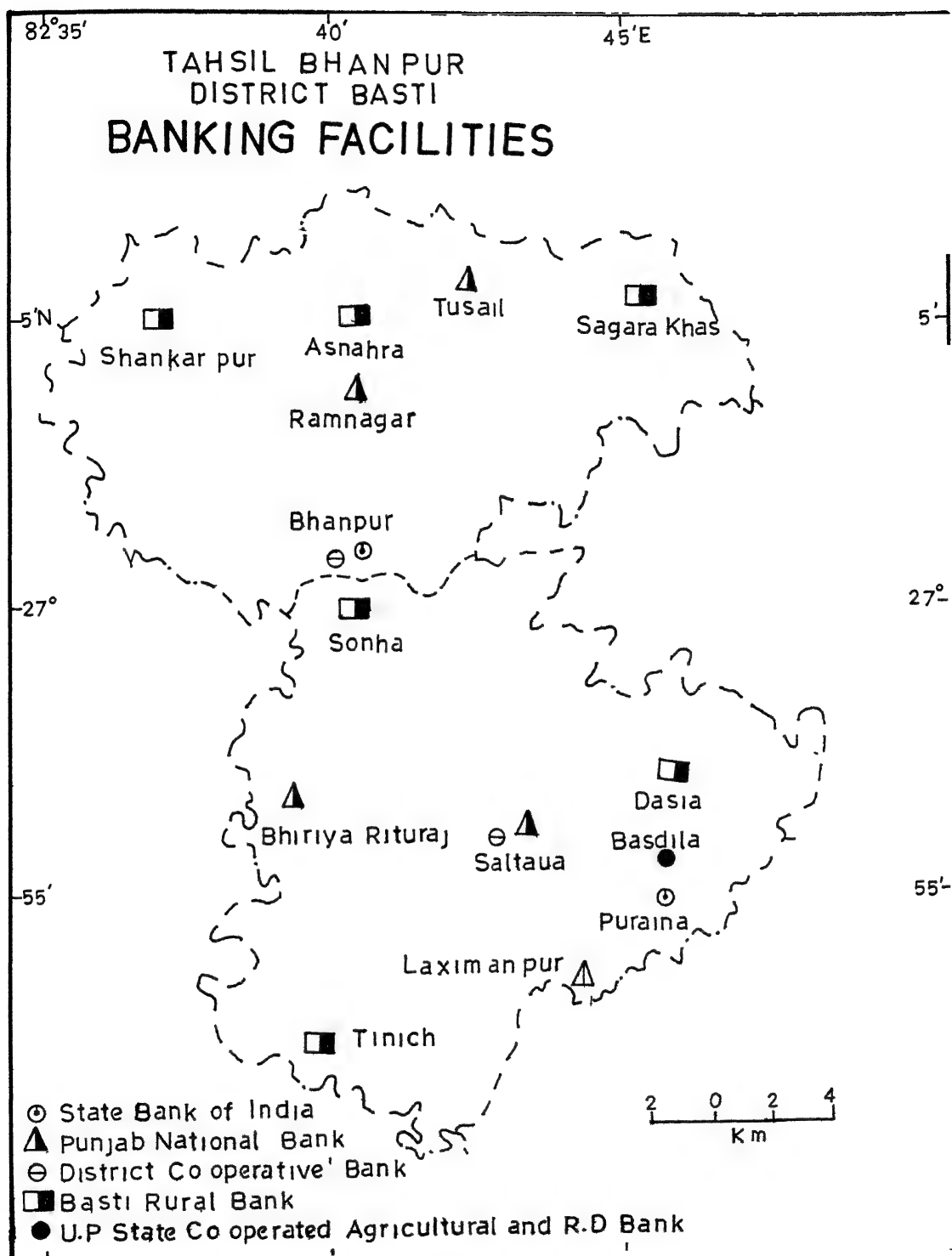


Fig.7-2

## 7.7 विद्युत आपूर्ति :-

ग्रामीण विकास के रूप में ऊर्जा मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है देश के आर्थिक विकास तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिये पोषण के बाद ऊर्जा का मुख्य स्रोत विद्युत की आपूर्ति है। विद्युत की आपूर्ति रूढ़ौली विद्युत उपकेन्द्र से पूरी की जाती है। तहसील भानपुर में विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत बढ़ता रहा है। अध्ययन क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों की कुल संख्या (जिसमें एल0टी0 मेन्स लगा दिये गये हैं) 272 है। विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियों की संख्या तहसील में 197 है। बहुत से ग्राम ऐसे हैं जहाँ अभी भी विद्युत की लाइनें नहीं सुलभ हो पायी हैं। सर्वेक्षण के दौरान शोधार्थी ने (ग्राम बरडाड नानकार) ग्राम पंचायत बाकेचोर बरगदवा रामनगर विकास खण्ड को पाया कि यहाँ पूरे ग्राम में विद्युत की आपूर्ति नहीं है लेकिन फिर भी लोग लगभग सभी भौतिक सुविधाओं (टी0वी0 टेपरिकार्डर तथा ट्राजिस्टर) मनोरंजन हेतु रखे हुये हैं। सल्टौवा विकास खण्ड में दसिया न्यायपंचायत के ग्राम पंचायत मुगरहा के राजस्व ग्राम बरगदवा का सर्वेक्षण किया। जहाँ अभी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पायी है लेकिन लोगों में जागरूकता रही है तथा मनोरंजन के साधनों का प्रयोग लोग बैटरी से कर रहे हैं। बिजली की आपूर्ति जल्द ही हो जाने की सम्भावना है। सर्वेक्षण के दौरान ग्रामवासियों से पता चला कि बिजली के खम्भे तो काफी दिनों से पास हो गये थे लेकिन लग नहीं रही थी लेकिन अब खम्भे आ गये हैं इसलिये बिजली आ जाने की सम्भावना है। ऐसे तहसील में बहुत ग्राम हैं। जहाँ विद्युत आपूर्ति अभी नहीं हो पायी है।



बिजली आपूर्ति ही कृषक के सिचाई का प्रमुख आधार है बिजली आपूर्ति न रहने से ग्रामवासियों का 1/2 समय अधरे में रहने से वे अपना कोई भी कार्य सुचारु ढंग से नहीं कर पाते हैं।

#### 7.8 नागरिक सुरक्षा :-

किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा वहाँ के पुलिस प्रशासन विभाग तथा राज्य सरकार की है। सुरक्षा किसी देश को प्रगति के पथ अग्रसर की प्रेरणा देता है। जो सुरक्षित है वही विकास कर सकता है। तहसील में मात्र एक पुलिस स्टेशन (थाना) सोनहा में है जो वर्तमान में तहसील मुख्यालय है। नागरिक सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है। अध्ययन क्षेत्र में मात्र एक पुलिस चौकी असनहरा (रामनगर विकास खण्ड) में है। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सल्टौवा दसिया में पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। सल्टौवा विकास खण्ड के बहुत से ग्राम रुघौली पुलिस स्टेशन (थाना) के अन्तर्गत आते हैं जिनके विवादों का निस्तारण तथा सुरक्षा का कार्य रुघौली थाना ही करता है, जो रुघौली विकास खण्ड में है।

#### 7.9 सामाजिक समस्याएँ :-

समाज की कुछ परम्पराओं एवं मान्यताएँ होती हैं इन मान्यताओं में रूढ़ियाँ, धर्मान्धता, अशिक्षा आदि समाज के विकास में बाधक हैं जिन्हें सामाजिक समस्या के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक दो रूपों में समस्याएँ होती हैं। ग्रामीण समाज रूढ़िवादी होने के कारण पारम्परिक प्रथाओं पर पूर्णतः अवलम्बित होता है। यह इन प्रथाओं पर औचित्य एवं तर्क की अपेक्षा अन्धानुकरण की अपना कर्तव्य एवं धर्म समझता है। जिससे ग्रामीण सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अध्ययन क्षेत्र की कतिपय प्रमुख सामाजिक समस्याएँ

दहेज प्रथा, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, अस्पृश्यता, बालमजदूर पर्दाप्रथा आदि है।  
जिनके कारण ग्रामीण विकास का चरमोत्कर्ष नहीं हो सकता है।

### 7.9.1 दहेज प्रथा :-

दहेज प्रथा अपने आप में एक अभिशाप है, 'दाइज' देने की परम्परा का विकृत रूप अब दहेज प्रथा के रूप में हमारी नारीजाति को काल का ग्रास बना रहा है, इसी कुप्रथा के कारण प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियाँ मौत के मुह में ढकेल दी जाती हैं। कन्या की शादी में प्राचीन काल से ही माता-पिता तथा सगे सम्बन्धियों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने की परम्परा रही परन्तु अब धन देने के लिए बर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को विवश किया जाता है, धन के अभाव में हमारे समाज की कन्याएँ अयोग्य लोगों के साथ परिणय सूत्र में बधने के लिए बाध्य होती हैं। आज दहेज हमारे दोहरे मानसिकता का परिणाम भी दिखाई देता है। एक तरफ तो हम इसकी निन्दा करते हैं परन्तु अपने लड़कों की शादी में हम दहेज लेने से नहीं चूकेगे, और बहाना ये बताते हैं कि हमने अपनी लड़कियों की शादी में दहेज दिया है, परन्तु हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि "हम सुधरेगे जग सुधरेगा।" इस क्षेत्र में लोगों को दहेज के बिना विवाह करके एक आदर्श समाज के सामने रखना होगा ताकि अन्य लोग इससे प्रेरणा ले, यद्यपि कि दहेज प्रथा को (1961), 1984, 1986 के अधिनियम (भारतीय दण्ड संहिता) अन्तर्गत निवारित किया गया है, परन्तु यह सामाजिक समस्या है। समाज स्तर से इसका मुख्य विरोध होना चाहिए और उस प्रत्येक परिवार का विरोध होना चाहिए जिसने भी दहेज लेने का प्रयास किया है। बृहद आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के साथ यदि किसी चीज में तीव्र वृद्धि हुई है तो वह नकद राशि और भौतिक वस्तुओं के रूप में दहेज की मात्रा है" (कपाडिया 1986)।

दहेज के समबन्ध में सर्वेक्षण के दौरान शोधार्थी के विभिन्न आयु वर्गों के लोगो से साक्षात्कार करने पर मात्र 5 से 6% लोगो ने ही पुत्र विवाह में दहेज न लेने का विचार व्यक्त किया। 95% से अधिक लोगो ने कहा कि अपने लड़की की शादी में दहेज हमको देना पड़ा है तो हम अपने लड़को की शादी में दहेज अवश्य लेंगे। समाज के लोग अब अधिक दहेज लेना परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। यही हमारे समाज की बिडम्बना है कि हम अपने को दिखाते कुछ और हैं परन्तु वास्तविक रूप कुछ और है इसी सब की परिणित इस कुप्रथा को बढ़ावा दे रही है। जिसे रोका जाना हर प्रबुद्ध भारतीय का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

#### 7.9.2 जाति व्यवस्था :-

जाति व्यवस्था बुराईयो का एक ऐसा दलदल है जिससे जनसमुदाय में विलगाव, घृणा, ईर्ष्या, उत्पीडन, शोषण आदि दुर्गुणों का जन्म होता है। जाति प्रथा के कारण ही समाज के लोग दूसरे से अलगाव महसूस करते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता बाधित होती है। जाति-व्यवस्था समुदाय द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत नियमों की एक कार्यात्मक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत उद्देश्य पूर्ण रूप से सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया गया है। (मार्गवेट-1969 पृ० 183)।

जाति व्यवस्था का स्पष्ट उद्देश्य जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को निर्धारित करके अपेक्षाकृत एक बन्द समाज का निर्माण करना है। सामाजिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था स्थिरता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ समय तक अवश्य उपयोगी रही लेकिन आज यह सामाजिक विघटन और जातीय पदानुक्रम को प्रदत्त अधिकारों के कारण शोषण का एक

प्रतीक बन गयी है जिससे समाज में जातिवाद की दुर्भावना का विकास हुआ है इससे अध्ययन क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है।

व्यक्ति के अन्दर जब जातिवाद का बीजारोपण हो जाता है तो वह व्यक्ति परोपकार, सामाजिक भातृत्व तथा न्याय एवं समानता के विचारों को त्याग देता है और केवल अपने जाति के लोगों के बारे में सोचने लगता है। इससे वह अपनी जाति के लोगों को लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया में दूसरी जाति के लोगों का नुकसान भी कर बैठता है। राजनैतिक दलों ने विभिन्न जातियों के मध्य पायी जाने वाली प्रतिस्पर्धा की भावना का फायदा उठाया है। चुनाव अब किसी ठोस कार्यक्रम के आधार पर जीते नहीं जाते बल्कि जातीय समीकरणों के हेर फेर पर जीते जाते हैं (सेगल – 1982, पृ० 247)। इसी तरह बहुत से नेता चाहे वे केन्द्र के या राज्य के हों अपनी-अपनी जातियों या क्षेत्र के प्रतीक माने जाते हैं। जाति व्यवस्था द्वारा जन्म से ही व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण कर देने से अध्ययन क्षेत्र की अनेक जातियाँ दूसरे प्रकार के लाभदायक व्यवसाय करने में अपने को असमर्थ पाते हैं जाति के प्रतिबन्धों के कारण ही व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। जाति व्यवस्था के कारण ही लोग विभक्त होकर छोटे-छोटे समूहों में बंट जाते हैं। जिससे समाज में भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का जन्म होता है। इससे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी भारतवासियों को सार्थक प्रयास करने होंगे। आरक्षण पद्धति को समाप्त करके जातिवाद निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण पर प्रतिबन्ध और अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देकर हम समाज में फैली जाति व्यवस्था नामक बुराई का अन्त कर सकेंगे तदुपरान्त हमारा समाज विकास पथ पर आगे बढ़ सकेगा।

### 7.9 3. अस्पृश्यता :-

अस्पृश्यता हमारे समाज में एक कोढ़ के समान व्याप्त है, इसके कारण हमारा धर्म, समाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, यह एक मानव जनित समस्या है, ईश्वर ने मनुष्यों को बनाने में कोई भेद भाव नहीं किया और सारे प्राणी उस परम पिता की सन्तान हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम चरित्र मानस में लिखा है – “अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर महि बराबरि दाया (उत्तरकाण्ड पृ० 405–574 राम चरित मानस)। फिर ऐसी कौन सी प्रतिष्ठा हम समाज में आरोपित करते हैं, जिसके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपस में साथ-साथ उठ बैठ नहीं सकते, खान-पान पर प्रतिबन्ध लगा है। अस्पृश्यता एक ऐसी बुराई है जिस पर निर्मम प्रहार की आवश्यकता है ताकि समाज में समरसता व्याप्त हो सके, हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। फिर भी अस्पृश्यता जाति व्यवस्था के समान सामाजिक समस्या है “अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो बहुत सी सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक अयोग्यताओं से पीड़ित हैं जिनमें से अधिकांश अयोग्यताओं को परम्परा द्वारा निर्धारित करे सामाजिक रूप से उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया है (मजूमदार, 1976)। जातिगत आधार पर अपने को उच्च मानने वाले लोग अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं।

इस पर पूर्ण रूप से अकुश नहीं लग पा रहा है। हमें समय रहते इस बुराई पर विजय प्राप्त करनी है, तभी भारतीय समाज पूर्णतः अक्षुण्ण रह पायेगा।

### 7.9.4. पर्दा प्रथा :-

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने कहा था कि ‘वेदों की ओर लौटो’ इस कथन का कारण था वैदिक समाज का एक आदर्श समाज होना उस समाज में

पर्दाप्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं नहीं थी, इस समय हम नारी को सचमुच अर्द्धांगी के रूप में देखते हैं जब वह शिक्षा, शासन, युद्ध, सामाजिक समारोहों में पुरुष के साथ-साथ खड़ी दिखाई देती है परन्तु सूत्र काल के आरम्भ होते ही इस पर्दा रूपी ग्रहण ने हमारी नारी जाति को अपने आगोश में कर लिया, जिसका रूप क्रमशः तुर्कों एवं मुगलों के आगमन के साथ और भयंकर होता गया इसी कुप्रथा ने नारी जाति के सभी अधिकार छीन लिए और इसको घर की चहारदीवारी में कैद रहने को बाध्य कर दिया। नारी जाति अब न तो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और न ही खुले रूप से सामाजिक समारोहों में भाग ले सकती थी। इसके विरोध में ब्रम्हसमाज, आर्यसमाज, स्वामी विवेकानन्द, थियोसोफिकल सोसाइटी इत्यादि ने आवाज बुलन्द की तो इस प्रथा का विभीषिका कुछ शान्त सी दिखाई देने लगी।

यह पर्दा प्रथा एक अनिष्टकारी प्रथा है इसने पुरुष से उसकी आधी शक्ति को छीन लिया है। इसलिए हम सभी का परम कर्तव्य है कि स्वतन्त्र बनाये गये घेरे से नारी को स्वतन्त्रता प्रदान करें और इस कुप्रथा को समाप्त करके, नारी को इस योग्य बना दें कि आधुनिक भारत में विकास के पथ पर स्त्री और पुरुष साथ-साथ आगे बढ़ सकें।

अध्ययन क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों की संख्या में अत्यन्त कमी का मुख्य कारण पर्दा प्रथा के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र में किसी भी महाविद्यालय का न होना भी शामिल है।

#### **7.9.5. बालविवाह :-**

बाल विवाह अध्ययन क्षेत्र की एक समस्या है। अध्ययन क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उसके अनुसार वंश वृद्धि की उत्कट अभिलाषा

अशिक्षा, दहेजप्रथा, लडके-लडकियों के दुश्चरित्र हो जाने का अभिभावकों का भय, सामाजिक दबाव, विवाह को एक भारपूर्ण जिम्मेदारी समझने की मानसिकता आदि बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण हैं। लडकियों के ऊपर अपरिपक्व मातृत्व का भार तथा बाल दम्पति पर बच्चों के पालन पोषण के दायित्व का निर्वाह से उनके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि में बाल विवाह की भी भूमिका होती है। बाल-विवाह पर अकुश सरकारी विधान है किन्तु अपेक्षित अकुश नहीं लग सका है। सर्वेक्षण के दौरान यह देखने में आया कि बाल-विवाह अशिक्षित परिवारों में ही ज्यादा प्रचलित है और जिन परिवारों के सदस्यों की साक्षरता अधिक है उनमें यह कुरीतियाँ नहीं हैं।

#### 7.9.6. सामाजिक वर्जनायें :-

ग्रामीण समाज में सामाजिक प्रथा के रूप में अनेक वर्जनाये विद्यमान हैं। ये सामाजिक प्रथाये चूँकि समाज के स्वीकृत व्यवहार का स्थायी रूप हैं, अतः समाज भी इसी के अनुकूल कार्य करता है। प्रथाये जनरीतियो एव रूढियो का वह स्वरूप है जिन्हे समाज व्यावहारिक और अनुभव के आधार पर स्वीकार करता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित होती रहती है। इन्हें ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक धरोहर कहा जाता है। ये प्रथाये इसलिये मानी जाती हैं क्योंकि ऐसा होता आया है। समाज के रूढिवादी होने का प्रभाव ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास पर पड़ता है। ग्रामीण समुदाय अभी भी अन्धविश्वासों, जादू, टोना, झाड़-फूंक आदि अनेक वर्जनाओं से ग्रस्त है जिसे सभ्य समाज मान्यता नहीं देता है।

ये प्रथाएँ ही धर्म, जाति, आवास, वस्त्र भोजन आदि के मानदण्डों का निर्धारण करती हैं। जन्म से मृत्यु तक के धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारों का आयोजन इन्हीं मान्यताओं से प्राप्त है। धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं से समाज निर्देशित तथा नियन्त्रित होता है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सामाजिक स्तर नहीं प्राप्त है। इनकी कोई स्वतन्त्रता नहीं है। स्त्रियों द्वारा पति को देवरूप मानकर उसके प्रत्येक उचित, अनुचित आदेशों का पालन करना, परिवार के बड़े सदस्यों की सेवा करना तथा घर के अन्दर रहना ही उनका परम कर्तव्य माना जाता है। ग्रामीण समाज में सर्वर्ण जातियों की बहुते मात्र मायके जाने अथवा चिकित्सकीय उपचार के लिये ही घर की सीमा से बाहर जाती हैं वह भी किसी पुरुष के संरक्षण में। समाज में आज भी विधवाओं को अपशुन माना जाता है। सन्तानहीन स्त्री को ग्रामीणजन, बौझ शब्द की संज्ञा देते हैं। पुरुष प्रधान समाज है।

इस प्रकार ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसका मूल कारण अशिक्षा एवं निर्धनता है। यदि अध्ययन क्षेत्र की जनता को साक्षर बना दिया जाये और प्रत्येक व्यक्ति (स्त्री, पुरुष, दोनों) को व्यावसायिक तथा उच्च शिक्षा न्यूनतम खर्च में सुलभ करा दिया जाय तो उपरोक्त सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन अपने आप ही हो जायेगा।





## REFERENCE

- Kothari, D S., 1964 The Indian Educational Policy, The Educational Review,  
Vol 15, Part 1, p 16
- Kapadia, K M 1986 Marriage and family in India, oxford University Press  
Bombay p 165
- Mishra, R S , 1992 . Rural Development and Social change in Allahabad  
District, Unpublished Thesis, Allahabad University, p 275.
- Majumdar, D N 1976 Races and culture of India, University Publication,  
Delhi p 226
- Margaref, H. 1969 A Dictionary of Sociology, Routledge and kegar paul Ltd  
London, p 183
- Segal R 1982 Crisis of India, Publication Department, New Delhi, p 247.
- Tiwari, S K., 1993 Rural Development And Social change in Independent  
India A case study of Phulpur Tahsil of Azamgarh District p. 222
- Upadghaj, D D. 1991 Critics on new education policy, Asia Press, New Delhi  
p 20.
- कुरुक्षेत्र, अक्टूबर 2002 पृ0 117 ग्रामीण विकास मन्त्रालय कृषि भवन नयी दिल्ली।
- भारतीय स्टेट बैंक, मार्गदर्शी बैंक कार्यालय, जनपद बस्ती।
- भारत 2002 प्रकाशन विभाग सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, नयी दिल्ली।
- तुलसीदास गोस्वामी . रामचरित मानस उत्तर काण्ड – दोहा संख्या 86 के उपरान्त  
सौतवी पक्ति; गीता प्रेस गोरखपुर

## ग्रामीण विकास के स्तर और सामाजिक परिवर्तन

प्रस्तावना :-

मानव अपने आर्थिक विकास के लिये प्राकृतिक ससाधनो का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में निरन्तर प्रयोग करता चला आ रहा है। ससाधनो का उपयोग जितना सुव्यवस्थित और अधिक होता है विकास का स्तर उतना ही उच्च होता है। विकास के उच्चस्तर से समाज में परिवर्तन आता है। ग्रामीण विकास के स्तर को ज्ञात करने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं। जिनमें से कुछ व्यक्तिगत तथा कुछ सस्थागत रूप में रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सस्थान, हैदराबाद सामाजिक व आर्थिक विकास की नीति और कार्यक्रमो की जाँच करता है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में उसके प्रभाव के स्तर को निर्धारित किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के स्वातन्त्र्योत्तर कालीन ग्रामीण विकास के स्तर को निरूपित करने का प्रयास किया गया है इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में विकास में विभिन्नता तथा ग्रामीण सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तनो का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

### 8.1 ग्रामीण विकास के सूचकांक :-

स्वतन्त्र भारत में विभिन्न योजना कालो, उत्तर प्रदेश सरकार तथा वित्त आयोगो के गठन के माध्यम से क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण विकास के लिये किये गये सभी प्रयासों ने सभी क्षेत्रों को एक समान रूप से प्रभावित नहीं किया है जो क्षेत्र ससाधन तथा तकनीकी दृष्टि से समृद्ध थे वही विकसित हो पाये हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में विषमताएं ही बढ़ी हैं।

अध्ययन क्षेत्र में इन्हीं विषयों को इंगित करने के लिये न्यायपचायत स्तर पर ग्रामीण विकास के लिये निम्नलिखित पांच प्रमुख अवयवों को आधार मानकर विकास के स्तर का निर्धारण किया गया है।

- (1) कृषि
- (2) उद्योग
- (3) शिक्षा
- (4) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- (5) परिवहन यातायात एवं संचार व्यवस्था

प्रस्तुत तथ्यों के अध्ययन वर्ष 1989-90 और वर्ष 2000-01 के मध्य की अवधि में ग्रामीण विकास के स्तर को कुछ प्रमुख सूचकांकों के सहयोग से निर्धारित किया गया है।

### **कृषि विकास के सूचकांक**

- (1) कृषि घनत्व
- (2) सकल बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत।
- (3) शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का सकल सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत।
- (4) शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत।
- (5) प्रतिहेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन।
- (6) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन।
- (7) व्यावसायिक फसलों के क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत।

### **शैक्षिक विकास के सूचकांक**

- (1) प्रति 100 किमी क्षेत्र पर जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या।
- (2) प्रति 100 किमी क्षेत्र पर सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या।

- (3) प्रति 100 किमी क्षेत्र पर हायर सेकेण्डरी/इन्टर कालेजों की संख्या।
- (4) प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या।
- (5) प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या।
- (6) प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्डरी/इन्टर कालेजों की संख्या।
- (7) ग्राम से एव 1 किमी से कम दूरी पर जूनियर बेसिक स्कूलों की सुविधा प्राप्त करने वाले ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत।
- (8) ग्राम से एक 1 किमी से कम दूरी पर सीनियर बेसिक स्कूलों की सुविधा प्राप्त करने वाले ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत।
- (9) ग्राम में एव 1 किमी से कम दूरी पर हायर सेकेण्डरी स्कूल/इन्टर कालेज की सुविधा प्राप्त करने वाले ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत।
- (10) साक्षरता

#### स्वास्थ्य एवं संचार साधनों के विकास के सूचकांक

- (1) प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में पक्की सड़कों की लंबाई।
- (2) प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या।
- (3) पक्की सड़कों से संयोजित ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत।
- (4) ग्राम में ही बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन की सुविधा प्राप्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत।
- (5) ग्राम में ही डाकघर की सुविधा प्राप्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत।
- (6) प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र पर डाकघरों/डाक एव तारघरों की संख्या।

## औद्योगिक विकास के सूचकांक

- (1) प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र पर पजीकृत लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या।
- (2) उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या।
- (3) उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत।
- (4) उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या का कुल कार्यशील जनसंख्या से प्रतिशत।
- (5) प्रति लाख जनसंख्या पर पजीकृत लघु उद्योगों की संख्या।

इन सूचकांकों के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र की 21 न्यायपंचायतों के वर्ष 1989-90 और वर्ष 2000-01 के विकासात्मक अन्तर को क्रमबद्ध किया गया है। न्यायपंचायत की स्वतन्त्रता के बाद विकास की स्थिति ज्ञात करने के लिये ग्रामीण विकास के उपर्युक्त पांचो अवयवों में से प्रत्येक के आधार पर प्रत्येक न्यायपंचायत की विकासात्मक प्रवृत्ति को ज्ञात किया गया है। इस प्रकार न्यायपंचायतों के विकासात्मक प्रवृत्ति को तीन वर्गों में तीव्र विकास, मध्यम विकास और न्यून विकास में विभक्त किया गया है। यह विभाजन 1989-90 और 2000-01 के मध्य हुये विकास अन्तरालों को घटते हुये क्रम के आधार पर श्रेणी बद्ध करके किया गया है। यदि किसी न्यायपंचायत में ग्रामीण विकास की प्रवृत्ति तीव्र है तो इसका अभिप्राय यह है कि अन्य न्यायपंचायतों की तुलना में अमुक न्यायपंचायत में वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 2000-01 के मध्य की अवधि में सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके विपरीत यदि किसी पंचायत की विकास प्रवृत्ति अतिमन्द है तो इसका आशय है कि उस न्यायपंचायत में अन्य न्यायपंचायत की तुलना में (वर्ष 1989-90 वर्ष 2000-01 की अवधि में) न्यूनतम विकास हुआ है। पुनः ग्रामीण विकास के

प्रकार के सूचकांको की प्रवृत्तियों की बारम्बारता के आधार पर प्रत्येक न्याय पंचायत का ग्रामीण विकास स्तर निर्धारित किया गया है।

## **8.2. ग्रामीण विकास के स्तर :-**

### **8.2.1 कृषि-विकास :-**

अध्ययन क्षेत्र के विकास का प्रमुख आधार कृषि है। जिस पर जनसंख्या का भार सर्वाधिक है। अध्ययन क्षेत्र के कृषि-विकास की प्रवृत्ति को निरूपित करने के लिये कृषि सम्बन्धी सात सूचकांको को अनुप्रयोग करके इनकी बहुलता के आधार पर समस्त न्यायपंचायतों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कलन्दर नगर, नरखोरिया, सल्टौवा, रामनगर, पचानू, कोठिला खास तथा दसिया न्यायपंचायतों में उर्वरकों का अधिक प्रयोग साक्षरता, उच्च शस्य गहनता, आदि कारणों से कृषि विकास की दर तीव्र रही है जबकि सगरा, घोषण, शकरपुर, बडोखर, भानपुर, भिरिया ऋतुराज तथा परसादमया में कृषि विकास की प्रवृत्ति मध्यम रही है शेष न्यायपंचायतों में कृषि के नवीनतम तकनीकों तथा उन्नतशील बीजों एवं उर्वर क्षेत्रों की कमी आदि कारणों से कृषि विकास अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है।

### **8.2.2. ग्रामीण शैक्षणिक विकास :-**

अध्ययन क्षेत्र में शैक्षणिक विकास की प्रवृत्ति के निर्धारण हेतु 10 सूचकांको को आधार बनाया गया है। विद्यालयों की सुलभता तथा जनपद मुख्यालय के समीप होने के कारण पिपराजप्ती का शैक्षिक विकास सबसे अधिक हुआ इसके साथ ही सल्टौवा, नरखोरिया, परसादमया का शैक्षणिक विकास तीव्रगति से हुआ है। जबकि पुरैना, कोठिला खास, सगराखास, थुम्हवा पाण्डेय दसिया, बडोखर, कलन्दरनगर न्यायपंचायत में मध्यम शैक्षणिक विकास की गति है। शेष 10

न्यायपचायतो में विद्यालयों का अभाव जनचेतना की कमी के कारण शैक्षणिक विकास मन्द है।

#### 8.2.3. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं का विकास :-

ग्रामीण विकास तथा सामाजिक उन्नति के लिये उत्तम ग्रामीण जन स्वास्थ्य अत्यावश्यक है। किसी भी क्षेत्र का विकास स्तर ज्ञात करने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की सुविधा का सूचकांक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक होता है। अध्ययन क्षेत्र में न्यायपचायतो की स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की सुविधाओं के विकास स्तर निर्धारण में 4 सूचकांकों को प्रयोग किया गया है। सल्टौवा, भानपुर, भिरिया ऋतुराज, नरखोरिया, पिपराजप्ती, सगराखास में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं में तीव्र विकास हुआ है। दसिया, परसादमया, कोठिला खास, तुषायल, पचमोहनी तथा जिनवा न्यायपचायतो में स्वास्थ्य सुविधाओं में मध्यम गति से और शेष 9 न्यायपचायतो में मन्द अथवा अति मन्द से विकास हुआ है। इस प्रकार तहसील के स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास सन्तोषजनक नहीं है।

#### 8.2.4. ग्रामीण यातायात एवं संचार साधनों का विकास :-

यातायात, संचार साधनों के अर्न्तगत सड़क मार्ग, डाकघर, तारघर, बसस्टॉप और रेलवे से सम्बन्धित 6 प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग करके सम्पूर्ण क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। भानपुर, सल्टौवा, पुरैना, नरखोरिया, आमा, कलन्दरनगर में संचार एवं यातायात साधनों का तीव्र विकास हुआ है। दसिया, परसादमया, जिनवा, पचानू भिरिया ऋतुराज, सगराखास न्यायपंचायतो में यातायात एवं संचार के साधनों के विकास की गति मध्यम जबकि शेष 9 न्यायपचायतों की गति मन्द है।

### 8.2.5 ग्रामीण औद्योगिक विकास :-

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में उद्योग काफी सहायक होते हैं क्योंकि इनसे न केवल आर्थिक लाभ होता है अपितु ग्रामीण संसाधनों का अधिकतम उपभोग भी होता है तथा अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। ग्रामीण औद्योगिक विकास स्तर का निर्धारण लघु उद्योगों से सम्बद्ध 5 सूचकांकों के आधार पर किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में उद्योग नगण्य है। भानपुर नरखोरिया तथा सल्टौवा न्यायपंचायतों में ही कुछ औद्योगिक विकास हुआ है वह भी बहुत छोटे पैमाने पर। बृहद अथवा मध्यम स्तर की कोई इकाई नहीं है ये लघु या कुटीर उद्योग के रूप में माने जा सकते हैं।

### 8.3. समेकित ग्रामीण विकास स्तर :-

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र का कुछ क्षेत्र कृषि की दृष्टि से, कुछ शैक्षणिक दृष्टि से, कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं तथा यातायात एवं संचार के साधनों के आधार पर विकसित है, किन्तु इससे अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भागों का समेकित विकास स्तर स्पष्ट नहीं होता। अतः न्यायपंचायतों के समेकित विकास स्तर के निर्धारणार्थ ग्रामीण विकास के पाँचों सूचकांकों के विकास स्तरों का योग करके इन्हें क्षेणीबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के तीन विकास स्तर विकसित क्षेत्र, विकासशील क्षेत्र एवं अविकसित क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं।

अध्ययन क्षेत्र का विकसित क्षेत्र अन्य भागों की तुलना से अपेक्षाकृति सर्वाधिक विकसित है। किन्तु इसे प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय विकास मानक के आधार पर नहीं माना जाना चाहिये। इसी प्रकार विकासशील तथा अविकसित क्षेत्र भी मात्र क्षेत्रीय अर्थ में है।



# THASIL BHANPUR

## TRENDS IN LEVEL OF RURAL DEVELOPMENT

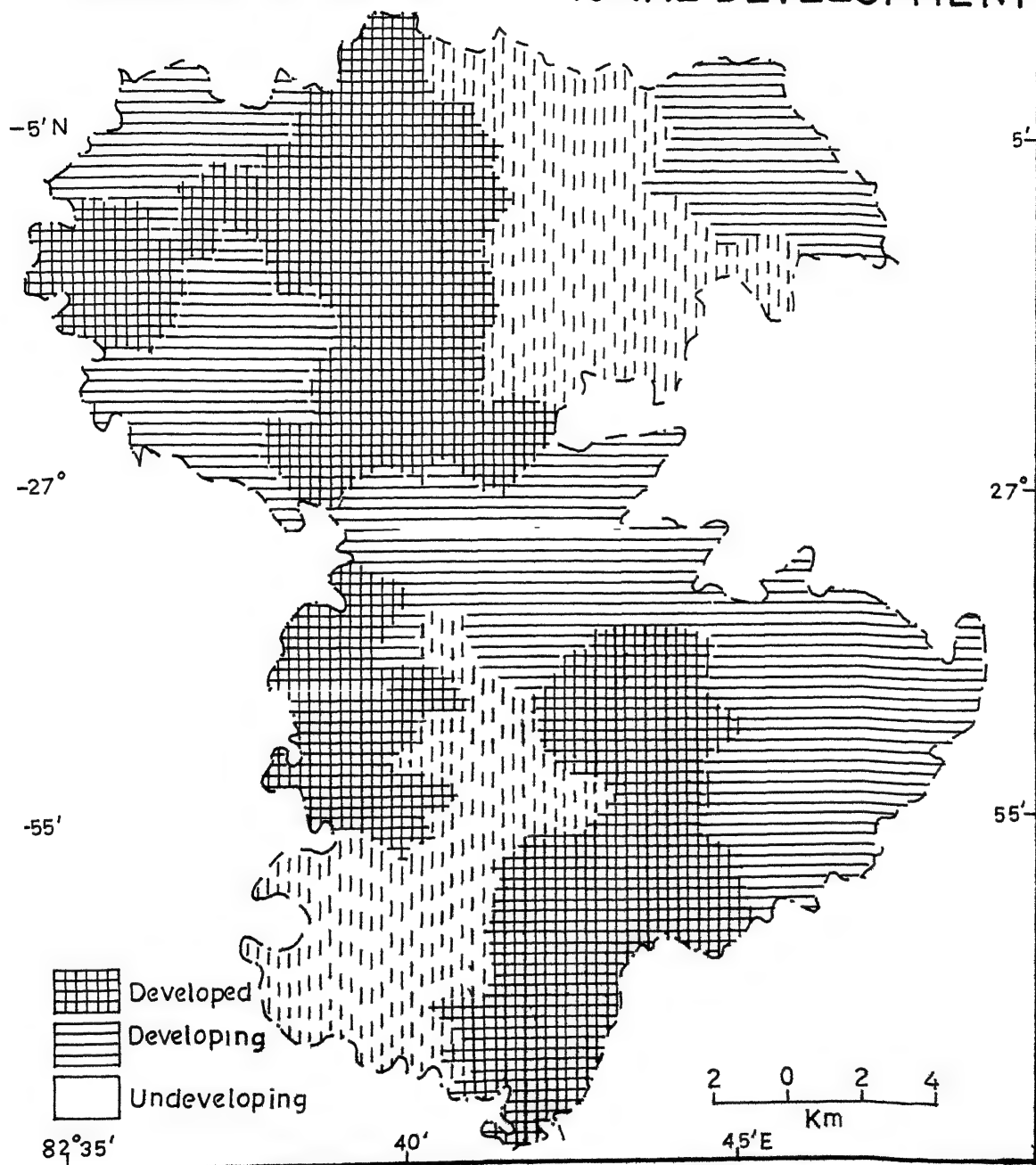


Fig.8-1

### 8.3.1. विकसित ग्रामीण क्षेत्र

विकसित क्षेत्र के अर्न्तगत अध्ययन क्षेत्र की 8 न्यायपचायते आती है जिसमे सल्टौवा, भानपुर, पिपराजप्ती, नरखोरिया, रामनगर, कलन्दरनगर भिरिया ऋतुराज तथा जिनवा है जो तहसील में 38% लगभग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार सम्पूर्ण तहसील का एक तिहाई भाग ही विकसित श्रेणी के अर्न्तगत आता है विकास खण्डों में रामनगर विकास खण्ड सर्वाधिक विकसित है। विकसित श्रेणी के अर्न्तगत समाहित होने वाली न्यायपचायतों में अन्य न्यायपचायतों के अनुपात में कृषि, शिक्षा, यातायात एवं संचार सम्बन्धी, स्वास्थ्य सेवाओं आदि का अधिक विकास हुआ है (मानचित्र संख्या 81)

### 8.3.2. विकासशील ग्रामीण क्षेत्र :-

अध्ययन क्षेत्र की 8 न्यायपचायते विकासशील हैं जो तहसील के 35% से अधिक क्षेत्र को आकृष्ट किये हुये हैं इसमें सल्टौवा गोपालपुर की 5 न्याय पचायते परसादमया, दसिया पुरैना, कोठिला खास तथा पचमोहनी आती हैं तथा 3 न्यायपचायते सगरा खास, शकरपुर तथा बडोखर राम नगर विकास खण्ड के अर्न्तगत आते हैं। विकासशील क्षेत्रों में कुछ सुविधाओं का प्रचुर विकास हुआ है जबकि कुछ ग्रामीण सुविधाओं का अभाव भी पाया गया है।

### 8.3.3. अविकसित ग्रामीण क्षेत्र :-

अविकसित ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सामाजिक सुविधाओं का सबसे कम उन्नयन हुआ है तहसील के 35% भूभाग को आविष्टित करने वाली तहसील की 5 न्यायपंचायते आती हैं सल्टौवा गोपालपुर की पचानू तथा आमा न्यायपचायते तथा रामनगर की तुषायल, थुम्हवा पाण्डेय तथा घोषण न्याय पंचायतें आती हैं।

पिपराजप्ती का साक्षरता सबसे अधिक होने के कारण यह विकसित क्षेत्रों के समान है।

उपरोक्त विवरण में तहसील के कुछ क्षेत्र विकसित श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु यदि विकास के अन्तर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर देखा जाय तो सम्पूर्ण अध्ययन प्रदेश पिछड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का प्राथमिकता दी है और सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं, जिसमें से अधिकांश वर्तमान समय में कार्यरत हैं यद्यपि अध्ययन क्षेत्र विकास के स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है जिसका मुख्य कारण साक्षरता में कमी तथा सरकारी कर्मचारियों की निष्क्रियता है अध्ययन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि ग्रामीण जनता को शत प्रतिशत साक्षर बनाया जाय जिससे ये सरकार द्वारा प्राप्त सरकारी सुविधाओं एवं सहयोग का अधिकतम सदुपयोग कर सकें तथा देश, समाज के विकास में योगदान कर सकें।

#### 8.4. ग्रामीण सामाजिक जीवन में परिवर्तन परिदृश्य :-

स्वतन्त्रता के उपरान्त देश के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति को अपने विकास कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु बनाया। योजनाओं के संचालन हेतु सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना पंचायती राज, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार आदि जैसी क्रान्तिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। स्वतन्त्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता में तीव्रगति से प्रगति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। यह परिवर्तन अध्ययन क्षेत्र में परिलक्षित हो रहे हैं। ग्रामीण परिवार की संरचना, वैवाहिक कार्यक्रम रीतिरिवाज

वेशभूषा एवं खानपान, आवास व्यवस्था, धार्मिक कार्य, रहन सहन तथा मानव मूल्यों आदि में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। गतिशील परिवर्तित समाज में सदैव परिवर्तन होते रहना सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन घनात्मक तथा ऋणात्मक दो रूपों में होता है।

सामाजिक परिवर्तन के दोनों रूपों को अध्ययन क्षेत्र में देखा जा सकता है जहाँ एक तरफ ग्रामीण समाज में साक्षरता, कृषि, उद्योग व्यापार, यातायात संचार खान-पान, आवास व्यवस्था, चिकित्सा आदि सुविधाओं से घनात्मक परिवर्तन हुआ है। ग्राम विकास में उन्नति हुई है वहीं दूसरी तरफ इसका कुप्रभाव से भौतिकता तथा व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति में वृद्धि होने से मानवीय मूल्यों एवं नैतिकता में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, जो विकास की उत्तरोत्तर प्रगति में बाधक सिद्ध होती है।

#### 8.5. सामाजिक जीवन पद्धति में परिवर्तन :-

यातायात संचार तथा कृषि विकास के साधनों में वृद्धि होने तथा शैक्षणिक सुविधाओं अपर्याप्तता ने ग्रामीण जनसंख्या के एक वर्ग को नगरोन्मुख किया है। आज ग्रामीण जनता रेडियो तथा दूरदर्शन एवं समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों से अवगत हो रहा है जिसका प्रभाव उसके सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक जीवन तथा जीवन पद्धति में होने वाले प्रमुख परिवर्तन अध्ययन क्षेत्र में दिख रहे हैं जिसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है।

##### 8.5.1. ग्रामीण पारिवारिक संरचना में परिवर्तन :-

अध्ययन क्षेत्र में परिवार मूलतः संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित थी जिसमें एक परिवार, एक मकान में एक मुखिया के नेतृत्व में रहते थे। परिवार के

सदस्यो द्वारा अर्जित धन सामूहिक माना जाता था। परस्पर अपनत्व तथा सामूहिक विकास की भावना होती थी परिवार का मुखिया आयु प्रधान होता था। जिसके आज्ञा का पालन प्रत्येक परिवार का कर्तव्य माना जाता था। व्यक्ति की पहचान उस परिवार से होती थी। वर्तमान में नगरीय संस्कृति तथा सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। एकाकी परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब परिवार सम्बन्धी कोई भी निर्णय लेने में मुखिया या वयोवृद्ध के एकाधिकार के स्थान पर युवापीढ़ी तथा महिलाओं का भी सहयोग लिया जाता है। उस प्रकार परिवार में बच्चों तथा स्त्रियों की भी समाज में भागीदारी बढ़ रही है।

#### 8.5.2. वैवाहिक परम्परा में परिवर्तन :-

समाजकी पारस्परिक वैवाहिक परम्परा में विवाह अपनी जाति के सदस्यों में ही होते थे किन्तु समगोत्रीय तथा अन्य जाति से विवाह निषिद्ध था। वैवाहिक सम्बन्धों का निर्धारण पूर्णतः लड़की के पिता या अभिभावक पर निर्भर करता था कि उसका किस परिवार में हो। इस सन्दर्भ में लड़की एवं लड़के का विचार जानना आवश्यक नहीं था। वैवाहिक कार्यक्रम कई दिनों तक चलता था। ग्राम नहीं पूरे क्षेत्र के लोग बाराती होते थे। बारात दो-तीन दिन तक कन्या पक्ष के अतिथि के रूप रहती थी। कन्या पक्ष को कन्यादान के साथ-साथ बहुत सारी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती थी। विवाह के बाद भी लड़की पिता या अभिभावक के घर पर ही रहती थी पुनः लड़के के यहाँ से कुछ दिन बाद बारात आती थी तब लड़की की बिदाई होती थी। (जिसे क्षेत्रीय भाषा में गौना कहा जाता है)।

समाज में होने वाले व्यापक परिवर्तनों का प्रभाव ग्रामीण वैवाहिक परम्परा पर भी पड़ा है बाल विवाह की प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है और युवा-विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है। विवाह में चुनाव (लड़की देखने की) की प्रथा का आविर्भाव हुआ है। विवाह में लड़के लड़कियों के भी विचार लिये जा रहे हैं। उनसे भी विचार विमर्श किया जा रहा है। वैवाहिक कार्यक्रमों के दिनों की संख्या घटकर एक हो गयी है कहीं कहीं तो दिन भर में ही विवाह का कार्य सम्पन्न कर दिया जा रहा है। भौतिकता तथा विवाह के अवसर पर अति प्रदर्शन की भावना से दहेज की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो विवाह जैसे पवित्र सम्बन्ध को कलंकित कर रही है। अब विवाह में लड़कियों की शिक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ रहा है।

#### 8.5.3. जाति-व्यवस्था :-

भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक संरचना की आधार शिला है। जातिगत आधार पर व्यवसाय का निर्धारण एवं सामाजिक पदानुक्रम अध्ययन क्षेत्र में दिखाई पड़ता है जातिगत व्यवसाय करना ही श्रेयस्कर माना जाता था। उच्चजातियों के कुछ अपने विशेषाधिकार होते थे तथा वे निम्नजातियों को अछूत मानते थे। किसी वस्तु के स्पर्श से ही वह वस्तु अपवित्र मान लिया जाता था क्योंकि स्पर्श करने वाला व्यक्ति निम्न जाति का है। शिक्षा में प्रसार, ग्रामीणों की नगरीय जनसंख्या से सम्पर्क, वृद्धि, निरन्तर बढ़ती आवश्यकताओं, सरकारी नीति, आदि विभिन्न कारणों से ग्रामीण जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है। उच्चनिम्न में सामाजिक विभेद कम हुआ है निम्नवर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अध्ययन क्षेत्र के बाजारों, दुकानों पर दृष्टिगोचर होता है जहाँ सभी वर्ग के लोग एक साथ एक दुकान पर जलपान करते हैं फिर भी कोई पात्र अपवित्र नहीं माना जाता है।

व्यवसाय अब व्यक्तिगत हो गया। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति स्वनिर्णय से व्यवसाय कर सकता है। उदाहरणार्थ – पहले दूकान मात्र वणिक वर्ग का कार्य माना जाता था जो वर्तमान में ब्राम्हण, क्षत्रिय, जैसी उच्च जातियाँ भी करने लगी हैं। दुग्धव्यवसाय से लेकर चाय की दुकान तक की व्यवसाय में विभिन्न जातियों के लोग सलग्न हैं। जातिगत विभेद तथा पदानुक्रम में कमी आयी है किन्तु जातिगत आधार पर वोट (चुनाव) की राजनीति ने अध्ययन क्षेत्र में समाज में जातीयता की भावना को प्रबल किया है जिससे आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है तथा वर्ग संघर्ष की सम्भावना भी बनी रहती है।

#### 8.5.4. आहार में परिवर्तन :-

समाज में पहले शाकाहारी भोजन प्रमुख आहार था जिसमें दुग्ध, घी की अधिकता होती थी तथा मासाहारी भोजन निषिद्ध था। ब्राम्हण जाति अपने शाकाहारी आहार के कारण ही समाज में सम्मान पाता था। समाज में शाकाहारी लोग समादरणीय होते थे। जबकि मासाहारी हेय तथा अछुत माने जाते थे किन्तु वर्तमान समय में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के आहार के सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतः भिन्न हो गयी। आज शाकाहारी लोग सकुचित मानसिकता के माने जाने लगे हैं। सर्वोच्च स्थान प्राप्त ब्राम्हण जाति के कुछ लोगों में मासाहार की प्रवृत्ति बढ़ी है जबकि परम्परागत मासाहारी लोग शाकाहार के प्रति उन्मुख हो रहे हैं। आहार में घी तथा दूध की मात्रा कम हो गयी है। पेय पदार्थों में चाय का सर्वाधिक प्रचलन हुआ है। पहले के जलपान में दूध गुड़ के शरबत, चना अनाज का स्थान बिस्कुट ने तथा डबल रोटी ने ले लिया है। देशी घी का स्थान वनस्पति घी ने ले लिया। शराब पीना आधुनिकता का प्रतीक माना जा रहा है। आहार प्रकार में वृद्धि हुई है किन्तु प्रति व्यक्ति आहार की मात्रा में काफी कमी

आयी है। पात्रो में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। स्टील पाउडर कौंच तथा प्लास्टिक निर्मित पात्रो का उपयोग किया जा रहा है।

#### 8.5.5. परिधान में परिवर्तन :-

ग्रामीण सामाजिक सुविधाओं में उन्नयन का ग्रामीण परिधान पर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। वस्त्रों की निर्माण सामग्री, आकार में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है पहले सूती वस्त्रों (रंग बिरंगे नहीं) का प्रयोग होता था पुरुष वर्ग सूती धोती, अगरखा तथा काण्ठ निर्मित खड़ाऊ के स्थान पर टेरीकाट, टेरीउल से बनी पैण्ट, कोट, टाई, और चर्म निर्मित जूतों चप्पलों का अधिक प्रयोग करने लगा है।

पगड़ी पहनने की प्रथा लगभग समाप्त हो रही है। विभिन्न प्रकार के पाश्चात्य टोपियों का प्रयोग बढ़ रहा है। सूती कपड़ा पहनना महिलाएँ अपना अपमान समझती हैं, इनके परिधान में भी पूर्ण परिवर्तन नजर आ रहा है। लडकियाँ भी लडकों की भाँति पैट तथा टी शर्ट का प्रयोग परिधान के रूप में करने लगी हैं।

#### 8.5.6. आवास व्यवस्था में परिवर्तन :-

अध्ययन क्षेत्र में अभी भी मिट्टी के बने कच्चे मकान दिखने को मिलते हैं लेकिन पक्के आवासों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। आवासों में ही स्नानघर तथा शौचालय का निर्माण किया जा रहा है जो कि पहले पोखरो तथा खेतों के माध्यम से किया जाता था। नगरीय आवासों के माडल पर ही ग्रामीण आवास बनाये जा रहे हैं। भवन निर्माण में लोग सुनियोजित ढंग से आवास मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं।



### 8.5.7. ग्रामीण सामुदायिक जीवन :-

अध्ययन क्षेत्र की यजमानी प्रथा द्वारा ग्रामीण जातियाँ परस्पर सम्बद्ध रही हैं यजमान पारिवारिक आधार पर वशानुगत हुआ करते थे जिन्हें यजमानी सेवाओं के यवज में अस्थायी भूमि तथा जन्म, मृत्यु, विवाह यज्ञ आदि आयोजनों के अवसरों पर भोजन वस्त्र या द्रव्य दिया जाता था किन्तु वर्तमान समय में यह प्रथा समाप्त हो रही है। कई पीढ़ियों से यजमानी, कार्य करने वाली जातियों (नाई, धोबी, कहार, लोहार दर्जी आदि) के युवा वर्ग इस प्रथा को अपना अपमान तथा शोषण समझने लगे हैं। ये यजमान दूकानों के माध्यम से नकद मौद्रिक भुगतान के माध्यम से अपनी प्रथा का निर्वाह कर रहे हैं यजमानी प्रथा का प्रचलन कम हो रहा है लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर यजमानों की उपस्थिति (विवाह में नाई की) अति आवश्यक मानी जाती है।

### 8.6. धार्मिक क्रिया कलाओं में परिवर्तन :-

समाज में प्रत्येक कार्य के साथ कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान मान्यता, परम्परा सलग्न है। लगभग प्रत्येक कार्य का शुभारम्भ धार्मिक अनुष्ठान से ही होता है। पहले पूर्वजन्म, परलोक, धर्म, ईश्वर आदि मान्यताओं को दैनिक कृत्यों में करना आवश्यक माना जाता था जैसे हिन्दू धर्म में स्नानोपरान्त जल चढ़ाना मन्त्र, पूजा पाठ, मुस्लिमों द्वारा नमाज आदि आवश्यक माना जाता था जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। युवापीढ़ी अब धार्मिक, अन्धानुकरण के स्थान पर रीति रिवाजों की तार्किक उपादेयता को महत्व दे रही है। यही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत कारणों से अलग धर्मानुपायियों में झगड़े होते हैं, किन्तु साम्प्रदायिक झगड़ों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है।

### 8.7. ग्रामीण मनोवृत्ति एवं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन :-

कृषि, शिक्षा, उद्योग स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं के उत्कर्ष, नगरो से सम्पर्क वृद्धि आदि के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनसंख्या की मनोवृत्तियों तथा उनके सामाजिक मूल्यों में व्यापक परिवर्तन हुआ है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहले परोपकार, त्याग, सादा जीवन, सामाजिक आदर्श माने जाते थे जिनका स्थान आज स्वार्थपरता एवं भौतिकता ने ले लिया है। पहले लोग पुण्य अर्जित करना जीवन का अन्तिम एवं परम लक्ष्य मानते थे वही अब अर्थाजन अन्तिम लक्ष्य हो गया है। मासाहार तथा शराब पीना कुलीन वर्ग तथा आधुनिकता का प्रतीक माना जाने लगा है।

सामाजिक मूल्यों आदर्शों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाता है। समानता का अधिकार प्राप्त हो रहा है।

मनोवृत्ति का ही परिणाम है कि कोई भी व्यवसाय जाति विशेष का नहीं रह गया है समस्त जातियों द्वारा कही भी किया जा सकता है। बाल विवाह में कमी, छुआछुत की समाप्ति, विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता, परिवार नियोजन तथा विकास आदि ग्रामीण सामाजिक मूल्यों एवं प्रवृत्तियों के परिवर्तन के ही परिणाम हैं।

यद्यपि मनोवृत्ति में परिवर्तन में प्राचीन परम्पराएँ एवं मान्यताएँ अपने आप अस्तित्व खोती जा रही हैं किन्तु उनको प्रश्रय देने वाले भी समाज में विद्यमान हैं इसलिये अध्ययन क्षेत्र में सभी प्राचीन परम्पराएँ विद्यमान हैं।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि आज अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। कुछ परिवर्तन अच्छी दिशा

मे हुये हैं जिनके परिणामस्वरूप गावों का आधुनिकीकरण हो रहा है किन्तु कुछ परिवर्तन ऐसी भी हुए हैं, जो गावों के परम्परागत सहयोग एवं सामूहिक जीवन को समाप्त कर रहे हैं। इसके परिवार स्वरूप स्थिति त्रिशुलक जैसे हो रही है। क्योंकि ग्रामीणवासी न तो प्राचीन पद्धति को छोड़ पाये हैं और न ही आधुनिकता को पूर्णतः स्वीकार कर पाये हैं इस संक्रमण स्थिति में नैतिक मूल्य पूर्णतः प्रभावित हुये हैं।

#### 8.8 अध्ययन क्षेत्र के उन्नयन हेतु सुझाव :-

शोध कार्य में अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण से प्राप्त अनुभवों तथा सरकारी आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की समुन्नति हेतु कतिपय सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

- (1) ग्रामीण विकास की योजनाओं के निर्माण का कार्य पंचायत, न्यायपंचायत, अथवा विकास खण्ड स्तर पर तैयार किया जाना चाहिये। उन योजनाओं के निर्माण कार्यान्वयन में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों की सहभागिता होनी चाहिये। सरकारी कर्मचारी केवल परामर्श एवं सहयोग कर्ता के रूप में कार्य करें।
- (2) ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम के ससाधनों का सर्वेक्षण कर समुचित उपयोग हेतु विकास योजनाएँ तैयार की जायें।
- (3) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
- (4) ग्रामीण कच्चे मालों को संशोधित एवं वर्धित कर घरेलू तथा लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये।
- (5) कृषि विकास हेतु कृषकों को आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये जिसकी अवधि नये फसल काल तक अवश्य होनी चाहिये।

- (6) भण्डारण एवं विपणन की समुचित व्यवस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत में होनी चाहिये।
- (7) ग्रामीण बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये। सरकार कानून के माध्यम से शिक्षा को अनिवार्य तो कर दी है लेकिन अभिभावक तथा परिवार का कर्तव्य है कि बच्चों की शिक्षा में समुचित योगदान है।
- (8) ग्रामवासियों को स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं कल्याण की जानकारी दी जानी चाहिये।
- (9) जनसम्पर्क एवं जनसंचार माध्यमों से ग्रामों में ऐसी सामाजिक चेतना को विकास किया जाना चाहिये कि जिससे सामाजिक कुरीतियों तथा पाश्चात्य प्रभावों से गावों की रक्षा की जा सके एवं विकासोन्मुख समाज का निर्माण हो।
- (10) शीर्षक यातायात एवं संचार एवं ग्रामीण सेवा केन्द्र में प्रस्तावित सेवाकार्यों का संचालन उल्लिखित केन्द्रों पर प्रारम्भ किया जाय।
- (11) प्रस्तावित उद्योगों की स्थापना की जाय (ग्रामीण औद्योगीकरण)।
- (12) ग्रामीण जनता को शत प्रतिशत साक्षर बनाने हेतु सामूहिक प्रयत्न किया जाये।
- (13) सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के माध्यम से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना का निर्माण सरकारी अधिकारियों को करना चाहिये।
- (14) ग्राम प्रधान तथा समाज से जुड़े प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को चाहिये कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी ग्रामवासियों तक पहुँचाये तथा उनके विकास में सहयोग दे।



## REFERENCES

- Alam, S M 1974 · The planning Atlas of Andhra Pradesh (Hyderabad Pilot  
Production plant Survey of India.)
- Chauhan, B R 1980 An Indian Village Some question Man in India : Vol  
45 No 2 p 126
- Chitlongi, B.M 1991 · Conceptual Aspect of Rural Development Kurushetra,  
Vol 36 No 5, p. 27
- Gosal, G S. and Gopal K. 1984 Regional Disparities in Levels of Socio-  
Economic Development in Punjab, Vishal Publication. p. 225.
- Lal, N 1989 Rural Development and planning cough publication Allahabad
- Smith, T L 1982 : The Sociology of "Rural life Sociology" Newyark 3<sup>rd</sup> ed  
1982 p 10
- Tiwari, R.C 1984 Settlement system in Rural India : A case study of the  
lower Ganga-Yamuna Doab (Allahabad Geographical Society,  
Allahabad)
- Tiwari, S.K. 1993 : Rural Development and Social change in Independent India  
· A case study of Phulpur Tahsil of Azamgarh District.



## अध्याय-9

### ग्रामीण विकास नियोजन

#### प्रस्तावना

यदि भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व उनके क्रियान्वयन की रणनीति पर दृष्टिपात किया जाये तो स्पष्ट होता है कि समय के साथ ही इसकी अवधारणा भी परिवर्तित होती जा रही है। एक लम्बे समय तक ग्रामीणविकास का तात्पर्य कृषि का विस्तार विकास तथा आधुनिकीकरण से लगाया जाता था यो कहा जा सकता है कि उसे कृषि विकास का पर्याय माना जाता था (तिवारी, आर0सी0 2002)।

शायद इस विचार का आधार यह तथ्य है कि ग्रामीणों का जीवन मूलतः कृषि पर ही आधारित होता है। सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ, इस संकल्पना में परिवर्तन आया क्योंकि इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवेश की पारम्परिक, रूढ़िवादी परम्पराओं का रूपान्तरण करना तथा उन्हें सविधान प्रदत्त समानता व न्याय का अधिकार दिलाकर जीवन पद्धति सुधारने में सहायता प्रदान करना था। सही अर्थों में ग्रामीण विकास के नियोजित प्रयास की शुरुआत 50 के दशक में सामुदायिक कार्यक्रमों के प्रारम्भ से हो गयी थी। यद्यपि उसमें काफी हद तक सफलता नहीं प्राप्त हुई थी फिर भी इसने ग्रामीण सेवाओं के विस्तार हेतु प्रेरणा प्रदान किया जो कि 60 के दशक कृषि विकास हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु जागरूकता पैदा करने में मददगार साबित हुई। किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हुए सुधार से इन कार्यक्रमों द्वारा होने वाले लाभों का अनुभव किया जा सकता है। इससे प्रादेशिक असमानता

एव गरीब व अमीर के बीच खाई में वृद्धि ही हुई। इसलिए यह अनुभव किया गया कि समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास संबंधी कार्यक्रमों से प्रत्यक्षत जोड़ा जाये। चौथी व पंचम पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता के लक्ष्य की दृष्टिगत रखकर शुरू की गयी थी।

ग्रामीण विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं

- (1) कृषि विकास की स्पष्ट रणनीति।
- (2) पशुपालन, दुग्ध व मत्स्यन विकास।
- (3) कृषि अनुसन्धान एवम् शिक्षा।
- (4) वानिकी जिसमें सामाजिक वानिकी सम्मिलित है।
- (5) ग्रामीण विकास एवम् गरीबी उन्मूलन।
- (6) सिंचाई कमान्ड एरिया विकास तथा बाढ़ नियन्त्रण।
- (7) ग्रामीण एवम् लघु औद्योगिक इकाईयाँ।
- (8) रोजगार, जन शक्ति नियोजन एवम् श्रमिक नीति।
- (9) सहकारी ऋण।

1 अप्रैल 1978 को अन्य कार्यक्रमों के साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत तो ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी साथ ही गरीबी उन्मूलन एवम् भूमिहीन मजदूरों, सीमान्त कृषकों व ग्रामीण शिल्पकारों का आर्थिक रूप से लाभान्वित करने का लक्ष्य भी रखा गया। पॉंचवी पंचवर्षीय योजना (1980-85) ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन एव प्रादेशिक असमानता घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। नौवी पंचवर्षीय योजना में राज्य के नीतियों में चार महत्वपूर्ण आयामों पर ध्यान दिया गया—जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, उत्पादक व्यवसायों तथा रोजगारों का प्रजनन, क्षेत्रीय सतुलन

एवम् आत्मविश्वास में वृद्धि। क्षेत्रीय ग्रामीण एवं रोजगार विकास मंत्रालय द्वारा बहुआयामी कार्यक्रमों की शुरुआत से यह उम्मीद की जाती है कि इसके द्वारा रोजगार की प्रचुर उपलब्धता से ग्रामीण परिवेश से गरीबी का पूर्ण उन्मूलन होगा तथा जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा। उस प्रकार ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार तथा वृहत्तर सामाजिक रूपान्तरण से लिया जा सकता है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी, विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधार पर विशेष बल देकर तथा ऋण एवं पूँजी उपलब्ध कराकर काफी हद तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार ग्रामीण विकास का सामाजिक पहलू होगा तथा गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पादन में वृद्धि आदि इसके विकास के महत्वपूर्ण पहलू होंगे।

‘ग्रामीण विकास’ का विस्तृत रूप में शाब्दिक आदि ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास से है। यहाँ हमारा अभिप्राय मुख्यतः मानव के विकास से है जिससे व्यक्ति, समुदाय व राष्ट्र के बीच उचित संबंध स्थापित हो जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाना चाहिए। विकास का केन्द्र बिन्दु मानव को बनाया जाय ताकि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय व आत्मनिर्भरता स्थापित हो और जिससे गरीब व अछूत लोगों को उच्च प्राथमिकता दी जा सके। यह विश्व बैंक की योजना में स्पष्ट दृष्टिगत होता है जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण विकास ग्रामीण गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने की रणनीति है। इनके माध्यम से ग्रामीण परिवेश में जीवन



यापन करने वाले लोगो को विकास के वृहद अवसर प्राप्त होते हैं। इस समूह में सीमान्त कृषक, काश्तकार व भूमिहीन लोग भी सम्मिलित हैं।

### 9.1. ग्रामीण विकास नियोजन हेतु कार्यक्रम :-

परास्वातन्त्र्य काल में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कई कार्यक्रम बनाये गये। ये कार्यक्रम गाँधीवादी विचारधारा के पुर्ननिर्माण तथा गरीबों के उत्थान पर आधारित थे। कुछ प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस प्रकार हैं -

**9.1.1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) :-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश को अनेक विकास खण्डों में बाँटा गया। प्रत्येक विकासखण्ड में कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सुविधायें प्रदान की गयीं परन्तु इस कार्यक्रम से आशातीत प्रगति नहीं प्राप्त हो सकी।

**9.1.2 गहन कृषि विकास कार्यक्रम :-** प्रारम्भ में यह कार्यक्रम गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से था जो 1961 में कृषि विकास हेतु शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में नवीन तकनीकी, बाजारों की सुविधा, प्रशासनिक एवं सगठनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करके भूमि उत्पादकता बढ़ाना था। गहन कृषि विकास कार्यक्रम वस्तुतः सन् 1966 में देश के अधिकांश जिलों में लागू किया गया परन्तु यह कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हुआ।

**9.1.3 लघु कृषक विकास कार्यक्रम :-** यह कार्यक्रम सन् 1969 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य कम जोत वाले किसानों की सहायता करके कृषि उत्पादन में समुचित वृद्धि करना था।

**9.1.4 सीमांत कृषक एवं कृषिक श्रमिक कार्यक्रम :-** यह कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया। यह माना गया था कि सीमान्त कृषक एवं कृषिक श्रमिक अपने आप में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। अतः इन्हें अलग से मदद की जाय।

**9.1.5 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम :-** पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु सन् 1971 में अलग कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत आसाम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों, पश्चिमी घाट, तामिलनाडु इत्यादि को सम्मिलित किया गया।

**9.1.6 कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम :-** यह कार्यक्रम सन् 1974-75 में केन्द्र द्वारा लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र में फील्ड चैनल, भूमि समतलीकरण, नालियों का निर्माण, भूमिगत और सतही जल का समुचित उपयोग, फसल प्रतिरूप निर्धारण, तथा जल प्रबन्धन हेतु कार्यक्रम बनाया जाता है।

**9.1.7 विशिष्ट पशु उत्पादन कार्यक्रम :-** यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में पशु उत्पादन में वृद्धि हेतु 1975 में लागू किया गया। इसका दूसरा अभिप्राय यह भी था कि पशुपालन उत्पादकता में वृद्धि करके इसमें लगे व्यक्तियों की आय के स्रोत को बढ़ाया जाय।

**9.1.8 कार्य बदले अनाज भोजन कार्यक्रम :-** यह कार्यक्रम सन् 1977 में लागू किया गया जिसमें कार्य के बदले अनाज देने की व्यवस्था की गयी जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर वर्ष के कुछ समय नहीं उपलब्ध रहते हैं वहां कुछ स्थायी कार्य कराकर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है जिससे उस क्षेत्र का विकास तथा विशिष्ट अवधि में गरीब लोगों का भरण-पोषण हो सके।

**9.1.9 नकद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :-** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें कार्य के बदले नकद रुपये देने की बात कही गयी।

**9.1.10 सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :-** यह कार्यक्रम सन् 1973 में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के विकास हेतु लागू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा एवं नदी

का बेहतर संरक्षण, जल ससाधन का अधिकाधिक वैज्ञानिक उपयोग, वनरोपण तथा चरी, चारागाह विकास और पारिस्थितिकीय सतुलन के माध्यम से शुष्क कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था।

**9.1.11 मरुभूमि विकास कार्यक्रम :-** पंचवर्षीय योजना में (1977-78) में मरुभूमि के विकास हेतु यह कार्यक्रम पांच राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में शुष्क किया गया। पूरी सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्रों को पुनः मरुस्थलीकरण से बचाकर स्थानीय ससाधनों (भूमि, जल, पशु एवं मानव) की उत्पादकता बढ़ाना, मिट्टी एवं जल संरक्षण, सुरक्षा पकृतियों का रोपण, चारागाह विकसित करना तथा पारिस्थितिकीय सतुलन बनाये रखना है।

**9.1.12. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम :-** जनजातियों के विकास हेतु यह कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के रहन-सहन में सुधार लाना तथा ऐसे क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष विकसित करना है। जनजातीय विकास कार्यक्रम मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं आन्ध्र प्रदेश में लागू है। इन कार्यक्रमों में आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनजातियों को प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

**9.1.13 समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम :-** समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सातवीं योजना में 200 विकास खण्डों में शुरू किया। ये विकास खण्ड विभिन्न कृषि जलवायिक कटिबन्धों में स्थित हैं। इसके तहत चुने हुए विकास खण्डों में वाणिज्यिक ऊर्जा का विस्तार, प्रशिक्षण व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास हेतु बनये अन्य विकास कार्यक्रमों से इनको जोड़ने की बात हुई। आठवीं योजना के अन्तर्गत

गाँवों में प्राथमिक आवश्यकता (भोजन पकाने, गर्मी वास्ते, प्रकाश हेतु) की पूर्ति (खास कर कमजोर वर्गों) हेतु ऊर्जा का प्रावधान किया गया।

**9.1.14 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :-** यह कार्यक्रम 1976-77 में 50 विकास खण्डों में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण जनसंख्या को लाभ दिलाना है।

**9.1.15 स्वरोजगार हेतु ग्रामीण नवयुवकों का प्रशिक्षण :-** यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के नवयुवकों की पारम्परिक कला। निपुणता के उन्नयन हेतु सन् 1979 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य नवयुवकों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना है।

**9.1.16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :-** यह कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सहायता गरीबी की दशा तथा कृषिक श्रमिकों, सीमान्त कृषकों, और सीमान्त कर्मचारियों की जनसंख्या पर दी जाती है।

**9.1.17 ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम :-** यह कार्यक्रम 50 जिलों में 1982-83 में शुरू किया गया। इसके तहत स्त्रियों के एक समूह को 15000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे कुछ कार्य शुरू कर सकें। इस बारे में यह कहा जाता है कि स्त्री समूहों में सम्मेलन की कमी तथा सही आर्थिक क्रिया के चुनाव न कर पाने के कारण परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा।

**9.1.18 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम :-** यह पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है जो सन् 1983 में शुरू किया। इसका उद्देश्य भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के समान ही था। लेकिन इसमें भूमिहीनों को

100 दिन की रोजगार गारंटी उपलब्ध करायी जाती है। इसके तहत 25% धन सामाजिक वानिकी, 10% सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभ तथा 20% आवास विकास के लिए खर्च किया जाता है।

**9.1.19 जवाहर रोजगार योजना :-** सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1989 में यह कार्यक्रम लागू किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादक क्रियाओं द्वारा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम की 80% पूंजी केन्द्र तथा 20% राज्य सरकारें वहन करती हैं। यह कार्यक्रम देश के सभी गाँवों में लागू की गयी है। वास्तव में पहले के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम को एक में मिलाकर यह योजना बनाई गई है।

**9.1.20 इन्दिरा आवास योजना :-** यह योजना सन् 1989 में शुरू की गयी। इसका उद्देश्य आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। राज्य स्तर पर सम्पूर्ण जवाहर रोजगार योजना का 6% धन इस पर खर्च करने का सुझाव दिया गया था।

**9.1.21 मिलियन कुओं योजना :-** यह योजना भी सातवी पंचवर्षीय योजना में लागू की गयी जिसमें जवाहर रोजगार योजना का 20% धन दस लाख कुओं की खुदाई पर खर्च करने के लिए आवंटित किया जाय।

**9.1.22 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :-** गरीबी उन्मूलन हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम सन् 1973 में 35 विकास खण्डों में शुरू किया गया। इसका मूल उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को प्राथमिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। प्रौढ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास विकास, ग्रामीण घरेलू ऊर्जा, ग्रामीण सैनिटेशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पोषण इत्यादि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।

**9.1.23 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना :-** 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शुरू की गयी। इसके तहत 65 वर्ष या अधिक उम्र के गरीब वृद्ध जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है उन्हें 75 रु० प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी। इसी तरह गर्भवती महिलाओं को (गरीबी रेखा के नीचे) भी पोषण हेतु 300 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है।

## **9.2 उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास की अद्यतन योजनाएँ :-**

उत्तर प्रदेश शासन का एक पिछड़ा प्रदेश है, यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए विगत तीन दशकों से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, ग्रामीणों के उत्थान के लिए सरकार ने अनेक प्रभावी कदम उठाए तथा अनेक ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, इन योजनाओं में कुछ को तो सफलता मिली, लेकिन कुछ को तो सफलता मिली, लेकिन कुछ के आशानुरूप परिणाम नहीं निकले, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया है इनमें प्रमुख रूप से अद्यतन ग्राम्य विकास योजनाएँ इस प्रकार हैं —

### **9.2.1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :-**

गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्राइसेस, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम (डवाकरा) उन्नत टूल किट योजना, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल विगत दो दशकों से संचालित की जा रही थी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से अनेक जटिलताएँ उत्पन्न हो रही थी इसलिए उपयुक्त छः कार्यक्रमों को विलीन कर, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना का सूत्रपात हुआ।

## **योजना का उद्देश्य :-**

इस योजना का उद्देश्य चयनित स्वरोजगारी को 2-3 वर्ष में 2000 रु० प्रतिमाह की शुद्ध आय अर्जित करने के योग्य बनाता है जिससे वह गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके।

## **योजना का लक्ष्य :-**

इस योजना का लक्ष्य सकल चिन्हित गरीब परिवारों में से 30 प्रतिशत परिवारों को आगामी 5 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।

### **9.2.2 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :-**

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999, को शुरू की गई ताकि पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित करके ग्राम स्तर पर ग्रामीण ढाँचागत सुविधाओं के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोगों की माँग पर स्थायी परिसम्पत्तियों सहित, सामुदायिक ग्रामीण ढाँचा तैयार करना और ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है, जिनसे ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार के स्थायी अवसरों में बढ़ोतरी हो सके, इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन बेरोजगारों के लिए मजदूरी रोजगार का सृजन करना है।

यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है और केन्द्र तथा राज्य को 75:25 के अनुपात में इसका खर्च वहन करना होता है।

### **9.2.3 ग्रामीण आवास योजना :-**

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए आवास की समस्या दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं -

- (1) **इन्दिरा आवास योजना** :- भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 से इन्दिरा आवास योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना है।
- (2) **ऋण एवं अनुदान ग्रामीण आवास योजना** :- ग्रामीण आवास सम्बन्धी ऋण-सहसस्सिडी योजना 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई है, योजना का लक्ष्य 32,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवार है, यद्यपि सस्सिडी 10,000 रु० तक सीमित है, परन्तु अधिकतम 40,000 रु० ऋण की राशि प्राप्त की जा सकती है, सस्सिडी, केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहन की जाती है।
- (3) **समग्र आवास योजना** :- समग्र आवास योजना को ऐसे जनपदों में जिनकी पहचान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भागीदारी दृष्टिकोण कार्यान्वित करने के लिए की गई है, शुरू करने का निर्णय किया गया है।
- (4) **ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास के लिए अभिनव योजना**  
ग्रामीण क्षेत्रों में इमारत/मकान क्षेत्रों में अभिनव किफायती और पर्यावरण अनुकूल समाधानों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई है।
- (5) **ग्रामीण भवन केन्द्र** :- ग्रामीण निर्मित केन्द्र स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य है -
- (क) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना का प्रसार।
  - (ख) प्रशिक्षण के जरिए कौशल उन्नयन।
  - (ग) किफायती और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उत्पादन।



#### 9.2.4 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना –

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 6 महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रारम्भ करने की घोषण की गई जो अधोलिखित है –

- (1) ग्रामीण सड़कों का निर्माण
- (2) ग्रामीण आवास
- (3) पुष्टाहार
- (4) स्वास्थ्य
- (5) पेयजल
- (6) बेसिक शिक्षा

#### 9.2.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का राज्य स्तर पर शुभारम्भ 25 दिसम्बर, 2000 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अगले 3 वर्षों में 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ योग्य सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना है तथा 2007 तक 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

#### 9.2.6 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) :-

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में आवास की कमी को दूर करने तथा इन क्षेत्रों में पर्यावरण विकास में मदद करने हेतु इन्दिरा आवास के पैटर्न पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास 2000–2001) कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत लक्ष्य समूह में ग्रामीण क्षेत्र में (वी.पी.एल) के

नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बन्धुआ मजदूर वर्ग के जाति/जनजाति तथा बन्धुआ मजदूर वर्ग के लोग हैं।

#### **9.2.7 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) :-**

वित्तीय वर्ष 2000-2001 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) संचालित की जा रही है। योजना का कार्यान्वयन जन सहभागिता तथा पंचायतो का अधिकतम सहयोग लेकर जल निगम द्वारा किया जाएगा।

#### **9.2.8 ग्रामीण पेयजल योजना :-**

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में तथा प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।

#### **9.2.9 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना :-**

ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार के अवसर सृजित हो सके इस हेतु पोर्जेक्ट एप्रोच के आधार पर एक विशेष रोजगार योजना के स्वरूप 25 सितम्बर 1991 से प्रारम्भ की गई जो सम्प्रति अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के नाम से क्रियान्वित है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय ससाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओं का निर्माण कर स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना है।

#### **9.2.10 रोजगार छतरी योजना :-**

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी के परिणामस्वरूप जनशक्ति को पर्याप्त रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए बेरोजगार युवक, भूमिहीन मजदूर लघु एवं सीमांत किसान, ग्रामीण दस्तकार व अन्य ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के लोग जो कार्य करना चाहते उन्हें रोजगार संकल्प के अन्तर्गत चिन्हित रोजगार

कार्यक्रमों व योजनाओं में लाभान्वित करने के उद्देश्य से रोजगार सकल्प का शुभारम्भ किया गया है।

#### 9.2.11 दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान :-

ग्राम विकास के मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अंचल में रोजगार सुविधाओं को सहज रूप से उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण जनसमुदाय की स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रयासों की ओर ही केन्द्रित है, प्रशिक्षण अनुसंधान तथा विकास एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, अतः नीति-निर्माताओं तथा कार्यक्रम संचालकों दोनों को शिक्षित करना आवश्यक है।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान इसी उद्देश्य के साथ प्रशिक्षण, शोध तथा परामर्शी गतिविधियों के लिए एक प्रादेशिक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है यह लखनऊ में स्थित है।

#### 9.2.12 पोषण परियोजना :-

उत्तर प्रदेश में 55 प्रतिशत महिलाएँ एवं बच्चे कुपोषित हैं, प्रदेश में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए, इस दिशा में सक्रिय सहयोग करने हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान अपने परम्परागत कार्यभार ग्राम्य विकास सम्बन्धित प्रशिक्षणों के संचालन के साथ-साथ अब एक अलग तरह का कार्यक्रम “पोषण परियोजना” को यूनीसेफ के सहयोग का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से कुपोषण की दर में कमी लाना है।

#### 9.3. ग्रामीण विकास नियोजन में पंचायती राज की भूमिका :-

ग्राम पंचायत भारत की प्राचीन लोकतान्त्रिक स्वायत्त शासन की आधारशिला रही है। इसका उल्लेख हमें भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ ऋग्वेद में “सभा और समिति” के रूप में मिलता है। इतिहास के विभिन्न काल में

अलग-अलग अवसरो पर केन्द्र (आज के सन्दर्भ में नहीं) में राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद स्वायत्तशासी शासन की यह इकाइयाँ आदिकाल से निरन्तर कार्यरत रही हैं।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चोल साम्राज्य में ग्रामीण की स्वायत्ता पर बल दिया गया है। आज की ग्रामीण स्वायत्ता बहुत कुछ चोल ग्रामों से मिलती है क्योंकि जिस सवैधानिक व्यवस्था को आज हम ग्रामीणों को देना चाहते हैं वैसी व्यवस्था चोल साम्राज्य की आधारशिला रही है

### 9.3.1 73वां संविधान संशोधन अधिनियम :-

भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित करके पंचायती राज संस्थाओं को सवैधानिक दर्जा दिया। अनु0 40 में उल्लिखित कि राज्य ग्राम पंचायत गठन करने और उन्हें ये सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उन्हें एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। इसका वर्णन राज्यों के नीति निर्देशकों में तत्वों में किया गया है।

### 9.3.2 विकास पर पंचायती राज का प्रभाव :-

73वां संशोधित अधिनियम लागू होने के पाँच वर्ष में ग्रामीण सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं की जड़े जमाने की दिशा में उत्साहजनक प्रगति हुई है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय ग्रामीण जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वर्तमान संदर्भ में पंचायती राज संस्थाएँ देश के सभी भागों में काम करने लगी हैं। इस व्यवस्था के अनुसार लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण से संबंधित सभी ग्रामीण विकास

कार्यक्रमों को ग्रामीण स्तर पर लागू के लिए पंचायती राज एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में आत्मसम्मान की भावना का संचार हुआ है। इसके अतिरिक्त गावों के अधिक उत्साही तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों में नेतृत्व की नई क्षमताओं का विकास हुआ है। सबद्ध विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के प्रभाव से आज ग्रामीण गतिशीलता में वृद्धि हुई है। यह गतिशीलता सामाजिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। पंचायतों अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से गाव में स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा के प्रचार में निर्दिष्ट प्रावधानों के प्रति जागरूकता बनाये हुई है।

अनेक लाभकारी प्रभावों के अलावा पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन में कुछ विघटनकारी प्रवृत्तियों को भी जन्म दिया है, जिनमें गुटबन्दी, संघर्ष तथा व्यक्तिवादिता आदि प्रमुख हैं। आज गावों में भी शहरों के समान व्यक्तिवादिता तथा मूल्यों के ह्रास की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। कुछ लोगों का विचार है कि ये दुष्परिणाम पंचायती राज व्यवस्था के न होकर दोषपूर्ण कार्यान्वयन के हैं। वास्तविकता यह है कि ये पंचायती राज के दुष्परिणाम इससे प्राप्त लाभों की तुलना में कम हैं। किसी भी समाज अथवा समुदाय की प्रगति का वास्तविक आधार इसके सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक जागरूकता है। पंचायती राज व्यवस्था ने ऐसी जागरूकता उत्पन्न करने में निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

### 9 3.3 मूल्यांकन :-

नई पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन को छह वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और ग्रामीण विकास पर इसके प्रभाव भी परिलक्षित होने लगे हैं। इन 6 वर्षों का मूल्यांकन किया जाए, तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्रामीण विकास की सफलता के लिए जागरूकता एक महत्वपूर्ण शर्त है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उसके लिए क्या उपयोगिता है और इन कार्यक्रमों से सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से उसे क्या लाभ होगा। पंचायती राज के प्रतिनिधि और इससे जुड़े कर्मचारी तथा पदाधिकारियों में भी जागरूकता की कमी पायी जाती है। निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि का अपने स्वतन्त्र विचारों के आधार पर राजनीतिक दलों के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम ही रहा है। लेकिन इतना तय है कि पंचायती राज का दलीकरण हुआ है। भविष्य में देश की दलगत राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। वित्तीय संसाधनों के संबंध में भी स्थिति सतोषजनक नहीं है। साधनों की समुचित व्यवस्था के अभाव में पंचायतों को सुचारु ढंग से नहीं चलाया जा सकता। हालाँकि अधिकांश राज्यों में वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, फिर भी उनकी कार्यप्रणाली से पंचायतों की पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्वशासी सरकार की स्थापना करना है। इसी आधार पर उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाने का अधिकार भी दिया गया है। इसका आशय यह हुआ कि पंचायतों को वित्तीय तथा प्रशासनिक स्तर पर स्वायत्त होना चाहिए लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।

यदि व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो पचायतो की हालत काफी दयनीय है। पचायत, विशेषकर ग्राम पचायत, के निर्वाचित प्रतिनिधि लगभग अशिक्षित या अल्प शिक्षित होते हैं। जिससे पचायत सदस्य को सभाये बुलाने की प्रविधि का ज्ञान नहीं होता और प्रस्ताव बनाना, पारित करना, बजट बनाना, लेखा तैयार करना, अकेक्षण करना, सरकारी योजनाओं की अनभिज्ञता आदि महत्वपूर्ण कारणों से असफल सिद्ध होते हैं। अतः आवश्यक है कि इन प्रतिनिधियों के लिए सतोषजनक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाएँ।

#### 9 3.4 निष्कर्ष :-

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में स्वतन्त्रता के पश्चात से ही अब तक के सतत प्रयासों में निःसन्देह 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा गंभीर प्रयास है। इस व्यवस्था से लोकतन्त्र सही अर्थों में गाँव के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचा है। यदि यह प्रक्रिया निर्विवाद रूप से क्रियान्वित रही, तो पिछड़े तथा उपेक्षित ग्रामीण समाज में सजगते और नवीन चेतना की अभिवृद्धि होगी। अतः पचायतों के पास उत्तरदायित्वों के साथ पर्याप्त वित्तीय स्रोत होने चाहिए, तभी “राज हमारा, अधिकार हमारा, शासन का हर द्वार हमारा,” का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा (जून 1999 कुरुक्षेत्र 15, 16)।



## **REFERENCES**

Tiwari R C 2002 Geography of India – page 849-851 Prayag Pustak Bhawan

20-A University Road, Allahabad

भारत 2002 प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश 2002 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, पृ० 188–201

सिंह, महेन्द्र बहादुर एवं दूबे, कमलाकान्त प्रादेशिक विकास नियोजन पृ० 265 – 270।

कुरुक्षेत्र, जून 1999 पृ० 15, 16 ग्रामीण विकास मन्त्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।





## सारांश तथा निष्कर्ष

यह सर्वथा सत्य है कि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त और वर्तमान समय की आवश्यकता है। देश के नियोजित विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और विकास के लिये किये गये सगठित प्रयास का ही परिणाम है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सन् 1961 में 57% से घटकर 1991 में 30% हो गया। राष्ट्रीय विकास के लिये ग्रामों में रहने वाले गरीब एक अमूल्य मानवीय सम्पदा हैं। यदि इनकी शक्ति का उपयोग प्रगति और नवनिर्माण में किया जाय तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील और उत्पादक बनाया जा सकता है।

प्राचीन समय में गांव मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति के जनक थे, परन्तु अब गांवों में न तो उतनी सम्पन्नता है और न ही उतनी सामाजिक सुविधायें हैं, जितनी नगरों में उपलब्ध हैं। गांवों में अमीर तथा गरीब के मध्य उत्पन्न असमानता को दूर करने में ग्रामीण विकास कहा तक सिद्ध हुआ है, प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इसी के मूल्यांकन का एक प्रयास है जिसमें ग्रामीण विकास के अवयवों के साथ-साथ ग्रामीण समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं तथा समाज के विभिन्न पक्षों में हुए परिवर्तन के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बस्ती जनपद की भानपुर तहसील को प्रतिदर्श मानकर सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े पन के कारणों तथा सामाजिक उन्नयन में बाधक, सामाजिक कुरीतियों तथा क्षेत्रों में प्रस्फुटित नूतन प्रवृत्तियों के विवेचन और इसके आधार पर ग्रामीणोत्कर्ष तथा सामाजिक उन्नयन हेतु कतिपय सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। शोध प्रबन्ध की सम्पूर्ण विषय वस्तु 9 अध्यायों में विभक्त हैं जिसमें विभिन्न संकल्पनाओं की वैधता की जांच के लिये नवीन भौगोलिक तकनीकों तथा विधि तन्त्र का प्रयोग किया गया है।

प्रथम अध्याय में ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के ऐतिहासिक और सैद्धान्तिक पक्षों को स्पष्ट किया गया है। जिसमें आर्थिक-सामाजिक असमानता को स्पष्ट करने के लिये सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर बल दिया गया है जिससे विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप में मिल सके तथा ग्रामीण विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन लाने में कहा तक सफल हुये हैं इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास से है जिसमें कृषि यातायात एवं संचार, उद्योग, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि अनेक तत्व सन्निहित हैं। ग्रामीण विकास का लक्ष्य देश के निर्धनतम क्षेत्रों का विकास करके उन्हें नगरीय क्षेत्रों के समकक्ष लाना है जिससे सम्पूर्ण देश का समोन्यन हो सके। जैसे-जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक वेशभूषा, आवासीय व्यवस्था, सामाजिक क्रियाकलापों आदि में परिवर्तन होगा। इस प्रकार दोनों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है।

द्वितीय अध्याय में अध्ययन क्षेत्र की उपस्थिति, प्रशासनिक सगठन, जलवायु आदि का सामान्य विवेचन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र-भानपुर तहसील, उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जनपद में  $26^{\circ}50'15''$  उत्तर से  $27^{\circ}7'20''$  उत्तरी अक्षांशों और  $82^{\circ}34'30''$  पूर्व से  $82^{\circ}48'50''$  पूर्वी देशान्तरों के मध्य अवस्थित है। अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 451.99 वर्ग किमी० है। जो जनपद बस्ती के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.31% है। इसके पूरब में बस्ती जनपद की बस्ती तहसील एवं दक्षिण पश्चिम में हरैया तहसील है। उत्तर में जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर पश्चिम में जनपद गोण्डा द्वारा इसकी बाह्य सीमा निर्धारित की जाती है।

तहसील की शतप्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण तहसील 2 विकास खण्डों, 21 न्यायपंचायतों, 151 ग्राम पंचायतों एवं 435 ग्रामों में विभक्त है। जिसमें 409 आबाद ग्राम हैं तथा 26 गैर आबाद ग्राम हैं।

सम्पूर्ण अध्याय क्षेत्र समतल मैदानी भूभाग है जिसमें दोमट मिट्टी की बहुलता है। इस क्षेत्र का क्षेत्रीय ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का है। तहसील में कुआनों, आमी, गरैइया, कठिनइया प्रमुख नदियाँ हैं। कुआनों नदी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा तथा आमी उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। बेडवा, रेहावर प्रमुख नाले हैं। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान लगभग 18.5 से०ग्रे० व अधिकतम 31.66 से०ग्रे० रहता है। 1995 में अधिकतम तापमान 45 से०ग्रे० तक पहुँच गया जो एक रिकार्ड है। वर्ष 1998-99 में तहसील में अधिकतम तापमान लगभग 44.8 से०ग्रे० तथा न्यूनतम तापमान 5.2 से०ग्रे० रिकार्ड किया गया। वर्ष 1998-99 में तहसील में वास्तविक वर्षा 851 मिमी० हुई। वर्षा उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में अधिक होती है। तहसील की 1999 में सामान्य वर्षा 1156 मिमी० रही है।

तृतीय अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के जनसंख्या प्रतिरूप का विवेचन है। स्वातन्त्र्योत्तर काल में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या में दो गुनी वृद्धि अंकित की गयी है। सन् 2001 की जनगणना की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के अनुसार भानपुर तहसील की जनसंख्या 302041 है। जिसमें शत-प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। जबकि 1961 में तहसील की जनसंख्या 1,55,916 थी सन् 1961 में जनघनत्व 344 व्यक्ति/किमी<sup>2</sup> था जो सम्प्रति 2001 में 668 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। तहसील की कुल जनसंख्या का मात्र 32.5% जनसंख्या ही कार्यशील है। सम्पूर्ण तहसील में पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 1000 : 952 है। अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण साक्षरता मात्र 38.95% है। जिसमें 52.08% पुरुष एवं 25.16% एवं 25.16% स्त्री साक्षर हैं। क्षेत्र की साक्षरता का प्रतिशत,

प्रादेशिक साक्षरता 57.36% एवं राष्ट्रीय साक्षरता 65.38% की तुलना में कम है। पिपराजप्ती न्यायपचायत (सल्टौवा विकास खण्ड) की साक्षरता सर्वाधिक है। अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 17.6% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ पूरे तहसील में केवल ग्राम उकडा (भानपुर न्यायपचायत) में मिलती हैं, इनकी कुल संख्या 20 है जिसमें पुरुष 10 तथा महिलाएँ 5 हैं।

अनुसूचित जाति की 92% बालिकाओं का शैक्षणिक जीवन जूनियर बेसिक स्कूल के बाद समाप्त हो जाता है। मात्र 6% छात्राएँ ही माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं। तहसील में 32.5% लोग कार्यरत हैं तथा 62.3% जनसंख्या बेरोजगार है, जबकि सीमांत रूप में कार्य करने वाले लोगों का योगदान 5.7% है। कुल कार्यरत जनसंख्या में 78% कृषक हैं 13.6% कृषि श्रमिक हैं। पशुपालन वृक्षारोपण में संलग्न 18% जनसंख्या है।

चतुर्थ अध्याय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मेरुदण्ड कृषि का विवेचन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की कृषि—पद्धति पारम्परिक प्रकार की, खाद्यान्न प्रधान है, तहसील में शुद्ध कृषिकृत भूमि 80.2% चारागाह, वन 42% कृषि योग्य बंजर भूमि 1.9% वर्तमान परती भूमि 0.8% पुरानी परती 1.0% तथा कृषि आयोग्य भूमि 0.9% है। क्षेत्र में तीन प्रकार की फसलो—रबी, खरीफ और जायद का उत्पादन होता है। रबी की फसलो में गेहूँ, चना, मटर एवं आलू तथा खरीफ की फसलो में धान, गन्ना, अरहर और मक्का की प्रमुखता होती है। गन्ना अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख मुद्रादायिनी फसल है। बोये गये सकल क्षेत्रफल के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ प्रथम, धान द्वितीय, गन्ना, तृतीय, मटर चतुर्थ तथा अरहर पंचम स्थान पर है। सिंचाई के प्रमुख स्रोत राजकीय नलकूप तथा निजी नलकूप हैं तहसील में 120 राजकीय नलकूप हैं जिसमें 73 नलकूप रामनगर विकास खण्ड में हैं। पूरे

तसहील में नहरो का निर्माण किया जा रहा है। पक्के कुओ की संख्या 1220 है। उर्वरको में सर्वाधिक प्रयोग नाइट्रोजन की 80% होता है।

ग्रामीण कृषि विकास और सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ सम्बन्ध है चूँकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है अतः कृषि विकास होने पर स्वाभाविक रूप में आर्थिक समुन्नयन होगा।

शोध प्रबन्ध के पाँचवें अध्याय में ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में अध्ययन क्षेत्र की यातायात एवं संचार-व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है अध्ययन क्षेत्र में तीन प्रकार के सड़क मार्ग हैं। प्रान्तीय मार्ग, जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग।

अध्ययन क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। प्रान्तीय मार्ग मात्र 2 हैं प्रान्तीय मार्ग संख्या 5 (बस्ती-बासी मार्ग) की लम्बाई तहसील में मात्र 10 किमी० है। प्रान्तीय मार्ग संख्या 26 (बस्ती-डुमरियागंज मार्ग) की तहसील में लम्बाई 24 किमी० है। वर्तमान समय (1999-2000) की तहसील में पक्की सड़को की कुल लम्बाई 172 किमी० है। तहसील के 31.16% आबाद ग्राम पक्की सड़को से संयोजित हैं। तहसील का व्यस्ततम मार्ग प्रान्तीय मार्ग संख्या 5 तथा 26 है। सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किमी० पर 38.13, तथा प्रति लाख जनसंख्या पर 69.45 किमी० है। तहसील में 10 किमी० लम्बी बड़ी लाइन की रेलमार्ग है। आमा स्टेशन इसी लाइन पर है बड़ी लाइन मुण्डेरवा से बभनान को जाती है, तहसील में स्थानीय यातायात के रूप में इसका विशेष योगदान नहीं है। सम्प्रति तहसील में 32 डाकघर, 3 तारघर, 370 टेलीफोन, 12 पब्लिक काल आफिस, 1 रेलवे स्टेशन, (हाल्ट सहित) तथा 17 बस स्टेशन हैं।

अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन में यातायात एवं संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण जनसंख्या का नगरों एवं महानगरों

के मध्य आवागमन में वृद्धि हुई है। वस्तुओं के क्रय विक्रय नौकरी एवं जीविकोपार्जन के साधनों की तलाश तथा उत्पादनातिरेक एवं उत्पादन-न्यूनता वाले क्षेत्रों में वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन स्थापित करने में यातायात एवं संचार माध्यमों ने उल्लेखनीय योगदान किया है। संचार माध्यमों द्वारा सामाजिक उन्नयन हेतु प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों से सामाजिक सुधारों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है।

सेवा केन्द्र अपनी कतिपय विशिष्ट सेवाओं द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सेवा केन्द्रों के प्रतिरूप का विश्लेषण करने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकासार्थ कतिपय सेवा केन्द्रों पर कुछ नूतन सेवा कार्यों को प्रारम्भ करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। सेवा केन्द्र ऐसे अधिवास या अधिष्ठान होते हैं जो अपनी सीमान्तर्गत स्थित विभिन्न कार्यों द्वारा एवं तथा परितः स्थित बस्तियों को सेवायें प्रदान करते हैं अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों के निर्धारण हेतु 28 केन्द्रीय कार्यों को आधार माना गया है। प्रत्येक सेवा कार्य को 100 अंक का अधिमान देकर प्रति इकाई महत्व का मान निकाला गया है। कुल संख्या से अधिमान को विभाजित किया जाता है जो सेवा केन्द्र का केन्द्रीयता मान होता है। दो प्रमुख सेवा केन्द्र हैं भानपुर तथा सल्टौवा गोपालपुर। सेवा केन्द्र नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं सेवा केन्द्र नूतन अविष्कारों, नवाचारों, नवीन तकनीकों आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में सहायक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी समस्त तत्वों को संचरण सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।

शोध प्रबन्ध के छठवें अध्याय में ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में उद्योग एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का निरूपण किया गया है। बृहद एवं मध्य स्तरीय औद्योगिक इकाई-विहीन अध्ययन क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लघु तथा

कुटीर उद्योग की छोटी छोटी इकाईया है। वर्तमान समय में विश्व के वही देश अग्रणी है, जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित है क्योंकि औद्योगिक सबुद्धि से देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष होता है। यद्यपि कृषि विकास से देश की खाद्यान्न समस्या का समाधान होता है किन्तु पूर्ण आर्थिक समुन्नति तो औद्योगिक विकास से ही सम्भव है।

सप्तम् अध्याय में अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख सामाजिक सुविधायें शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों, पेयजल, विद्युतीकरण आदि का उल्लेख किया गया है सम्प्रति तहसील में 190 प्राइमरी स्कूल, 26 सीनियर बेसिक स्कूल, 9 हाईस्कूल/इन्टर कालेज हैं। क्षेत्र में कोई भी डिग्री कालेज, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। बालिका विद्यालय (इन्टर कालेज) एक भी नहीं है, जिसके कारण बालिका शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तहसील में लगभग 33,560 जनसंख्या पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 9 है परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या 44 है। पशु चिकित्सालय 4 है। वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर 1 चिकित्सालय, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की सुविधा प्राप्त है। अध्ययन क्षेत्र में बैंकों की संख्या 15 है जिसमें 7 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 6 है जबकि 2 अन्य राष्ट्रीयकृत हैं। अध्ययन क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों की कुल संख्या 272 है। विद्युत की आपूर्ति रूघौली विद्युत उपकेन्द्र से पूरी की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में 1 डाक बगला तथा 1 पुलिस स्टेशन है।

अष्टम अध्याय में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, यातायात एवं संचार तथा उद्योग से सम्बन्धित वर्ष 1989-90 और 2000-01 के आंकड़ों से परिगणित विभिन्न सूचकांकों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को विकसित विकासशील और अविकसित

तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत 8 न्यायपचायतो सल्टौआ, भानपुर, पिपराजप्ती, नरखोरिया, रामनगर, कलन्दरनगर, भिरिया ऋतुराज तथा जिनवा है जो तहसील के 38% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

विकासशील क्षेत्र में 8 न्यायपचायते आती हैं जिसमें 5 सल्टौआ गोपालपुर तथा 3 रामनगर विकास खण्ड में हैं। इसी प्रकार अविकसित श्रेणी के अन्तर्गत 5 न्यायपचायतो आती हैं। जो तहसील की 35% भूभाग को आवेष्टित किये हुये हैं।

यद्यपि उर्पयुक्त विवरण में तहसील में कुछ क्षेत्र विकसित श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं किन्तु यदि अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय मानक के आधार पर परिकलन किया जाय तो सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। ज्ञातव्य है कि अध्ययन क्षेत्र के विकसित, विकासशील क्षेत्र राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं निरूपित किये गये हैं। वरन् ये मात्र अध्ययन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ही विकसित या विकासशील हैं।

नवम अध्याय में ग्रामीण विकास नियोजन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया तथा उत्तर प्रदेश की अद्यतन योजनाओं का वर्णन भी किया गया है। ग्रामीण विकास में पचायती राज की भूमिका की विवेचना अंत में की गयी है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग परिवहन एवं संचार माध्यमों, प्रमुख सामाजिक सुविधाओं आदि में वृद्धि के परिणामस्वरूप जहां ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति हुई है वहीं दूसरी तरफ नैतिक मूल्यों का ह्रास तथा दहेज, दहेज हत्या, की प्रवृत्ति जैसी कतिपय सामाजिक बुराइयों का उद्भव हुआ है।



उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र नदी निर्मित एक समतल मैदानी भाग है। यहाँ की शत प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, जिसकी आजीविका का प्रधान स्रोत कृषि है जिसमें परिमाणात्मक एवं परिणामात्मक अभिवृद्धि हो रही है।

तहसील की वर्तमान साक्षरता 38.95% है जो कि जनपदीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय दर तीनों की तुलना में अत्यन्त निम्न है। तहसील में बालिका विद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों तथा व्यावसायिक, औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव है।

परिवार एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो सका है।

यातायात, संचार का विकास हुआ है किन्तु इनकी गुणवत्ता के और अधिक विकास की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र में मात्र लघु तथा अतिलघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ ही हैं। मध्यम और बृहद स्तरीय इकाइयों का पूर्णतया अभाव पाया जाता है।

उच्चस्तरीय सेवा केन्द्रों के अभाव के कारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय सेवा केन्द्रों से नहीं हो पाती है।

स्वतन्त्रता के पश्चात जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अकुश लगा है। किन्तु दहेज प्रथा तथा अनावश्यक प्रदर्शनों से धन का अपव्यय आदि सामाजिक बुराईयों का पोषण हो रहा है।

आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन के समस्त क्षेत्रों (यथा-परिवार, रीतिरिवाज, खान-पान, वेशभूषा इत्यादि) में परिलक्षित होता है।

अध्ययन क्षेत्र के स्वातन्त्रोत्तर कालीन ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी सकलित समस्त तथ्यों के विश्लेषण एवं सश्लेषण तथा सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों

के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं —

- (1) बालक के सर्वांगीण विकास में माता की भूमिका विशेष होती है जबकि अध्ययन क्षेत्र में माध्यमिक बालिका विद्यालय एक भी नहीं है।

अतः स्त्री साक्षरता के विकास को प्रथम लक्ष्य मानकर अध्याय 5 में प्रस्तावित केन्द्रों पर तदनुरूप बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाय तथा साथ ही शत-प्रतिशत साक्षरता हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में परिणामस्वरूप तथा गुणात्मक अभिवृद्धि की जाय।

- (2) ग्रामीण विकास की योजनाओं के निर्माण में ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित लोगों की भागीदारी है।

- (3) योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम सभा अथवा अधिकतम न्यायपंचायत स्तर पर किया जाय।

- (4) प्रत्येक ग्राम सभा में एक सार्वजनिक वाचनालय की स्थापना की जाय जहाँ ग्रामीणों के विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं तथा सरकारी सुविधाओं का पूर्णज्ञान कराने हेतु प्रचुर पाठ्य सामग्री सदैव उपलब्ध रहे।

- (5) ग्राम विकास से सम्बन्धित सभी विभागों के अधिकारियों को चाहिये कि सरकारी आकड़ों पर ही केवल न निर्भर रहे बल्कि स्वयं क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के माध्यमों से सफलता तथा असफलता का अध्ययन करें और ग्रामीणों के आवश्यकतानुसार योजनाओं में संशोधन करने तथा क्रियान्वयन करने का प्रयास करें।

- (6) ग्रामीण विकास और सामाजिक विकास हेतु क्षेत्रीय बुद्धिजीवियों तथा ग्राम प्रतिनिधियों का सहयोग वांछित है।

- (7) ग्रामीण क्षेत्रों पर शोध करने वाले छात्रों को सरकारी प्रोत्साहन प्रदान किया जाय तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने तथा उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
- (8) संचार माध्यमों तथा आदर्श प्रसारण के माध्यम से ग्रामीण सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु कठोर कानून बनाने तथा मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है।

यदि उपरोक्त सभी सुझावों का पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाय तो निश्चित रूप से अध्ययन क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास तथा उन्नयन भी हो सकता है तथा क्षेत्र की जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठ सकता है क्योंकि जब इनकी भी भागीदारी राष्ट्र विकास में होगी तभी राष्ट्र का विकास पूर्ण हो सकता है।



ਤਰਿਨੇਕੁ

82°35'

40'

45'

TAHSIL BHANPUR  
DISTRICT BASTI  
VILLAGE LOCATION MAP

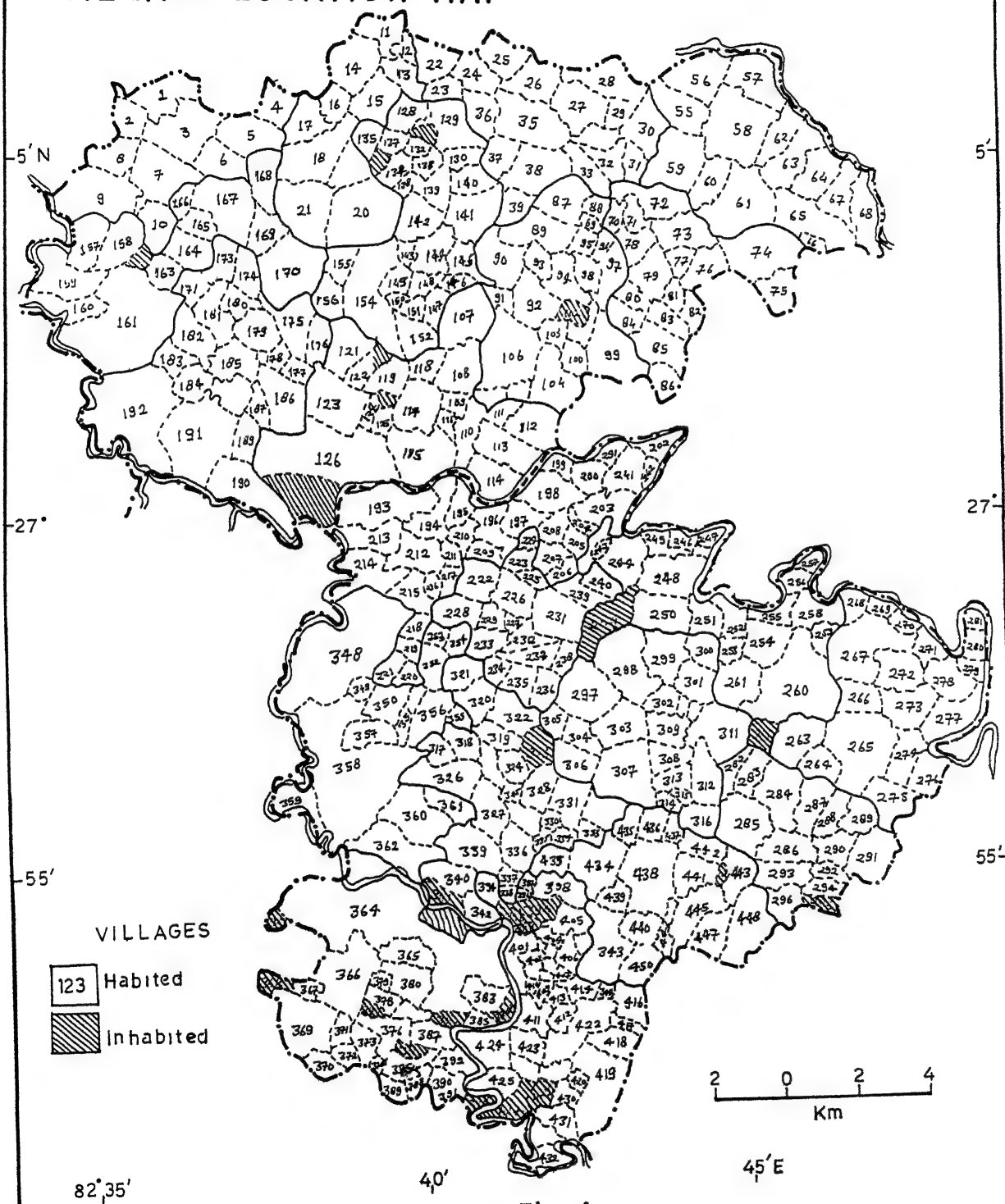


Fig. 1

**भानपुर तहसील**  
**रामनगर विकास खण्ड**

<b>1 शकरपुर न्याय पंचायत</b> लोकेशन      गाँव का कोड न      नाम 1      पिरैला नरहरिया 2      तेन्दुहना 3      छितिरगाँव 4      खम्हरिया 5      आल्हे कोइयाँ 6      पकरी 7      शकरपुर 8      भोलापुर 9      चन्दोखा 10      आदमपुर	<b>2 नरखोरिया न्याय पंचायत</b> 11      खोरिया 12      कुरथिया 13      बडौगी 14      मझौवा रामप्रसाद 15      चिरई बुजुर्ग 16      डिउई माफी 17      धौरहरा 18      नौवागाँव 19      छपिया खास 20      नरखोरिया 21      मझारी
<b>3 तुसायल न्याय पंचायत</b> 22      बैदौली उर्फ दुबौली 23      गन्धरिया नानकार 24      बरडीहा 25      अतर डीहा 26      कटरिया नानकार 27      कोहडा 28      अहिरौली 29      रामापुर 30      आमारेडीहा 31      काटे खैरा 32      सकतपुर 33      पाटी चक 34      इब्राहिम चक उर्फ शेखपुर 35      तुसायल 36      करौता 37      उमरभरिया 38      पिपरहिया 39      हलुवा हसनपुर	<b>4 सगरा खास न्याय पंचायत</b> 55      तुरकौलिया राय 56      परसोहिया 57      कोल्हुई 58      सगरा खास 59      अहिरौला 60      हरिहरपुर 61      चैसार 62      बढया लालसिंह 63      खम्हरिया 64      अतर डीहा 65      पटवरिया 66      मझरिया 67      गन्धरिया बुजुर्ग 68      गन्धरिया खुर्द
<b>5 थुम्हवा पाण्डेय न्याय पंचायत</b> 69      शाह औलिया चक 70      देई डीहा 71      गोपिया 72      बेलगडी 73      ओबरी डीहा 74      टडौठी 75      कुसमही कुवर 76      थुम्हवा पाण्डे 77      सुभिया 78      गदहपुर चक अगया हातिम 79      पिरैला गरीब 80      बैदौलिया 81      सोनबरसा 82      नकथर 83      गगवार 84      सफीपुर उर्फ नौवागाँव 85      बाके चौर 86      बरडाड नानकार	<b>6 घोषण न्याय पंचायत</b> 87      लछिमनपुर 88      सुदई डीहा 89      मझारी 90      परसा कुतुव 91      अचलपुर 92      धोसड 93      सखिया डीह 94      मझौवा लालसिंह 95      दिलावल चक 96      मिनहाड चक उर्फ तकिया 97      करायन 98      कौलपुर 99      बरगदवा 100      पटखौली 101      वाजिद जोत 102      कोटिया 103      मनकौरा 104      असुरैना 105      डढ़िया 106      खैरा

**7 भानपुर न्याय पंचायत**

107	सिसवा बुजुर्ग
108	परसौनिया
109	करहिया
110	बनटिकरा
111	धुम्हवा
112	पेलनी
113	बैदौला
114	कोपा
115	जोगिया
116	निकुरहा
117	भानपुर
118	सिसवा खुर्द
119	उकडा
120	कोनार
121	जमोहना
122	कडजहना
123	जगदीशपुर उर्फ नौगढ
124	बडहरा उर्फ मठिया
125	बहादुरपुर
126	धवाय
127	बडहरा बुजुर्ग

**8 रामनगर न्याय पंचायत**

128	मोहम्मदनगर
129	बसडिलिया
130	बस्ती नाथू
131	शनिचरा
132	पतरिया
133	माहबानू चक
134	चिरई बान्धा
135	कुतुबपुर
136	हिसामुद्दीन चक
137	असनहरा
138	राफिया चक
139	असनहरी
140	बस्ती अलावल
141	बनगवाँ
142	करौली
143	राढी जोत
144	बेइली
145	टेढी कोइयाँ
146	रिखियाँ
147	हथिअवा
148	पिपरा
149	मलपुरवा
150	तकिया चक
151	पचासी
152	बनवडिया
153	खुटहना
154	रामनगर
155	चेरुइया
156	बाराकोनी

**9 कलन्दरनगर न्याय पंचायत**

157	इटाहिया
158	शेखापुर चक दोस्त मोहम्मद
159	खाजेपुर
160	अढवा घाट
161	परसा खुर्द बुजुर्ग दरियापुर जगल
162	चेतरा
163	सादुल्लाहपुर
164	मैलानी साहेब वाजिद
165	कटया
166	वाहिद चक
167	जोगिया
168	धौरहरी
169	नकछेद चक उर्फ कलन्दरनगर
170	भैसहिया खुर्द बुजुर्ग

**10 बडोखर न्याय पंचायत**

171	पान कोइयाँ
172	रुस्तमपुर
173	मैलानी उर्फ बेलवा
174	मैलानी उर्फ हिदूनगर
175	नाथपुर
176	अमखला
177	बरगदहिया
178	सिलवटिया
179	लोढवा
180	पटखौली
181	माधोपुर
182	मनौडी
183	परसा शिवराज
184	पिपरा
185	बडोखर
186	भिगवापार
187	नकछेद चक
188	थरुआपुर
189	परसा खुर्द
190	नरकटहा
191	तुरकौलिया उर्फ करमहिया
192	तेन्दुआ असनहरा

# सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड

## 11 कोठिला खास न्याय पंचायत

193	बनरही जगल
194	आहर
195	मडक
196	आमा
197	परसा झुगिया
198	सरैनी
199	परसोहिया टप्पा कोठिला
200	परसा लगडा
201	परसोहिया टप्पा उमरा
202	शाहपुर
203	तेनुवा
204	गोपालपुर
205	मुडिला
206	गोविन्दपुर
207	भौखरी
208	भगवानपुर
209	करमहिया
210	फेरसम
211	सोन्हा
212	कोठिला खास
213	करौता उर्फ करलपुर
214	कटक
215	रामपुर
216	रखौलिया
217	कोठिया डीह
218	केवटा खोर
219	बस्ती
220	बिशम्भर चक
221	डमरी

## 13 दसिया न्याय पंचायत

241	फरेन्दिया
242	कमदा
243	हरिहरपुर
244	सिसवा बरूआर
245	सिहारी सरदहा
246	बढया सरदहा
247	सिहारी खुर्द
248	बसडीला
249	मौरी परासी
250	छनवतिया
251	मुन्डेरवा
252	रामबारी
253	पडरिया
254	परसा पुरई
255	मुगरहा
256	बरगदवा
257	सेखुई
258	बहादुरपुर
259	पिपरा रहीम
260	दसिया
261	सेहमू
262	गोबरहिया

## 12 पचमोहनी न्याय पंचायत

222	महनुआ
223	पकरी मोती
224	मिश्रौलिया
225	डगडोआ
226	कोठिली
227	महुवा डाबर
228	पडरी
229	सेखापुर
230	कोहडी
231	एकडगवा
232	लौकी
233	लपसी
234	पिपरी ठाकुर
235	मधवापुर
236	बरगदवा
237	पचमोहनी
238	बैरिहवा
239	जौता
240	करमा

## 14 परसा दमया न्याय पंचायत

263	केऊवा जप्ती
264	बालेडीहा
265	उमरा खास
266	बसौका
267	परसा दमया
268	बिशुनपुर
269	रतनपुर
270	करहा
271	करही
272	हटवा
273	पडरी चेतसिह
274	मनिकौरा
275	पडरिया धारीघाट
276	मुनियॉव
277	मझौवा बैकुण्ठ
278	मधवापुर
279	बगरिया
280	गोविन्दपुर
281	लेवारपार



15 पुरैना न्याय पंचायत	16 सल्टौवा गोपालपुर न्याय पंचायत
282 करमा पाठक 283 औराडीह 284 सुभई 285 मझौवा खजुरी 286 पुरैना 287 बसडीला 288 बसडिलिया 289 दुहवा 290 डडवा 291 पकरी चौबे 292 पोखर भिटवा 293 सिसवारी 294 बिछियागज 295 बिछिया आसरे 296 मुस्ताफाबाद	297 कनेथू बुजुर्ग 298 जसोवर 299 रेगी 300 बागडीह उर्फ गायसाथ 301 देई डीहा 302 रुदलपुर 303 परसा खाल 304 कनेथुई 305 बढया कलौ 306 खरहरा जप्ती 307 सल्टौवा गोपालपुर 308 परसा काशी 309 कोईलसा 310 मझौवा खुर्द 311 सिंहबरा 312 जोगिया जूडी कुइयों 313 सेवई 314 ककरहिया 315 भरवलिया 316 बिशुनपुर
17 पचानू न्याय पंचायत	18 भिरिया ऋतुराज न्याय पंचायत
317 सिकन्दरपुर 318 गोरखर 319 रमवापुर बाबू 320 गोहनिया 321 लेदवा 322 हसनपुर 323 दरहिया बुजुर्ग 324 बघौडी 325 रेहार जगल 326 धौरपारा 327 सूरतगढ 328 मुरादपुर 329 मनवा 330 बधनगाव चौबे 331 पचानू 332 देईपार खुर्द 333 देईपार बुजुर्ग 334 पिपरहिया 335 दरिया पट्टी 336 भितरी पचानू 337 झुलहनिया 338 मेहौरा 339 मझौवा खुर्द 340 भिटिया जालिमसिह 341 गौछा 342 महादेवा 343 पकरी भीखी 344 मोहम्मदपुर 345 धेनकी 346 पिपरी जप्ती 347 भितरा	348 औड जगल 349 तुरकौलिया 350 पिटउत 351 तेलिया डीह 352 बन्जरिया 353 परसौना 354 द्वारिका चक 355 चौकवा 356 सेखुई 357 भिटिया रितुराज 358 अमरौली शुमाली 359 सेउवा 360 बसथनवा 361 अमरौली जनूबी 362 चौरा

## 19 आमा न्याय पंचायत

363	ओरवलिया
364	अजगैबा
365	पचलौरिया
366	शिवपुर
367	सुल्तानपुर
368	सगर दिनवा
369	टिनिच शुकुल
370	बेलवा डाउ
371	कैथवलिया
372	बरगवों
373	साडी कलों
374	साडी हरनाम
375	साडी हिक्छा
376	आमा
377	इमिलिया महिपतसिह
378	बेदौलिया
379	डिगार भारी
380	घुरहूपुर
381	कोदारी
382	भभर गाडा
383	भदाना
384	बारह छतर
385	सबरिहवा
386	शिवगढ
387	बेतउहा
388	खडसरपुर
389	सेवई
390	बनकटा
391	चेतरा
392	बलुआ कुन्ड
393	सिधौनी

## 20 पिपरा जप्ती न्याय पंचायत

394	तबौहा
395	बलुई
396	डडिया खुर्द
397	रेहार बाबू
398	बॉसापारा
399	बानौ
400	छितहा
401	बरहिया दीगर
402	खोरियापुर
403	भनगवा बाबू
404	रमवापुर पाडे
405	जगतपुर
406	बखरिया
407	कोईलरा
408	बेनीपुर
409	कोईलरी
410	लबारापुर
411	भीटा इन्द्रजीतसिह
412	ससारपुर
413	महुआपार
414	जगदीशपुर
415	मझरिया बशराज
416	नेवादा
417	दुबोली
418	पडरी
419	बहेरिया
420	बेलौरी बरगाह
421	बेलौरी शुकुल
422	पिपरा जप्ती
423	सुकरौली
424	अतरा
425	चमरहुआ
426	हाथा खुर्द
427	सिधौनी
428	हरैया
429	नियामतपुर
430	करनपुर
431	देवरहरा
432	सकरीला
449	भादी खुर्द
450	मझरिया

## 21 जिनवा न्याय पंचायत

433	अगया
434	आमा
435	परसा कुसुम
436	बेलहसा
437	खरहरा शुकुल
438	जिनवा
439	नरायनपुर
440	बरहुआ
441	कल्यानपुर
442	पोखर भिटवा
443	रघुनाथपुर
444	धन्नी जीत
445	बहरामपुर
446	निबिया
447	लक्ष्मनपुर